{ संपादकीय }

नई दिल्ली, मंगलवार 30 जुलाई 2024

संस्थापक-सम्पादक : स्व. मायाराम सुरजन

राहुल के सामने भाजपा सरकार पस्त

सोमवार को लोकसभा में केन्द्रीय बजट पर अपना पक्ष रखते हुए विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने देश के सामने न केवल भारतीय जनता पार्टी सरकार को बेनकाब कर दिया वरन यह भी बतला दिया कि किस प्रकार से जनता को एक चक्रव्यूह में फंसाया गया है। वैसे उन्होंने दावा किया कि प्रतिपक्षी गठबन्धन इंडिया उस चक्रव्यूह को तोड़ देगा। किसान, मजदूर, छात्र, मध्यमवर्ग और इन सबके साथ वे पत्रकार जिन्हें संसद में एक कमरे में कैद करके रिपोर्टिंग करने कहा जा रहा है, उन सबके लिए राहुल ने आज सदन में आवाज़ उठाई।

राहुल ने अपने भाषण की शुरुआत में कहा कि महाभारत में उल्लिखित चक्रव्यूह का आकार कमल की तरह होता है जो भाजपा का निशान है। जैसे ही उन्होंने बतलाना शुरू किया कि जिस प्रकार से महाभारत में वर्णित चक्रव्यूह के केन्द्र में छह लोग (द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा और शकुनी) थे, वैसे ही भाजपायी चक्रव्यूह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह, अदानी, अंबानी, मोहन भागवत हैं, छठे का नाम लेने के पहले ही सदन में कोहराम मच गया। स्पीकर ने नियमों का हवाला देते हुए उन्हें ऐसे किसी व्यक्ति का नाम लेने से मना किया जो सदन का सदस्य नहीं है। राहुल ने एक तरफ से उन्हें ही फंसाते हुए पूछ लिया कि उनके (अदानी-अंबानी) लिये वे 'आखिर क्या कहकर संकेत करें कि लोग समझ जायें कि किसके बारे में कहा जा रहा है।' उन्होंने पूछा कि क्या उन्हें 'नंबर 3' और 'नंबर 4' कह सकते हैं या फिर ए 1 और ए 2 कहें। संसदीय मंत्री किरण रिजिजू ने जब उनसे संसदीय मर्यादा का पालन करने को कहा तो राहुल ने उन पर तंज कसा कि 'मंत्री को ऊपर से आदेश है कि उनकी (अदानी-अंबानी) की रक्षा की जाये।' बिरला हमेशा की तरह सरकार के पक्ष में खड़े दिखलाई दिये। अध्यक्ष बार-बार कहते रहे कि वे विपक्ष के नेता से उम्मीद करते हैं कि वे संसद के नियमों का पालन करेंगे। उन्होंने कई बार यह भी बतलाया कि स्वयं सदन में कांग्रेस संसदीय दल के उप नेता ने यह आग्रह किया है कि ऐसे लोगों का नाम न लिया जाये जो कि सदन के सदस्य नहीं हैं। वैसे एक बार और अदानी-अंबानी के नाम लेकर राहुल ने माफी तो मांग ली परन्तु माना जाता है कि ऐसा उन्होंने रणनीति के तहत किया।

अपनी चक्रव्यूह वाली बात को आगे बढ़ाते हुए राहुल ने कहा कि नोटबन्दी, जीएसटी, तीन कृषि कानून, अग्निपथ जैसी योजनाओं के जरिये लोगों को चक्रव्यूह में फंसाया गया है। वैसे उन्होंने भरोसा जताया कि इंडिया के पास इस चक्रव्यूह को तोड़ने के उपाय हैं। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना (मनरेगा), किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी और जातिगत जनगणना के जरिये जनता को फंसाये गये चक्रव्यूह को काटा जायेगा। ये दोनों बातें कांग्रेस के घोषणापत्र में भी थीं, लेकिन राहुल ने सदन के भीतर इनका ऐलान करके बता दिया कि ये बातें महज चुनावी नहीं हैं, राहुल इनके जरिए न्याय की एक नयी नींव देश में रखने की तैयारी में हैं।

राहुल ने कहा कि वर्तमान में बजट का पूरा लाभ मुट्ठी भर लोगों को मिल रहा है। उन्होंने इसका कारण यह बतलाया कि गिने-चुने लोगों द्वारा बजट तैयार किया जाता है जिनमें कोई भी आदिवासी नहीं होता और न ही कोई दलित या पिछड़ा वर्ग का अधिकारी। उन्होंने साफ कहा कि जब तक ऐसा होगा समाज के निचले वर्गों को इस बजट का कोई फायदा नहीं होगा। राहुल गांधी ने वह तस्वीर दिखलानी चाही जिसमें वे अधिकारी थे जिन्होंने बजट तैयार किया है। उन्होंने कहा कि इसमें कोई भी अधिकारी वंचित समाज का नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष की नामंजूरी के पहले ही वे इस चित्र को दिखाने में कामयाब रहे। इस पर काफी शोर-शराबा तो हुआ लेकिन राहुल का उद्देश्य पूरा हो चुका था। हताश विपक्ष ने राहुल को उनके द्वारा हिन्दू धर्म का उल्लेख करने के वक्त भी शोर मचाकर उन्हें फंसाने की कोशिश की परन्तु नाकामयाब रहे। सत्ता दल के सदस्य फिर से एक बार इस बात का प्रयास करते नज़र आये कि वे इस बात को मुद्दा बना सकें कि राहुल हिन्दू धर्म का अपमान कर रहे हैं पर वे इसमें बिलकुल ही कामयाब नहीं हुए।

वैसे तो इनमें से अनेक ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें राहुल लगातार सदन के भीतर व बाहर उठा रहे हैं परन्तु सोमवार का उनका भाषण बजट पर चर्चा के दौरान होने से उसका अतिरिक्त महत्व है। देखना यह होगा कि लोकसभा अध्यक्ष उनके भाषण का कितना हिस्सा रहने देते हैं और कितना रातों-रात विलोपित करते हैं। नेता प्रतिपक्ष के पूरे भाषण में टोका-टाकी करते हुए बिरला ने कई बार सरकार का बचाव करने की कोशिश की, जैसा वे हमेशा करते आये हैं। सत्ता पक्ष से रिजिजू के भी प्रयास इस दिशा में असफल होते नज़र आये और राहुल के भाषण की भरपूर सराहना हो रही है जो सरकार के लिये चिंता का विषय हो सकता है। इसके साथ ही राहुल के भाषण के दौरान मोदी की अनुपस्थिति भी मुद्दा बनी। राहुल ने कहा कि वे जानते हैं कि जब भी वे भाषण देंगे, पीएम सदन में आयेंगे ही नहीं। इस प्रकार से भी प्रधानमंत्री को आईना दिखाने में राहुल ने कोताही नहीं बरती। सरकार व भाजपा राहुल के सामने बेबस नज़र आई। राहुल का आज का भाषण देश बरसों तक याद रखेगा। संसद के विशेष सत्र में भी राहुल के भाषण का जवाब देने की कोशिश में मोदी ने उन्हें बालक बुद्धि कहा था, हो सकता है, अब मोदी किसी और तरह से राहुल पर हमला करें, लेकिन इन हमलों से क्या उन सवालों को भाजपा खत्म कर पाएगी, जो राहुल ने उठाए हैं।

चोरी की जीत के सिकंदर ?

बेशक, 4 जून की मतगणना के बाद, नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बावजूद, इस चुनाव के जनादेश की प्रकृति पर और संघ-भाजपा के जीत के दावों पर, गंभीर सवाल उठे हैं और अब तक बने हुए हैं। ये सभी सवाल, जो संघ-भाजपा के 'जो जीता वही सिकंदर' के तर्क पर टिके जीत के दावों को प्रश्नांकित करते हैं, इस कथित जीत पर मुख्यत: दो पहलुओं से सवाल उठाते हैं। पहला, यह कथित जीत किन परिस्थितियों में और किस तरह हासिल की गयी है और इसलिए क्या इसे वाकई जीत माना जा सकता है ? इस पहलू से उठे सबसे महत्वपूर्ण सवाल इस चुनाव की प्रकृति और चुनाव आयोग द्वारा चुनाव के संचालन से संबंधित थे। यह बलपूर्वक दर्ज किया गया था कि ये चुनाव व्यवहार में, पूरी तरह से गैर-बराबरी के मैदान में हो रहे थे, जहां सत्ता पक्ष को पहले ही हर प्रकार से बढ़त हासिल थी, जबकि विपक्ष को हाथ पीठ के पीछे बांधकर लड़ना पड़ रहा था।

मोदी राज के दस साल में, चुनावी बांड समेत विभिन्न तरीकों से आर्थिक संसाधनों के अनुपातहीन तरीके से सत्ताधारी दल के पक्ष में और विपक्ष के खिलाफ मोड़े जाने ने और इजारेदारों के द्वारा पैसा लगाए जाने की इसी प्रक्रिया के हिस्से के तौर पर, मीडिया में सत्ताधारी दल के लगभग पूर्ण बोलबाले ने, चुनावी मुकाबले को जितना असमानतापूर्ण बना दिया था, वह किसी भी वस्तुगत टीकाकार से छिपा नहीं था। इसके ऊपर से सत्ता के अधिक से अधिक तानाशाहीपूर्ण होते आचरण ने, इस ऊंचे-नीचे मैदान को जिस तरह किसी वास्तविक मुकाबले के लिए और भी अनुपयुक्त बनाया था, वह भी किसी से छुपा हुआ नहीं था। केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर, चुनाव की पूर्व-संध्या में दो-दो मुख्यमंत्रियों को, जो अपनी-अपनी पार्टियों के शीर्ष नेता भी हैं, जेल में बंद कराए जाने से लेकर, विरोधी राजनीतिक पार्टियों के खाते जाम कराए जाने तक, इस चुनाव के ऐन पहले तथा चुनाव के दौरान हुई अभूतपूर्व ज्यादतियों को भी, सभी ने कम से कम दर्ज जरूर किया था।

कोढ़ में खाज यह कि चुनाव आयोग ने, जिसके ऊपर स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी थी, मुकाबले के मैदान को पूरी तरह से ऊबड़-खाबड़ तथा वास्तव में अखेल्य बनाने वाली, इन तमाम स्थितियों को न सिर्फ प्रदत्त या सामान्य मानकर स्वीकार कर लिया था बल्कि खुद भी अपनी करनियों और अकरनियों से, मुकाबले को और एकतरफा बनाने में सक्रिय रूप से योग दिया था। खुद प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, सत्ताधारी दल द्वारा अपने अल्पसंख्यकविरोधी सांप्रदायिक रुख के अनुरूप, खुल्लमखुल्ला सांप्रदायिक प्रचार किए जाने को, देश के चुनाव कानून तथा आदर्श चुनाव संहिता के तहत स्पष्ट मनाही के बावजूद, जिस तरह चुनाव आयोग ने चलने दिया था और हर तरफ से शिकायतें आने के बावजूद, अंत-अंत तक कोई कार्रवाई नहीं की थी, उसे भी सभी ने दर्ज किया था।

दुर्भाग्य से चुनाव आयोग का यह पक्षपात, सत्तापक्ष के अतिक्रमणों के बचाव तक ही सीमित नहीं रहा था। यह पक्षपात खुद उसके सत्तापक्ष के सांप्रदायिक रुख के रंग में रंगने तक भी जाता था और इसके चलते, चुनाव से पहले अनेक स्थानों पर बड़ी संख्या में अल्पसंख्यकों के नाम मतदाता सूचियों से काटे जाने से लेकर, मतदान के दौरान कई चुनाव क्षेत्रों में बड़ी संख्या में अल्पसंख्यकों तथा अन्य कमजोर तबके के लोगों को मताधिकार से वंचित किए जाने तक की शिकायतें सप्रमाण सामने आयीं, जिन्होंने चुनाव की निष्पक्षता पर ही सवाल खड़े कर दिए। दुर्भाग्य से चुनाव आयोग इतने पर भी नहीं रुका। चुनाव के दौरान उसने चरणवार मतदान के पूरे आंकड़े देने में अनुचित देरी लगाई और सुप्रीम कोर्ट तक विवाद पहुंचने के बाद जब देरी से अंतिम आंकड़े जारी भी किए, मतदान के दिन ही देर शाम को जारी मतदान के कच्चे आंकड़ों और अंतिम आंकड़ों में संदेहास्पद तरीके से भारी और असामान्य अंतर था।

दूसरा पहलू खुद उस जनादेश का था, जो 4 जून को हुई मतगणना में निकल कर सामने आया था। बेशक, इस मतगणना से निकला नतीजा ही था कि नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। लेकिन, इसी मतगणना से दूसरे उल्लेखनीय नतीजे भी निकले थे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण नतीजा तो यही था कि सत्ताधारी भाजपा, पिछले दो चुनावों के विपरीत, बहुमत से काफी पीछे, 240 के आंकड़े पर ही अटक गयी थी और इसके चलते अपने गठबंधन के सहयोगी दलों के समर्थन के बल पर ही, बहुमत का आंकड़ा पार कर पाई थी। इस तरह, इस चुनाव का जनादेश, सत्ताधारी भाजपा को सत्ता से दूर रखे जाने और सहयोगी पार्टियों के सहारे ही सरकार बनाने दिए जाने का जनादेश था। चार सौ पार के नारे और मोदी के चेहरे तथा मोदी की गारंटी के हथियार के सहारे चुनाव मुकाबले में उतरी, सत्ताधारी भाजपा और उसके सुप्रीमो के अपराजेयता के अहंकार के टूटने का जनादेश था। यह सत्ताधारी पार्टी की राजनीतिक व नैतिक हार का जनादेश था।

फिर भी, इस चुनाव नतीजे के फलस्वरूप एक बार फिर मोदी के नेतृत्व में, बेशक एनडीए की सरकार का बनना, स्वयंसिद्ध मान लिया गया था। कम से कम इस चुनाव नतीजे पर छुट-पुट सवालों के सिवा कोई बड़ा सवाल नहीं था कि भाजपा-240 तथा एनडीए 292 और इंडिया 232। लेकिन अब, महाराष्ट्र के एक प्रतिष्ठित नागरिक अधिकार मंच, वोट फॉर डैमोक्रेसी (वाइएफडी) ने एक विस्तृत रिपोर्ट जारी कर, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाने से आगे जाकर, चुनाव नतीजे की इन संख्याओं पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं और पूछा है कि एनडीए की कथित जीत भी कहीं चोरी की जीत तो नहीं है !

राजेंद्र शर्मा

> अपने तमाम सवालों के संदर्भ में वाईएफडी ने सभी संदेहों तथा आरोपों की 'स्वायत्त निगरानी में एक स्वतंत्र जांच' की मांग की है, जिस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बहरहाल, फिलहाल इस तरह की जांच की ज्यादा संभावना भले ही नहीं लगे, वाईएफडी की रिपोर्ट ने चुनाव आयोग की भूमिका और निष्पक्षता से जुड़े उन सभी सवालों को नये सिरे से उठा दिया है, जो इस आम चुनाव के दौरान लगातार उठते रहे थे।

वाईएफडी की रिपोर्ट में मतदान के सभी चरणों में मतदान की शाम को जारी मत प्रतिशत के आंकड़ों और मतदान के अंतिम आंकड़ों में भारी और असामान्य अंतर की विशेष रूप से गहराई से छानबीन की गयी है। रिपोर्ट रेखांकित करती है कि मतदान के फौरन बाद जारी आंकड़ों और अंतिम आंकड़ों में लगभग 5 करोड़ (एकदम सटीक संख्या 4,65,46,885) वोट का अंतर है। रिपोर्ट रेखांकित करती है कि इससे पहले के चुनावों में मतदान की शाम जारी किए जाने वाले कच्चे मतदान अनुमान और मतदान की अंतिम गणना के बीच 1 फीसद से ज्यादा वृद्धि कभी दर्ज नहीं की गयी थी। लेकिन, 18वीं लोकसभा के चुनाव के सभी सात चरणों में यह अंतर 3.2 से 6.32 फीसद के बीच रहा है, जो पूरी तरह से असामान्य है। रिपोर्ट बताती है कि यह अंतर 'आंध्र प्रदेश में 12.54 फीसद और ओडिशा में 12.48 फीसद' रहा है, जबकि कुल मिलाकर इस अंतर का औसत 4.72 फीसद बैठता है।

वाईएफडी की रिपोर्ट की इस टिप्पणी से शायद ही कोई असहमत होगा कि 'ईसीआई ने अब तक इस बढ़ोतरी के पीछे कोई विश्वसनीय कारण नहीं बताया है।' याद रहे कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान भी, विवाद के सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंचने के बाद, जब चुनाव आयोग ने देरी से ही सही अंतिम आंकड़े जारी करना शुरू किया था, उसी समय वोट में इस असामान्य बढ़ोतरी पर विपक्ष की ओर से और निष्पक्ष प्रेक्षकों द्वारा भी काफी सवाल उठाए गए थे। एक पूर्व-मुख्य चुनाव आयुक्त ने बाकायदा अंतिम आंकड़े जारी किए जाने में देरी और इस भारी अंतर को "समझ में न आने वाला" तक कहा था। जाहिर है कि तब भी चुनाव आयोग इसकी कोई विश्वसनीय सफाई पेश नहीं कर पाया था। बहरहाल, चुनाव आयोग की चुनाव के मामले में सर्वाधिकार-संपन्नता के दबाव में और चुनाव की हड़बड़ी में, यह मामला इसलिए दबकर रह गया कि यह सीधे चुनाव आयोग की ईमानदारी पर सवाल खड़ा करता था। बहरहाल, अब वाईएफडी की रिपोर्ट में जोरदार तरीके से यह सवाल उठाया गया है।

इस असामान्य बढ़ोतरी के सवाल को उसके तार्किक निष्कर्ष तक ले जाते हुए, वाईएफडी का अध्ययन बताता है कि जिन 15 राज्यों में अंतिम मतदान प्रतिशत में यह असाधारण बढ़ोतरी दर्शायी गयी थी, उनमें 79 सीटों पर भाजपा के नेतृत्ववाले एनडीए की जीत का अंतर, वोट में हुई इस बढ़ोतरी से कम था यानी वोट में यह बढ़ोतरी, इन सीटों के नतीजे को बदलने के लिए काफी थी। इनमें ओडिशा की 18, महाराष्ट्र की 11, प. बंगाल की 10, आंध्र प्रदेश की 7, कर्नाटक की 6, छत्तीसगढ़ तथा राजस्थान की 5-5, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश तथा तेलंगाना की 3-3, असम की 2 और अरुणाचल प्रदेश, गुजरात तथा केरल की एक-एक सीटें शामिल थीं।

इसके अलावा वाईएफडी की रिपोर्ट में यह भी रेखांकित किया गया है कि 10 राज्यों में एनडीए के 18 उम्मीदवारों ने, बहुत मामूली अंतर से जीत हासिल की है। ये सभी ऐसे चुनाव क्षेत्र हैं जहां नागरिक समाज के सदस्यों और विपक्षी उम्मीदवारों ने, मतदान के और मतगणना के दौरान, ईवीएम की खराबी और गड़बड़ियों की गंभीर शिकायतें दर्ज कराई थीं। इनमें बिहार में सारण, महाराष्ट्र में उत्तर-पश्चिम मुंबई, उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद, बांसगांव तथा फूलपुर आदि सीटें शामिल हैं, जहां से एनडीए के उम्मीदवार बहुत कम अंतर से जीते हैं। इस सब के आधार पर रिपोर्ट यह वैध सवाल उठाती है कि इस चुनाव में एनडीए की जीत, एक चुराई गई जीत भी हो सकती है।

अपने तमाम सवालों के संदर्भ में वाईएफडी ने सभी संदेहों तथा आरोपों की 'स्वायत्त निगरानी में एक स्वतंत्र जांच' की मांग की है, जिस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बहरहाल, फिलहाल इस तरह की जांच की ज्यादा संभावना भले ही नहीं लगे, वाईएफडी की रिपोर्ट ने चुनाव आयोग की भूमिका और निष्पक्षता से जुड़े उन सभी सवालों को नये सिरे से उठा दिया है, जो इस आम चुनाव के दौरान लगातार उठते रहे थे। यह रिपोर्ट याद दिलाती है कि भारत के चुनाव आयोग के साथ सब कुछ ठीक किसी भी तरह से नहीं है, कि मौजूदा चुनाव आयोग डा. आम्बेडकर द्वारा संविधान में संबंधित धाराओं पर बहस के दौरान व्यक्त की गई इसकी आशंकाओं को सच साबित करता लगता है कि संविधान में रोक-थाम के प्रावधान के अभाव में, चुनाव आयुक्त (अब मुख्य चुनाव आयुक्त) बनने वाला, चुनाव आयोग को 'कार्यपालिका के अंगूठे के नीचे' पहुंचा सकता है। इस लिहाज से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के संबंध में पिछले ही वर्ष संसद द्वारा बनाये गये नये कानून का प्रतिरोध महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित की गई प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय कमेटी में से, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को निकालकर और उसकी जगह पर प्रधानमंत्री द्वारा नामजद एक अन्य मंत्री को शामिल कर, नियुक्ति समिति में और उसके जरिए चुनाव आयोग में, कार्यपालिका की ही मनमर्जी चलना सुनिश्चित किया गया है। चुनाव आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित किए बिना, चुनाव की स्वतंत्रता तथा निष्पक्षता भी सुनिश्चित नहीं की जा सकती है।

(लेखक साप्ताहिक पत्रिका लोक लहर के संपादक हैं।)

गंगा के उपासक जीडी : अविरलता के लिए आत्मोत्सर्ग

■ राजेन्द्र सिंह

प्राकृतिक मूल्यों को सर्वोपरि मानने वाले ऋषि और गंगा की अविरलता बनाए रखने की खातिर 111 दिन के उपवास के बाद प्राण त्यागने वाले प्रोफेसर जीडी यानि गुरुदास अग्रवाल उर्फ स्वामी ज्ञानस्वरूप सानंद का स्मरण मुझे हर क्षण बना ही रहता है। मैंने जब उनसे 'तरुण भारत संघ' के संचालक मंडल का सदस्य बनने के लिए कहा तो उसका विधान पढ़कर वे बोले - मैं तुम्हारा सदस्य नहीं बन सकता, क्योंकि यह विधान तो मानवीय मूल्यों को सर्वोपरि मानकर बनाया गया है। मैं तो प्रकृति को सर्वोपरि मानता हूं। वे बोले- मैं तो मानव को प्रकृति का एक मामूली-सा अंग मानता हूं; इसलिए मानव मेरे लिए सर्वोपरि नहीं हो सकता।

स्वामी सानंद अपने मित्र और वकील महेशचन्द्र मेहता के साथ जुलाई 2007 में गंगोत्री जाते समय 'लोहारी-नागपाला परियोजना' द्वारा गंगा को गायब होते देखकर बहुत दुखी हुए थे। उसी समय उन्होंने गंगा का नए तरीके से चिंतन आरंभ किया था। इन्हीं दिनों वे राजस्थान की छोटी, सूखी नदी अरवरी को कल-कल बहते देखकर गए थे। उन्हें लगा जब छोटी नदी दुबारा बह सकती है, तो गंगा को भी शुद्ध-सदानीरा बना सकते हैं। उन्होंने गंगा का शुद्ध-सदानीरा बनाना ही अपने जीवन का एक मात्र लक्ष्य बना लिया।

> प्रो. जीडी अग्रवाल को पर्यावरण व गंगा के विज्ञान, अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिक संबंधों की गहराई और पर्यावरणीय प्रवाह की जितनी समझ थी, उतनी आज किसी की नहीं है। वे प्राकृतिक मूल्यों को भारतीय आस्था और पर्यावरणीय रक्षा का आधारभूत विज्ञान मानते थे। उनका जीवन, सामाजिक संस्कार, भारतीय आस्था, पर्यावरणीय रक्षा के आधार की गहरी समझ व शक्ति थी।

उन्होंने वर्ष 2007 के अंत में कहा कि अभी तक तो मैं छोटे-छोटे बांधों को बड़े बांधों का विकल्प मानकर बनवाने का काम प्रायश्चित के तौर पर कर रहा था, लेकिन प्रायश्चित के लिए 20 वर्ष बहुत हैं। अब मैं बड़े बांधों को तुड़वाने, रुकवाने व आगे नहीं बनने देने के काम में लगूंगा। गंगा को अब सघन चिकित्सा की आवश्यकता है। चिकित्सा मैं कर सकता हूं, लेकिन सरकार मेरी चिकित्सा को नहीं मानेगी। वह तो गंगा माई से भी कमाई करना चाहती है।

मैं सबसे पहले गंगा से कमाई के सभी रास्ते बंद करूंगा। मां गंगा मेरी आस्था की माई हैं। उनसे मैं स्वयं कोई कमाई नहीं करूंगा, किसी को करने भी नहीं दूंगा। यह बात सरकार मेरे बारे में जानती है, इसलिए वह मुझे गंगा के काम में अपने साथ नहीं जोड़ेगी, न ही मुझे काम करने देगी। मेरा सरकारों के साथ काम करने का लम्बा अनुभव है। मैं अच्छे से जानता हूं कि सरकार का विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियान्त्रिकी की प्रज्ञा से या संवेदना-समझदारी से कोई रिश्ता नहीं होता।

मैं अपनी मां गंगा की खातिर उसकी अविरलता हेतु सत्याग्रह करूंगा। मां गंगा को निर्मल बनाने का काम तो कमाई का धंधा है। उस धंधे को करने वालों की सरकार के पास बहुत बड़ी भीड़ मौजूद है। वे तो उसी धंधे के नाम पर मां का सभी कुछ लूट रहे हैं। वे लूटते रहें, उन्हें रोकने वाली ताकत भी एक दिन खड़ी होगी। इस अविरलता के काम को पूरा करके हम बाद में भ्रष्टाचार को रोकने में भी लगेंगे।

जीडी अग्रवाल का कहना था कि जो कुम्भ कभी सत्य की खोज के लिए शुरू हुआ था, वही कुम्भ अब गंगा की पवित्रता, निर्मलता, अविरलता पर विचार नहीं करके उसे और अधिक गंदा ही करता है। गंगा जी जब तक स्वस्थ होवें, अपने गंगत्व की विशिष्टता को पुन: प्राप्त करें, तब तक गंगा किनारे कुम्भ आयोजित करने पर रोक लग जानी चाहिए। यह बात कोई सच्चा आस्थावान भारतीय ऋषि ही बोल सकता है। ये बात वे बड़ी नम्रता से मुझसे कई बार बोले थे। कुम्भ पर रोक लग जायेगी तो समाज गंगा का गंगत्व बचाने में जुट जायेगा।

जीडी अग्रवाल ने अमेरिका के बर्कले विश्वविद्यालय के इतिहास में सबसे कम समय में अपनी पीएचडी की थी। आईआईटी-कानपुर में 17 साल पढ़ाने के बाद 1979 में वे 'केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल' के पहले सदस्य-सचिव बने। सरकार में अपनी ईमानदारी के कारण वे कभी भी किसी के चहेते नहीं रहे। उनका गुरुत्व सरकार को बहुत भारी होता था। आज की सरकार ने तो उन्हें खा ही लिया। इसको प्रो. जीडी अग्रवाल का जाना कभी-न-कभी बहुत भारी पड़ेगा।

प्रो. जीडी अग्रवाल को पर्यावरण व गंगा के विज्ञान, अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिक संबंधों की गहराई और पर्यावरणीय प्रवाह की जितनी समझ थी, उतनी आज किसी की नहीं है। वे प्राकृतिक मूल्यों को भारतीय आस्था और पर्यावरणीय रक्षा का आधारभूत विज्ञान मानते थे। उनका जीवन, सामाजिक संस्कार, भारतीय आस्था, पर्यावरणीय रक्षा के आधार की गहरी समझ व शक्ति थी।

उनके अंदर असाधारण ठहराव था। 'मातृ सदन, हरिद्वार' में चिमटा गाड़ दिया था। अंत तक वहीं उनका चिमटा गड़ा रहा, वे वहीं गंगा में रम गए। वहीं पर वे सबसे मिलते थे। बाबा रामदेव हों या उनके गुरू स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, सभी से वे बहुत बार मिलते थे। स्वामी शिवानंद सरस्वती के प्रति उनका बहुत विश्वास था। उनकी बुराई करने वाले बहुत लोग उनके पास पहुंचते थे, उन्हें भी वे अच्छे से सुनते थे।

उनके कई अधूरे काम हैं। 10 अक्टूबर 2018 को 'गंगा पर्यावरणीय प्रवाह' भारत सरकार ने प्रकाशित कर दिया था। वह आज भी गंगा या भारत की किसी भी दूसरी नदी में कहीं भी प्रभावी रूप में लागू नहीं है। स्वामी सानंद को यह दस्तावेज गंगा में स्वीकार नहीं था, फिर भी जो है वह भी लागू नहीं है। केवल यह प्रकाशित कराके भारत सरकार ने प्रस्तुत कर दिया है। गंगा मंत्री नितिन गडकरी ने 'गंगा संरक्षण प्रबंधन प्रारूप' का दिसम्बर 2018 तक गजट-नोटिफिकेशन करने और कानून बनाने का 'गांधी शांति प्रतिष्ठान' की बैठक में पहुंचकर वायदा किया था।

'गंगा संरक्षण प्रबंधन अधिनियम' को दिये हुए 9 वर्ष बीत गए हैं। स्वामी सानंद ने वर्ष 2012 में ही पहला प्रारूप पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को दिया था। फिर 2014 में उमा भारती को भी दिया। इन्होंने उस पर एक और सरकारी प्रारूप तैयार कराया था। 2018 में वह भी तैयार हो गया था। उस प्रारूप के विरोधाभास पर हमने दिल्ली में चर्चा कराई थी। उसमें भी गडकरी जी ने आकर स्वामी सानंद को लिखित में वायदा दिया था। उसके बाद बनारस, इलाहाबाद, कानपुर में चर्चा भी कराई थी।

सरकार ने अब यह कानून ठंडे बस्ते में रख दिया है, क्योंकि सरकार काशी में चबूतरा और जल वाहक प्लेटफार्म बनाने में लगी हुई है। कानून के काम को स्वयं मंत्री नितिन गडकरी ने ही रुकवा दिया। उन्हें गंगा जी पर ही चार धाम रोड बनाना था। इस कानून को लागू होने से तो गंगा जी को संरक्षण मिलना था। गंगा में विकास के नाम पर विनाश कार्य रोकने वाला 'गंगा संरक्षण प्रबंधन कानून' का प्रारूप अब तो सरकारी तौर पर भी तैयार है, लेकिन इसे संसद में प्रस्तुत नहीं किया गया है। कानून बन जाये तो मां की चिकित्सा ठीक से आरंभ हो सकती है। सानंद जी अपनी मां को स्वस्थ्य नहीं देख पाये। सानंद जी को देखने वाले गंगा मां को स्वस्थ्य देख पायें, ऐसी उम्मीद है।

(लेखक 'तरूण भारत संघ' के अध्यक्ष एवं 'जल बिरादरी' के राष्ट्रीय समन्वयक हैं।)

https://t.me/AllNewsPaperPaid

आपके पत्र

मनु भाकर ने कांस्य पदक जीतकर भारत के लिए जगाई उम्मीद

मनु भाकर ओलंपिक का कांस्य पदक जीतकर भारत के लिए पदक बटोरने की शुरुआत कर दी है। इस बार देश को 7 से अधिक ओलंपिक पदक मिलने की आशा है और पहला पदक देशवासियों के लिए उत्साह और उमंग बढ़ाने वाला है। गत कुछ वर्षों से देश का युवा वर्ग इस विश्व की सबसे कठिन प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए जागृत हुआ है। इसमें सरकार द्वारा दी गई सुविधाएं, कारपोरेट जगत का भरपूर सहयोग के साथ इस बार भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने भी ओलंपिक के लिए करोड़ों रुपए की राशि दी है। जिसके चलते खिलाड़ियों को प्रशिक्षण लेने और पौष्टिक आहार इंस्ट्रूमेंट आदि की पूरी सुविधाएं उपलब्ध कराना बहुत सहयोगी सिद्ध हो रही है।

अभी तक देश में सिर्फ क्रिकेट के प्रति ही दीवानगी है और क्रिकेटरों को करोड़ों रुपए के विज्ञापनों के ऑफर मिल जाते हैं। अब उद्योग जगत को ऐसे ही ऑफर ओलिंपिक खिलाड़ियों को भी देना चाहिए। सिर्फ पदक विजेताओं को ही नहीं, ओलंपिक में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों को विज्ञापन ऑफर किया जाना चाहिए ताकि वह और अधिक उत्साह से खेलों के लिए तैयारी कर सके और भारत पदक तालिका में निरंतर ऊपर बढ़ता जाए !

-सुभाष बुड़ावन वाला, रतलाम एमपी

ललित सुरजन की कलम से

राहुल! आप किस सोच में डूबे हैं ?

'नेहरूजी ने संगठन की कभी परवाह नहीं की। उनका ध्यान हर समय आम जनता की ओर ही लगा रहता था। पार्टी में अनेक वरिष्ठ व प्रभावशाली साथी उनकी नीतियों और विचारों से असहमत रहते थे लेकिन खुलकर विरोध इसीलिए नहीं करते थे कि वे जनता के दिलों में वास करते थे। 1952 के आम चुनावों के पहले संगठन के कर्णधारों ने उन्हें चुनौती देने की ठानी थी। उनके इशारे पर 1951 में मध्यप्रदेश के गृहमंत्री डी.पी. मिश्र ने पद से इस्तीफा देकर विद्रोह का बिगुल बजाया था, लेकिन उनकी यह दुरभिसंधि सफल नहीं हो सकी। उल्टे मिश्राजी को ही ग्यारह-बारह साल का वनवास भुगतने पर विवश होना पड़ा। इंदिराजी के समय भी ऐसे षड़यंत्र रचे गए जो सफल नहीं हुए। फर्क इतना था कि अजातशत्रु नेहरू क्षमा करना जानते थे। वह गुण इंदिराजी में नहीं था। इतना सब लिखने का प्रयोजन यही है कि आपको जनता के बीच जाकर ताकत हासिल करना चाहिए। आपका अपना राजनैतिक भविष्य भी उसी पर निर्भर करता है।'

(देशबन्धु में 4 जुलाई 2019 को प्रकाशित)

पावन प्रसंग

शुभ संकल्प अपनाएं

कई बार मनुष्य अपने अनुचित कार्यों या आदतों के संबंध में दुखी भी होता है और सोचता है कि उन्हें छोड़ दूं। अवांछनीय अभ्यासों की प्रतिक्रिया उसने देखी-सुनी भी होती है। परामर्श उपदेश भी उसी प्रकार के मिलते रहते हैं, जिनमें सुधारने-संभालने के लिए कहा जाता है। सुनने में वे परामर्श सारगर्भित भी लगते हैं। किंतु जब छोड़ने की बात आती है तो मन मुकर जाता है, अभ्यस्त ढर्रे को छोड़ने के लिए सहमत नहीं होता है। नशेबाजों में यही प्रक्रिया आए दिन चरितार्थ होते देखी जाती है। आर्थिक तंगी, बदनामी, शरीर की बर्बादी, परिवार में मनोमालिन्य जैसी हानियां प्रत्यक्ष रहती हैं। उनका अनुभव भी होता है, छोड़ने को जी भी करता है पर जब तलब लगती है, तब सब सोचा-समझा बेकार हो जाता है। आदत उभर आती है और अपना काम करने लगती है। बार-बार सुधरने की बात सोचने और समय आने पर उसे न कर पाने से मनोबल टूटता है। बार- बार टूटने पर वह इतना दुर्बल हो जाता है कि यह विश्वास ही नहीं जमता कि उनका सुधार हो सकता है. कल्पना करने लगता है कि जिंदगी ऐसी ही बीतेगी। आदतों से किसी भी प्रकार छुटकारा न मिल सकेगा।

आश्चर्य की बात यह है कि मनुष्य अपने मन का स्वामी है। शरीर पर भी उसका अदिकार है। सामान्य जीवन में वह अपनी अभिरुचि के अनुरूप सोचता है और आवश्यकानुसार कार्य करता है। यही स्वाभाविक भी है और इसी विधा को चरितार्थ होते हुए भी देखा जाता है। फिर दुष्प्रवृत्तियों के संबंध में ही ऐसी क्या बात है, जिसके कारण वे चाहते हुए भी नहीं छूटतीं ? प्रयत्न करने पर भी भूत की तरह सिर पर लदी रहती हैं ? अंधविश्वास, कुप्रचलन इसी आधार पर अपनी जड़ जमाए हुए हैं। अनेक कुरीतियां ऐसी हैं जिन्हें बुद्धि और तर्क के आधार पर हर कोई अस्वीकार ही करता है, किंतु जब करने का समय आता है, तो पुराने ढर्रे पर चल पड़ते हैं। खर्चीली शादियों के संबंध में यही बात आमतौर पर देखी गई हैं। दहेज, प्रदर्शन और प्रचलित रीति-रिवाजों का जंजाल सभी को कष्टकारक, असुविधाजनक खर्चीला, मूर्खतापूर्ण होने के कारण विचारशीलता उसके विरुद्ध ही रहती है, इतने पर भी समय आने पर पुराना ढर्रा ही हावी हो जाता है और वही करना पड़ता है, जिसे न करने की बात अनेकों बार सोची थी। ऊंचा उठने के संबंध में तो और भी अधिक अड़चन है। महापुरुषों के कुछ अपने गुण, कर्म और स्वभाव ही ऐसे होते हैं, जो महत्वपूर्ण लोकोपयोगी कार्यों में लगते हैं. अवरोधों से जूझते हुए लक्ष्य तक पहुंचने का साहस प्रदान करते हैं। उन्हें अनुकरणीय और अभिनंदनीय माना जाता है। उनकी उपलब्धियों, प्रशंसा, प्रतिष्ठा को देखकर अनेकों का मन चलता है कि हमें भी यह सुयोग्य मौका मिला होता तो कितना अच्छा होता। इस दिशा में वे सोचते तो बहुत कुछ हैं. पर बन पड़े ऐसा कुछ कर नहीं पाते।

युग निर्माण .योजना

प्रकाशक, मुद्रक : राजीव रंजन श्रीवास्तव द्वारा पत्रकार प्रकाशन प्रा. लि. के लिए 506, आई.एन.एस. बिल्डिंग, 9, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित एवं बीएफएल इंफोटेक लि., सी 9, सेक्टर-3, नोएडा से मुद्रित। सम्पादक : राजीव रंजन श्रीवास्तव, (पी.आर.बी. एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार)। आर.एन.आई. नं. DELHIN/2008/24216. दिल्ली कार्यालय :फोन: 011-23718195,23357784, फैक्स: 011-43581404, नोएडा कार्यालय: फोन: 0120-4114404 फैक्स: 0120-4273770

ई-मेल: deshbandhudelhi@gmail.com वेब: www.deshbandhu.co.in

देश की नई यूथ आइकॉन

मनु भाकर ने पेरिस ओलिंपिक में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। ओलंपिक में शूटिंग में पदक जीतने वाली वह प्रथम भारतीय महिला बन गई हैं। जब पूरा देश यह आस लगाए बैठा है कि पेरिस ओलिंपिक में हमारे एथलीट टोक्यो में जीते अब तक के सबसे ज्यादा 7 पदकों का रिकॉर्ड तोड़कर नई और लंबी लकीर खींचेंगे, तब मनु भाकर की जीत ने स्वाभाविक रूप से सबका जोश कई गुना बढ़ा दिया है। उनका यह कांस्य पदक सिर्फ इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि यह पेरिस ओलिंपिक में किसी भारतीय एथलीट का पहला मेडल है। इस उपलब्धि की ऐतिहासिक चमक के पीछे कई और बातें हैं। पहली बात तो यह कि मनु ने कांस्य पदक पर कामयाब निशाना लगाकर एक साथ कई कीर्तिमान स्थापित कर दिए हैं। वह ओलिंपिक मेडल जीतने वाली देश की पहली महिला शूटर हो गई हैं। इससे पहले इस ऑल बॉयज क्लब में राज्यवर्धन सिंह राठौर, अभिनव बिंद्रा, गगन नारंग और विजय कुमार ही थे। यही नहीं, मनु पिछले 20 साल में किसी इंडिविजुअल इवेंट में ओलिंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली पहली देश की महिला भी बनीं। 10 मीटर एयर पिस्टल मुकाबले में तो आज तक कोई महिला शूटर ओलिंपिक फाइनल में पहुंची ही नहीं थी। मनु जिस मंजिल पर पहुंची हैं, उसे उनकी उतार-चढ़ाव भरी यात्रा भी खास बनाती है। मात्र 19 साल की उम्र में तोक्यो ओलिंपिक तक पहुंचकर वहां अचानक पिस्टल खराब होने की वजह से चूक जाना किसी भी टीनेजर के लिए कितना बड़ा झटका होगा, यह आसानी से समझा जा सकता है। मनु न केवल उस झटके से उबरीं बल्कि अगले ही ओलिंपिक में जीत दर्ज कराकर अपनी फाइटिंग स्पिरिट का सिक्का जमा लिया। सबसे बड़ी बात यह है कि मनु महज एक एथलीट नहीं हैं। वह युवा एथलीटों की उस पूरी कौम की नुमाइंदगी करती हैं जो देश का गौरव बढ़ाने के अभियान में लगे हैं। चाहे नीरज चोपड़ा हों या पीवी सिंधु या विनेश फोगाट औ? मीराबाई चानू- ये उन दर्जनों नामों में शुमार हैं जो अपना खून-पसीना जलाते हुए देश का मान बढ़ाने में लगे हैं। इनमें से कई नाम अगले कुछ दिनों में देश को सुनहरी आभा प्रदान करें तो आश्चर्य नहीं। उनके इस प्रदर्शन से पूरे देश में उत्साह की लहर है। मनु देश की नई यूथ आइकॉन बनकर उभरी हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि उनकी जीत से महिलाओं में शूटिंग खेल का आकर्षण बढ़ेगा और वे इसे अपने कॅरियर के रूप में अपनाएंगी। उन्हें हमारी तरफ से भी बधाई।

महाराष्ट्र में देवेन्द्र फडणवीस से क्यों डरा रहता है विपक्ष?

आरके सिन्हा

(लेखक वरिष्ठ संपादक, स्तंभकार और पूर्व सांसद हैं)

लोकसभा चुनावों के नतीजे आने और केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार सरकार बनने के बाद अब अक्टूबर में महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। भारत की मजबूत होती अर्थव्यवस्था की जान है महाराष्ट्र। इसलिए सारे देश की निगाहें महाराष्ट्र पर लगी रहती हैं। राज्य विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की राजनीति भी गरमा चुकी है। आरोप-प्रत्यारोप के नियमित दौर चल रहे हैं। महाराष्ट्र का विपक्ष महाविकास आघाडी राज्य के उस नेता पर आरोप लगा रहे हैं, जिसने राज्य का मुख्यमंत्री रहते हुए प्रदेश का चौतरफा विकास करवाया। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के शिखर भाजपा नेता और वर्तमान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की।

देवेंद्र फडणवीस राज्य के एक बड़े नेता होने के साथ ही काफी दूरदर्शी और अनुभवी रणनीतिकार के रूप में भी जाने जाते हैं। वह कई बार मुश्किलों में फँसी पार्टी को बाहर निकालकर अपनी योग्यता साबित कर चुके हैं। जब वह राज्य के मुख्यमंत्री थे, तब उनके कार्यकाल में राज्य के बुनियादी ढांचे के विकास में कई काम हुए । मुंबई मेट्रो विस्तार और मुंबई-नागपुर समृद्धि महामार्ग जैसी प्रमुख परियोजनाओं की शुरूआत की गई। तब महाराष्ट्र की प्रतिष्ठा एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र के रूप में और बढ़ी। देवेंद्र फडणवीस ने ही कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पुलिसिंग को मजबूत किया और अपराध की रोकथाम के लिए टेक्नोलॉजी ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरूआत की। समाज कल्याण को लेकर भी उन्होंने काफी पहल की। हाशिए पर पड़े समुदायों के उत्थान और सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम लागू किए गये।

महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बीते दिनों देवेन्द्र देवेंद्र फडणवीस पर आरोप लगाया कि वे जब राज्य के गृहमंत्री थे तब उन्होंने (देवेंद्र फडणवीस ने)उन पर दबाव बनाया था कि वे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और महाविकास आघाडी के तीन अन्य नेताओं के खिलाफ केस दर्ज करवा दें। हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने देशमुख के इस आरोप को सिरे से खारिज किया है। कुल मिलाकर लग यह रहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जनता के बुनियादी मसलों से हटकर आरोप-प्रत्यारोप लगते रहेंगे। विपक्ष सत्ता हासिल करने के लिए तबीयत से कीचड़ उछालेगा।

जाहिर है फडणवीस ने भी देशमुख को उनकी ही भाषा में जवाब भी दिया। सबको याद है कि अप्रैल 2021 में गृह मंत्री रहे देशमुख पर तत्कालीन मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने यह आरोप लगाया था कि उन्होंने महाराष्ट्र की पुलिस को शहर के होटल और बार मालिकों से पैसे वसूलने पर लगा दिया था। अब देशमुख कह रहे हैं कि फडणवीस के निर्देश पर परमबीर सिंह ने उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए। अब तीन साल बाद वही एनसीपी नेता देशमुख यह दावा कर रहे हैं कि फडणवीस ने उन पर उद्धव और आदित्य ठाकरे, तत्कालीन डिप्टी सीएम अजित पवार और मंत्री अनिल परब सहित एमवीए के प्रमुख लोगों के खिलाफ झूठे आरोप लगाने के लिए दबाव डाला था। साफ है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में टकराव बढ़ने वाले हैं और महाविकास आघाडी के निशाने पर देवेंद्र फडणवीस ज्यादा रहने वाले हैं। देवेंद्र फडणवीस पर विपक्ष गठबंधन महाविकास आघाडी के नेता रणनीति के तहत हल्ला बोल रहे हैं। उन्हें लगता है कि देवेंद्र फडणवीस को घेरकर वे विधानसभा चुनाव में बढ़त बना सकते हैं।

बेशक, यह अफसोसजनक स्थिति है कि जिस फडणवीस के मुख्यमंत्रित्व काल में राज्य का अभूतपूर्व विकास हुआ, उन पर मिथ्या आरोप लग रहे हैं। उनके ही नेतृत्व में मुंबई मेट्रो का विस्तारीकरण हुआ। मुंबई-नागपुर समृद्धि महामार्ग, आर्थिक गलियारों और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए एक्सप्रेस वे परियोजना की शुरूआत हुईं। बढ़ती शहरी आबादी को समायोजित करने के लिए किफायती आवास योजनाओं को उन्होंने ही लागू किया। सड़क और रेल परियोजनाओं सहित सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क में सुधार किया। आतंकवाद-रोधी उपायों के तहत संभावित खतरों को रोकने और उनका जवाब देने के लिए सुरक्षा ढांचे को बढ़ावा दिया। देवेंद्र फडणवीस ने सामुदायिक पुलिसिंग पर जोर दिया। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के तहत मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ने के लिए इस समुद्री पुल की शुरूआत की।

गोपीनाथ मुंडे के निधन के बाद देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की राजनीति में एक प्रमुख नेता के रूप में सामने आए। उन्होंने राज्य भाजपा को एकजुट किया। यह फडणवीस ही थे जिन्होंने भाजपा की ताकत बढ़ाने के लिए शिवसेना के बिना चुनाव लड़ने का हिम्मती फैसला किया। उन्होंने राज्य के लिए भाजपा की स्वतंत्र ताकत और दृष्टि पर जोर दिया और उनके नेतृत्व में ही भाजपा राज्य में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। राज्य में शिव सेना के बिना भाजपा की सरकार बनाने के लिए फडणवीस ने ही मंच तैयार किया।

अब भी वह सत्तासीन गठबंधन में स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उनका रणनीतिक कौशल जबर्दस्त रहा है। वह शासन में निरंतरता और प्रगति सुनिश्चित करते हुए लचीलेपन के साथ हर मुद्दे का राजनीतिक समाधान तलाशने में महारत रखते हैं। वही विभिन्न वर्गों के साथ प्रभावी ढंग से बातचीत करने में आगे रहे हैं। उनकी नेतृत्व शैली और उपलब्धियों ने उन्हें महाराष्ट्र की राजनीति में एक केंद्रीय व्यक्ति के रूप में स्थापित किया है। वह पैराशूट वाले नेता नहीं हैं। महाराष्ट्र में वह भाजपा में रैंक के माध्यम से आगे बढ़ने वाले नेता हैं। फडणवीस 1989 में युवा विंग के अध्यक्ष रहे हैं और केवल 27 साल की उम्र में नागपुर के मेयर नियुक्त हुए और 44 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बन गए। वह एक ऐसे नेता हैं जो भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व और आरएसएस दोनों में स्वीकार्यता रखते हैं। वह संघ के मूल मूल्यों को समझते हैं और पार्टी के भीतर उसको अपनाने की कोशिश भी करते हैं। महाराष्ट्र में हाल ही में हुए राजनीतिक उथल-पुथल जैसे चुनौतीपूर्ण समय के दौरान स्थिति को स्थिर करने और पार्टी के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने में उनकी बड़ी भूमिका रही है। हाल के लोक सभा चुनावों में पार्टी की हार को अपनी जिम्मेदारी के रूप में स्वीकार करते हुए इस्तीफा देने की उनकी पेशकश, नैतिक बल को ही दशार्ती है।

फडणवीस पर 2024 के विधानसभा चुनावों में भाजपा को जीत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी है। राज्य के राजनीतिक हलकों में कई लोगों को लगता है कि पिछले दस वर्षों से महाराष्ट्र में भाजपा के निर्विवाद नेता के रूप में फडणवीस ही राज्य में भाजपा की पुनः वापसी कर सकते हैं। वे विपक्ष को पटकनी देने में सक्षम हैं। विपक्ष भी हमेशा फडणवीस से ही डरा हुआ दिखाई देता है। किसी न किसी तरह से उन पर निशाना साधने में महाविकास अघाडी के नेता कोई कसर नहीं छोड़ते। यह अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवेन्द्र फडणवीस पर भरोसा रखते हैं।

2019 के विधानसभा चुनावों में भाजपा को अच्छी सफलता मिली, सबको लगा कि फडणवीस एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनने की अपनी महत्वाकांक्षा के साथ आगे आ गए। उन्हें अपने पुराने सहयोगी - भारतीय जनता पार्टी को दगा देने में कोई संकोच नहीं किया। शरद पवार ने कांग्रेस नेतृत्व को राजी किया और उन्हें उद्धव ठाकरे का समर्थन करने के लिए मजबूर किया और अपनी सरकार बना ली, लेकिन फडणवीस ने जून 2022 में पवार साहब की साजिश को माकूल जवाब दे दिया। केवल ढाई साल की अवधि के लिए उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने। अब वही ठाकरे शरद पवार के हाथों खिलौना बने हुए हैं।

यह तो केवल ट्रेलर है, पूरी फिल्म बाकी है

प्रशांत रंजन

(सदस्य, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड)

फिल्म प्रोत्साहन नीति–2024

भारत के एक छोटे से कोने में मनाया जाने वाला करवा-चौथ आज देश के कोने-कोने में मनाया जा रहा है, तो इसके पीछे मुख्यधारा की बड़ी हिंदी फिल्मों में उस त्योहार को प्रस्तुत किया जाना है। लेकिन, आज तक किसी बड़ी फिल्म में छठ महापर्व को नहीं दिखाया गया। इसमें सबसे अधिक दोषी बिहार से निकले फिल्मकार हैं। भारतीय सिनेमा के सवा सौ साल से अधिक के इतिहास में बिहार का मौलिक प्रतिनिधित्व करने वाली फिल्मों के नाम याद करेंगे, तो बात ह्लतीसरी कसमह्न से शुरू होकर वहीं पर ठहर जाएगी। वह तो शैलेंद्र की जीवटता थी, तो फिल्म साकार हुई। उसमें दही-चुड़ा से लेकर पुर्णिया की पगडंडी तक व्याप्त है। फिर वैसा प्रयास करने का साहस किसी अन्य ने नहीं किया। हिंदी की मुख्यधारा के फिल्मकारों को पता है कि बिहार से उनकी फिल्मों को क्या ही हासिल होगा? जनसंख्या के अनुपात में यहां सिनेमाघर अत्यंत कम हैं। किसी हिंदी फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर कुल धन संग्रह का कितना प्रतिशत बिहार के सिनेमाघरों से आता है, यह पक्ष भी बिहार की कहानी कहने से फिल्मकारों को रोकता है। यह विशुद्ध व्यवसायिक मामला है। इसलिए सिनेमा में बिहार के प्रतिनिधित्व को ठीक करने के लिए सबसे पहले बिहार में सिनेमाघरों की संख्या बढ़ानी चाहिए, जो कि राज्य सरकार के सहयोग के बिना कठिन है। राहत की बात है कि फिल्म प्रोत्साहन नीति-2024 में बंद पड़े या खराब हालात वाले सिनेमाघरों को ठीक किए जाने की बात कही गई है।

लंबी प्रतीक्षा के बाद आखिरकार बिहार में फिल्म नीति की घोषणा हो गई। 19 जुलाई को बिहार के उपमुख्यमंत्री सह कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने प्रेसवार्ता कर ह्यबिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति-2024ह्न की औपचारिक रूप से घोषणा की। इस नीति के लागू होने के बाद बिहार के सिने संसार में क्या–क्या बदलने वाला है, इसकी पड़ताल आवश्यक है। 'बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति-2024' के बारे बताया गया है कि चार करोड़ तक की राशि फिल्म निर्माण के लिए दी जाएगी अथवा कुल बजट का 25 प्रतिशत व क्षेत्रीय फिल्मों के लिए 50 प्रतिशत, जो भी कम हो। इसके अलावा बिहारी कलाकारों व बिहार के शूटिंग स्थलों पर 75 प्रतिशत शूटिंग करने पर 50 लाख रुपए तक का अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा।

भारतीय सिनेमा का नाम उच्चारते ही मानस पटल पर बंबइया शैली की हिंदी फिल्में व व्यावसायिक तड़के से सज्जित दक्षिण भारतीय फिल्में छा जाती हैं। अगर सोचने वाला व्यक्ति बौद्धिक जमात से है, तो इन फिल्मों के अतिरिक्त वह बंगाली, मराठी या असमिया सिनेमा की बात करेगा। जाहिर सी बात है कि भारत के क्षेत्रीय सिनेमा की प्रासंगिकता इसीलिए है कि वह अपने क्षेत्र विशेष की न केवल कहानी कहता है, बल्कि एक पूरे सामाजिक-सांस्कृतिक संरचना को पर्दे पर उकेरता है। शायद यही कारण है कि पश्चिमी दुनिया अन्य स्त्रोतों के अलावा फिल्मों के जरिए भी भारत को समझने की चेष्टा करती है। लेकिन, एक पल के लिए ठहर कर सोचना चाहिए कि इस सिनेमाई यात्रा में बिहार कहां पीछे छूट गया है?

ध्यान देने वाली बात है कि यहां बिहारियों की बात नहीं हो रही, क्योंकि फिल्म उद्योग में व्यक्तिगत रूप से उनका पताका तो लहरा ही रहा है। विचारणीय है बिहार। बिहार व बिहार के बाहर के फिल्मकारों को जब भी मौका लगा, उन्होंने व्यवसायिक पक्ष को साधने के लिए बिहार की नकारात्मक छवि प्रस्तुत की। सिनेमा के इस रचनात्मक विडंबना का एक और स्याह पक्ष है कि बिहार की छवि दांव पर लगाकर बनी फिल्मों से बिहार को कुछ हासिल हुआ होता, तो भी किंचित संतोष की बात होती। लेकिन, बिहार की कहानी कहने वाली फिल्मों की शूटिंग बिहार के बाहर होती है और उन फिल्मों के अधिकतर कलाकार बिहार के बाहर के होते हैं, यानी मौद्रिक लाभ के मोर्चे पर दोहरा घाटा। यह तो हुई हिंदी फिल्मों की बात। भोजपुरी सिनेमा तो और वक्री हो गया है। हर वर्ष रिलीज होने वाली 90 प्रतिशत भोजपुरी फिल्मों में आपको बिहार नहीं दिखेगा। अस्सी के दशक में बनी बी-ग्रेड हिंदी फिल्मों की सी-ग्रेड रीमेक बनाकर भोजपुरी वाले खुश हैं।

भारत के एक छोटे से कोने में मनाया जाने वाला करवा-चौथ आज देश के कोने-कोने में मनाया जा रहा है, तो इसके पीछे मुख्यधारा की बड़ी हिंदी फिल्मों में उस त्योहार को प्रस्तुत किया जाना है। लेकिन, आज तक किसी बड़ी फिल्म में छठ महापर्व को नहीं दिखाया गया। इसमें सबसे अधिक दोषी बिहार से निकले फिल्मकार हैं। भारतीय सिनेमा के सवा सौ साल से अधिक के इतिहास में बिहार का मौलिक प्रतिनिधित्व करने वाली फिल्मों के नाम याद करेंगे, तो बात ह्लतीसरी कसमह्न से शुरू होकर वहीं पर ठहर जाएगी। वह तो शैलेंद्र की जीवटता थी, तो फिल्म साकार हुई। उसमें दही-चुड़ा से लेकर पुर्णिया की पगडंडी तक व्याप्त है। फिर वैसा प्रयास करने का साहस किसी अन्य ने नहीं किया। हिंदी की मुख्यधारा के फिल्मकारों को पता है कि बिहार से उनकी फिल्मों को क्या ही हासिल होगा? जनसंख्या के अनुपात में यहां सिनेमाघर अत्यंत कम हैं। किसी हिंदी फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर कुल धन संग्रह का कितना प्रतिशत बिहार के सिनेमाघरों से आता है, यह पक्ष भी बिहार की कहानी कहने से फिल्मकारों को रोकता है। यह विशुद्ध व्यवसायिक मामला है। इसलिए सिनेमा में बिहार के प्रतिनिधित्व को ठीक करने के लिए सबसे पहले बिहार में सिनेमाघरों की संख्या बढ़ानी चाहिए, जो कि राज्य सरकार के सहयोग के बिना कठिन है। राहत की बात है कि फिल्म प्रोत्साहन नीति-2024 में बंद पड़े या खराब हालात वाले सिनेमाघरों को ठीक किए जाने की बात कही गई है।

हालांकि, 25 साल की चिर प्रतीक्षा के बाद बिहार को अपनी फिल्म नीति मिल गई, जो कई दृष्टि से अन्य प्रदेशों की फिल्म नीति से बेहतर भी है। लेकिन, फिल्म नीति के अधिकतर विधान अनुदान देने व निर्माण करने तक सीमित प्रतीत होती है। उसका सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है, वरना उसे पता होता कि डिजिटल युग में स्मार्टफोन से रियल लोकेशन पर फिल्में बन रही हैं। ऐसे में सरकार अगर यही सुनिश्चित कर दे कि बिहार की कहानी कहने वाली फिल्म को कम से कम बिहार में बड़ा पर्दा नसीब होगा, तब भी स्थिति सुधर सकती है। इस नीति के आने के बाद क्या सचमुच बिहार में एक सिने उद्योग खड़ा हो सकता है? इस प्रश्न का उत्तर ही इस नीति का लिटमस टेस्ट होगा। यानी अभी नीति के रूप में केवल ट्रेलर आया है, पूरी फिल्म आनी बाकी है।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

दिल्ली त्रासदी

छात्रों की मृत्यु

दिल्ली की एक त्रासदी में 'बेसमेंट' में पानी भरने के कारण तीन छात्रों की दु:खद मृत्यु हो गई। यह प्रशासनिक संवेदनहीनता और लापरवाही का एक और उदाहरण है। यह घटना त्रासद व हृदय विदारक है। कल्पना करना कठिन है कि तीन छात्रों की एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से मृत्यु हो सकती है। इस हृदय विदारक घटना से एक बार फिर शहरी ढांचागत संरचना और प्रशासन में व्याप्त भयानक कमी उजागर होती है। एक बेसमेंट में पानी भरने के कारण तीन सिविल सर्विस उम्मीदवार छात्रों की जान चली गई। इस विभीषिका से बचा जा सकता था। इससे आधिकारिक लापरवाही, सुरक्षा मानकों की अनदेखी तथा बार-बार होने वाली ऐसी घटनाओं की असलियत सामने आती है। उस दुर्भाग्यपूर्ण शाम शहर में भारी बरसात हुई जिससे शहर की अनुपयुक्त जल निकासी व्यवस्था निपट नहीं पा रही थी। जिस बेसमेंट में छात्र पढ़ रहे थे, वहां तेजी से पानी भर गया। भागने के अनेक प्रयासों के बावजूद पानी के बढ़ते स्तर के कारण तीन नौजवानों को दु:खद रूप से अपनी जान गंवानी पड़ी। कामर्शियल भंडारण के लिए बने बेसमेंट को अवैध रूप से एक कोचिंग सेंटर में बदल दिया गया था। हवा निकलने का रास्ता, आपात निकास या जल-निकासी व्यवस्था के अभाव में यह बरसात के समय मौत का फंदा बन गया। यह दुर्घटना अनेक शहरवासियों के समक्ष मौजूद यथार्थ रेखांकित करती है जो अधोमानक व असुरक्षित आवासों में रहने को मजबूर हैं। इसका कारण अनपयुक्त आवास नीतियां तथा रियल इस्टेट के तेजी से बढ़ते दाम भी हैं।

यदि 'बिल्डिंग कोड' का कठोर क्रियान्वयन होता तथा समय पर जल निकासी व्यवस्था का रखरखाव होता तो इन छात्रों को मरने से बचाया जा सकता था। लेकिन इस दुर्घटना ने एक बार फिर उन अधिकारियों की लापरवाही उजागर की है जो नागरिकों की सुरक्षा और बेहतरी सुनिश्चित करने के जिम्मेदार हैं। इस क्षेत्र के निवासियों ने खराब जल निकासी और बेसमेंटों को अवैध रूप से आवासीय स्थल बनाने की बार-बार शिकायत की थी। लेकिन इन चेतावनियों के बावजूद कोई कदम नहीं उठाया गया। नगर निगम अधिकारियों की लापरवाही तथा गैर-जिम्मेदारी ने एक और त्रासदी को जन्म दे दिया। तीन छात्रों की मृत्यु के बाद यह समय बहुतों के लिए सोशल मीडिया पर घड़ियाली आंसू बहाने का है। विडंबना है कि राजनेता वर्ग का एक बड़ा हिस्सा ऐसी घटनाओं पर शोक प्रकट करने के सिवा और कुछ नहीं करता है। वास्तव में इसका कारण स्थानीय राजनेताओं, नौकरशाहों व संदिग्ध पहचान वाले बिजनेस मालिकों के बीच गठजोड़ है जिससे तेजी से पैसा कमाने के लिए मानकों की धज्जियां उड़ा दी जाती हैं। यह कोई अलग-थलग घटना नहीं है, बल्कि अतीत में भी ऐसी घटनायें होती रही हैं। यह परेशान करने वाली प्रवृत्ति है जहां प्रभावशाली लोग आमतौर से सुरक्षा मानकों की अनदेखी करते हैं। अवैध निर्माण, अनाधिकृत परिवर्तन तथा ढांचागत संरचना का खराब रखरखाव राजधानी शहर समेत अनेक शहरों में आम हो गया है। अक्सर बिल्डर और भूस्वामी नियमों की अनदेखी कर मुनाफे के लिए निवासियों की सुरक्षा से समझौता करते हैं। खतरनाक रूप से ऐसी घटनायें बार-बार होती हैं। हर बार खराब ढांचागत संरचना, लापरवाही तथा जवाबदेही की कमी जैसे समान मुद्दे उजागर होते हैं। लेकिन हर त्रासदी के बाद जनता के शोरशराबे और मीडिया में सुर्खियों के बावजूद कोई खास परिवर्तन नहीं होता है। एक रस्मी जांच होने के बाद उसकी रिपोर्ट आ जाती है और इसके बाद इसे दूसरी घटना होने तक जनता और देश की समृति से भुला दिया जाता है।

विकास-केन्द्रित केन्द्रीय बजट

सरकार ने पिछले चार वर्ष की उपलब्धियों के आधार पर एक विकास-केन्द्रित बजट पेश किया है। इसमें नौजवानों को नौकरियां देने तथा उनके कौशल संवर्धन हेतु कई योजनाओं की घोषणा शामिल है।

उत्तम गुप्ता
(लेखक, नीति विश्लेषक हैं)

लगातार तीन साल से सकल घरेलू उत्पाद-जीएसटी वृद्धि 8 प्रतिशत से अधिक होने से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 23 जुलाई, 2024 को प्रस्तुत 2024-25 के केन्द्रीय बजट में इस वर्ष भी यह गति बनाए रखने की पूरी उम्मीद है। वर्तमान वित्त वर्ष में उन्होंने 1111,111 करोड़ के पूंजीगत खर्च का अनुमान लगाया है जो वित्त वर्ष 2023-24 के संशोधित अनुमान से 17 प्रतिशत अधिक है। 2019-20 के बजट में उन्होंने 2024-25 तक भारतीय अर्थव्यवस्था के 5 ट्रिलियन डालर तक पहुंचने का अनुमान लगाया था। इस लक्ष्य के अनुरूप उन्होंने अगले पांच वर्ष में ढांचागत निर्माण हेतु 100 लाख करोड़ रुपये के निवेश का अनुमान लगाया है। इसमें से 39 प्रतिशत या 39,00,000 करोड़ केन्द्र और राज्यों से आएगा तथा बाकी 22,00,000 करोड़ निजी क्षेत्र से आने की उम्मीद है। पिछले चार वर्ष में केन्द्र का पूंजीगत खर्च 2020-21 में 439,000 करोड़, 2021-22 में 554,000 करोड़, 2022-23 में 750,000 करोड़ तथा 2023-24 में 1000,964 करोड़ रुपये रहा है। कुल मिला कर यह 2700,000 करोड़ रुपये है। यदि इसमें 2024-25 के 1111,111 करोड़ को जोड़ दिया जाए तो यह 3800,000 करोड़ हो जाता है। यह लगभग केन्द्र द्वारा इच्छित योगदान के बराबर है। केन्द्र सरकार राज्यों की सहायता उनके पूंजीगत खर्च को बढ़ाने के लिए कर रही है। 2022-23 में उसने राज्यों को 50 साल के लिए 100,000 करोड़ ब्याज मुक्त कर्ज दिए थे। 2023-24 में ऐसे हस्तांतरण 130,000 करोड़ रुपये थे। वर्तमान वित्त वर्ष के लिए 150,000 करोड़ रुपये हस्तांतरण का लक्ष्य बजट में रखा गया है।

निजी क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए केन्द्र ने कार्पोरेट टैक्स घटा कर नए विनिर्माण उद्यमों के लिए 15 प्रतिशत तथा वर्तमान उद्यमों के लिए 22 प्रतिशत किया है। इस वर्ष के बजअ में विदेशी फर्मों पर भी टैक्स 40 प्रतिशत से घटा कर 35 प्रतिशत किया गया है। इसके साथ ही अनुमान लगाया गया है कि निजी उपभोग व मांग मजबूत बनी रहेगी। इसका कारण व्यक्तिगत आयकर में 17,500 रुपये की रियायत, नई आईटी व्यवस्था में टैक्स स्लैबों में परिवर्तन तथा मानक कटौती में 25,000 रुपये की बढ़ोत्तरी है। इसके साथ ही अमेरिकी अर्थव्यवस्था में उछाल के साथ निर्यात बढ़ रहे हैं। ऐसे में भारत 6.5-7 प्रतिशत वृद्धि प्राप्त कर सकता है जिसका अनुमान 2023-24 के आर्थिक सर्वेक्षण में लगाया गया है।

लेकिन एक समस्या भी है। सीतारमण ने राजकोषीय घाटे-एफडी का अनुमान जीडीपी का 4.9 प्रतिशत लगाया है जो अंतरिम बजट में घोषित 5.1 प्रतिशत के लक्ष्य से 0.2 प्रतिशत कम है। यह भारतीय रिजर्व बैंक-आरबीआई द्वारा हस्तांतरित भारी-भरकम 210,000 करोड़ रुपये से संभव हुआ है। यह हस्तांतरण केन्द्र सरकार को वित्त वर्ष 2023-24 के कामकाज पर आधारित है जो अंतरिम बजट में निर्धारित 80,000 करोड़ रुपये से 130,000 करोड़ रुपये अधिक है। ऐसे में वर्तमान वित्त वर्ष में 4.9 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त करना कठिन होगा। इसका कारण यह है कि 3840,000 करोड़ का सकल कर राजस्व-जीटीआर प्राप्त करने का लक्ष्य अति-महत्वाकांक्षी हे। बजट में पीएसयू में सरकारी शेयरों के विनिवेश से 50,000 करोड़ रुपये प्राप्त करने का लक्ष्य है, जबकि अब तक उसने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाए हैं। इसके साथ ही साल में आगे बढ़ने के साथ बड़े खर्च भी नियंत्रण से बाहर जाने की आशंका है।

उदाहरण के लिए, 2024-25 के बजट में 'उर्वरक सब्सिडी' के लिए 164,000 करोड़ रुपये रखे गए हैं। यह इस अनुमान पर आधारित है कि उर्वरकों और उनके उत्पादन में प्रयोग होने वाले कच्चे माल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में गिरावट की प्रवृत्ति है। यह प्रवृत्ति 2023-24 से लगातार दिख रही है और वर्तमान वित्त वर्ष में भी बनी रहेगी। लेकिन वैश्विक सप्लाई में वर्तमान अनिश्चित भू-राजनीतिक स्थिति के कारण बाधा आई है जिसके बने रहने की आशंका है। इससे यह अनुमान गलत हो सकता है। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने 2021-22 के बजट में इस वर्ष एफडी का अनुमान 4.9 प्रतिशत रखा था जिसे घटा कर 4.5 प्रतिशत किया गया है। यदि आरबीआई पहले की तरह केन्द्र को बड़ा उपहार न दे तो इसे प्राप्त करना कठिन हो सकता है। प्रेस से बातचीत करते समय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2026-27 तथा इसके आगे के राजकोषीय रोडमैप का खुलासा नहीं किया। वित्त मंत्री द्वारा पहले निर्धारित लक्ष्य अक्सर विफल हुए हैं। केन्द्र का कर्ज-जीडीपी अनुपात वर्तमान समय में 57 प्रतिशत है, जबकि एफआरबीएम संशोधन कानून, 2018 के अनुसार 2024-25 में इसकी सीमा 40 प्रतिशत रखी गई थी। इस बीच रोजगार, एमएसएमई व कृषि के सरोकारों को संबोधित करने के लिए अनेक पहलें की गई हैं। एमएसएमई के लिए नई कर्ज योजना की घोषणा की गई है ताकि बिना बंधक रखे या तीसरे पक्ष की गारंटी के मशीनरी व उपकरण खरीदने के लिए आसानी से कर्ज मिल सके। इसके साथ ही 'मुद्रा लोन' की सीमा उनके लिए बढ़ा कर 2000,000 की गई है जिन्होंने पिछला कर्ज चुका दिया हो। इसके साथ ही सिडबी की शाखायें बढ़ाई गई हैं ताकि और आर्थिक विकास के लिए कर्ज तक बहु-प्रतीक्षित पहुंच आसान हो सके। रोजगार पर पहलों को इम्प्लाईज़ प्राविडेंट फंड आर्गेनाइजेशन-ईपीएफओ से जोड़ा गया है। इसमें पहली योजना के अंतर्गत 15,000 रुपये प्रति माह वेतन वाले कर्मचारियों को एक महीने का योगदान पहली नौकरी की स्थिति में दिया जाएगा। इसका भुगतान तीन किश्तों में किया जाएगा और यह औपचारिक क्षेत्र में 100,000 प्रति माह तक वेतन पाने वाले युवाओं पर लागू होगा। दूसरी योजना का उद्देश्य विनिर्माण क्षेत्र में 'अतिरिक्त' रोजगार सृजन करना है और इसे भी पहली बार नौकरी मिलने वाले कर्मचारियों से जोड़ा गया है। इसमें कर्मचारियों और सेवायोजकों को ईपीएफओ की ओर से नौकरी के पहले चार साल तक इंसेंटिव दिया जाएगा।

उम्मीद है कि इन योजनाओं से 240 लाख नौजवानों को लाभ होगा। तीसरी योजना का उद्देश्य सेवायोजकों को सहायता देना है। यह सभी क्षेत्रों में 100,000 प्रति माह तक वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त रोजगार सृजन पर लागू होगी। अतिरिक्त कर्मचारियों को नौकरी देने पर सरकार सेवायोजकों को पत्येक अतिरिक्त कर्मचारी पर ईपीएफओ योगदान की स्थिति में दो साल तक 3000 रुपये मासिक की प्रतिपूर्ति करेगी। उम्मीद है कि इस योजना से लगभग 50 लाख युवाओं को लाभ होगा। युवाओं को खासकर विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार योग्य बनाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई केन्द्र-प्रायोजित योजना की घोषणा की है जो राज्यों और उद्योगों के सहयोग से नौजवानों को नए कौशल प्रदान करने में सहायता करेगी। इस योजना के अंतर्गत अगले पांच साल में 2000,000 नोजवानों का कौशल संवर्धन किया जाएगा। केन्द्र सरकार ने बजट में घोषणा की है कि 'हब एंड स्पोक' व्यवस्था के अंतर्गत एक हजार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों-आईटीआई का उच्चीकरण किया जाएगा। इसके लिए पाठ्यक्रम का निर्धारण उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाएगा। कृषि व्यवस्था में सुधार तथा किसानों की आय बढ़ाने के लिए अगले दो साल में 10 मिलियन किसानों को 'प्राकृतिक खेती' के दायरे में लाने का लक्ष्य है। इसके साथ ही अगले 100 दिनों में 32 क्षेत्रों और बागवानी फसलों की जलवायु-प्रतिरोधी 109 नई बीज किस्में जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा पांच राज्यों में जन-समर्थ आधारित किसान क्रेडिट कार्ड झींगा पालन व निर्यात हेतु दिए जाएंगे, राष्ट्रीय सहकारिता नीति की घोषणा होगी तथा अगले तीन साल में 60 मिलियन किसानों के लिए डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर-डीपीआई का सृजन होगा। किसानों के लिए बड़े पैमाने पर प्रमुख उपभोग केन्द्रों के निकट बड़े 'वेजीटेबल क्लस्टर' बनाए जांएगे, एफपीओ को प्रोत्साहित किया जाएगा, सब्जी सप्लाई श्रृंखला में सहकारिताओं व स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा तथा दालों व तिलहनों का उत्पादन मिशन लागू किया जाएगा। इन सभी योजनाओं का सटीक जमीनी क्रियान्वयन महत्वपूर्ण होगा।

व्यक्तिगत मुक्ति का मार्ग

> "दृढ़ इच्छाशक्ति वाले व्यक्ति के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए आइए यह संकल्प लें कि हम खुद को सही मायने में मुक्त करेंगे।"

ब्रह्मकुमार निकुंज
(लेखक आध्यात्मिक उपदेशक हैं)

हम वही हैं जो हम बार-बार करते हैं, अरस्तू ने कहा... अगर हम आदत के शब्दकोश अर्थ पर नज़र डालें, तो यह कहता है कुछ ऐसा जो आप अक्सर और नियमित रूप से करते हैं, कभी-कभी बिना यह जाने कि आप ऐसा कर रहे हैं। इसे सरल शब्दों में परिभाषित करने के लिए, आदतों को अनैच्छिक क्रियाएँ कहा जा सकता है। वे एक तरह के स्वचालित व्यवहार हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति उन्हें बहुत सोच-समझकर नहीं करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस दुनिया में लगभग हर किसी को कोई न कोई बुरी आदत होती है। क्या हम सभी को नहीं होती? जैसे, बहुत से लोगों को धूम्रपान की बुरी आदत होती है। लेकिन, अगर आप उन्हें बताते हैं कि यह एक बुरी आदत है, तो उनमें से कुछ थोड़ा सा दर्शनशास्त्र लेकर आएंगे और कुछ इसे चिकित्सा राय के साथ भी समर्थन देने की कोशिश करेंगे।

वे कहेंगे, धूम्रपान बहुत उत्साहवर्धक है। यह मेरे मस्तिष्क के लिए अच्छा है क्योंकि यह मुझे एकाग्रता प्रदान करता है। दूसरे कहेंगे, धूम्रपान करने से मेरी आंतें साफ रहती हैं। फिर भी कुछ लोग स्वीकार करेंगे कि यह एक बुरी आदत है जिसे छोड़ना उनके लिए मुश्किल है। अधिकांश लोगों को यह एहसास ही नहीं होता कि यह एक बुरी आदत है जो उनके शारीरिक तंत्र और वातावरण को प्रदूषित करती है और कैंसर जैसी बीमारियों का कारण बनती है। इसी तरह, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा बोलने की आदत होती है। वे दो मिनट भी चुप नहीं रह पाते। इन लोगों को यह एहसास ही नहीं होता कि बेकार की बातों में बहुत सारी साँसें और ऊर्जा बरबाद होती है।

इसे मौन ध्यान में खर्च किया जा सकता है। लेकिन समस्या यह है कि आज जो बोलता है और बोलता है उसे होशियार, चतुर और बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता है और जो कम बोलता है उसे सामान्य ज्ञान की कमी या

बातचीत की कला में कमी वाला माना जाता है! बुरी आदतों के ऐसे कई उदाहरण हैं, लेकिन, इन उदाहरणों से हमें यह समझने की ज़रूरत है कि, ज़्यादातर मामलों में, लोगों को यह एहसास ही नहीं होता कि यह एक बुरी या हानिकारक आदत है और जहाँ इस सच्चाई का एहसास होता है, वहाँ इसकी गिरफ़्त से मुक्त होने की तीव्र इच्छा नहीं होती और इसीलिए कुछ लोग दार्शनिक रूप से कहते हैं; मेरी यह आदत तभी मरेगी जब मैं मर जाऊँगा।

तो अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पाने का उपाय क्या है? क्या यह व्यावहारिक रूप से संभव है? हाँ! थोड़े प्रयास और ध्यान से यह संभव है। शुरुआत करने के लिए बहुत उत्साह की आवश्यकता होती है जो बुरी आदतों को छोड़ने के लिए बहुत आवश्यक है। अंग्रेजी में एक प्रसिद्ध कहावत है- अच्छी शुरुआत आधी सफलता होती हैं। इसलिए, जब आपको एहसास हो जाए कि जिस आदत को छोड़ने का आपने फैसला किया है, वह वास्तव में बुरी है, तो आपको इस बुराई के खिलाफ़ बहादुरी और जोश से लड़ना चाहिए। शुरू से ही अपनी सारी छिपी हुई शक्तियों को न केवल इसकी जड़ और शाखा को काटने के लिए बल्कि इसके बीज को नष्ट करने के लिए भी बुलाएँ, क्योंकि अगर बीज बच गया, तो पेड़ के फिर से उगने की संभावना है। जब किसी घर में आग लगती है, तो घर के लोग कितनी तत्परता और ऊर्जा से प्रतिक्रिया करते हैं? उस समय, वे पूरी तरह से एकाग्र होते हैं और आग को बुझाने के लिए सभी साधनों का उपयोग करते हैं।

अपने संकल्प को तुरंत अमल में लाएँ। दूसरा, अपने मन से असंभव, कठिन, मैं नहीं कर सकता आदि शब्दों को निकाल दें। ये एक कमज़ोर या डरपोक व्यक्ति के भाव हैं। खुद को खुश रखें। इस सच्चाई को समझें कि बुरी आदत आपकी अपनी रचना है, आपने इसे जन्म दिया है और इसे विकसित करने के लिए पोषित किया है और अब आपको कमज़ोर इच्छाशक्ति के साथ यह नहीं कहना चाहिए कि इसे नियंत्रित करना मुश्किल है। हमेशा याद रखें! आदतें आपकी मूल प्रकृति नहीं हैं; वे आपकी दूसरी प्रकृति हैं। आपने उन्हें अर्जित किया है और आप कहते हैं कि आप उन्हें छोड़ नहीं सकते? आप उनके स्वामी हैं और आप स्वयं को उनका दास मानते हैं? विश्वास, यह सही कहा गया है, पहाड़ों को हिला सकता है और यह आपकी आदत केवल एक राई है। इसलिए, उठो और प्रयास का धनुष उठाओ और इस शैतान को - अपनी बुरी आदत को - मारने के लिए ईश्वर का एक साधन बनो, क्योंकि, ईश्वर आपके साथ हैं क्योंकि वे हमेशा अच्छे लोगों के पक्ष में होते हैं। लेकिन, याद रखें! बुराई को खत्म करने की केवल इच्छा या चाहत ही पर्याप्त नहीं है। आपके पास एक निश्चित लक्ष्य और उद्देश्य के अलावा शुद्ध और दृढ़ इच्छाशक्ति होनी चाहिए। इच्छा या चाहत मन की झील में एक छोटी, अस्थायी लहर है लेकिन इच्छाशक्ति वह शक्ति है जो इच्छा को पूरा करने के लिए क्रियान्वित करती है। दृढ़ इच्छाशक्ति वाले व्यक्ति के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए आइए यह संकल्प लें कि हम खुद को सही मायने में मुक्त करेंगे।

आप की बात

मनु को बधाई

मनु भाकर ने निशानेबाजी में ओलंपिक का कांस्य पदक जीतकर भारत के लिए पदक बटोरने की शुरुआत कर दी है। उनको बहुत-बहुत मुबारकवाद। इस बार देश को 7 से अधिक ओलंपिक पदक मिलने की आशा है। पहला पदक देशवासियों के लिए उत्साह और उमंग बढ़ाने वाला है। गत कुछ वर्षों से देश का युवा वर्ग इस विश्व की सबसे कठिन प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए जागृत हुआ है। इसमें सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं और कारपोरेट जगत के भरपूर सहयोग के साथ ही इस बार भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने भी ओलंपिक के लिए करोड़ों रुपए की राशि दी है। इसके चलते खिलाड़ियों को प्रशिक्षण लेने और पौष्टिक आहार तथा उपयुक्त उपकरणों आदि की पूरी सुविधाएं बहुत सहयोगी सिद्ध हो रही है। उद्योग जगत को क्रिकेटरों की तरह आकर्षक आफर अन्य खिलाड़ियों व खासकर ओलिंपिक खिलाड़ियों को भी देने चाहिए। प्रशंसनीय रूप से प्रधानमंत्री मोदी ने मनु भाकर से बात कर न केवल उनका, बल्कि पूरी ओलंपिक टीम का उत्साह बढ़ाया। उम्मीद करनी चाहिए कि सरकार तथा भारतीय उद्योग जगत भारत को 2036 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार करेंगे तथा खेल सुविधाओं का व्यापक विस्तार इस उद्देश्य से किया जाएगा।

–**सुभाष बुडावन वाला,** रतलाम

बरसात के जोखिम

दिल्ली के राजेंद्र नगर क्षेत्र में एक कोचिंग के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की डूबने से मौत हो गई तथा छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में कोयला खदान में निरीक्षण करने गए दो अधिकारी अचानक खदान में पानी भर जाने से डूबे। इनमें से एक को बचा लिया गया किन्तु दूसरे की तलाश जारी है। वर्षा के सुहाने मौसम का आनंद लेने पर्यटक अपने क्षेत्रों में स्थित पर्यटन स्थलों पर काफी मात्रा में जाते हैं। लेकिन उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि जोखिम भरी जगहों पर जाने की गलती न करें। मनोरंजन स्थलों पर स्थित झरनों, नदियों व बांधों में अचानक पानी का सैलाब आ सकता है। अपने शहरों में भी सड़कों पर पैदल या वाहनों से चलते समय लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। नागरिकों को जोखिम से बचने के प्रयासों के साथ ही स्थानीय प्रशासन को अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही पूरी तरह निभानी चाहिए। दिल्ली में उदीयमान छात्रों की दु:खद मृत्यु के पीछे बिल्डरों, कोचिंग संचालकों तथा प्रशासन के साथ ही नगर निगम और अग्निशमन विभाग के लोगों की जिम्मेदारी है जो नोटिस देने के बाद यह चिंता नहीं करते हैं कि उनका क्रियान्वयन हुआ या नहीं। बरसात से निपटने की तैयारियों की घोषणायें अक्सर गलत साबित होती हैं।

– **शकुंतला महेश नेनावा,** इंदौर

पश्चिम बंगाल में तुष्टीकरण

कांग्रेस द्वारा चलाई तुष्टिकरण नीतियों के गर्भ से पाकिस्तान का जन्म हुआ था, लेकिन विडंबना है कि इससे कोई सबक नहीं सीखा गया। आज पश्चिम बंगाल में मुस्लिम तुष्टीकरण अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहा है। ममता बनर्जी सत्ता के मोह में यही खेल खेल रही हैं। मुस्लिम वोटबैंक के लिए समस्त सेक्युलर लॉबी में जो होड़ लगी है, उसमें ममता सबसे आगे है। हाल में ममता ने अनधिकार चेष्टा दिखाते हुए बांग्लादेशियों के लिए बंगाल के दरवाजे खोलने की घोषणा की थी। भारत के विदेश मंत्रालय के साथ ही बांग्लादेश सरकार ने इसके लिए ममता बनर्जी की आलोचना की। कहा जाता है कि बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठियों व रोहिंग्याओं के चलते बंगाल के तीन मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तरी दिनाजपुर में मुस्लिम आबादी 50 प्रतिशत से अधिक हो गई है। अमेरिकी पत्रकार सुश्री जेनेट लेवी ने अपनी पुस्तक-मुस्लिम टेकओवर आफ वेस्ट बंगाल में लिखा है कि बंगाल में जनसंख्या असंतुलन के कारण भारत एक और विभाजन की ओर बढ़ रहा है। यह स्थिति प्रत्येक देशभक्त को डराने वाली है। ऐसे में राजनेताओं व सामाजिक संगठनों को पश्चिम बंगाल की जनता में व्यापक जागरूकता अभियान चलाने पर विचार करना चाहिए।

– **नरेंद्र टोंक,** मेरठ

भारतीय वेशभूषा

बेंगलुरू में हाल ही में जब एक मॉल में व्यक्ति को धोती पहनने पर प्रवेश करने से रोका गया तब सरकार ने दंडस्वरूप शॉपिंग मॉल को सात दिन के लिए बंद करवा दिया। धोती पहनने वाले व्यक्ति के मानवाधिकार का हनन करने वाले शॉपिंग मॉल का मुद्दा कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष ने भी उठाया जिस पर सरकार ने कठोर कार्रवाई की। यह भारतीय वेशभूषा को सम्मान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अंग्रेजों को देश से गए 75 साल से अधिक हो गए, लेकिन देश में अब भी ऐसे क्लब मिल जांएगे जो भारतीय वेशभूषा पहने लोगों को आने की अनुमति नहीं देते हैं। इसके पीछे अनेक प्रकार के बहाने बनाए जाते हैं, पर स्वतंत्र भारत में इनका कोई स्थान नहीं होना चाहिए। वैसे जन-जीवन में भी पश्चिमी परिधानों के बजाय विभिन्न प्रदेशों की भारतीय वेशभूषा को लोकप्रिय बनाने के प्रयास अभियान की तरह चलाए जाने चाहिए। इस दिशा में स्थापित फैशन डिजाइनरों के साथ फैशन डिजाइनिंग में अपनी प्रतिभा निखारने का प्रयास करने वाले युवाओं और युवतियों की महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए।

– **गोपाल सोनी**, मनावर

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से responsemail.hindipioneer@gmail.com पर भी भेज सकते हैं।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

संपादकीय

अग्निपथ योजना सेना में सुधार का प्रयास है...

देश व राज्य के कुछ मामले राजनीति से परे होते हैं,कम से कम उस पर तो राजनीति नहीं करनी चाहिए। देश की सुरक्षा, सेना में सुधार, सेना को मजबूत करने का प्रयास कोई भी सरकार कर रही है विपक्ष को उसमें खुले मन से सहयोग करना चाहिए क्योंकि सेना किसी दल की नहीं होती है, वह देश की होती है।वह मजबूत होगी तो देश की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी।देश मे पहली बार विपक्ष सेना के सुधार के मामले में राजनीति कर रहा है ताकि कोई सुधार का काम मोदी सरकार कर रही है तो उसे हर कीमत पर गलत कहना है और देश के लोगों तथा युवाओं को गुमराह करना है।सरकार की तरफ से कई बार कहा जा चुका है तथा कारगिल विजय दिवस पर पीएम मोदी ने फिर एक बार कहा है कि अग्निपथ योजना का मकसद देश की सेनाओं को युवा व हरदम युध्द के लिए तैयार रखना है।उन्होंने इस योजना का विरोध करनेवाले को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि अग्निपथ योजना व एयरफोर्स मे फाइटर विमान का विरोध करने वाले वही लोग हैं, जिन्होंने रक्षा सौदे मे हजारों करोड़ के घोटाले कर सेना को कमजोर बनाए रखा है।अतीत में हमेशा सेना में सुधार के नजरअंदाज किया है।उनका कहना है कि अग्निपथ योजना रक्षा के क्षेत्र में बरसों बाद किया जा रहा अहम सुधार कार्य है। इससे सेना की औसत आयु कम होगी तथा हमेशा युध्द के लिए तैयार रहेगी और दुश्मन को ठीक समय पर मुंहतोड़ जवाब दे सकेगी। सेना का मतलब होता है कि जब भी दुश्मन देशों से युध्द हो तो उसका मुकाबला ठीक से किया जा सके और उसे हराया भी जा सके। सेना तो जीतने वाली होनी चाहिए।सेना अतीत में जब भी भारत पर हमला हुआ है तो सेना युध्द के लिए तैयार नहीं थी,इसलिए भारत को नुकसान हुआ है। माना जाता है कि सेना हमेशा युध्द के लिए तैयार रहे तो वह युध्द जीतती है और उसे किसी तरह का नुकसान नहीं होता है। कहा जाता है कि कारगिल युध्द के बाद से ही सेना महसूस कर रही थी कि सेना की औसत आयु कम करने की जरूरत है यानी सेना में ज्यादा युवाओं की जरूरत है। कारगिल युध्द के बाद जितनी सरकारे हुई उनमें से शायद की किसी सरकार ने सेना में सुधार की जरूरत को समझा और सुधार किया।सेना की मजबूती के लिए विश्वस्तर पर जो सुधार सभी देशों में होते है, देश की सेना की मजबूती के लिए भी सुधार समय समय पर होते रहने चाहिए। जो सुधार कार्य कई सरकारों ने नहीं किया वह काम मोदी सरकार कर रही है तो उसकी सराहना होनी चाहिए तो विरोध हो रहा है। विरोध करने वाले भी गजब के हैं। वह अग्निपथ योजना को देश के युवाओं के सामने नौकरी देने वाली योजना के रूप में पेश कर रहे हैं। कांग्रेस सहित विपक्ष देश के युवाओं को यह बता रहे हैं कि इससे तुमको क्या नुकसान होगा। मोदी सरकार बता रही है कि इससे देश की सेना को क्या फायदा होगा। अग्निपथ योजना में साल में दो बार सेना में भर्ती की जाती है।उनको चार साल प्रशिक्षण दिया जाता है।उसके बाद उनको रेटिंग दी जाती है।इसमें मेरिट में आने वाले 25 प्रतिशत जवानों को सेना में लिया जाता है। बाकी की सेवाएं खत्म कर दी जाती हैं।इसी आधार पर राहुल गांधी कहते हैं कि यह योजना यूज एंड थ्रो है। कांग्रेस अध्यक्ष खरगे कहते हें कि इस योजना के तहत अग्निवीरों को कुछ नहीं मिलता है,न तो उनको जवानों की तरह पेंशन मिलती है,ने ग्रेच्यूटी, न पारिवारिक पेंशन,न उदारीकृत पारिवारिक पेंशन,न ही उनके बच्चों के लिए शिक्षा भत्ता दिया जाता है।कांग्रेस का कहना है कि इस योजना को बंद कर दिया जाना चाहिए। कांग्रेस और विपक्ष मोदी सरकार की तरह देश व जनता के हित में कोई अच्छी योजना बना नहीं पाते हैं तो वह पीएम मोदी जो योजना जनता व देशहित में लाते हैं, उसका विरोध करने लगते हैं। उसमें मीनमेख निकालने लगते हैं। उसे देश व जनता के लिए नुकसानदेह बताते हैं। मोदी सरकार ने किसानों के लिए कानून बनाकर कृषि क्षेत्र में सुधार का प्रयास किया था तो कांग्रेस सहित विपक्ष ने उसका भी विरोध किया था। उसे वापस लेने की मांग को लेकर कुछ राज्यों के किसानों को भड़का कर आंदोलन करने प्रेरित किया था। किसानों के आंदोलन के कारण बाद में सरकार को कृषि कानूनों को वापस ले लिया था।

शादियों पर दिखावा बंद हो

रघु ठाकुर

मुकेश अंबानी के बेटे अनंत और राधिका के लगभग 93वें दिन के विवाह पर्व का समापन हो गया और बकाया देश की तो मैं नहीं जानता, परंतु मेरे जैसे समाचार पत्रों के पाठकों को कुछ सुकून मिला। वरना तीन माह से कब मंगनी हुई, कब फलनी हुई, कहाँ इटली में प्रीवेडिंग हुई, द्वीप किराये पर लिये, कितने हवाई जहाज, कितने बम्बई के फिल्मी दुनिया के नचईये-गवईये शामिल हुए, कितने हजार करोड़ की शादी हुई, इन्हीं उबाई वाली खबरों से मीडिया भरा पड़ा था।

विवाह के खर्च के बारे में लोगों के अलग-अलग अनुमान हैं जो हजार करोड़ से लेकर 5-10 हजार करोड़ तक के खर्च बताते हैं। यह अनुमान स्वाभाविक है। क्योंकि इटली में पूरा द्वीप कई दिनों तक किराये पर लेना, विवाह के अंतिम दिन समारोह में आये मेहमानों को दो-दो करोड़ के गिफ्ट देना यह सामान्य घटना नहीं है और खर्चों के 5000 करोड़ के अनुमान को सही ठहराती है।

ऐसा लग रहा है कि जैसे अंबानी के थुलथुल बेटे की शादी कोई राष्ट्रीय पर्व बन गया हो और जिसका खर्च कहने को अंबानी कर रहे हों परंतु देश के आम नागरिक को इसमें अपना हिस्सा अदा करना पड़ रहा है। विवाह के आयोजनों के दौर में अंबानी ने जियो फोन की दरों को बढ़ा दिया और एक प्रकार से देश के जियो के ग्राहकों के ऊपर विवाह टैक्स लगा दिया। स्वाभाविक है कि प्रधानमंत्री का दोस्त वही हो सकता है जो आपदा में अवसर खोज लेता हो। इस शादी से और उसकी चर्चा से देश में कई प्रकार की मनोविकृतियां पैदा हुई।

आम आदमी ऐसे भारी महंगी शादियां जिसमें तथाकथित वीवीआईपी या सेलिब्रिटीश् शामिल हों के प्रति लालायित आकर्षित होता है। और इसका परिणाम यह होगा कि ये और उनके बच्चे अपनी शादियों में इस दिखावे के लिये क्षमता से अधिक खर्च करेंगे। मुझे स्मरण है कि लगभग 35-36 वर्ष पहले, जब स्व. माधवराव सिंधिया की बेटी की शादी का आयोजन ग्वालियर में हुआ था तो हेलीकाप्टर से फूल बरसाये गये थे। मैं व मेरे उस समय के मित्र स्व. शरद यादव उस शादी के कुछ दिनों के बाद ग्वालियर की यात्रा पर थे तथा हमारे समाजवादी साथी स्व. विष्णुदत्त तिवारी के मकान पर बैठे थे, तब एक गाँव का किसान मिलने के लिये आया था जो अंचल की पिछड़ी जाति गुर्जर समाज से था और उसने हम लोगों से पूछा कि 'हेलीकाप्टर का किराया कितना लगता है। हम लोगों ने बताया कि बहुत पैसा लगता है और क्यों जानना चाहते हो तो उसने बताया कि मैं मेरी बेटी की शादी में हेलीकाप्टर से फूल बरसाना चाहता हूं।' हमने उससे पूछा कि इतना पैसा तुम कहां से लाओगे? तो उसने उत्तर दिया कि 10 एकड़ जमीन बेच दूंगा पर हेलीकाप्टर से फूल बरसाऊँगा। ऐसे खर्चीले व दिखावटी आयोजन का आमजन के मानस पर कितना विपरीत प्रभाव पड़ता है यह इस घटना से समझा जा सकता है। और उसके बाद पिछले वर्षों में अनेकों ऐसे समाचार मीडिया में आये हैं जहाँ गाँव के किसान और पिछड़ी जाति के लोगों ने फूल बरसाने या वर-वधु की विदाई के लिए हेलीकाप्टर किराये पर लिये।

अंबानी के इस वैभवपूर्ण विवाह ने जहां एक तरफ आमजन के मानस में भोगविलास, दिखावा, फिजूलखर्ची के कीटाणु पैदा कर दिल व दिमाग को विकृत्त किया है, उसके साथ ही बाजार के लिये नये द्वार भी खोल दिये हैं। इन सब दिखावों के ऊपर जो पैसा खर्च होगा अंततः वह बाजार में ही जायेगा। और इसलिये शायद मीडिया ने इन खबरों को आकर्षक बनाकर परोसा है क्योंकि मीडिया के मालिक भी वही उद्योगपति व व्यापारी हैं। मीडिया अगर एक सामान्य व्यक्ति अपने परिवार के विवाह में 5-10 लाख रुपये खर्च करता होगा तो अपवाद छोड़ दें तो वह अब अपनी क्षमता से बाहर जाकर भले ही उसे अचल संपत्ति बेचना पड़े, कर्ज लेना पड़े, पर वह 20-30 लाख रुपये खर्च करेगा। उसके बच्चे उसे बाध्य करेंगे। उदाहरण के लिये मान लीजिये एक वर्ष में देश में 1 करोड़ शादियां होती हों और उनमें से 50-60 लाख शादियां मध्यमवर्गीय परिवारों की हो तो देश के बाजार को आसानी से 5-10 लाख करोड़ का व्यापार मिल जायेगा। मनोविकृत्तियों को बिगाड़कर, भोग और जलसे और दिखावे की मानसिकता को तैयार कर, पैसा कमाने के कई प्रकार के प्रयोग पिछले वर्षों से मीडिया ने शुरू कराये हैं। विवाह की वर्षगांठ, विवाह के 25 साल, 50 साल और इन्हें एक बार फिर से नये विवाह के समान बारात और जुलूस से लेकर सभी नाटकीय पुनरावृत्ति शुरू कराई गई। जिन पर 10-20 लाख का खर्च तो मामूली तौर पर होता है। याने अब ऐसा समय आयेगा जिसमें जितनी शादीयां होंगी उनसे ज्यादा शादीयों की वर्षगांठ होगी। जन्म दिवस के उत्सव, मुंडन का उत्सव और न जाने कितने प्रकार के उत्सव शुरू करा दिये गये जिनमें दिखावे व प्रचार ने मध्यमवर्ग को उलझा दिया। इस उत्सवधर्मिता ने एक और लाभ व्यापार जगत को पहुंचाया है वह यह है कि मध्यमवर्गीय व उच्च मध्यमवर्गीय वर्ग अपने सारे, सामाजिक सरोकारों को भूल जाता है व केवल इन समारोहों के विजर्सन, उनमें शिरकत करने में फँसा रहता है।

अगर उसके जीवन के कालखण्ड का सामान्य अध्ययन किया जाये तो साल के लगभग 100 दिन, समाज के उच्च व मध्यम वर्ग के लोग विवाह, विवाह की वर्षगांठ, जन्मदिन, कथा और भण्डारे, तीर्थदर्शन आदि पर खर्च करता है और बकाया समय अपने पारिवारिक दायित्व की पूर्ति के लिए डूयटी पर जाता है। याने वह आम समाज से शारारिक और मानसिक रूप से कट जाता है तथा अपने समाज या देश के बारे में सोचने-विचारने, उसमें सहभागिता करने का न समय उसके पास होता है और न ही उसका मन होता है।

अंबानी के इस विवाह का निमंत्रण उन्होंने राज्यों के मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों, केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री मंत्रियों और विरोधी दलों के नेताओं को भी दिया था, जिनकी देर सवेर सत्ता में आने की संभावनायें हैं या जिनके उनके साथ राजनीति व व्यापारिक रिश्ते हैं जो संसद या विधानसभा के माध्यम से उन्हें लाभ या हानि पहुँचा सकते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी तो उनके समारोह में न केवल सम्मिलित हुये बल्कि मीडिया के अनुसार 2 घंटे 40 मिनिट वहाँ रहे। मैं मान सकता हूं कि चूंकि दोनों गुजरात के हैं और प्रधानमंत्री की राजनीति व धीरूभाई अंबानी के परिवार में गहरा रिश्ता होगा, परंतु एक देश का प्रधानमंत्री एक उद्योगपति के विवाह पर्व में पौने 3 घंटे रहे क्या यह देश के प्रशासन तंत्र को खुला संदेश नहीं है? और सत्ता प्रतिष्ठान व उद्योग प्रतिष्ठान के गहरे रिश्तों का खुलासा नहीं करता। फिर प्रधानमंत्री जी की इस विवाह यात्रा का खर्च किसने उठाया? प्रधानमंत्री की यात्रा पर पर खर्च, विमान, सुरक्षा आदि मिलाकर करोड़ों में होता हैं। क्या प्रधानमंत्री ने यह खर्च निजी कोष से उठाया है? क्या यह खर्च अंबानी समूह ने उठाया है? या देश की गरीब जनता को भोग और जलसों के लिये, प्रेरित करने का खर्च भी सरकारी खजाने याने जनता ने उठाया है? अगर प्रधानमंत्री जी ने यह खर्च स्वतरू उठाया हो या अभी भी इसकी राशि जमा कर दें तो कम से कम यह उनकी नैतिकता होगी परंतु यह होगा नहीं।

मुकेश अंबानी ने कांग्रेस के संसदीय दल की नेता श्रीमती सोनिया गांधी को भी निमंत्रण दिया था और मीडिया के अनुसार वह 1 घंटे उनके साथ रहे। एक निमंत्रण के देने में 1 घंटे का समय कुछ आश्चर्यजनक भी है और कुछ राजनैतिक संदेश व संभावनायें भी पैदा करता है। गुजरात के एक राजनेता श्री देवेन्द्र यादव ने तो आरोप ही लगाया है कि अंबानी ने कांग्रेस के साथ कुछ डील कर ली है और उसी का एक हिस्सा है कि श्री राहुल गांधी ने (यद्यपि वे शादी में नहीं गये थे या पता नहीं उन्हें निमंत्रित किया गया था या नहीं) गुजरात में जाकर कहा कि अब गुजरात में सरकार कांग्रेस की आयेगी। उनकी यह असामयिक घोषणा कुछ चौंकाने वाली तो है। क्योंकि उद्योग जगत ईश्वर प्रदत्त दोनों हाथों से बाँटता है। एक से सत्ता के लिये और दूसरे से सत्ता के संभावितों के लिये। यद्यपि व्यक्तिक निमंत्रण पत्र इंडिया गठबंधन के बड़े हिस्सेदार सुश्री सुश्री ममता बनर्जी, श्री अखिलेश यादव, श्री शरद पवार, श्री उद्धव ठाकरे, तो इस विवाह में शामिल हुये ही, साथ ही श्री लालू प्रसाद जी तो संपूर्ण परिवार की फौज के साथ शामिल हुये। अगर इसे गणित से तौला जाये तो इंडिया गठबंधन का बहुमत विवाह समारोह में शामिल हुआ।

मेरी राय में ऐसी शादियों पर देश में रोक लगनी चाहिये जो अमीरी व विलासिता का नग्न प्रदर्शन करती है। श्री अंबानी के ऊपर इस विलासिता के खर्च के लिये विशेष टैक्स लगाया जाना चाहिये और वह दिन सुखद दिन होगा जब मीडिया स्वतः अपने लाभ व व्यापार का मोह छोड़कर ऐसी शादियों को प्रचारित करना बंद करेगा। वर्ना अभी तो देश में एक सुनियोजित अभियान चल रहा है कि हर व्यक्ति, हर युवा के मन में अंबानी पैदा कर दिया जाये। जो संपत्ति से भले ही अंबानी नहीं हो पर दिमागी तौर पर उस सभ्यता का पिछलग्गू होगा व विषमता के लिये अपना आदर्श मानेगा।

सामाजिक संगठनों को चाहिये कि ये शादियों की इन परंपराओं, दिखावों, फिजूलखर्ची और बेहतर हो कि रात्रि की शादियों पर रोक लगायें। आजकल एक प्रीवेडिंग नाम का चलन शुरू हुआ है। यह एक प्रकार से शादी पूर्व शादी या शादी के समान ही खर्चीली परंपरा शुरू की गई है। इस प्रीवेडिंग के नाम पर 50-50 लाख रुपये खर्च किये जा रहे हैं और मानसिक तौर पर पूंजीवाद के बीज डाले जा रहे हैं। मेरे एक मित्र ने बताया कि प्रीवेडिंग की उनकी बेटी की जिद के कारण उन्हें शादी के अनुमानित खर्च में लगभग दो गुना खर्च करना पड़ा और उन्होंने अपनी एक एकड़ जमीन बेचकर उसे चुकाया। यह दुखद है कि समाजवाद व लोहिया का नाम लेने वाले कुछ लोग भी ऐसी शादियों में शामिल होकर या उनकी नकल कर समाजवादी आंदोलन को एवं समता के सघर्ष को कमजोर कर रहे हैं। राजनीति मात्र सत्ता का खेल नहीं है बल्कि समाज के मानसिक बदलाव, राजनैतिक बदलाव व सांस्कृतिक क्रांति का भी माध्यम होती है। जो गांधी, लोहिया व समाजवाद को मानते हैं अगर वह इतना भी आत्म निर्णय कर लें कि न ऐसे किसी दिखावटी आयोजन को करेंगे न उसमें शामिल होंगे तो यह भी एक अच्छी शुरूआत हो सकती है।

अध्यात्म

ज्ञान प्राप्त करने के लिए मन को खाली करना है जरूरी

एक बार व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। उसने हाथ जोड़कर बुद्ध से कहा, 'कृपया मुझे अपना शिष्य बना लें। मैं आपसे ज्ञान पाना चाहता हूं, जिससे मेरा जीवन बदल सके।' बुद्ध ने उस व्यक्ति की ओर देखा और कहा, 'यदि तुम मुझसे शिक्षा लेना चाहते हो तो तुम आज से दस दिन बाद मेरे पास आना।' वह व्यक्ति दस दिन बाद फिर बुद्ध के पास आया और कहा, 'अब दस दिन बीत गए हैं, कृपया मुझे शिक्षा दें।' बुद्ध का उत्तर फिर यही था, 'यदि तुम कुछ सीखना चाहते हो, तो दस दिन बाद आओ।' ऐसा कई महीनों तक चलता रहा। जब भी शिष्य उनके पास आता तो बुद्ध उसे यह कहकर वापस भेज देते कि दस दिन बाद आना। आखिरकार उस व्यक्ति का धैर्य टूट गया। इस बार उसने बुद्ध से पूछा, 'आप हर बार मुझे वापस भेज देते हैं। ऐसा क्यों?' बुद्ध ने उससे एक गिलास पानी लाने को कहा। वह व्यक्ति पानी ले आया। इसके बाद बुद्ध ने कहा, 'जाओ, एक गिलास पानी और ले आओ।' वह उनके निर्देशानुसार पानी से भरा एक और गिलास ले आया। अब बुद्ध ने कहा, 'पहले गिलास में थोड़ी मिट्टी डाल दो।' उस व्यक्ति ने बिना कोई प्रश्न पूछे वैसा ही किया। मिट्टी डालते ही पहले गिलास का पानी पूरी तरह गंदा हो गया। अब बुद्ध ने उससे कहा, 'पहले गिलास का पानी दूसरे गिलास में डालो।' इस पर उस व्यक्ति ने कहा, 'यदि मैं ऐसा करूंगा तो पहले गिलास का पानी न केवल बाहर गिरेगा, बल्कि गंदा भी हो जाएगा। पहला गिलास पानी से भरा हुआ है, उसमें दूसरे गिलास का पानी कैसे आ सकता है? इस पर बुद्ध मुस्कुराए और कहा, 'मैं तुम्हें यही समझाना चाहता हूं कि तुम अभी ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो क्योंकि तुम्हारा दिमाग गंदे पानी से भरे उस गिलास की तरह पहले से ही सभी प्रकार के बुरे ज्ञान से भरा हुआ है। ऐसी स्थिति में मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान तुम्हारे मस्तिष्क में कैसे समा सकता है? यदि मैं ज्ञान देने लगूंगा तो वह ज्ञान व्यर्थ चला जाएगा, इसलिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने मन को नकारात्मक विचारों से खाली करना होगा। आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए मन का पूर्णत खाली होना आवश्यक है।' भगवान बुद्ध का कथन सुनकर उस व्यक्ति को उनकी बात का मर्म समझ में आ गया।

उधार का मायाजाल...

एक तरफ होती है मासिक किस्त और दूसरी तरफ होता है क्रेडिट कार्ड का बिल। कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि इसकी टोपी उसके सिर का कोई खेल हो गई है जिंदगीज 'न सांस लेने की फुर्सत है न जीने का अहसास', बस हाथ से रेत की तरह फिसलती जा रही है हम सबकी जिंदगी। कहने का मतलब यह है कि बाजारवाद से इतने घिरे हुए है हम कि अब जीवन पूरी तरह उन्हीं पर निर्भर हो गया है। बात सेहत की हो तो स्वास्थ्य बीमा, गाड़ी खरीद ली गई हो तो कार बीमा, घर खरीदा हो तो उसका बीमा और यहां तक कि हमारे मर जाने के बाद के लिए भी जीवन-बीमा। यह बात अब बहुतों की जुबान या दिमाग में है कि केवल जिंदगी के साथ ही नहीं, जिंदगी के बाद भी।

पल्लवी सक्सेना

आधुनिकता की होड़ में जीवन इतनी तेजी से भाग रहा है कि अब मनुष्य को हर चीज चुटकियों में चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि आजकल कोई अपनी किसी इच्छा को पूरा करने के लिए धैर्य रखना नहीं चाहता। सबको जैसे एक अलादीन का चिराग चाहिए कि इधर इच्छा व्यक्त की और उधर पूरी हो जाए। यह समझना मुश्किल हो जाता है कि आखिर लोगों के भीतर इतनी तेजी और इतनी हड़बड़ी क्यों है? सब कुछ तुरंत और बहुत तेज रफ्तार से क्यों चाहिए? जबकि सच यह है कि वास्तव में ऐसा संभव नहीं है कि इच्छा जाहिर की और किसी 'जिन्न' की तरह कोई प्रकट हुआ और उसने तुरंत इच्छा पूरी कर दी। मगर आजकल यह 'जिन्न' वाला काम कुछ बैंक वाले करने का दावा करने लगे हैं। व्यक्ति की हर छोटी-बड़ी आवश्यकताओं की उनके पास फेहरिस्त होती है और उसे वे ईएमआइ यानी मासिक किस्त में बांधकर लोगों के सामने पेश कर देते हैं। दुनिया जहान की किसी भी चीज की जरूरत हो तो बस उसकी किस्तें बंधवा ली जाए और चीज हमारे घर में होगी। मसलन, सोफा, टीवी, फ्रिज, माइक्रो वेव, मोबाइल आदि कुछ भी। घर तो किस्तों पर मिलता ही रहा है। फिर अपने-अपने दफ्तरों में रगड़ते रहा जाए खुद को और एक लंबे अरसे तक भरते रहा जाए किस्त-दर-किस्त अपने माथे पर बोझ की तरह पड़ चुके ऋण की। आश्चर्य तो तब होता है जब हमको यह पता चलता है कि हमारी आमदनी से ज्यादा हमारे उधार हैं और यह एक मायाजाल है, जिसमें हम बस दूसरों को दिखाने के चक्कर में फंसते चले जाते हैं। दूसरी ओर, आवश्यकताएं हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेती और न ही उधार लेने का सिलसिला ही कभी रुकता है।

एक तरफ होती है मासिक किस्त और दूसरी तरफ होता है क्रेडिट कार्ड का बिल। कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि इसकी टोपी उसके सिर का कोई खेल हो गई है जिंदगीज 'न सांस लेने की फुर्सत है न जीने का अहसास', बस हाथ से रेत की तरह फिसलती जा रही है हम सबकी जिंदगी। कहने का मतलब यह है कि बाजारवाद से इतने घिरे हुए है हम कि अब जीवन पूरी तरह उन्हीं पर निर्भर हो गया है। बात सेहत की हो तो स्वास्थ्य बीमा, गाड़ी खरीद ली गई हो तो कार बीमा, घर खरीदा हो तो उसका बीमा और यहां तक कि हमारे मर जाने के बाद के लिए भी जीवन-बीमा। यह बात अब बहुतों की जुबान या दिमाग में है कि केवल जिंदगी के साथ ही नहीं, जिंदगी के बाद भी। जीवन बीमा का तो फिर भी समझ में आता है जो हमारे बाद परिवार के काम आता है, लेकिन बाकी जरूरतें क्या इतनी आवश्यक हैं कि उन्हें ईएमआइ यानी मासिक किस्तों पर लिया जाना चाहिए?

यह माना जा सकता है कि मासिक किस्तों की व्यवस्था में पैसा थोड़ा-थोड़ा कटता है तो चीजों का बोझ महसूस नहीं होता। वह भी तब, जब हमारे घर में दो आमदनियां हों, अन्यथा एक ही आमदनी पर तो मासिक किस्तों का यह बोझ भारी पड़ने लगता है, क्योंकि यह किसी एक वस्तु से संबंधित नहीं होती, बल्कि अनेक वस्तुओं से संबंधित होती है। वह भी एक साथ। इससे भी ज्यादा आश्चर्य तो तब होता है, जब दो-दो लोगों की आमदनी होते हुए भी लालच लोभ इतना अधिक बढ़ जाता है कि गैरजरूरी चीजों के लिए भी हम यानी मासिक किस्त और क्रेडिट कार्ड पर निर्भर होते चले जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। यह सोचने की जरूरत है कि बुरा वक्त कभी कहकर नहीं आता। कोरोना जैसी आपदा के बाद जब लाखों की संख्या में लोगों की नौकरियां चली गई, तब उनका क्या हाल हुआ, यह तो वे ही जानते हैं। विदेश में तो और भी बुरा हाल है। हमारे वृद्ध जनों ने यों ही कर्ज को खराब नहीं बताया है। कर्ज ही वह कारण है, जिसकी वजह से हमारे किसान भाइयों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। फिर एक हम हैं कि हमारी आंखें नहीं खुल रही हैं।

जबकि हमारे आसपास अक्सर ऐसी घटनाएं होती देखने-सुनने को मिल रही हैं कि कर्ज में डूबा कोई व्यक्ति नौकरी या रोजगार जाने के बाद मासिक किस्त या कर्ज चुकाने में सक्षम नहीं रहा और इससे उपजे दबाव और तनाव ने उसकी जिंदगी लील ली। कोई गंभीर बीमारी का शिकार होकर और ज्यादा बड़े मकड़जाल में फंस गया तो कोई वक्त के थपेड़ों को सह नहीं सका और किसी ने कभी अकेले तो कभी परिवार सहित जान दे दी। जिंदा भर रह सकने के लिए किसी से उधार लेना अलग बात है, मगर यह कितना त्रासद है कि बहुत मामूली सुविधाओं या दिखावे के सामान खरीदने के लिए हम कर्ज के जाल में फंस जाते हैं और होश तब आता है, जब हमारा गला कसने लगता है।

सच यह है कि कुछ निजी और अहम जरूरतों के अतिरिक्त कुछ अन्य ऐसी चीजें हैं, जिनके बिना रहा नहीं जा सकता। लेकिन समाज में हैसियत की बात, उसका दिखावा और दूसरों से प्रतियोगिता का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। ऐसे में अगर कोई दिखावे में विश्वास रखता है तो किस्त-दर-किस्त भरने के लिए उसे अपनी मेहनत की कमाई को यों ही खर्च करने में गुम होना पड़ेगा। अन्यथा सादा जीवन उच्च विचार का रास्ता हमेशा खुला है। कहा भी जाता है कि 'जिसकी जरूरतें कम हैं, उसके हाथ में दम है'।

आज का कार्टून

राशिफल

मेष
व्यापार में बड़ा आर्थिक लाभ मिल सकता है। आलस्य की वजह से काम में रुकावटें आ सकती हैं। आपके मान-सम्मान में वृद्धि होगी।

वृषभ
अति आत्मविश्वास के कारण आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है। अनावश्यक मामलों में उलझ सकते हैं। बुरी संगत वाले लोगों से दूरी बनाकर रखें।

मिथुन
व्यवसाय में बड़ा फेरबदल कर सकते हैं। मृदु व्यवहार के कारण लोगों के चहेते बने रहेंगे। कार्यक्षेत्र में आपको नये अनुभव मिलेंगे। मित्रों के साथ आत्मीयता बढ़ेगी।

कर्क
सामाजिक कार्यों में आप काफी सक्रिय रहेंगे। धार्मिक कार्यों में मन लगायेंगे।वैवाहिक जीवन में परस्पर सम्मान की भावना में वृद्धि होगी।

सिंह
वरिष्ठ जनों का सहयोग प्राप्त होगा। लोग आपसे काफी अपेक्षा रखेंगे। जीवनसाथी और इष्टमित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। घर में कुछ बदलाव कर सकते हैं।

कन्या
रुके हुये सरकारी कार्य आज पूरे हो जायेंगे। बड़े अधिकारी आपसे बहुत प्रसन्न रहने वाले हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी बातों को विशेष महत्व मिलेगा।

तुला
आपके व्यवहार में गम्भीरता की प्रशंसा होगी। मनोरञ्जन सम्बन्धित कार्यों में आप धन खर्च करेंगे। आपकी जीवनशैली में सुधार आयेगा।

वृश्चिक
आज काम के प्रति एकाग्र नहीं हो पा रहे हैं इसीलिये नये काम की शुरूआत न करें। प्रेम सम्बन्धों को लेकर तनाव बढ़ेगा। सुख-सुविधाओं में कमी आयेगी।

धनु
आप अपने व्यक्तिगत जीवन को काफी महत्व देंगे। घुटनों में दर्द की शिकायत हो सकती है। वैवाहिक जीवन में प्रेम भाव बढ़ेगा। कारोबारी अनुबन्धों के लिये दिन बहुत ही अच्छा है।

मकर
कानूनी मामलों में आज आपको नहीं फँसना चाहिये। दूसरों कही-सुनी बातों पर सहसा विश्वास न करें। बच्चों की उपलब्धि से हर्षित रहेंगे। निर्माण कार्यों में तेजी आयेगी।

कुंभ
सभी कार्यों को समय पर पूरा करने का प्रयास करें। यदि आप किसी काम को टालते हैं तो भविष्य में भी उसके टलने की सम्भावना बढ़ जायेगी।

मीन
सहकर्मियों का बेहतरीन सहयोग प्राप्त होगा। आप वही काम करना पसन्द करेंगे जो आपका शौक बन गया हो। समझदारी पूर्वक स्थितियों को सम्भालने का प्रयास करें।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 17 अंक 141

स्पष्ट रोडमैप की जरूरत

गत सप्ताह नीति आयोग की संचालन संस्था की नौवीं बैठक के बाद एक 'दृष्टिकोण पत्र' जारी किया गया। इसमें 2047 तक विकसित भारत बनाने को लेकर विजन पेश किया गया है। यह लक्ष्य चर्चा में है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार इसका उल्लेख कर चुके हैं। यह महत्त्वपूर्ण है कि इस बात का आकलन किया जाए कि सरकार का थिंक टैंक इस बारे में क्या सोचता है कि इसे हकीकत में बदलने के लिए क्या कुछ करना होगा। दस्तावेज में काफी आत्मविश्वास नजर आता है और वह इस मान्यता पर आधारित है कि भारत ने 'बदलाव के अपने सफर में कई ऐसे मुकाम हासिल किए जो नजर आते हैं और अब वह उड़ान भरने को तैयार है।' परंतु कई लोगों का तर्क है कि भारत बीते कम से कम दो दशकों से रनवे पर ही खड़ा है और उसकी उड़ान अभी भी कुछ दूर नजर आती है।

संबंधित दस्तावेज में बीते एक दशक के प्रदर्शन की काफी बात की गई है और यह दर्शाया गया है कि भारत ने तेज छलांग लगाने की क्षमताएं दिखाई हैं। इस बात को जन धन खातों में विस्तार, चंद्रयान की उपलब्धि और एशियाई खेलों में पदक तालिका में स्थान तक के संदर्भ में कहा गया है। ये सभी बातें गर्व करने लायक हैं लेकिन ये तथा ऐसे अन्य उदाहरणों का आवश्यक तौर पर यह अर्थ नहीं हो सकता है कि ये आर्थिक विकास की योजनाओं में भी अनिवार्य तौर पर अपनी भूमिकाएं निभाएं। इसका काफी हिस्सा इस बात की पड़ताल करता है कि विकसित भारत का क्या अर्थ हो सकता है। यह दावा किया गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर 15 लाख लोगों के साथ संवाद करके विकसित भारत 2047 के लिए विजन का प्रारूप तैयार किया गया। बहरहाल इसमें कुछ लोकप्रिय मांगें मसलन स्वच्छ पेय जल, सबके लिए कौशल तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जीवंत बनाना आदि शामिल हैं और इस आधार पर लगता है कि इसके लिए इतनी गहन चर्चा की क्या आवश्यकता थी। 'आंतरिक चुनौतियों' वाला हिस्सा सबसे अधिक प्रासंगिक है। इसमें ऊर्जा क्षेत्र की दिक्कतें दूर करना, ग्रामीण शहरी असमानता और औद्योगिक प्रतिस्पर्धा जैसे विषय शामिल हैं। हालांकि इन पर कैसे काम होगा, ये सुझाव भी प्राप्त करने होंगे।

आखिर में सबसे अहम हैं आर्थिक लक्ष्य। ऐसा इसलिए कि विकसित भारत के अन्य लक्ष्यों को हासिल करने के लिए जरूरी गति वृद्धि से ही हासिल होगी।

पत्र में कहा गया है, 'हमें 2047 तक 30 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना है और उस समय तक हम 18,000 डॉलर वार्षिक की प्रतिव्यक्ति आय का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं।' हालांकि इसे हकीकत में बदलने के लिए दो अंकों की वृद्धि लगातार बरकरार रखनी होगी। पत्र में ऐसी वृद्धि के उदाहरणों में जापान, जर्मनी, सिंगापुर और कोरिया के साथ चीन का नाम पढ़ना दिलचस्प है। इन देशों ने दशकों तक उच्च वृद्धि हासिल की है और इसे नाटकीय संस्थागत और साामजिक बदलावों से भी मदद मिली है। सिंगापुर ने अपनी अफसरशाही में सुधार किया, कोरिया ने नए तरह की निजी-सार्वजनिक भागीदारी विकसित की, जापान ने अपने सार्वजनिक क्षेत्र में, नियमन और न्यायपालिका में पूरी तरह पश्चिमी उदारवादी मॉडल अपना लिया। चीन में 1970 के दशक के बाद ऐसा ही बदलाव हुआ और संचालन की प्रक्रिया में खुलापन लाया गया, निजी मुनाफे की इजाजत दी गई और निर्णयों का विकेंद्रीकरण किया गया।

भारतीय संस्थानों में ऐसे बदलाव के बिना लगातार उच्च वृद्धि हासिल करना मुश्किल होगा। उदाहरण के लिए हमारे देश के पुराने और सख्त अफसरशाही ढांचे की वजह से निर्णय प्रक्रिया में देरी होती है और विशेषज्ञता या अनुभव को तवज्जो नहीं दी जाती है। स्पष्ट है कि प्रशासनिक सुधार भी काफी समय से लंबित हैं। कई संस्थानों में बदलाव की आवश्यकता है। न्यायिक प्रक्रिया में बहुत समय लगता है, कानून का प्रवर्तन करने में मनमानापन है, तीसरे स्तर की सरकार को पर्याप्त फंडिंग नहीं है और उसके यहां जवाबदेही का अभाव है। महिलाओं को श्रम शक्ति में अधिक भागीदारी देने जैसे सामाजिक बदलावों को लागू करना तब और कठिन हो सकता है। इन सभी के लिए राजनीतिक और सामाजिक सहमति की आवश्यकता होगी। नीति आयोग को उसे हासिल करने पर काम करना चाहिए।

ओबीएस के निर्यात में अपार संभावनाएं

भारत में ओबीएस निर्यात के प्रमुख स्रोत के रूप में उभर रही हैं और सरकार से पर्याप्त एवं उचित समर्थन मिलने पर ये सॉफ्टवेयर एवं सूचना-प्रौद्योगिकी को भी पछाड़ सकती हैं। बता रहे हैं अजय श्रीवास्तव

वर्ष 2030 तक अन्य कारोबारी सेवाएं (ओबीएस) भारत से निर्यात का अगला बड़ा स्रोत हो सकती हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि ये सॉफ्टवेयर एवं सूचना-प्रौद्योगिकी (आईटी) सेवा क्षेत्र को भी पीछे छोड़ देंगी। दूसरे शब्दों में कहें तो भारत से सेवा निर्यात में ओबीएस नए असरदार भागीदार के रूप में उभर रही हैं।

ओबीएस खंड में वे सेवाएं आती हैं जो विविध कारोबारी परिचालनों जैसे कारोबार परामर्श, अभियांत्रिकी (इंजीनियरिंग) और रिसर्च एवं डिजाइन (आरऐंडडी) से संबंधित होती हैं। इसमें विज्ञापन, जन संपर्क, बाजार शोध, लॉजिस्टिक्स, लेखा, अंकेक्षण (ऑडिट), वास्तुशिल्प एवं विधि सेवाएं सहित कई विधा आती हैं।

वित्त वर्ष 2022-23 में भारत से 150 अरब डॉलर मूल्य (वैश्विक हिस्सेदारी का 20 प्रतिशत) की सॉफ्टवेयर एवं आईटी सेवाओं और 80 अरब डॉलर मूल्य (वैश्विक हिस्सेदारी का 4.2 प्रतिशत) की ओबीएस का निर्यात हुआ। सॉफ्टवेयर एवं आईटी सेवाओं की भारत से सेवाओं के कुल निर्यात में आधी से अधिक हिस्सेदारी रहती है और ओबीएस की लगभग एक चौथाई हिस्सेदारी होती है।

आइए, यह समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों ओबीएस में आईटी से भी आगे निकलने की क्षमता है। यद्यपि सॉफ्टवेयर एवं आईटी भारत से निर्यात के सबसे बड़े स्रोत हैं मगर ओबीएस का व्यापार भी तेजी से बढ़ रहा है। वैश्विक स्तर पर सेवाओं का निर्यात लगभग 7.1 लाख करोड़ डॉलर रहा। इनमें ओबीएस का निर्यात 1.8 लाख करोड़ डॉलर (25.4 प्रतिशत) और सॉफ्टवेयर एवं आईटी का 762 अरब डॉलर (10.7 प्रतिशत) रहा। आने वाले वर्षों में आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) और केवल एक देश पर निर्यात संबंधी निर्भरता के कारण सॉफ्टवेयर एवं आईटी क्षेत्र की वृद्धि नरम पड़ सकती है। भारत आईटी निर्यात से जो कमाई करता है, उसमें अमेरिका की हिस्सेदारी 70 प्रतिशत से अधिक होती है। कुछ रणनीतिक कदमों से आने वाले वर्षों में भारत से ओबीएस निर्यात सॉफ्टवेयर एवं आईटी की तुलना में तेज गति से आगे बढ़ सकता है।

ओबीएस का बढ़ रहा वैश्विक व्यापार

विशेष सेवाओं की बढ़ती मांग, सेवाओं का विनिर्माण से जुड़ाव और तकनीक में प्रगति ओबीएस की वृद्धि को बढ़ावा दे रहे हैं। बड़ी विनिर्माण कंपनियां लागत कम करने के लिए संरचना, विकास एवं उत्पादन कार्य अलग-अलग जगहों पर ले जा रहे हैं। इस कदम के बाद अभियांत्रिकी, आईटी, लॉजिस्टिक्स एवं आरऐंडडी की मांग बढ़ रही है। सेवाओं का विनिर्माण में यह जुड़ाव विनिर्माण के 'सेवाकरण' या सर्विसिफिकेशन के नाम से जाना जाता है, जो ओबीएस को बढ़ावा दे रहा है। उदाहरण के लिए कार बनाने वाली कोई अमेरिकी कंपनी इंजन बनाने का जिम्मा भारत में किसी इंजीनियरिंग कंपनी को दे रही है। यह 'सर्विसिफिकेशन' के रुझान को दर्शा रहा है। इसके अलावा विदेश में कारोबार विस्तार करने वाली कंपनियों को नए बाजारों में अधिक सेवाओं की आवश्यकता होती है। तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में तेज वृद्धि भी इंजीनियरिंग, विज्ञापन और आरऐंडडी सेवाओं की मांग बढ़ाती हैं। तकनीक में प्रगति जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग, दूर बैठे काम करने की तकनीक और डिजिटल प्लेटफॉर्म दुनिया भर में अधिक सेवाएं पहुंचा रही है, जिससे उनका व्यापार तेजी से बढ़ रहा है।

विभिन्न क्षेत्रों में डिजिटल माध्यम के अधिक इस्तेमाल से तकनीकी एवं इंजीनियरिंग सेवाओं की मांग और तेजी से बढ़ रही है। यूरोप की किसी दवा कंपनी द्वारा भारत में आरऐंडडी केंद्र के लिए रकम मुहैया कराना या किसी भारतीय एजेंसी द्वारा किसी कोरियाई इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के लिए मार्केटिंग अभियान चलाना इन गतिविधियों का उदाहरण हो सकता है।

कम से कम लागत में ज्यादा से ज्यादा काम होना भी एक अन्य कारक है। कंपनियां इंजीनियरिंग, आरऐंडडी और विज्ञापन जैसे कार्य भारत जैसे कम खर्चीले स्थानों से कराती हैं। इससे इन कंपनियों को प्रमुख कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है और विशेष सेवाओं के लिए दूसरे देशों की विशेषज्ञता पर निर्भर रहती हैं। इसके अलावा नियामकीय दबावों के कारण व्यवसायों को अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुपालन के लिए परामर्श सेवाओं की आवश्यकता महसूस हो रही है। इन सभी कारणों से दुनिया भर में ओबीएस का वैश्विक व्यापार तेजी से बढ़ रहा है। भारत को इस रुझान से लाभान्वित होने का पूरा हक है।

भारत के ओबीएस निर्यात की ताकत कौन?

भारत से 80 अरब डॉलर मूल्य के ओबीएस का निर्यात होता है, जिनमें आधा वैश्विक क्षमता केंद्रों (जीसीसी) से और शेष हिस्सा विभिन्न आकार की कंपनियों एवं परामर्श इकाइयों से आता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों (एमएनसी) द्वारा स्थापित जीसीसी आईटी सेवाएं, वित्त, मानव संसाधन, आरऐंडडी और विभिन्न बैक-ऑफिस (प्रशासन एवं सहायता कर्मियों वाला विभाग जो सीधे ग्राहकों से संवाद नहीं करते हैं) परिचालन आदि कार्य संभालते हैं। भारत में लगभग 1,500 जीसीसी हैं, जो बेंगलूरु, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, मुंबई, गुरुग्राम और नोएडा में हैं। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, आईबीएम, जीई, वॉलमार्ट, जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स, एचएसबीसी, सीमेंस और इंटेल जैसी कंपनियां ये जीसीसी स्थापित करती हैं। जीसीसी बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (बीपीओ) और नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग (केपीओ) के विकास का अगला चरण हैं।

बीपीओ और केपीओ ने कई ग्राहकों को अपनी सेवाएं दीं मगर बड़ी एमएनसी अब धीरे-धीरे अपने जीसीसी लगाकर यह काम खुद करने लगी हैं। इससे इन कंपनियों को रकम बचाने और डेटा सुरक्षा से जुड़े मसलों से बेहतर तरीके से निपटने में मदद मिलती है। जीसीसी ने भारतीय आईटी कंपनियों से कुछ कारोबार छीन लिए हैं। जीसीसी के बाहर ओबीएस निर्यात में मुख्यतः स्थानीय कंपनियों का योगदान होता है। कई छोटी नई कंपनियां और बड़ी सलाहकार इकाइयां लेखा एवं कर, विधि सेवा, प्रबंधन सलाह, विपणन एवं विज्ञापन सेवा, वास्तुशिल्प सेवा एवं लॉजिस्टिक्स सेवा जैसे क्षेत्रों में विशिष्ट सेवाएं देती हैं। ये कंपनियां अपनी सेवाएं पहुंचाने के लिए सीधे ग्राहकों के साथ या मध्यस्थों के साथ मिलकर काम करती हैं। कुछ भारतीय कंपनियां इंजीनियरिंग, निर्माण और आईटी विकास में परियोजना के आधार पर काम कर अंतरराष्ट्रीय परियोजनाएं हासिल कर लेती हैं। वे दुनिया भर में अपनी सेवाएं देने के लिए अक्सर स्वतंत्र इकाइयों (फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म) का इस्तेमाल करती हैं।

निर्यात क्षमता हासिल करने की रणनीति

कई छोटी कंपनियां ओबीएस का निर्यात तो करती हैं मगर भारत में ज्यादातर अभियांत्रिकी, शोध एवं प्रबंधन पेशेवर इस क्षेत्र में व्यापक संभावनाओं से परिचित नहीं हैं। पर्याप्त एवं उचित समर्थन दिया जाए तो ओबीएस निर्यात करने वाली कंपनियों की संख्या में भारी इजाफा हो सकता है। इस दिशा में पांच-सूत्री योजना फायदेमंद हो सकती है।

नियामकीय समीक्षाः सरकार को ओबीएस क्षेत्र में प्रत्येक विशिष्टीकृत सेवा के लिए स्थानीय नियमों की समीक्षा करनी चाहिए और उन्हें श्रेष्ठ वैश्विक मानकों के अनुरूप करना चाहिए।

प्रमाणन नियमः ओबीएस में जरूरी विभिन्न पेशेवर हुनर एवं नियामकीय जानकारियों के लिए वैश्विक बाजार की आवश्यकताओं पर आधारित प्रमाणन मानक लागू किया जाना चाहिए। इससे पेशेवरों को अपने हुनर विश्व-स्तरीय बनाने में मदद मिलेगी।

संघ स्थापित करने की जरूरतः सॉफ्टवेयर एवं आईटी खंडों की तुलना में ओबीएस में सैकड़ों विशिष्ट सेवाएं हैं और इनमें प्रत्येक के लिए अलग हुनर, नियम एवं कारोबारी बाधाएं हैं। इसे देखते हुए बड़ी ओबीएस श्रेणियों के लिए संघ/संगठन स्थापित करने की जरूरत हैं। ये संघ सदस्यों को भारत और दुनिया में नियामकीय चुनौतियों से बाहर निकलने में मदद करेंगे। दूसरे देशों में अपने समान संघों/संघठनों से सहयोग कर भारतीय संघ खरीदार एवं विक्रेताओं से जुड़ पाएंगे। ये संगठन कितने असरदार रहेंगे, यह उनके नेतृत्व एवं संरचना पर निर्भर करेगा। कई लोग गर्व से यह याद करते हैं कि किस तरह देवांग मेहता की सक्रियता ने 1990 के दशक में भारत के आईटी उद्योग को शुरुआती दौर में मदद पहुंचाई।

व्यापार आंकड़ों का प्रकाशनः भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) लेन-देन के देशवार आंकड़े जारी नहीं करता है। किसी खास ओबीएस पर विस्तृत आंकड़े विभिन्न ओबीएस श्रेणियों में विभिन्न क्षेत्रों के लिए मौजूद संभावनाओं को रेखांकित कर सकते हैं।

व्यापार वार्ताः व्यापार वार्ता के दौरान भारत साझेदार देशों पर दबाव डाल सकता है कि वे अपने बाजारों तक भारतीय कंपनियों के पहुंचने की राह में लगाई गई पाबंदी कम करें। ये प्रतिबंध ज्यादातर डेटा सुक्षा से जुड़ी चिंता, मालिकाना हक की सीमा, राष्ट्रीयता की जरूरत या खास सेवा प्रकारों पर पाबंदी से जुड़े हैं।

भारत में ओबीएस क्षेत्र की वृद्धि न केवल अर्थव्यवस्था को मजबूती देगी बल्कि उद्यमशीलता के उच्च गुणवत्ता वाले अवसर भी लाखों की संख्या में पैदा करेगी। अब ओबीएस खंड की पूर्ण क्षमता का लाभ उठाने के लिए निर्णायक कदम उठाने का समय आ गया है।

(लेखक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनीशिएटिव के संस्थापक हैं)

रेशम उत्पादन में छिपीं तरक्की की संभावनाएं

खेती बाड़ी

सुरिंदर सूद

रेशम कीड़ों के पालन और उनके कोकून से पैदा होने वाले रेशम फाइबर के उत्पादन में आई तेजी के कारण भारत 2030 तक रेशम और रेशम उत्पादों का प्रमुख उत्पादक देश बनने की ओर अग्रसर है। रेशम उत्पादन की प्रक्रिया को सेरीकल्चर कहा जाता है। वर्ष 2022-23 में अनुमानित रेशम उत्पादन 36,500 टन था, जिसके अगले दशक के शुरू तक बढ़कर कर 50,000 टन पहुंचने की संभावना है। यदि भारत इस आंकड़े को छू लेता है तो वह विश्व के सबसे बड़े रेशम उत्पादक चीन को पीछे छोड़ देगा।

भारत इस समय रेशम उत्पादन में आधुनिक तकनीक अपनाने पर अधिक जोर दे रहा है क्योंकि इस पेशे में लगे किसानों की बड़ी तादाद सदियों पुरानी पद्धति से ही काम कर रही है। सरकार रेशम कीड़ों के पलने-बढ़ने के लिए सबसे जरूरी पौधे शहतूत, अरंडी और दूसरे पौधों का क्षेत्रफल कई अन्य राज्यों में भी बढ़ाने की योजना बना रही है ताकि रेशम की खेती किसी एक राज्य में ही सिमट कर न रह जाए।

सेरीकल्चर से उत्पन्न होने वाले अन्य उत्पादों को भी लाभ कमाने का जरिया बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इनमें कई ऐसे उत्पाद हैं, जिनसे भरपूर व्यावसायिक लाभ लिया जा सकता है। इससे न केवल रेशम उत्पादकों की आमदनी बढ़ेगी, बल्कि रेशम फाइबर, फैब्रिक और रेशम के कपड़ों समेत इससे जुड़े अन्य उत्पादों की गुणवत्ता में भी इजाफा होगा।

केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के साथ-साथ कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे कुछ बड़े रेशम उत्पादक राज्यों के अलावा उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे छोटे रेशम उत्पादक भी सेरीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए महत्त्वाकांक्षी योजनाएं तैयार कर रहे हैं। रेशम उद्योग से जुड़े सूत्रों का कहना है कि अनुमानों के मुताबिक वर्ष 2023 में सेरीकल्चर बाजार 53,000 करोड़ रुपये का था, जिसके 2030 तक 15 प्रतिशत से अधिक की वार्षिक वृद्धि दर के साथ बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपये पर पहुंचने की संभावना है।

हालांकि भारतीय सेरीकल्चर निर्यात में अप्रत्याशित रूप से गिरावट देखने को मिली है क्योंकि देश के भीतर ही इसकी मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है। देश में जितनी मांग है, उसके मुकाबले उत्पादन बहुत कम है। भारत को देश के भीतर रेशम आधारित उद्योगों की जरूरत पूरी करने के लिए हर साल 4,000 टन रेशम आयात करना पड़ता है। इसलिए देसी स्तर पर रेशम उत्पादन बढ़ने के बावजूद इसका निर्यात सीमित ही रहेगा और पिछले दिनों की तरह इसमें घट-बढ़ होती रहेगी। वर्ष 2021-22 में रेशम और इससे बने उत्पादों का निर्यात 24.86 करोड़ डॉलर रहा था, जो इससे एक वर्ष पहले के मुकाबले 25.3 प्रतिशत अधिक था, लेकिन वर्ष 2022-23 में यह निर्यात गिरकर 22.05 करोड़ डॉलर पर आ गया। इस उतार-चढ़ाव में कोविड महामारी की कितनी बड़ी भूमिका रही, यह पता नहीं लग पाया। भविष्य में निर्यात की स्थिति क्या रहेगी, अभी यह कहना भी बहुत मुश्किल है।

भारत की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां चारों प्रकार के रेशम- शहतूत, मूगा, एरी और टसर का उत्पादन होता है। भिन्न-भिन्न किस्मों का रेशम अलग-अलग प्रजाति के कीड़ों द्वारा पैदा किया जाता है, जिन्हें मोठ भी कहा जाता है। सभी प्रकार के रेशम की गुणवत्ता में भी अंतर होता है। इनमें शहतूत रेशम का उत्पादन मोठ प्रजाति के बोमबिक्स मोरी द्वारा किया जाता है। इसके कीड़े शहतूत के पत्तों पर पाले जाते हैं। देश में अधिकांश रेशम इन्हीं कीड़ों द्वारा पैदा किया जाता है। शहतूत रेशम अपनी मजबूती, बढ़िया बनावट और शानदार चमक के लिए मशहूर है। इसलिए भारतीय महिलाओं का पारंपरिक परिधान साड़ी बनाने में इसकी मांग बहुत अधिक होती है। मूगा रेशम विशेष प्रकार की सुनहरी रंगत लिए हुए होता है। यह एंथेरिया असमेंसिस नाम के रेशम कीड़े द्वारा तैयार होता है। ये कीड़े मुख्य रूप से असम और आसपास के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यह रेशम अपनी चमक, चमकदार बनावट और लंबे समय तक चलने जैसी विशेषता के लिए जाना जाता है। आमतौर पर इसकी कीमत भी ऊंची होती है।

इरी रेशम, जिसे एंडी और एरांडी के नाम से भी जाना जाता है, खासतौर पर असम समेत पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में समी रिसिनी कीटों द्वारा तैयार किया जाता है। इस कीट का रंग हल्का पीला और सुनहरा होता है, जो अरंडी की पत्तियों पर पलता है।

रेशम कीड़ों को आम तौर पर फाइबर निकालने की प्रक्रिया के दौरान कोकून में ही मार दिया जाता है, जिसके लिए उन्हें पानी में उबाला भी जाता है। मगर मोठ कीड़े आम तौर पर रेशम निकालने की प्रक्रिया से पहले ही कोकून छोड़ देते हैं। इसीलिए इस रेशम को अहिंसा रेशम भी कहा जाता है। यही वजह है कि इसे शाकाहारी लोग और बौद्ध भिक्षु बहुत अधिक पसंद करते हैं।

टसर रेशम जिसे संस्कृत के प्राचीन ग्रंथों में कोसा भी कहा गया है, की खासियत यह होती है कि मौसम के बदलाव का इस पर खास फर्क नहीं पड़ता। इससे बने कपड़े जाड़ों में गर्म रहते हैं और गर्मियों में ठंड का अहसास कराते हैं।

इसका उत्पादन मुख्य रूप से बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और झारखंड में अधिक होता है। बिहार का भागलपुर इसका मुख्य केंद्र है। अन्य कृषि क्षेत्रों के मुकाबले सेरीकल्चर कहीं अधिक फायदा देने वाला क्षेत्र है। इसके उप उत्पादों का ठीक तरह प्रचार-प्रसार कर और अधिक लाभ कमाया जा सकता है। इस दिशा में कई रेशम उत्पादक देशों ने अच्छी प्रगति कर ली है। इनमें बहुत कम रेशम का उत्पादन करने वाले क्यूबा का जिक्र खास तौर पर किया जा सकता है, जो रेशम कीटों के प्यूपा से तेल निकाल रहा है। यह तेल स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। क्यूबा शहतूत जूस का भी उत्पादन कर रहा है, जिसकी बाजार में बहुत अधिक मांग है। भारत के शायद ही किसी राज्य में रेशम उत्पादन से जुड़े इन उत्पादों पर व्यावसायिक लिहाज से काम किया जा रहा हो। अच्छी बात यह है कि अब नीति निर्धारकों का ध्यान सेरीकल्चर की तरफ जा रहा है। सेरीकल्चर से जुड़े उत्पादों के लिए बाजार तैयार कर भारत के रेशम किसान भी मोटा मुनाफा कमा सकते हैं, जैसा इस क्षेत्र से जुड़े अन्य देशों के लोग कमा रहे हैं।

आपका पक्ष

सब्जियों के दाम मूल्य निगरानी सूची में शामिल हो

देश में गर्मियों और मॉनसूनी बारिश के बाद अक्सर सब्जियों के दाम बढ़ जाते हैं। एक सर्वे से पता चला है कि 16 प्रतिशत लोग पहले से ही कम सब्जी खरीद रहे हैं या फिर उन्हें प्याज, आलू, टमाटर की बढ़ी कीमतों की वजह से काफी परेशानी हो रही है। खाने-पीने की चीजों में सबसे ज्यादा उतार-चढ़ाव सब्जियों की कीमतों में देखने को मिलता है। चावल, दाल, आटा, तेल, साबुन आदि के दाम संभवतः स्थिर रहते हैं। लेकिन आलू, प्याज टमाटर तथा अन्य सब्जियों के दाम अचानक दोगुने से तीन गुने तक बढ़ जाते हैं। इसलिए सरकार को मूल्य निगरानी वाली नई संभावित वस्तुओं में सब्जियों को शामिल करना चाहिए। गौरतलब है कि फिलहाल सरकार इस सूची में शामिल सिर्फ 22 वस्तुओं की कीमतों की ही निगरानी करती है। इस सूची में शामिल जरूरी वस्तुओं की कीमतों में होने वाले फेरबदल पर सरकार नजर रखती है। इससे सरकार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर इनके पड़ने वाले प्रभाव का आकलन कर सकेगी। देश भर के 167 केंद्रों से इन वस्तुओं के थोक और खुदरा कीमतों को रोजाना एकत्रित किया जाता है। इसके बाद इनका विश्लेषण किया जाता है। आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ने पर सरकार हस्तक्षेप करके कीमतों को नियमित करती है। इन हस्तक्षेपों को मूल्य स्थिरीकरण कोष अथवा मूल्य समर्थन योजना जैसी योजनाओं के जरिए आगे बढ़ाया जाता है। अतः सब्जियों को मूल्य निगरानी वाली सूची में सम्मिलित करने से सब्जियों की मौसमी महंगाई पर काफी हद तक काबू पाया जा सकेगा।

सुधीर कुमार सोमानी, देवास

कोलकाता में सोमवार को सब्जियों के दाम बढ़ने पर विरोध प्रदर्शन करते कांग्रेस कार्यकर्ता

आमजन की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा बजट

आम बजट में महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, आर्थिक असमानता पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। बजट में राजकोषीय घाटे, कर्ज और मुफ्तखोरी पर अंकुश की कोई ठोस नीति नहीं दिखती है। इस बार आम बजट में कर्मचारियों, किसानों, गरीब-मध्यम वर्ग को खास राहत नहीं दी गई है। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के क्षेत्र की उपेक्षा हुई। नौकरीपेशा वर्ग ने पुरानी पेंशन, व्यापारी ने बाजार में पूंजी निवेश और गृहिणियों ने बढ़ती महंगाई को थामने के लिए जो उम्मीदें पाल रखी थीं, बजट उस पर खरा नहीं उतरा। बजट वास्तविकता के धरातल पर आमजन की अपेक्षानुरूप नहीं रहा।

मोहित सोनी, कुक्षी

विकसित भारत के संकल्प का बजट

यह बजट विकसित भारत की संकल्प यात्रा का दिशा-निर्देशक बजट है, जो समृद्ध और दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ भारत के संकल्प को नई मजबूती प्रदान करेगा। आम बजट में किसान, मध्यम वर्ग, महिला से लेकर सभी वर्गों के लिए जो रूपरेखा रखी है, वह भारतीय अर्थव्यवस्था को सही राह की तरफ और उज्ज्वल भविष्य की ओर आगे बढ़ाएगी। बजट में रोजगार को भी प्राथमिकता देने से बेरोजगारी कम होगी।

आशीष सकलेचा, जावरा

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

चिली के सैनटियागो में वेनेजुएला के वाणिज्य दूतावास के समीप एक चौक पर वेनेजुएला के नागरिक अपने देश में हुए राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों का इंतजार करते हुए।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । मंगलवार, 30 जुलाई 2024

फिर न हो ऐसा हादसा

देश की राजधानी में IAS बनने की आकांक्षा लेकर आए तीन स्टूडेंट्स की जिन हालात में मौत हुई, वह दुखद तो है ही, शर्मनाक भी है। इस घटना ने राष्ट्रीय राजधानी में इन्फ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस से जुड़े तमाम विभागों और उनके कर्मचारियों पर ही नहीं, इनके संचालन और देखरेख की जिम्मेदारी संभाल रहे राजनीतिक नेतृत्व पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।

हादसे के बाद टूटी नींद | घटना की गंभीरता ने स्थानीय प्रशासन और राजनीतिक नेतृत्व को जैसे नींद से जगाया। न केवल धड़ाधड़ कई गिरफ्तारियां कर ली गईं बल्कि कुछ कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ बर्खास्तगी और निलंबन जैसे कदम उठाते हुए घटना के सभी पहलुओं की विस्तृत जांच के आदेश भी दे दिए गए। संसद में भी यह मामला गूंजा।

तीन छात्रों की मौत का मामला

हालात नए नहीं | गौर करने की बात यह है कि इस दुखद घटना को अंजाम देने वाले हालात न तो नए हैं और न ही ऊपर से नीचे तक सरकारी तंत्र का कोई भी हिस्सा इनसे अनजान है। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्रनगर और मुखर्जी नगर जैसे इलाके IAS कोचिंग हब के रूप में काफी पहले से जाने जाते रहे हैं। वहां कैसी इमारतों में किन हालात में कोचिंग सेंटर चलते हैं और स्टूडेंट्स प्रतिष्ठित सेवाओं की तैयारी करते हैं, यह किसी से छिपा नहीं है। इससे पहले भी आग लगने जैसी घटनाएं उन विषम हालात की ओर सबका ध्यान खींच चुकी हैं।

स्पष्ट जवाब नहीं | सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब सबको पहले से यह सब पता था, तो समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं हुई और यह भी कि क्या गारंटी है, कुछ समय बाद फिर सबकुछ पहले जैसा ही नहीं हो जाएगा। यही इस पूरी घटना का सबसे गंभीर पहलू है और इसी बिंदु पर हमें कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिलता। घटना के बाद BJP और आम आदमी पार्टी के बीच जिस तरह एक-दूसरे पर दोष मढ़ने का सिलसिला शुरू हो गया, वह भी निराश करता है।

परस्पर दोषारोपण की होड़ | जहां BJP इसके लिए MCD और राज्य की सत्ता संभाल रही AAP को यह कहते हुए जिम्मेदार बता रही है कि सारे संबंधित विभाग इन्हीं दोनों के अंतर्गत आते हैं, वहीं AAP नेताओं का कहना है कि तमाम अफसरों को दंडित या पुरस्कृत करने का अधिकार LG के हाथों में है। सवाल यह है कि क्या ऐसी हर त्रासदी पर राजनीति दिल्ली के लोगों की नियति है या कोई आगे बढ़कर इनकी जिम्मेदारी भी लेगा और ऐसी घटनाएं दोबारा न होने देने का संकल्प भी करेगा।

धूप-छांव

ग़ुलामी में ग़फ़लत

प्रणव प्रियदर्शी

चाहे व्यक्ति हो या परिवार या फिर देश- उतार-चढ़ाव तो जीवन में आते ही हैं। जो चुनौतियां राह में आती हैं, उनसे निपटते हुए ही आगे बढ़ना होता है। क्या कोई ऐसा व्यक्ति, परिवार या राष्ट्र हो सकता है जो चुनौतियों से मुंह चुराता रहे और बगैर उनका सामना किए ही आगे बढ़ जाए? जिंदगी जो चुनौतियां भेजती हैं, वे ऐसी वेल्ली तो नहीं होतीं कि हमसे मिलने आएं और हम अपॉइंटमेंट न दें तो सिर झुकाए वापस हो लें। उन चुनौतियों से हम न मिलना चाहें तो भी वे हमसे मिलेंगी। हम उन पर हावी न हुए तो वे हम पर हावी हो जाएंगी। अंग्रेजी की एक कहावत के सहारे बात को साफ किया जाए तो कमरे में हाथी की मौजूदगी हम स्वीकार न करें, इससे न हाथी को खास फर्क पड़ता है, न ही कमरे को। हमारी अपनी सुरक्षा पर जरूर फर्क पड़ सकता है।

अक्सर कहा जाता है कि एक राष्ट्र के रूप में हमने लंबे समय तक चुनौतियों से आंखें चुराते रहना ही उनसे निपटने का सबसे अच्छा तरीका मान रखा था। एक के बाद एक विदेशी हमलावर आते रहे, हमें रौंदते रहे। कुछ लूटकर चले गए और कुछ ने स्थायी तौर पर यहीं अपना ठिकाना बना लिया। वे हमारी मिट्टी में रच-बस कर इसका हिस्सा तो बाद में बने, जिस समय वे आए थे, तब तो विदेशी हमलावर ही थे। तब क्या इस राष्ट्र ने उनका सही ढंग से मुकाबला किया था? यह सवाल इतना बड़ा है कि इस छोटी सी जगह में इसे उठाना ही बचकाना कहलाएगा। इसलिए इसे छोड़कर सिर्फ यह देखने की कोशिश की जाए कि क्या समस्याओं और चुनौतियों से भागना, उनका सामना न करना हमारे राष्ट्रीय चरित्र की एक स्थायी विशेषता है?

अगर ऐसा होता तो अंग्रेजों के बरक्स भी हमारा यही रवैया दिखता। मगर नहीं, उनके मामले में हमारा समाज ऐसा प्रतिरोध करता नजर आता है, जिसकी मिसाल ढूंढनी मुश्किल है। सौ साल के अंदर 1857 का ऐसा विद्रोह होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाकर ब्रिटिश सरकार खुद कमान संभालने को मजबूर हो जाती है। बाद के सौ सालों में भारतीय समाज आजादी हासिल करने की ऐसी राह चुनता है कि दुनिया को सत्य और अहिंसा के नए राजनीतिक औजार मिल जाते हैं। आखिर गांधी भी तो इसी देश, इसी समाज, इसी मिट्टी की उपज थे। यह मिट्टी अपने चरित्र से बिल्कुल अलग कोई चीज कैसे पैदा कर सकती है? जाहिर है, हमारे चश्मे का नंबर गड़बड़ है। आजादी की आने वाली वर्षगांठ के मौके पर हमें यह जरूर सोचना चाहिए कि चुनौतियों को देखने-समझने में, गुलामी की परिभाषा और हमलावरों की पहचान करने में हम कोई भूल तो नहीं कर रहे। अंग्रेजों और पहले के हमलावरों को हमारे समाज, हमारी मिट्टी ने तो एक जैसा नहीं माना। फिर हम कैसे उन्हें एक जैसा कह सकते हैं?

बोल वचन

कलेजा काढ़ दिया

राहुल पाण्डेय

गांव में इधर शाम दस्तक देने को होती, उधर घरैतिनों की कंघी-टिकुली-सेनुर-शीशा निकल आता। मचिया पर बैठकर घर की बुजुर्ग घरैतिन बड़े जतन से बिटिया या बहू के उलझे बाल सुलझाती। फिर कंघी से धीमे-धीमे उसके बाल काढ़ना शुरू करती। फिर मांग काढ़ती। बिटिया खुद को शीशे में देखती। बिटिया को शीशा देखते घर की बहू देखती तो दांत काढ़ती। फिर तो एक-दूसरे की इज्जत कायदे से काढ़ी जाती। यह देख कुंए से पानी काढ़ रही नाइन भी खूब खीस काढ़ती। काढ़ने का अर्थ बरतन में से कोई चीज बाहर निकालना, आवरण हटाकर दिखाना, सुई-धागे से कपड़े पर बेल-बूटे बनाना। लेकिन यह काढ़ा पीने वाला काढ़ा नहीं है, जो कड़वा होने के चलते काढ़ा है। इस काढ़ने का कड़वेपन से कुछ लेना-देना नहीं है। अवध में काढ़ने का पहला अर्थ है निकालना। मांग काढ़ना- मांग निकालना। कलेजा काढ़ना- कलेजा निकालना। अवधी कवि द्विज छोटकुन की अवधी चौताल का एक अंश है- 'कंत जेंवाय, सोवय पलंग पर, अपनो औसर पावौं। पायल काढ़ि छिपाय धरौं तन सारी, सबुज लगावौं।' यानी पायल निकालकर छिपा दी है। इसका एक अर्थ बनाना भी होता है। नाली काढ़ना- नाली बनाना। पकौड़ा काढ़ना- पकौड़ा बनाना। इसका एक अर्थ करना भी होता है। घूंघट काढ़ना- घूंघट करना। काका हाथरसी कहते हैं- 'कह 'काका' कवि, लज्जावती दहाड़ रही है। दर्शनदेवी लंबा घूंघट काढ़ रही है।' इतने सारे अर्थों वाले काढ़ने को इंग्लिश कायदे से काढ़ नहीं पाई है। हर काढ़ने के लिए इंग्लिश में अलग-अलग शब्द हैं। शायद इंग्लिश को अपने आप को अभी और काढ़ना होगा।

Subrata Dhar

पंजाब में BSF और पुलिस की चौकसी तेज़ हुई तो पाकिस्तानी तस्करों ने बदल दिया निशाना

राजस्थान कैसे बन गया ड्रग्स का अड्डा

विजय विद्रोही

राजस्थान से सटी पाकिस्तान सीमा पर जब तारबंदी नहीं थी, तब उस पार से ऊंटों पर ड्रग्स की तस्करी होती थी। वहां से स्थानीय तस्कर इस माल को देशभर में पहुंचा देते। उस समय बॉर्डर पर BSF की हर पोस्ट पर पगी या खोजी हुआ करते थे। ये खोजी ऊंटों के पैरों के चिह्नों का पीछा करते, सीधे स्थानीय तस्कर के घर तक पहुंच जाते।

ड्रोन से तस्करी | कई बार तस्कर ड्रग्स को रेत में दबा दिया करते थे। हालांकि इससे भी वे बच नहीं पाते थे। पद चिह्नों को देखकर खोजी यह भी अंदाजा लगा लेते थे कि कितना माल लादकर ऊंट चले थे और कितना माल अब गायब है। यह बात है तारबंदी से पहले की, 60-70 के दशक की। 2024 की बात करें तो अब ऊंट नहीं, ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है तस्करी में। तब घरेलू खपत बहुत कम थी, लेकिन अब बहुत ज्यादा हो चुकी है।

पंजाब पीछे | राजस्थान के एक सीमावर्ती जिले में SP रह चुके एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का कहना है कि ड्रग्स के मामले में उड़ता पंजाब कहा जाता था, लेकिन अब उड़ता राजस्थान बन गया है। ड्रग्स भी उड़ते हुए आ रही है ड्रोन से और नौजवान पीढ़ी नशे का शिकार हो रही है। मादक पदार्थ नियंत्रण विभाग के आंकड़े भी इसकी पुष्टि करते हैं। पिछले ढाई साल में राजस्थान में इस तरह के 16,768 मामले दर्ज हुए और 20 हजार से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए।

आसान शिकार | राजस्थान ने पंजाब को पीछे छोड़ दिया है और इसकी वजह भी परोक्ष रूप से पंजाब ही है। दरअसल, पाकिस्तान से सटी पंजाब की सीमा पर BSF और पुलिस की चौकसी तेज हुई है। सरहदी गांवों के लोग भी नशाखोरी से परेशान हैं और तस्करों की मुखबिरी करते हैं। सीमा पार से जमीनी रास्तों से ड्रग्स लाना लगभग असंभव हुआ तो पाकिस्तानी तस्कर ड्रोन का इस्तेमाल करने लगे। हालांकि पंजाब में बड़ी संख्या में ड्रोन गिराए जाने लगे, तो वहां के तस्करों ने राजस्थान के रास्ते पंजाब माल भेजने की रणनीति बनाई।

जवानों की कमी | राजस्थान की करीब 1100 किलोमीटर सीमा पाकिस्तान से सटी हुई है। BSF में जवानों की कमी का फायदा तस्करों को मिल रहा है। एक जवान के जिम्मे आमतौर पर 500-600 मीटर की पेट्रोलिंग होती है, लेकिन राजस्थान में एक से डेढ़ किलोमीटर तक का हिस्सा एक जवान को संभालना पड़ रहा है।

अफीम की कुप्रथा | पश्चिमी राजस्थान के मारवाड़ में अफीम सेवन एक कुप्रथा है। यहां तो चुनावों में भी अमल (अफीम का पानी) चटाकर वोट पुख्ता किए जाते रहे हैं। बाड़मेर के एक बड़े नेता की चुनावी सभा का एक विडियो बहुत पहले लीक हुआ था, जिसमें वह अमल चखाकर अपने पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे थे। शादी विवाह से लेकर मृत्यु भोज तक में अमल चखने का रिवाज है।

कितनी बड़ी चिंता

- नशाखोरी में पंजाब से आगे राजस्थान
- देश भर में भेजी जा रही है ड्रग्स
- तस्करी ज्यादा, पकड़ में आ रही कम

डोडा पोस्त का मार्केट | पंजाब से सटे गंगानगर हनुमानगढ़ में डोडा पोस्त का बाकायदा सेवन किया जाता है। वहां सरकार की तरफ से लाइसेंसधारी दुकानें भी हैं, जहां नशेड़ियों को सरकार डॉक्टरों के परामर्श पर रजिस्टर करती रही है। लेकिन, यह सब सीमित मात्रा में ही हुआ करता था। राजस्थान हाई कोर्ट ने 2016 में डोडा पोस्त की बिक्री पर रोक लगा दी। पाकिस्तान के हेरोइन तस्करों को पंजाब के बाद नया बाजार मिल गया।

पाकिस्तानी साजिश | पंजाब से सटे पाकिस्तान में तो तारबंदी तक खेती होती है, आबादी बसती है। लेकिन राजस्थान से सटे पाकिस्तान में तारबंदी से 20-20 किलोमीटर का इलाका वीरान है। तस्कर सस्ते किस्म के ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ड्रोन ज्यादा दूरी तय नहीं कर पाते। साफ है कि पाकिस्तानी सेना की मदद से ही तस्करी का धंधा चल रहा है। अफगानिस्तान से अफीम की खेप पाकिस्तान भेजी जाती है। वहां चोरी-छुपे हेरोइन में तब्दील किया जाता है और भारत में ड्रोन के माध्यम से खेतों में गिरा दिया जाता है। वहां से स्थानीय तस्कर माल को राज्य और देश के दूसरे भागों तक पहुंचाते हैं।

इतना नुकसान मंजूर | आमतौर पर एक किलो अफीम का दाम 50 हजार रुपये मिल जाता है। लेकिन, इसे हेरोइन में तब्दील करते ही कीमत बढ़कर पांच करोड़ रुपये प्रति किलो हो जाती है। वहीं, एक ड्रोन की कीमत 10-15 हजार रुपये बताई जाती है। जाहिर है, कुछ ड्रोन अगर नष्ट होते हैं, तो भी तस्करों को खास फर्क नहीं पड़ने वाला।

तस्कर आगे | 2022 से अब तक सिर्फ 14 ड्रोन मार गिराए गए, जबकि 2023 में 79 किलो हेरोइन जब्त की गई। साल 2022 में यह आंकड़ा 35 किलो ही था। इस साल अब तक 48 किलो हेरोइन पकड़ी जा चुकी है। इसका मूल्य 244 करोड़ रुपये बताया जा रहा है। साफ है कि जितने ड्रोन मार गिराए जा रहे हैं, उससे कई गुना ज्यादा ड्रोन ड्रग्स को खेतों में गिराने में कामयाब हो रहे हैं।

बेरोजगारी वजह | एक पुलिस अधिकारी का कहना है कि ड्रग्स जितनी आसानी से उपलब्ध होगी, उसी अनुपात में नशेड़ियों की संख्या भी बढ़ने की आशंका रहती है। पंजाब इसका उदाहरण रहा है। कुछ जानकारों का कहना है कि युवा वर्ग नशे की तरफ ज्यादा तेजी से आकर्षित होता है। इसकी वजह बेरोजगारी भी है और निजी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होने की हताशा भी।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

Ai Image

वो अपुन के बाजू वाली कमला आंटी नहीं रे

नमिता जोशी

सर्किट और चिरकुट दोनों आजकल अक्खा दिन मोबाइल से एक-दूसरे का फोटो क्लिक करते रहते हैं। अपुन ने पूछा, क्या सीन है? शादी वादी बनाने का है क्या? किसके वास्ते इतनी फोटो खिंचा रयेले हो? चिरकुट बोला, नहीं भाई अपुन तो बस अमेरिका जाने के वास्ते तैयारी कर रयेले हैं? ये फोटो तो वीजा और पासपोर्ट में लगेगी ना अपुन कू। तुम दोनों ने आज तक नाला सोपारा के बाहर का दुनिया नहीं देखा, ये अमेरिका जाने का सपना किदर से देख लिया? सच सच बता, कौन तुम्हारा भेज फ्राई किएला है? उस चिंदी चोर को अभीच ठिकाने लगाता है अपुन।

अपुन का गुस्सा देख के दोनों डरने के बजाय अपुन का मजाक उड़ाने लगे। भाई तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर मस्त है एकदम। अपुन ने एक फॉरवर्ड मेसेज पढ़ा, उस दिन से अपुन का खुशी का ठिकाना नहीं। तुम तो जानते इच हो अपुन कू बचपन से अमेरिका जाने का सपना आता था। अब वोइच सपना सच होने वाला है। कमला देवी आंटी उदर की प्रेजिडेंट बनने वाली है।

कौन कमला देवी और तू कइसे जानता है उनको? सवाल सुनके चिरकुट बोला, मुन्ना भाई वो अपने हरीश अंकल की वाइफ हैं ना कमला देवी हरीश। सर्किट उनकी बात कर रयेला है। वो दस साल पहले इदर इच रहते थे, तीन गली छोड़ के। बाद में उनका बेटा अमेरिका में उनको बुला लिया और आज देखो कितनी तरक्की कर डाली कि प्रेजिडेंट का चुनाव लड़ रयेली है। और तुमको मालूम होना चाहिए, कमला आंटी अपुन कू भोत प्यार करती थी। उनके घर का अक्खा राशन अपुन इच उठा के लेके आता था। अब अपुन कू सौ टक्का यकीन है कि वो अपुन कू इदर से उठाके लेके जाएंगी। इसी का वास्ते अपुन दोनों पासपोर्ट वीजा के वास्ते फोटो खींच रयेला है। टेंशन नहीं लेने का। अपुन एक बार सेटल हो जाए तो तुमको और चिंकी भाभी दोनों को इच अमेरिका बुला लेगा। बस एक बार ये वीजा मिल जाए।

तुम दोनों पंटर लोग को काइकू मिलेगा अमेरिका का वीजा? अपुन ने पूछा तो चिरकुट चिड़िया के माफिक फुदकते हुए बोला भाई, काइकू नहीं मिलेगा, ये बताओ। कमला देवी हरीश इंडियन, अपुन इंडियन, वीजा वाला अपुन के पांव में रखेगा वीज़ा। तुम बस देखते जाओ इंडिया का जलवा। चिरकुट की चिरचिर सुनके दिल में तो आया कि दोनों के कान के नीचे तबला बजा डालूं पर सोचा उससे अच्छा है इनकी अकल ठिकाने लगाना। कमला देवी वो अपनी पड़ोसन आंटी नहीं है रे। वो अमेरिका की वाइस प्रेजिडेंट एकदम अलग पर्सनैलिटी है। उनका खाली नाम इंडियन है। वो हरीश अंकल की नहीं डगलस अंकल की वाइफ हैं। दूसरी बात ये कि क्या तुम लोग को ऋषि सुनक का न्योता मिला था, जो कमला देवी के अमेरिका इनविटेशन का वेट कर रयेले हो? अबे ढक्कन लोग ये बताओ कि पटाखे तुमने तब भी फोड़े थे और लड्डू तुमने तब भी बांटे थे पर ऋषि सुनक ने कौना सा वीजा बना दिया था अपुन लोग का? ठीक है, नाम उनका इंडियन जैसा है, मनाओ इस बात की खुशी कि उनके दादा परदादा या नानी परनानी कभी इंडिया में रहे होंगे, पर कमला हैरिस को कमला हरीश समझकर वीजा की तैयारी करना वइसा इच है जइसे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो जाए।

Ai Image

भेजा फ्राई

मुंबइया स्टाइल में मुन्ना और सर्किट का ये भेजा फ्राई आपको कैसा लगा? हमें अपनी राय लिखकर भेजिए इस मेल आईडी पर **nbtreader@timesgroup.com** और सब्जेक्ट में लिखें-'भेजा फ्राई'

पहले शिक्षक तबादले की गड़बड़ियां ठीक करेंगे, फिर शुरू करेंगे भर्तियां

विशुद्ध राजनीति इंटरव्यू

छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने अपनी पहली ही कैबिनेट मीटिंग में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख से ज्यादा घरों को स्वीकृति दी, जिसे अभी केंद्र सरकार की ओर से मंजूरी मिलनी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का कहना है कि राज्य की पिछली यानी कांग्रेस सरकार ने केंद्र से 60 पर्सेंट हिस्सा लिया ही नहीं तो यह फंड दूसरे राज्यों को चला गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री **विष्णु देव साय** से बात की **पूनम पाण्डे** ने। पेश हैं बातचीत के अहम अंश :

■ चुनाव के वक्त घोषणापत्र में कई वादे किए गए थे। कौन-कौन से वादे पूरे हुए हैं अब तक?

सरकार बनने के दूसरे ही दिन कैबिनेट की बैठक में 18,12,743 जरूरतमंद परिवारों को प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराने की स्वीकृति देने का फैसला लिया गया और इसके लिए 12,168 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। अटल जी के जन्मदिन सुशासन दिवस पर 13 लाख किसानों के बैंक खातों में 3,716 करोड़ रुपये का बकाया धान बोनस देकर इस गारंटी को भी पूरा किया गया। 32 हजार करोड़ रुपये के समर्थन मूल्य की राशि का तत्काल भुगतान किसानों को किया और फिर 12 जनवरी को 24,75,000 किसानों को कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत 13,320 करोड़ रुपये की राशि दी गई। राज्य में तेंदूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक दर 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर अब 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा कर दी गई है। चालू तेंदूपत्ता सीजन से ही 12 लाख 50 हजार तेंदूपत्ता संग्राहकों को योजना का लाभ मिल रहा है। संग्राहकों के लिए राज्य सरकार द्वारा चरण पादुका योजना भी शुरू की जाएगी, साथ ही उन्हें बोनस का लाभ भी दिया जाएगा। PSC घोटाले की जांच CBI को सौंप दी गई है।

■ प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर आपने तो स्वीकृति दे दी है लेकिन विधानसभा में आपकी सरकार ने बताया कि अभी केंद्र सरकार से मंजूरी नहीं मिल पाई है...

इसमें 60 और 40 का रेश्यो रहता है। 40 पर्सेंट राशि राज्य सरकार देती है और 60 पर्सेंट केंद्र सरकार। हमने इसके लिए बजट की व्यवस्था कर दी है। केंद्र से भी पैसा मिल जाएगा। पिछली राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से 60 पर्सेंट हिस्सा लिया ही नहीं तो केंद्र ने इसे दूसरे प्रदेशों को दे दिया।

■ बजट में छत्तीसगढ़ को कुछ खास नहीं मिल पाया। आपने विजन-2047 भी सामने रखा है। बिना बजट कैसे पूरा होगा?

हम बजट से संतुष्ट हैं। विजन डॉक्युमेंट पर भी काम होगा। धीरे-धीरे सब होगा। बजट में 3 करोड़ और घर बनाने की बात कही गई है। पहले पुराने पात्रों को मिल जाएगा और फिर औरों को भी मिलेगा।

■ राज्य में कानून-व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। क्या ज्यादातर मंत्री नए हैं, इसलिए दिक्कत हो रही है?

हमारे गृह मंत्री ने इसका तफसील से जवाब दिया है और पूरा कंपैरिजन करके बताया है कि कांग्रेस सरकार के शुरू के छह महीनों में कानून-व्यवस्था कैसी थी और हमारे वक्त में कैसी है। मौजूदा सरकार पिछली सरकार से हर मामले में बेहतर है। क्राइम भी कम हुआ है।

■ राज्य के युवा भर्ती खुलने का इंतजार कर रहे हैं, अब तक कोई भर्ती नहीं निकली?

शिक्षा सबसे बड़ा विभाग है, जहां भर्तियां होती हैं। छत्तीसगढ़ में पिछली सरकार के कार्यकाल में शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापना में बहुत अनियमितताएं हुईं, जिसके कारण शिक्षा के क्षेत्र में अव्यवस्था हुई है। राज्य में पर्याप्त संख्या में शिक्षक होने के बावजूद कई जगह शिक्षकों का अभाव नजर आया। वहीं अनेक जगह ऐसी थीं, जहां आवश्यकता से अधिक शिक्षक भेज दिए गए। छत्तीसगढ़ में शिक्षकों और विद्यार्थियों का अनुपात राष्ट्रीय अनुपात से बेहतर है। देश में 26 विद्यार्थियों के पीछे एक शिक्षक का अनुपात है जबकि प्रदेश में 21 विद्यार्थियों के पीछे एक शिक्षक का। हमारी सरकार पहले इस अव्यवस्था को ठीक करके बैलेंस बनाएगी और उसके बाद भर्तियां की जाएंगी।

■ आपके राज्य में कई नक्सली घटनाएं हुई हैं। हालांकि नक्सली मारे भी गए हैं और सरेंडर भी किया है। लेकिन अभी भी स्थिति पूरी तरह ठीक नहीं लगती। क्या कहेंगे?

नक्सलियों के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ी जा रही है और नक्सली का क्षेत्र सिकुड़ता जा रहा है। हमने नियद नेल्ला नार योजना शुरू की है जिसका अर्थ है 'आपका अच्छा गांव'। इस योजना का मकसद बस्तर के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा शिविरों के आसपास के 5 किलोमीटर के अंदर आने वाले गांवों में बुनियादी सुविधाएं और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देना है।

रीडर्स मेल

www.edit.nbt.in

■ सफलता की सीढ़ी

29 जुलाई का संपादकीय 'मनु का कमाल' पढ़ा। मनु भाकर ने कांस्य पदक जीत कर अपना नाम उस सुनहरी फेहरिस्त में शामिल करा लिया है, जिसमे अभिनव बिंद्रा, राज्यवर्धन सिंह राठौर, गगन नारंग और विजय कुमार शामिल हैं। इसके साथ ही वह ओलिंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला शूटर बन गई हैं। मनु ने टेनिस, स्केटिंग और बॉक्सिंग से शुरुआत की थी। लेकिन 8 वर्ष पहले उन्होंने शूटिंग की तरफ रुख किया और कॉमनवेल्थ सहित कई गेम्स में स्वर्ण पदक जीता। वह सभी युवा लड़कियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई हैं।

बाल गोविंद, नोएडा

■ शादी वाला डांस

16 जुलाई को 'भेजा फ्राई' कॉलम में लेख 'नागिन डांस करना है, किदर है शादी' पढ़ा। पूरा आर्टिकल किसी मुंबइया फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा लगता है, लेकिन है बहुत मजेदार। सर्किट तो बेचारा शादी में नहीं जा पाया, लेकिन इससे पता चला कि उसे डांस कितना पसंद है। वाकई अगर शादी-विवाह या किसी फंक्शन में डांस न हो, तो कुछ अधूरा-अधूरा लगता है। मौके पर किसकी खुशी कितनी बड़ी है, इसका पता तो डांस से ही चलता है। जिसके पैर ज्यादा थिरकें, समझिए कि उससे अपनी खुशी नहीं संभाली जा रही। डांस खुद को व्यक्त करने का बेहतरीन जरिया है।

शिवानी रावत, ईमेल से

■ यूपी की राजनीतिक हवा

उत्तर प्रदेश की राजनीति बेहद पेचीदा होती जा रही है। यूपी में BJP की अंदरूनी कलह सार्वजनिक हो चुकी है। केशव प्रसाद मौर्य कभी दिल्ली में बड़े नेताओं से चर्चा कर रहे हैं और कभी उत्तर प्रदेश में अपनी मुहिम को धार देने में लगे हुए हैं। हाल ही में मौर्य ने आरक्षण के संबंध में जानकारी मांग ली। स्वाभाविक है मुख्यमंत्री को ये बातें असहज करती होंगी।

वीरेंद्र कुमार जाटव, दिल्ली

nbtedit@timesgroup.com पर अपनी राय नाम-पते के साथ मेल करें।

अंतिम पत्र

राहुल गांधी ने कहा, देश के हर क्षेत्र में डर है – एक खबर
– डर के आगे जीत है!

सुनील ठाकुर

THE SPEAKING TREE

और पढ़ने के लिए देखें hindi.speakingtree.in

बचकर, किसी तानाशाह जैसी है आपकी क़िस्मत

दयाशंकर शुक्ल सागर

मनुष्य ने ईश्वर के बाद जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया, वह है किस्मत या नियति। इसे हम सभी अपने और आसपास के जीवन में बखूबी महसूस करते हैं। जरा गौर करें तो पाएंगे कि इस जीवन को आप नहीं, बल्कि यह नियति चला रही है। किस्मत एक तरह से कुछ रहस्यमयी धागों की कताई की तरह है, जिसके जरिए पूरे ब्रह्मांड की घटनाएं तय होती हैं। तो आप देखिए नियति का दायरा कितना बड़ा है। इसमें हमारा जीवन सबसे छोटी इकाई है। सब कुछ यानी हमारे जीवन की हर छोटी-बड़ी घटना पहले से तय है। लेकिन वह घटना हमें चौंकाती है क्योंकि हमें उसके पीछे के सूत्रों का जरा भी पूर्वाभास नहीं होता।

पश्चिम के महान दार्शनिक स्पिनोजा कहते हैं, जिसे हम भाग्य कहते हैं वह दरअसल निसर्ग का नियम (Law of Nature) है जो एक-सा और अखंड है। इस नियम में फेरबदल संभव नहीं। घटनाओं की एक श्रृंखला है, जो नियति को निर्धारित करती है। व्यक्ति का वर्तमान में लिया गया कोई भी फैसला पूर्व में लिए गए किसी फैसले की कड़ी का हिस्सा होता है। यानी वर्तमान में लिया गया हर फैसला उस व्यक्ति के भविष्य की किसी नई घटना की नींव रखता है। अब सवाल उठता है कि किसी क्षण हम कोई फैसला लेते हैं तो क्या वह फैसला सिर्फ हमारा ही होता है? प्रत्यक्ष तौर पर फैसला हम ही लेते दिखते हैं, पर कोई और है जो हमारे जरिए निर्णय लेता है।

वह ऐसे हालात बनाता है कि हम वही निर्णय लेने के लिए बाध्य होते हैं। आखिर में पाएंगे कि आप एक कठपुतली से ज्यादा कुछ नहीं। तो क्या फिर हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें और सब नियति पर छोड़ दें? मजे की बात है कि आप ऐसा भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह फैसला भी नियति को लेना है। नियति आपको हाथ पर हाथ धरे बैठने नहीं देगी या हो सकता है बैठने भी दे। आप कल्पना कर सकते हैं कि नियति जितनी रहस्यमय है, उतनी ही क्रूर और आक्रामक भी। सही मायनों में वह एक तानाशाह है। तो क्या नियति ही ईश्वर है?

अनंत ब्रह्मांड या आकाशगंगाओं के पीछे कहीं दूर बैठा, न दिखने वाला ईश्वर कोई आठ अरब मनुष्यों और ब्रह्मांड के अनंत जीवों के भाग्य या किस्मत का लेखा-जोखा रखे, यह बात न तार्किक लगती है और न व्यावहारिक। दुख में ईश्वर का स्मरण मनोवैज्ञानिक रूप से एक उम्मीद जरूर देता है, लेकिन इससे कुछ हासिल होगा या इससे आपके दुख दूर हो जाएंगे यह कहना मुश्किल है। सच पूछिए तो आपकी जिंदगी में दखल देने में ईश्वर की कोई दिलचस्पी नहीं। तो आप फिर करें क्या? इसका सबसे सटीक जवाब गीता में है, जो नतीजों की आकांक्षा किए बिना कर्म की सलाह देती है।

खूब परोपकार करें। इससे आपको आंतरिक शांति मिलेगी। इससे आपके नजदीक जो परिस्थितियां बनेंगी, वे जीवन के फैसलों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगी। उसके नतीजे भी सकारात्मक होंगे। शायद इसीलिए दुनिया के तमाम धर्म दया, परोपकार, सत्य, अहिंसा, सेवा का पाठ पढ़ाते दिखते हैं। तो आप भले नास्तिक हों, इन धर्म ग्रंथों की अच्छी बातें अपने जीवन में उतारें क्योंकि नियति ने और कोई रास्ता आपके आगे नहीं छोड़ा है।

आर.एन.आई. नं. 510/57© सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति के बिना संपूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित। स्वत्वाधिकारी बैनेट, कोलमैन एण्ड कम्पनी लिमिटेड के लिए राजीव यादव द्वारा, 7 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित तथा **टाइम्स ऑफ इंडिया प्रेस, साइट IV, औद्योगिक क्षेत्र साहिबाबाद** और प्लॉट नंबर 7-8, सेक्टर M-11, ट्रांसपोर्ट हब, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, मानेसर, हरियाणा से मुद्रित। फोन : 23302000 फैक्सः 23492047, पंजीकृत कार्यालय : दादाभाई नौरोजी रोड, मुंबई-400001। विमान सेवा शुल्क : 1 रु. प्रति कॉपी। नेपाल में कुल मूल्य : सोमवार से शनिवार : नेपाली 5 रु. ; रविवार : नेपाली 6 रु.
संपादक (दिल्ली मार्केट) : आशीष पांडे (इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी)

https://t.me/AllNewsPaperPaid

राष्ट्रीय सहारा
नई दिल्ली • मंगलवार • 30 जुलाई • 2024
www.rashtriyasahara.com

अनमोल वचन

शब्दों के भी भाग्य होते हैं
-आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी

खामियाजा भरना नामुमकिन

दिल्ली के ओल्ड राजेन्द्र नगर स्थित नामी कोचिंग सेंटर राव के बेसमेंट में जलभराव से तीन छात्रों की मौत वाकई दुखद है। कोचिंग संस्थान, सिविक एजेंसी और सरकारी मशीनरी की काहिली से यह जानलेवा स्थिति बनी। यहां बरसात का पानी अचानक भर गया, वहां बनी लाइब्रेरी में तकरीबन 35 छात्र पढाई कर रहे थे। बता रहे हैं, शुरुआत में पानी थोड़ा था पर अचानक बरसाती पानी की रफ्तार बहुत तेज हो गई। तेज स्पार्किंग के साथ धमाका हुआ और बिजली गुल हो गई। अफरा-तफरी में वे बाहर की तरफ भागे मगर बायोमैट्रिक लगा होने के कारण दरवाजा नहीं खुला। पांच मिनट में भूतल में 10-12 फीट पानी भर गया था। बचाव दल ने छात्रों को बमुश्किल निकाला। दो छात्रों का पोस्टमार्टम में उनकी मौत डूबने व गंदा पानी फेफड़ों में भरने से होने की रपट है,

एक छात्र के परिजन के पहुंच न पाने के कारण शव सुरक्षित रखा गया। मामले में कोचिंग सेंटर के मालिक अभिषेक गुप्ता समेत कुल सात आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। नियमानुसार जिस भूतल को केवल स्टोर के लिए इस्तेमाल करना था, वहां कक्षा है और पुस्तकालय भी। राजधानी में केंद्र सरकार की नाक के नीचे ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना की देश भर में काफी निंदा की जा रही है। दमकल विभाग का कहना है, वहां मौजूद तमाम कोचिंग सेंटरों ने मुख्यद्वार स्लाइडिंग बनाए हैं। ताकि बरसात का पानी वहां न आ पाए। ऐसे तेरह सेंटरों को आनन-फानन सील भी कर दिया गया है। नौ माह का शुल्क डेढ़ लाख से अधिक लेने वाले राव जैसे अन्य सेंटरों के कुछ छात्र इस अव्यवस्था की लिखित शिकायत भी कर चुके थे। यहां संकरी गलियों के छोटे-छोटे घरों में रहने व पढाई करने वाले छात्रों का जमावड़ा रहता है। कुछ ही दिन पहले ऐसे ही सेंटर में आग लगने की घटना हो चुकी है। सरकार ने मुंह छिपाने के लिए आनन-फानन नए नियम लागू कर दिए हैं। मगर इन होनहार छात्रों के जीवन का खामियाजा तो किसी भी तरह नहीं भरा जा सकता। सख्त सजा से जरूरी है, देश भर के छात्रों की सुरक्षा व्यवस्था पर कड़ी नजर रखी जाए और लापरवाही करने वाले संस्थानों को यूं ही मुक्त न छोड़ दिया जाए। मालिकों व प्रबंधकों के अतिरिक्त इस हादसे की सरकार भी कम जिम्मेदार नहीं है। उसे अपनी लापरवाही को सुधारना होगा। कुल मिलाकर खराब जल निकासी और सरकारी तंत्र की घोर लापरवाही के चलते दूरदराज से अधिकारी बनने का ख्वाब लिए बच्चों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। दिल दुखाने वाली इस घटना की टीस लंबे आजीवन रहेगी।

मनु ने फैलाई खुशियां

मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर पिछले दो ओलंपिक खेलों से निशानेबाजी में चले आ रहे सूखे को खत्म कर दिया है। मनु भाकर ओलंपिक निशानेबाजी में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। इससे पहले भारत ने निशानेबाजी में चार पदक जीते हैं और यह पदक जीतने वाले सभी चारों निशानेबाज पुरुष हैं। मनु भाकर ने ओलंपिक खेलों की शुरुआत में ही पदक पर निशाना साधकर इन खेलों में भाग ले रहे शूटरों का ही नहीं बल्कि पूरे भारतीय दल की बॉडी लेंग्वेज बदल दी है। इससे अन्य खिलाड़ियों को अपना बेस्ट देने की प्रेरणा मिलेगी, जिससे भारत अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में सफल हो सकता है। यह मनु की सफलता का ही प्रभाव था कि रमिता झिंदल ने 10 मीटर एयर राइफल के फाइनल में स्थान बनाया। हालांकि वह फाइनल में पहुंचकर भी पदक नहीं पा सकीं और उन्हें

सातवें स्थान से ही संतोष करना पड़ा। हम सभी जानते हैं कि भारतीय निशानेबाज यदि तीन चार पदकों पर निशाना साधने में सफल हो जाएं तो भारतीय पदकों की संख्या दो अंकों में पहुंच सकती है। भाकर 2021 में हुए टोक्यो ओलंपिक में पिस्टल खराब हो जाने की वजह से अपना बेस्ट नहीं दे सकीं थीं। इसके बाद उनके कोच जसपाल राणा से संबंध खत्म हो गए थे, लेकिन जसपाल ने अलग होने के बाद उनके प्रदर्शन में गिरावट आती गई। वह तो खुदा का शुक्र है कि उन्हें सही समय पर जसपाल राणा से फिर से जुड़ने की जरूरत महसूस हुई। मनु ने पदक जीतने के बाद कहा कि एक बार पदक पक्का हो जाने पर खुशी हुई। पर आगे नहीं बढ़ पाने का अफसोस है। वह कहती हैं कि अगली स्पर्धा में पदक का रंग पीला यानी गोल्ड करने का प्रयास करूंगी। वह अपना ध्यान केंद्रित रखने के लिए गीता का पाठ करती हैं, जिसमें कहा गया है कि खुद के कर्म पर भरोसा रखो। यह बात भारतीय दल के सभी सदस्यों पर लागू होती है। भारत इस समय निशानेबाजी के अलावा बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी, बॉक्सिंग आदि में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और एथलेटिक्स और कुश्ती शुरू होने पर भारत की पदक संभावनाएं और बढ़ेंगी। बहुत संभव है कि हम इस बार दर्जन भर पदकों तक पहुंच जाएं। पर हमें यहीं संतुष्ट होकर नहीं बैठना चाहिए क्योंकि अभी हम आबादी के हिसाब से विश्व स्तर से काफी पीछे हैं।

टू दि प्वाइंट/ आलोक पुराणिक

सर्वर उर्फ फूफा

माइक्रोसाफ्ट का सर्वर ठप हो गया, तो तमाम एयरलाइंस, टीवी चैनल बैंक वगैरह समेत जाने क्या क्या ठप हो गया। सर्वर ने जो ठप ना किया, उसे कई निकम्मे इंप्लाइज ने ठप कर दिया। एक सरकारी बैंक के कर्मचारी ने जवाब दिया कि आज कुछ ना हो सकता, सर्वर ठप है। जबकि कस्टमर ने सिर्फ यह पूछा था कि भाई साहब बहुत गरमी है पानी मिल सकता है क्या। भानगढ़ किले के भूत ने उस भुतहा टीवी कार्यक्रम में आने से इनकार कर दिया यह कहते हुए कि सर्वर ठप है। वैसे भानगढ़ किले का भूत परमानेंट न्यूज से गायब हो जाए, ऐसे सर्वर ठप्पीकरण का तो वेलकम किया जाना चाहिए। सर्वर चलता रहा है, तो कोई ना पूछता था। सर्वर रुक गया, तो चर्चा हो गई।

मतलब मामला कुछ-कुछ शादी के नाराज फूफा टाइप हो लिया। किसी शादी में कोई फूफा टाइप बहुत शराफत से खा पीकर चले जाएं, तो कोई नोटिस नहीं करता। अगर कोई फूफा नाराज हो जाएं, हल्ला सा काट दें, तो सब तरफ उनका नोटिस लिया जाता है। यानी चलते सर्वर और शरीफ साढ़ू का कोई नोटिस नहीं लेता। ठप सर्वर और नाराज साढ़ू को सब नोटिस करते हैं और उसकी चर्चा करते हैं। कई निकम्मों ने अपने निकम्मेपन की जिम्मेदारी सर्वर पर डाल दी।

एक शराबी दारू पीकर दादर स्टेशन पर लुढ़क गया, पुलिस ने डपटा तो उसने बताया कि सर्वर ठप है। अब बस यह ना हो कि राहजन आपको रिवाल्वर दिखाकर कहे कि निकाल दीजिए रकम और यह बहाना मत बनाइए कि सर्वर ठप है, बिना सर्वरबाजी के आपकी रकम मेरी जेब में आ सकती है। सर्वर ठप हुआ तो प्लेन ना उड़े, जिसके पास जितने एडवांस्ड कंप्यूटर वाले प्लेन उसके प्लेन उतने ही ज्यादा ठप। पाकिस्तानी एयर फोर्स ने बयान जारी करके कहा कि हम तो अमेरिकन सर्वर पर डिपेंड ही नहीं करते, हम तो चाइनीज प्लेन्स पर डिपेंड हैं, दस में पांच बार तो चाइनीज प्लेन उड़ ही जाते हैं।

पहले भी दस में से पांच उड़ते थे, अब भी दस में से पांच उड़ रहे हैं, कोई असर नहीं। तालिबानियों ने कहा कि हमारा क्या काम कंप्यूटर सर्वर से, हम तो हाथ से खींचकर ले जाते हैं राकेट, सर्वर चले या ना चले, हमें क्या।

बदलते आयाम और स्वरूप

मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस

राजेश मणि

मानव तस्करी के खिलाफ हमारी लड़ाई में, हमें लगातार नवाचार के माध्यम से जुड़ने और एकजुट होने का प्रयास करना चाहिए, जिसमें डिजिटल प्रौद्योगिकी के हमारे उपयोग का अनुकूलन भी शामिल है। तस्कर दूसरों का शोषण करने के लिए इंटरनेट की लगातार बदलती प्रकृति का लाभ उठाते हैं; यह जरूरी है कि हम भी इस प्रवृत्ति का मुकाबला करने के लिए प्रौद्योगिकी को अपनाएं। डिजिटल तकनीक ने हमें तस्करी को रोकने, पीड़ितों की रक्षा करने, बुरे लोगों पर मुकदमा चलाने और इस अपराध से निपटने के लिए वैश्विक साझेदारी बनाने के नए तरीके दिए हैं।

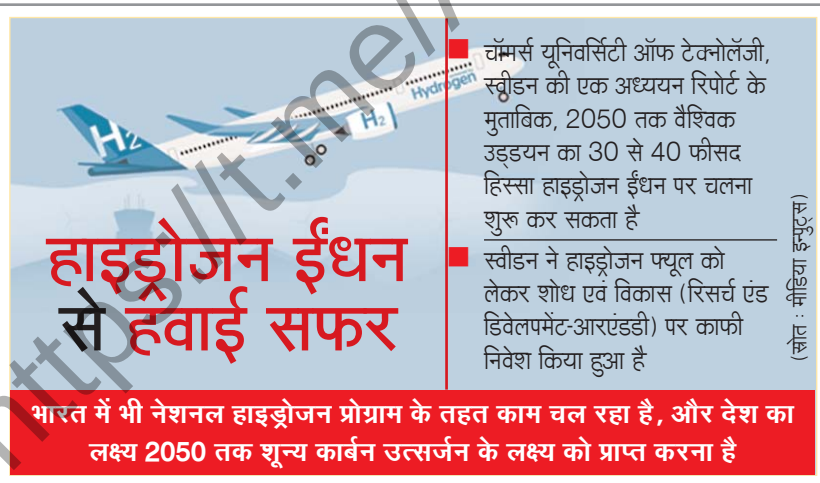

डिजिटल तकनीक और मानव तस्करी के बीच एक तरह का संबंध तब हो सकता है जब तस्कर पीड़ितों का शोषण करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि यह कोई नई घटना नहीं है, लेकिन इस मुद्दे पर नए सिरे से ध्यान दिया गया क्योंकि कई लोगों ने कोविड-19 महामारी के चरम पर अपनी दैनिक गतिविधियों को ऑनलाइन कर दिया। कई देशों की रिपोर्टों ने ऑनलाइन वाणिज्यिक यौन शोषण और यौन तस्करी में भारी वृद्धि को प्रदर्शित किया, जिसमें बच्चों का ऑनलाइन यौन शोषण (OSEC 'Online sexual exploitation of Children'), और बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM 'Child sexual abuse material') की मांग और वितरण शामिल है। तस्करों ने पीड़ितों को तैयार करने, धोखा देने, नियंत्रित करने और उनका शोषण करने के लिए डिजिटल उपकरणों का उपयोग करके व्यक्तियों का शोषण करने की योजनाओं को आगे बढ़ाना जारी रखा है।

इनमें से कुछ योजनाएं लोगों को सैकड़ों मील दूर, सीमाओं के पार भी लुभाती हैं, जबकि अन्य के लिए उन्हें अपने घरों से बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं होती है। मानव तस्करी के पीड़ितों और बचे लोगों ने तेजी से साझा किया है कि वे पहली बार अपने तस्करों से ऑनलाइन जुड़े थे, जबकि तस्कर डिजिटल तकनीकों के अपने उपयोग को परिष्कृत और उन्नत करना जारी रखते हैं, सरकारों और अन्य तस्करी विरोधी हितधारकों को मानव तस्करी से निपटने के लिए ऐसा ही करना चाहिए। तस्कर संभावित पीड़ितों की पहचान और उन्हें तैयार करने के लिए इंटरनेट का उपयोग करते हैं। यूएनओडीसी (United Nations Office on Drugs and Crime) के अनुसार, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तस्करों को सक्रिय रूप से और गुमनाम रूप से एक विशिष्ट प्रकार के व्यक्ति की खोज करने में मदद करते हैं, जिनके बारे में उन्हें लगता है कि वे उनकी योजना को आगे बढ़ाने के लिए विशेष रूप से अतिसंवेदनशील हैं (शिकार प्रक्रिया), या ऑनलाइन पोस्ट करके और प्रतिक्रिया की

प्रतीक्षा करके संभावित पीड़ितों को निष्क्रिय रूप से आकर्षित करते हैं (मछली पकड़ने की प्रक्रिया)। अपराधी संभावित पीड़ितों के साथ बातचीत करते समय नकली खातों और प्रोफाइल के माध्यम से अपनी असली पहचान छिपाने के लिए सोशल मीडिया, ऑनलाइन विज्ञापन, वेबसाइट, डेटिंग ऐप और गेमिंग प्लेटफॉर्म-या ऐसे उपकरणों की धोखाधड़ी या भ्रामक नकल-का उपयोग कर सकते हैं।

एक बार जब संभावित पीड़ितों की पहचान हो जाती है और संपर्क स्थापित हो जाता है, तो इंटरनेट के माध्यम से संचार शिक्षा, रोजगार, आवास या रोमांटिक संबंधों के झूठे वादों के साथ व्यक्तियों को धोखा देने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में कार्य करता है, केवल उन्हें श्रम और यौन तस्करी की स्थितियों में लुभाने के लिए। उदाहरण के लिए, एक तस्कर एक ऑनलाइन व्यावसायिक वेबसाइट बना सकता है, जिस पर वे अक्सर पीड़ित का विश्वास जीतने के लिए यथार्थवादी तस्वीरें शामिल करते हैं और उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि अवसर प्रामाणिक है और उनके करियर को आगे बढ़ाने या उनके जीवन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। इंटरनेट शोषणकारी योजना को आगे बढ़ाने के लिए एक मंच के रूप में भी काम कर सकता है, जिसमें सेक्सटॉर्शन के माध्यम से भी शामिल है। संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई) सेक्सटॉर्शन को एक गंभीर अपराध के रूप में परिभाषित करता है जो तब होता है जब अपराधी पीड़ित द्वारा यौन प्रकृति की तस्वीरें, यौन एहसान या पैसे न दिए जाने पर निजी और संवेदनशील सामग्री वितरित करने की धमकी देता है।

इसके अतिरिक्त, तस्कर जबरन अपराध को बढ़ावा देने के लिए इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं, जो एक तेजी से आम तंत्र है जिसमें तस्कर अपने पीड़ितों को ऑनलाइन घोटाले के संचालन से लेकर व्यावसायिक सेक्स तक के कामों में शामिल होने या उनका समर्थन करने के लिए मजबूर करते हैं। तस्कर बड़े पैमाने पर ऑनलाइन नौकरी लिस्टिंग के माध्यम से पीड़ितों को भर्ती करते हैं, उन्हें परिसरों में बंद कर देते हैं और गंभीर नुकसान की धमकी देकर उन्हें ऑनलाइन आपराधिक गतिविधि में शामिल होने के लिए मजबूर करते हैं। ऑनलाइन घोटाले के संचालन में अवैध ऑनलाइन जुआ, क्रिप्टोकरेंसी निवेश योजनाएं और रोमांस घोटाले शामिल हैं, जिनमें से सभी में तस्करी का शिकार व्यक्तियों के साथ संबंध बनाता है ताकि उन्हें महत्त्वपूर्ण रकम का धोखा दिया जा सके। संक्षेप में, तस्कर अपने तस्करी कार्यों की पहुंच, पैमाने और गति को बढ़ाने के लिए इंटरनेट जैसे डिजिटल उपकरणों का उपयोग करते हैं। हालांकि तकनीकी विकास के साथ तरीके और साधन विकसित हो सकते हैं, लेकिन तस्करी के मूल में शोषण अभी भी जारी है, जो इस अपराध की जांच और उससे निपटने के लिए व्यापक और अभिनव दृष्टिकोण की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है।

हम सभी को विशेषकर बच्चों पर ध्यान देने की आवश्यकता है या मॉनिटिरंग करने की आवश्यकता है। तस्कर आए दिन अपने तरीके बदलते रहते हैं। अपने देश में इस मुद्दे को यानी मानव तस्करी को गृह मंत्रालय मॉनिटर करता है और इस संगठित अपराध को कम करने के लिए संकल्पित भी है। गृह मंत्रालय ने एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग थाने का गठन करने के लिए सभी प्रदेशों को आदेश भी दिया है। आदेश के बाद लगभग राज्यों में इसका गठन हो भी चुका है। साथ ही प्रमुख स्टेकहोल्डर्स के प्रिशिक्षण के लिए भी गृह मंत्रालय कार्य कर रहा है।

(लेखक मानव सेवा संस्थान सेवा के निदेशक हैं)

> हम सभी को विशेषकर बच्चों पर ध्यान देने की आवश्यकता है या मॉनिटिरंग करने की आवश्यकता है डिजिटल प्रयोग कितना है और किस प्रकार का है। तस्कर आये दिन अपने तरीके बदलते रहते हैं। अपने देश में मानव तस्करी को गृह मंत्रालय मॉनिटर करता है और इस संगठित अपराध को कम करने के लिए संकल्पित भी है। गृह मंत्रालय ने एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग थाने का गठन करने के लिए सभी प्रदेशों को आदेश भी दिया है। लगभग राज्यों में गठन हो भी चुका है

हाइड्रोजन ईंधन से हवाई सफर

- चॉमर्स यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, स्वीडन की एक अध्ययन रिपोर्ट के मुताबिक, 2050 तक वैश्विक उड्डयन का 30 से 40 फीसद हिस्सा हाइड्रोजन ईंधन पर चलना शुरू कर सकता है
- स्वीडन ने हाइड्रोजन फ्यूल को लेकर शोध एवं विकास (रिसर्च एंड डिवेलपमेंट-आरएंडडी) पर काफी निवेश किया हुआ है

(स्रोत : मीडिया इनपुट्स)

भारत में भी नेशनल हाइड्रोजन प्रोग्राम के तहत काम चल रहा है, और देश का लक्ष्य 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना है

दिल्ली के शीर्ष नौकरशाह किसके प्रति जवाबदेह हैं? एलजी या दिल्ली सरकार के मंत्रियों के प्रति। यदि जल निकासी डी-सिल्टिंग पर चर्चा के लिए 28 जून को बैठक बुलाई गई थी, तो कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? कब तक बिना किसी जवाबदेही वाले अधिकारियों की इन बहु-श्रृंखलाओं के कारण कीमती जानों की कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या दिल्ली अब भगवान भरोसे है?

राजदीप सरदेसाई, पत्रकार
@sardesairajdeep

खत्म करने की चुनौती

भुखमरी | रविशंकर

दुनियाभर के लिए भुखमरी आज एक वैश्विक समस्या बन गई है। जनसंख्या बढ़ने के साथ ही विश्वभर में भुखमरी का आंकड़ा भी दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जबकि पृथ्वी पर हर एक इंसान का पेट भरने लायक पर्याप्त भोजन का उत्पादन हो रहा है, लेकिन फिर भी दुनिया के कुछ हिस्सों में भुखमरी बढ़ती जा रही है।हकीकत ये है कि आधुनिक दुनिया में आज हर 11वां इंसान अभी भी खाली पेट सोने को मजबूर है। मतलब की दुनिया में 73.3 करोड़ लोग ऐसे है,जिन्हें भरपेट खाना नसीब नहीं हो रहा है। यदि 2019 की तुलना में देखें तो इन लोगों की संख्या में 15.2 करोड़ का इजाफा हुआ है।

अफ्रीका में हालात तो और भी कहीं ज्यादा खराब है, जहां हर पांचवां इंसान भुखमरी का सामना करने को मजबूर है। ये जानकारी दुनिया में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति पर जारी एक नई रिपोर्ट में सामने आई है। 'द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2024' नामक ये रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ), अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष (आईएफएडी), यूनिसेफ, विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने संयुक्त रूप से प्रकाशित की है।

इस रिपोर्ट में बताया गया है कि आज दुनिया की एक तिहाई आबादी ऐसी है, जो पोषण युक्त आहार खरीदने में सक्षम नहीं है। रिपोर्ट में जो आंकड़े साझा किए गए हैं वो खाद्य सुरक्षा की एक गंभीर तस्वीर पेश कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में 233 करोड़ लोग ऐसे हैं, जिन्हें नियमित तौर पर पर्याप्त भोजन हासिल करने के लिए जूझना पड़ रहा है। इनमें 86.4 करोड़ लोग वो हैं जिन्हें गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ा। यानी उन्हें कुछ समय बिना खाए ही गुजारा करना पड़ा है। वास्तविकता में देखें तो पोषण के मामले में दुनिया 15 साल पीछे चली गई है और कुपोषण का स्तर 2008-2009 के स्तर पर पहुंच चुका है। हालांकि देखा जाए तो ये स्थिति तब है जब सतत विकास के लक्ष्यों के तहत 2030 तक किसी को खाली पेट न सोने देने की बात कही गई थी। मतलब की इन छह वर्षों में दुनिया को एक लंबा सफर तय करना है। रिपोर्ट में ये चेतावनी भी दी गई है कि अगर मौजूदा हालात इसी तरह से जारी रही, तो 2030 तक लगभग 58 करोड़ से ज्यादा लोग गंभीर

कुपोषण का शिकार हो जाएंगे। इनमें से आधे अफ्रीका में होंगे। साफ है, दुनियाभर में तमाम प्रोग्राम और संयुक्त राष्ट्र की कोशिशों के बावजूद खाद्य असामनता और कुपोषण जैसे मुद्दे पर अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। यूं तो इंसान पांच दशक पहले ही चांद पर पहुंच गया, लेकिन इसी दुनिया में आज भी करोड़ों लोगों को चांद रोटी में नजर आता है। ताजा रिपोर्ट देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि दुनिया में भुखमरी की संख्या घटने की बजाए तेजी से बढ़ रही है। साफ है, भूख की समस्या को पूरी तरह समाप्त करने के लिए अभी दुनिया को एक लंबा रास्ता तय किया जाना बाकी है। ये कैसी विडंबना है एक ओर हमारे और आपके घर में रोज सुबह रात का बचा हुआ खाना बासी समझ कर फेंक दिया जाता है तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें एक वक्त का खानातक नसीब नहीं हो रहा है और वे भूख से जूझ और मर रहे है। दुनिया भर में हर साल जितना भोजन तैयार होता है उसका लगभग एक-तिहाई बर्बाद हो जाता है। बर्बाद किया जाने वाला खाना इतना होता है कि उससे दो अरब लोगों के भोजन की ज़रूरत पूरी हो सकती है। गौर करने वाली बात ये है कि दुनिया में बढ़ती संपन्नता के साथ ही लोग खाने के प्रति असंवेदनशील हो रहे हैं। खर्च करने की क्षमता के साथ ही लोगों में खाना फेंकने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। कमोबेश हर विकसित और विकासशील देश की यही कहानी है। अगर इस बर्बादी को रोका जा सके तो कई लोगों का पेट भरा जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ, खाद्यान्न की क्षति और बर्बादी न केवल संसाधनों के कुप्रबंधन का मुद्दा है बल्कि ये बड़े पैमाने पर ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में भी योगदान देती है। खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) का अनुमान है कि वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के आठ प्रतिशत के लिए खाद्य अपशिष्ट भी जिम्मेदार होते हैं।

वर्तमान समय में हर देश विकास के पथ पर आगे बढ़ने का दावा करता है। अल्पविकसित देश विकासशील देश बनना चाहते हैं तो वहीं विकासशील देश विकसित देशों की श्रेणी में शामिल होना चाहते हैं। इसके लिए देशों की सरकारें प्रयास भी करती हैं तथा विकास के संदर्भ में अपनी उपलब्धियों को गिनाती हैं। यहां तक कि विकास दर के आंकड़े से ये अनुमान लगाया जाता है कि कोई देश किस तरह विकास कर रहा है कैसे आगे बढ़ रहा है? ऐसे में जब कोई ऐसा आंकड़ा सामने आ जाए जो आपको ये बताए कि अभी तो देश 'भूख' जैसी 'समस्या को भी हल नहीं कर पाया है, तब विकास के आंकड़े झूठे लगने लगते हैं। ये कैसा विकास है जिसमें बड़ी संख्या में लोगों को भोजन भी उपलब्ध नहीं है।

शून्यता का अनुभव | ओशो

ध्यान में तुम्हें कभी कभी एक तरह की शून्यता का अनुभव होता है; वह वास्तविक शून्यता नहीं है। मैं उसे एक तरह की रिक्तता कहता हूं। ध्यान में कुछ क्षणों के लिए तुम्हें ऐसा अनुभव होगा जैसे कि विचार की प्रक्रिया ठहर गई है। शुरू-शुरू में ऐसे अंतराल आएंगे, लेकिन क्योंकि तुम्हें ऐसा अनुभव होता है जैसे कि विचार की प्रक्रिया ठहर गई है, इसलिए यह भी एक विचार ही है बहुत सूक्ष्म विचार। तुम क्या कर रहे हो? तुम भीतर-भीतर कह रहे हो। 'विचार की प्रक्रिया ठहर गई है।' लेकिन यह क्या है? यह एक सूक्ष्म विचार प्रक्रिया है, जो अब आरंभ हुई है। और तुम कहते हो, यह शून्यता है। तुम कहते हो, अब कुछ घटित होने वाला है। यह क्या है? फिर एक नई विचार प्रक्रिया आरंभ हो गई। जब ऐसा फिर हो तो उसके शिकार मत बनना। जब तुम्हें लगे कि कोई मौन उतर रहा है, तो उसे शब्द देना मत शुरू कर देना। शब्द देकर तुम उसे नष्ट कर देते हो। प्रतीक्षा करो; किसी चीज की प्रतीक्षा नहीं, सिर्फ प्रतीक्षा करो। कुछ करो मत। यह भी मत कहो कि यह शून्यता है। जैसे ही तुम यह कहते हो, तुम उसे नष्ट कर देते हो। उसे देखो, उसमें प्रवेश करो, उसका साक्षात करो। लेकिन प्रतीक्षा करो, उसे शब्द मत दो। जल्दी क्या? शब्द देकर मन फिर दूसरे रास्ते से प्रवेश कर गया; उसने तुम्हें धोखा दे दिया। मन की इस चालबाजी के प्रति सजग रहो। शुरू-शुरू में ऐसा होना अनिवार्य है। तो जब फिर ऐसा हो तो रुको, प्रतीक्षा करो। उसके जाल में मत फंसो। कुछ कहो मत; चुप रहो। तब तुम गहरे प्रवेश करोगे, और तब वह खोएगी नहीं। क्योंकि तुम एक बार सच्ची शून्यता को जान लो तो फिर वह खोती नहीं है। सच्ची शून्यता कभी नहीं खोती है, यही उसकी गुणवत्ता है। और एक बार तुमने अपने आंतरिक खजाने को जान लिया, एक बार तुम अपने अंतरतम केंद्र के संपर्क में आ गए, तो फिर तुम अपने काम धाम में लगे रह सकते हो, तुम जो चाहो कर सकते हो, तुम सामान्य सांसारिक जिंदगी जी सकते हो और यह शून्य तुम्हारे साथ रहेगा। तुम इसे भूल नहीं सकते; भीतर वह शून्य बना रहेगा। तुम जो भी करोगे, करना सतह पर रहेगा, भीतर तुम शून्य के शून्य रहोगे। और अगर तुम भीतर शून्य रह सके, करना सिर्फ सतह पर चलता रहा, तो तुम जो भी करोगे वह दिव्य हो जाएगा, तुम जो भी करोगे उसमें भगवत्ता का स्पर्श होगा। क्योंकि अब कृत्य तुमसे नहीं आ रहा है, अब कृत्य मूलभूत शून्यता से आ रहा है।

रीडर्स मेल

दर्ज हो हत्या का मुकदमा

अपनी आंखों में सिविल सेवा का सपना संजोए हुए अनेकों युवा दिल्ली का रुख करते हैं। नियम-कानून को ताक पर रखकर देश में कोचिंग उद्योग कुकुरमुत्ता की तरह छा गया है। दिल्ली में सिविल सेवा की तैयारी कराने वाले एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से तीन छात्रों की मौत लापरवाही की पराकाष्ठा है। बेसमेंट में स्टोर या पार्किंग की अनुमति प्रदान किया गया था, लेकिन नगर निकाय की मिलीभगत से बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाया जा रहा था द्य मामले की लीपापोती के लिए आनन -फानन में कोचिंग संस्थान के दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना के लिए नगर निकाय के जिम्मेदार पदाधिकारियों पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करना चाहिए। इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए समस्या की जड़ पर प्रहार करना अनिवार्य है।

हिमांशु शेखर, गया

है पदक की उम्मीद

पेरिस ओलंपिक में भारतीय निशानेबाज मनु भाकर ने कांस्य पदक जीतकर भारत का मान बढ़ाया है। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम होगी। इससे अन्य खिलाड़ियों को भी अपने खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की प्रेरणा मिलेगी। विगत कुछ वर्षों में अनुभव किया जा रहा है कि ओलंपिक में हमारा प्रदर्शन आशानुरूप नहीं रहता। वर्तमान खेल नीति व क्रिकेट के अलावा अन्य खेलों की घटती लोकप्रियता के कारण अन्य खिलाड़ी स्वयं को उपेक्षित महसूस करते हैं। आजकल बच्चे मोबाइल में व्यस्त रहते है। यदि वास्तविक रूप से हम ओलंपिक में प्रदर्शन अच्छा करना चाहते हैं तो ऐसी नई खेल नीति बनाई जाए जिसमें किशोरावस्था से ही बच्चे खेलों के प्रति प्रेरित हों। तहसील व जिला स्तर से ही खेलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। स्कूली स्तर पर प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान कर उन्हें प्रोत्साहित किया जाए। बहरहाल, अब भारत की झोली में एक पदक आ चुका है, अत यह उम्मीद की जानी चाहिए कि खिलाड़ी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे।

गोपाल सोनी, धार, मप्र

ये बहाना नहीं चलेगा

उत्तर प्रदेश के शिक्षकों के पास काम न करने के कई बहाने हैं। कभी वो कहते हैं रास्ते में पानी भरा है, कभी ज्यादा सर्दी तो कभी गर्म मौसम का बहाना बनाते हैं। हालांकि ये दिक्कतें तो सभी कामकाजी लोगों के लिए है। सभी अपना काम कर रहे हैं। इसमें कोई बहाना नहीं है। क्योंकि आदमी पेट के लिए तो ये सब करता है। देखा गया है कि बहाने बनाने में सरकारी शिक्षक सबसे आगे हैं। सघन जांच के वक्त ये शिक्षक जब-तब गायब मिलते हैं। पेपर में पढ़ा कि एक शिक्षिका गर्मी को बर्दाश्त ना कर पाने के कारण बेहोश हो गई। इससे पहले भी ये शिक्षक रास्ते में पानी भराव का बहाना बनाकर ऑनलाइन हाजिरी का विरोध करते दिखे। मीठा-मीठा हप्प कड़वा कड़वा थू थू। ये नहीं चलेगा। ये शिक्षक चाहते तो यही हैं कि काम पर ना जाना पड़े और वेतन मिलता रहे। सरकार का सख्त रवैया भी इस मामले में काबिलेतारीफ है। आखिर सरकार उन्हें वेतन दे रही है वह जनता का ही पैसा है। और नेताओं को भी इस अव्यवस्था का जनता को जवाब देना है। इसलिए सरकार चाहती है शिक्षक ड्यूटी के प्रति चौकस रहें।

दिलीप कुमार गुप्ता, बरेली

letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

https://t.me/AllNewsPaperPaid

राष्ट्रीय सहारा • राष्ट्रीयता • कर्तव्य • समर्पण
वर्ष-33, अंक 347
सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया कादरी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3,4, सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा 705-706, सातवां तल, नवरंग हाउस, 21 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित। समूह संपादक - डॉ. विजय राय। स्थानीय संपादक - रत्नेश मिश्र*।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 23352368, 23352369, 23352371, 23352372, फैक्स - 23352370, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750
आर.एन.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2024-2026
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन तथा कानूनी मामलों के लिए उत्तरदायी

ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्
भगवान इस जग के कण-कण में विद्यमान हैं।

मनु भाकर : कर्म और फल

"कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन्" श्रीमद्भागवत गीता के श्लोक का अर्थ है तेरा कर्म करने का अधिकार है इन के फलों में नहीं। तू कर्म के फल के प्रति आसक्त न हो या कर्म करने के प्रति प्रेरित न हो। भाव यह है कि अगर कोई व्यक्ति बार-बार कर्म के फल के बारे में ही सोचता रहे तो उसके द्वारा किए गए कर्मों में उसका पूरा ध्यान नहीं रह पाएगा। उसकी कर्म में ही रुचि नहीं रहेगी। यह कुछ इस तरह का है जैसे कोई राही लंबे रास्ते पर निकला हो और चलते-चलते बीच-बीच में ही पीछे मुड़कर देखता रहे तो क्या होगा। जीवन के हर क्षेत्र में विजय हासिल करने के लिए कर्म करना बहुत जरूरी है। भारतीय निशानेबाज और हरियाणा की छोरी मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में कांस्य पदक जीतकर इतिहास तो रचा ही साथ ही वह शूटिंग में ओलंपिक मैडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज बन गई है। मनु भाकर ने इतिहास रचने के बाद कहा कि वह फाइनल के दौरान हिन्दू धर्म के महाग्रंथ श्रीमद्भागवत के शब्दों को याद करती रही इससे मुझे मदद मिली। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि जो तुम्हें करना है करो परिणाम की चिंता मत करो।

भगवान श्रीकृष्ण द्वारा अर्जुन को कहे गए शब्दों को आत्मसात करने पर ही उसे लक्ष्य हासिल हुआ। हरियाणा के झज्जर जिले के गोरिया गांव की मनु भाकर पर आज समूचा राष्ट्र गर्व कर रहा है। बधाईयों का तांता लगा हुआ है। इस सफलता के पीछे मनु भाकर का जोश, जज्बा और जुनून तो है ही लेकिन उसके कौशल और समर्पण के पीछे माता-पिता की भी बड़ी भूमिका रही। स्कूल की निशानेबाजी प्रतियोगिता में उसने इतना स्टीक निशाना लगाया था कि सभी शिक्षक हैरान रह गए थे। फिर प्रैक्टिस और ट्रेनिंग के बाद जगह-जगह आयोजित प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने का सिलसिला शुरू हुआ। तब मुश्किल यह थी कि मनु लाइसैंसी पिस्टल लेकर बसों में सफर नहीं कर सकती थी। बेटी के सपनों को साकार करने के लिए उसके पिता रामकिशन ने मरीन इंजीनियर की नौकरी तक छोड़ दी थी। मनु भाकर की मां ने भी हमेशा उसे कर्म करने के लिए प्रेरित किया और उससे कोई उम्मीद नहीं रखी।

हरियाणा के झज्जर जिले के गोरिया गांव की मनु भाकर पर आज समूचा राष्ट्र गर्व कर रहा है। बधाईयों का तांता लगा हुआ है। इस सफलता के पीछे मनु भाकर का जोश, जज्बा और जुनून तो है ही लेकिन उसके कौशल और समर्पण के पीछे माता-पिता की भी बड़ी भूमिका रही। स्कूल की निशानेबाजी प्रतियोगिता में उसने इतना स्टीक निशाना लगाया था कि सभी शिक्षक हैरान रह गए थे। फिर प्रैक्टिस और ट्रेनिंग के बाद जगह-जगह आयोजित प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने का सिलसिला शुरू हुआ। तब मुश्किल यह थी कि मनु लाइसैंसी पिस्टल लेकर बसों में सफर नहीं कर सकती थी। बेटी के सपनों को साकार करने के लिए उसके पिता रामकिशन ने मरीन इंजीनियर की नौकरी तक छोड़ दी थी।

2018 मनु भाकर के लिए एक शूटर के रूप में सफल साल था। उन्होंने एक साल पहले ही अपनी क्षमता की झलक दे दी थी। 2017 की राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में मनु भाकर ने ओलंपियन और पूर्व वर्ल्ड नंबर 1 हीना सिद्धू को चौंका दिया। मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में सिद्धू के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 242.3 का रिकॉर्ड स्कोर बनाया। एक साल बाद मनु भाकर महज 16 साल की उम्र में कॉमनवैल्थ गेम्स में गोल्ड मैडल पदक जीतकर सोशल मीडिया सनसनी बन गईं। 2018 में मैक्सिको के ग्वाडलजारा में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप में मनु भाकर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मैडल जीता। इस खेल में उन्होंने दो बार की चैंपियन मैक्सिको की एलेजांद्रा जवाला को हराया। मनु भाकर ने 2019 म्यूनिख आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में चौथे स्थान पर रहकर ओलंपिक कोटा भी हासिल किया। टोक्यो ओलंपिक में मनु भाकर से बहुत उम्मीदें थीं, भले ही यह उनका पहला ओलंपिक था। हालांकि, उनका डेब्यू योजना के अनुसार नहीं हुआ। इवेंट के दौरान उनकी बंदूक में खराबी आ गई जिससे वह व्याकुल हो गईं। कई इवेंट में पसंदीदा में से एक होने के बावजूद उन्होंने तीन साल पहले टोक्यो ओलंपिक को बिना मैडल के समाप्त किया। मनु भाकर साल 2020 में टोक्यो ओलंपिक में मैडल जीतने में नाकाम रहने के बाद निशानेबाजी रेंज से रोते हुए बाहर निकली थीं।

टोक्यो ओलंपिक के बाद मनु भाकर ने एक महीने तक पिस्तौल की ओर नहीं देखा था लेकिन परिवार के सहयोग और गीता के श्लोकों ने उसके संकल्प को फिर मजबूत कर दिया। फाइनल में मनु का मुकाबला काफी कड़ा था। एक समय तो ऐसा लग रहा था कि वह रजत पदक जीतने के करीब है। उसे अपने कोच जसपाल राणा से भी मानसिक दृढ़ता बनाए रखने के लिए काफी प्रेरणा मिल चुकी थी इसलिए वह विचलित हुए बिना पूरी ऊर्जा के साथ निशाने लगा रही थी। उसने कोशिश की और अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। वह बहुत ही मामूली अंतर से तीसरे नंबर पर रही। हालांकि उसे दूसरे स्थान पर रहना भी पसंद नहीं है। पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर उसने टोक्यो ओलंपिक में अपनी निराशा को पीछे छोड़ दिया। 22 वर्षीय मनु भाकर के पास पदक का रंग बदलने के लिए काफी समय है। अंतर्राष्ट्रीय मंच उसके लिए खुला है जहां वह और पदकों की हकदार हो सकती है। निशानेबाजी में गोल्ड और रजत जीतने वाली दोनों निशानेबाज दक्षिण कोरिया की ही रही। मनु भाकर के लिए भविष्य में हर बड़े निशानेबाज को चुनौती देना सहज रहेगा। मनु भाकर की उपलब्धि, असाधारण कौशल और दृढ़ता का सबूत है और मनु युवा एथलीटों का रोल मॉडल बनेगी और उन्हें उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करती रहेगी।

आदित्य नारायण चोपड़ा
Adityachopra@punjabkesari.com

हरियाणा की बेटी ने विश्व में...

गीता पाढा

वो देश की अन्य बेटियों के लिए बन गई प्रेरणा की खान है,
मनु भाकर पर आज समस्त देश को मान है,
दकियानूसी सोच रखने वाले लोगों को दिया कड़ा पैगाम है,
हरियाणा की बेटी ने विश्व में ऊंचा किया भारत देश का नाम है...!!

स्टार्टअप ने सृजित किए 15.5 लाख प्रत्यक्ष रोजगार

नई दिल्ली, (आईएएनएस): केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा कि देश में सरकार से पहचान प्राप्त कर चुके स्टार्टअप ने मिलकर अब तक 15.5 लाख से ज्यादा प्रत्यक्ष रोजगार के मौके सृजित किए हैं। सरकार की ओर से बीते एक दशक में देश में स्टार्टअप कल्चर को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं।कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (एमएसडीई) ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड (डीपीआईआईटी) की ओर से 1,40,803 स्टार्टअप की पहचान की गई है।

केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम एंटरप्राइजेज (एमएसएमई) ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) को लागू किया है। इसके तहत उद्योगपतियों को नए एंटरप्राइजेज गैर-कृषि क्षेत्र में सेट अप करने में मदद करना है।

बेगानी शादी में दुनिया क्यों दीवानी..?

डा. विजय दर्डा
संपादक : लोकमत समूह
पूर्व राज्यसभा सांसद

एक फिल्मी गाना आप सबने सुना होगा...बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना...! फिल्म थी 'जिस देश में गंगा बहती है' आप कहेंगे कि इस गाने की याद मैं आपको क्यों दिला रहा हूं? दरअसल जब से अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोर रहा है तब से इस गाने की धुन पर कुछ पंक्तियां मेरे जेहन में बार-बार कौंध रही हैं...बेगानी शादी में दुनिया क्यों दीवानी...?

यूं तो दुनिया के किसी भी देश में चुनाव हो, दूसरे देशों की नजर उस पर बनी रहती है, खासकर उन देशों की नजर ज्यादा होती है जिनके आपसी रिश्ते ज्यादा जुड़े हुए या ज्यादा जटिल होते हैं। हर देश यह अंदाजा लगाता है कि उसके लिए किस व्यक्ति का सत्ता में आना फायदेमंद रहेगा लेकिन जब बात अमेरिका की होती है तो पूरी दुनिया की नजर उस पर होती है क्योंकि अमेरिका एक ऐसा देश है जो हर देश को प्रभावित करता है। उसके प्रभाव की जड़ें पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक फैली हुई हैं, वहां राष्ट्रपति कौन होने वाला है इससे दुनिया की राजनीति के बदलने के अनुमान लगाया जाना स्वाभाविक है। आपको याद ही होगा कि ट्रम्प अफगानिस्तान में लड़ाई लड़ रहे थे लेकिन बाइडेन ने सत्ता में आते ही अफगानिस्तान को उसकी किस्मत पर छोड़ कर अपनी फौज को अचानक वापस बुला लिया था। ऐसे और भी कई उदाहरण हैं।

यही कारण है कि इस बार भी पूरी दुनिया इस चर्चा में मशगूल है कि रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रम्प जीतेंगे या डेमोक्रेटिक कमला हैरिस? हालांकि कमला हैरिस अभी तक अधिकृत तौर पर उम्मीदवार नहीं बनी हैं लेकिन वो बनेंगी, यह तय है। और यदि वे राष्ट्रपति चुनी गईं तो पढ़े-लिखे और सबसे विकसित कहे जाने वाले अमेरिका की वे पहली महिला राष्ट्रपति होंगी।

मैं खासतौर पर भारत के संदर्भ में बात करूंगा कि किसकी जीत हमारे अनुकूल होगी। चूंकि हम भारतीय रिश्तों को लेकर भावनाओं से भरे होते हैं इसलिए जब ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने तो हम खुश हो गए और जब बाइडेन की जगह कमला हैरिस का नाम आया तो चेन्नई से 300 किलोमीटर दूर थुलासेंद्रापुरम गांव में जश्न मनाया जाने लगा क्योंकि कमला की मां श्यामला इसी गांव से निकल कर अमेरिका पहुंची थीं। तो क्या कमला हैरिस के दिल में भारत के लिए कोई खास जगह है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। उनकी मां भारतीय थीं तथा पिता जमैका से थे लेकिन वह अपने मूल को लेकर कोई खास उत्साह नहीं दिखाती हैं, बल्कि कई मौकों पर उन्होंने भारत विरोधी तेवर ही अपनाया है।

2019 में जब जम्मू-कश्मीर से धारा 370 का खात्मा किया गया था तब उन्होंने इसका विरोध किया था। उन्होंने यहां तक कहा था कि 'हम कश्मीरियों को याद दिलाना चाहते हैं कि वो अकेले नहीं हैं, हम हालात पर नजर बनाए हुए हैं।' दोस्ती का भाव रखने वाला कोई व्यक्ति ऐसा कभी नहीं कह सकता।

एक बात और याद दिलाना चाहूंगा कि 2021 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे तो उन्होंने कमला को भारत आने का न्यौता दिया था लेकिन बदले में उन्होंने लोकतंत्र पर खतरे का राग छेड़ दिया था।

2023 में अमेरिका यात्रा के दौरान पीएम ने कमला की काफी तारीफ की थी लेकिन उपराष्ट्रपति बनने के बाद कमला ने भारत की ओर कभी रुख किया ही नहीं। सच तो यह है कि भारत और अमेरिका के रिश्तों को और बेहतर बनाने में उन्होंने अब तक कोई रुचि ही नहीं दिखाई है।

अब चलिए जरा इस बात पर ध्यान दें कि यदि ट्रम्प जीते तो भारत से रिश्तों का क्या होगा? आमतौर पर धारणा यही रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रम्प के निजी रिश्ते काफी मजबूत हैं। फरवरी 2020 में ट्रम्प जब भारत आए थे तब गुजरात में उनके लिए शानदार आयोजन किया गया था और उसके पहले अमेरिका में हाउडी मोदी कार्यक्रम की याद तो आपको होगी ही। अभी ट्रम्प पर हमला हुआ तो तत्काल उसकी आलोचना करने वालों में नरेंद्र मोदी भी शामिल थे।

इधर ट्रम्प इस बात को जानते हैं कि चीन को लेकर उनका जो नजरिया है, उसमें भारत बड़ी भूमिका निभाने की ताकत रखता है। दुनिया में भारत एक बढ़ती हुई शक्ति है इसलिए जाहिर सी बात है कि वे भारत को हर हाल में तरजीह देंगे। लेकिन क्या ट्रम्प खुले रूप से भारत के लिए फायदेमंद हैं? मुझे इसमें भी शंका है क्योंकि जब भी अमेरिकी हितों की बात आएगी तो स्वाभाविक रूप से कमला हों या ट्रम्प, वे अमेरिका के बारे में ही सोचेंगे और ट्रम्प तो 'अमेरिका फर्स्ट' की नीति के घनघोर समर्थक भी हैं। इस चुनाव प्रचार के दौरान ट्रम्प ने हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल पर ज्यादा टैक्स लगाने के मामले को लेकर भारत को निशाने पर लिया लेकिन उनका स्वर बहुत कठोर नहीं था।

वैसे एक बात और बता दूं कि ट्रम्प ने उपराष्ट्रपति पद के लिए जेडी वेंस को मैदान में उतारा है और उनकी पत्नी ऊषा भारतीय मूल की हैं, यानी रिपब्लिकन हों या डेमोक्रेटिक, दोनों तरफ भारतीय रिश्ता जुड़ा है लेकिन एक पहलू यह भी है कि अमेरिकी कांग्रेस के 535 सदस्यों में से केवल 5 ही भारतीय मूल के हैं इसलिए ज्यादा खुशफहमी पालने की जरूरत नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति की कुर्सी पर 78 वर्षीय ट्रम्प बैठें या फिर 59 वर्षीय कमला हैरिस, स्वाभाविक तौर पर वे भारत नहीं अमेरिका के हितों के बारे में ज्यादा सोचेंगे, दूसरे की शादी में दीवाना होकर हमें नाचने की जरूरत नहीं है बल्कि हमें यह सोचने की जरूरत है कि हम अमेरिका को अपनी राह पर कैसे लाएं ...और इसके लिए हमारे पास एस. जयशंकर जैसा प्रखर विदेश मंत्री मौजूद है...!

महाराष्ट्र में फडणवीस और विपक्ष की सियासत ?

आर. के. सिन्हा
पूर्व राज्यसभा सांसद

लोकसभा चुनावों के नतीजे आने और केन्द्र में नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार सरकार बनने के बाद अब महाराष्ट्र विधानसभा के आगामी अक्तूबर के महीने होने वाले चुनाव हैं। भारत की मजबूत होती अर्थव्यवस्था की जान है महाराष्ट्र। इसलिए सारे देश की निगाहें महाराष्ट्र पर लगी रहती हैं। वहां राज्य विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की राजनीति भी गरमा चुकी है। आरोप-प्रत्यारोप के नियमित दौर चल रहे हैं। महाराष्ट्र का विपक्ष महाविकास आघाड़ी राज्य के उस नेता पर आरोप लगा रहे हैं, जिसने राज्य का मुख्यमंत्री रहते हुए प्रदेश का चौतरफा विकास करवाया। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के शिखर भाजपा नेता और वर्तमान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की।

देवेंद्र फडणवीस राज्य के एक बड़े नेता होने के साथ ही काफी दूरदर्शी और अनुभवी रणनीतिकार के रूप में भी जाने जाते हैं। वह कई बार मुश्किलों में फंसी पार्टी को बाहर निकालकर अपनी योग्यता साबित कर चुके हैं। जब वह राज्य के मुख्यमंत्री थे, तब उनके कार्यकाल में राज्य के बुनियादी ढांचे के विकास में कई काम हुए। मुंबई मेट्रो विस्तार और मुंबई-नागपुर समृद्धि महामार्ग जैसी प्रमुख परियोजनाओं की शुरुआत की गई। तब महाराष्ट्र की प्रतिष्ठा एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र के रूप में और बढ़ी। देवेंद्र फडणवीस ने ही कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पुलिसिंग को मजबूत किया और अपराध की रोकथाम के लिए टेक्नोलॉजी आपरेटेड सिस्टम की शुरुआत की। समाज कल्याण को लेकर भी उन्होंने काफी पहल की। हाशिए पर पड़े समुदायों के उत्थान और सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम लागू किए गये।

महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बीते दिनों देवेन्द्र फडणवीस पर आरोप लगाया कि वे जब राज्य के गृहमंत्री थे तब उन्होंने (देवेंद्र फडणवीस ने) उन पर दबाव बनाया था कि वे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और महाविकास आघाड़ी के तीन अन्य नेताओं के खिलाफ केस दर्ज करवा दें। हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने देशमुख के इस आरोप को सिरे से खारिज किया है। कुल मिलाकर लग यह रहा है कि परब सहित एमवीए के प्रमुख लोगों के खिलाफ झूठे आरोप लगाने के लिए दबाव डाला था। साफ है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में टकराव बढ़ने वाला है और महाविकास आघाड़ी के निशाने पर देवेंद्र फडणवीस ज्यादा रहने वाले हैं। देवेंद्र फडणवीस पर विपक्ष गठबंधन महाविकास आघाड़ी के नेता रणनीति के तहत हल्ला बोल रहे हैं। उन्हें लगता है कि देवेंद्र फडणवीस को घेरकर वे विधानसभा चुनाव में बढ़त बना सकते हैं।

फडणवीस ने भी देशमुख को उनकी ही भाषा में जवाब भी दिया। सबको याद है कि अप्रैल 2021 में गृहमंत्री रहे देशमुख पर तत्कालीन मुंबई पुलिस कमिनर परमबीर सिंह ने यह आरोप लगाया था कि उन्होंने महाराष्ट्र की पुलिस को शहर के होटल और बार मालिकों से पैसे वसूलने पर लगा दिया था। अब देशमुख कह रहे हैं कि फडणवीस के निर्देश पर परमबीर सिंह ने उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए।

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जनता के बुनियादी मसलों से हटकर आरोप-प्रत्यारोप लगते रहेंगे। विपक्ष सत्ता हासिल करने के लिए तबीयत से कीचड़ उछालेगा।

जाहिर है फडणवीस ने भी देशमुख को उनकी ही भाषा में जवाब भी दिया। सबको याद है कि अप्रैल 2021 में गृहमंत्री रहे देशमुख पर तत्कालीन मुंबई पुलिस कमिनर परमबीर सिंह ने यह आरोप लगाया था कि उन्होंने महाराष्ट्र की पुलिस को शहर के होटल और बार मालिकों से पैसे वसूलने पर लगा दिया था। अब देशमुख कह रहे हैं कि फडणवीस के निर्देश पर परमबीर सिंह ने उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए। अब तीन साल बाद वही एनसीपी नेता देशमुख यह दावा कर रहे हैं कि फडणवीस ने उन पर उद्धव और आदित्य ठाकरे, तत्कालीन डिप्टी सीएम अजीत पवार और मंत्री अनिल

बेशक, यह अफसोसजनक स्थिति है कि जिस फडणवीस के मुख्यमंत्रित्वकाल में राज्य का अभूतपूर्व विकास हुआ, उन पर मिथ्या आरोप लग रहे हैं। उनके ही नेतृत्व में मुंबई मेट्रो का विस्तारीकरण हुआ। मुंबई-नागपुर समृद्धि महामार्ग, आर्थिक गलियारों और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए एक्सप्रेसवे परियोजना की शुरुआत हुई। बढ़ती शहरी आबादी को समायोजित करने के लिए किफायती आवास योजनाओं को उन्होंने ही लागू किया। सड़क और रेल परियोजनाओं सहित सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क में सुधार किया। आतंकवाद-रोधी उपायों के तहत संभावित खतरों को रोकने और उनका जवाब देने के लिए सुरक्षा ढांचे को बढ़ावा दिया। देवेंद्र फडणवीस ने सामुदायिक पुलिसिंग पर जोर दिया। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के तहत मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ने के लिए इस समुद्री पुल की शुरुआत की।

गोपीनाथ मुंडे के निधन के बाद देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की राजनीति में एक प्रमुख नेता के रूप में सामने आए। उन्होंने राज्य भाजपा को एकजुट किया। यह फडणवीस ही थे जिन्होंने भाजपा की ताकत बढ़ाने के लिए शिवसेना के बिना चुनाव लड़ने का हिम्मती फैसला किया। उन्होंने राज्य के लिए भाजपा की स्वतंत्र ताकत और दृष्टि पर जोर दिया और उनके नेतृत्व में ही भाजपा राज्य में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। राज्य में शिवसेना के बिना भाजपा की सरकार बनाने के लिए फडणवीस ने ही मंच तैयार किया।

अब भी वह सत्तासीन गठबंधन में स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उनका रणनीतिक कौशल जबर्दस्त रहा है। वह शासन में निरंतरता और प्रगति सुनिश्चित करते हुए लचीलेपन के साथ हर मुद्दे का राजनीतिक समाधान तलाशने में महारत रखते हैं। वही विभिन्न वर्गों के साथ प्रभावी ढंग से बातचीत करने में आगे रहे हैं। उनकी नेतृत्व शैली और उपलब्धियों ने उन्हें महाराष्ट्र की राजनीति में एक केंद्रीय व्यक्ति के रूप में स्थापित किया है। वह पैराशूट वाले नेता नहीं हैं। महाराष्ट्र में वह भाजपा में रैंक के माध्यम से आगे बढ़ने वाले नेता हैं। फडणवीस 1989 में युवा विंग के अध्यक्ष रहे हैं और केवल 27 साल की उम्र में नागपुर के मेयर नियुक्त हुए और 44 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बन गए। वह एक ऐसे नेता हैं जो भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व और आरएसएस दोनों में स्वीकार्यता रखते हैं। वह संघ के मूल मूल्यों को समझते हैं और पार्टी के भीतर उसको अपनाने की कोशिश भी करते हैं। महाराष्ट्र में हाल ही में हुए राजनीतिक उथल-पुथल जैसे चुनौतीपूर्ण समय के दौरान स्थिति को स्थिर करने और पार्टी के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने में उनकी बड़ी भूमिका रही है। हाल के लोकसभा चुनावों में पार्टी की हार को अपनी जिम्मेदारी के रूप में स्वीकार करते हुए इस्तीफा देने की उनकी पेशकश, नैतिक बल को ही दर्शाती है।

फडणवीस पर 2024 के विधानसभा चुनावों में भाजपा को जीत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी है। राज्य के राजनीतिक हलकों में कई लोगों को लगता है कि पिछले दस वर्षों से महाराष्ट्र में भाजपा के निर्विवाद नेता के रूप में फडणवीस ही राज्य में भाजपा की पुन: वापसी कर सकते हैं। वे विपक्ष को पटकनी देने में सक्षम हैं। विपक्ष भी हमेशा फडणवीस से ही डरा हुआ दिखाई देता है। किसी न किसी तरह से उन पर निशाना साधने में महाविकास अघाड़ी के नेता कोई कसर नहीं छोड़ते। यह अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवेन्द्र फडणवीस पर भरोसा रखते हैं।

2019 के विधानसभा चुनावों में भाजपा को अच्छी सफलता मिली, सबको लगा कि फडणवीस एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे लेकिन उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनने की अपनी महत्वाकांक्षा के साथ आगे आ गए। उन्हें अपने पुराने सहयोगी भारतीय जनता पार्टी को दगा देने में कोई संकोच नहीं किया। शरद पवार ने कांग्रेस नेतृत्व को राजी किया और उन्हें उद्धव ठाकरे का समर्थन करने के लिए मजबूर किया और अपनी सरकार बना ली, लेकिन फडणवीस ने जून 2022 में पवार साहब की साजिश को माकूल जवाब दे दिया। केवल ढाई साल की अवधि के लिए उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने। अब वही ठाकरे शरद पवार के हाथों खिलौना बने हुए हैं।

नोएडा में खंभों की मजबूती पर खर्च होंगे 36 करोड़

नोएडा, (पंजाब केसरी) : सेक्टर-96 में बन रहे नोएडा प्राधिकरण के नए कार्यालय के कमजोर खंभों की मजबूती का काम सितंबर में शुरू होगा। प्राधिकरण ने इस भवन के रेट्रो फिटिंग कार्य के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस कार्य पर प्राधिकरण करीब 36 करोड़ खर्च करेगा। अगले सात-आठ महीने में नया कार्यालय बनकर तैयार होने की उम्मीद है। आईआईटी की जांच में नोएडा प्राधिकरण के नए कार्यालय भवन के 200 खंभे कमजोर पाए गए थे। सैंपल रिपोर्ट के आधार पर नोएडा प्राधिकरण ने पूरी बिल्डिंग के इन खंभों को चिह्नित कर मजबूती बढ़ाने का एस्टीमेट तैयार किया है। एस्टीमेट का आईआईटी से परीक्षण कराने के बाद प्राधिकरण ने कार्य के लिए टेंडर जारी कर दिया है। इस पर करीब 36 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

वंदे भारत ट्रेन भारत के तीव्र विकास की है गाथा : मुख्यमंत्री नायब सिंह

चंडीगढ़, राजेश जैन (पंजाब केसरी) : हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में तीव्र गति से विकास हुआ है और वंदे भारत जैसी ट्रेन इसका उदाहरण है। उनका सौभाग्य है कि आज वे वंदे भारत ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आज चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से अमृतसर-अजमेर वंदे भारत ट्रेन से दिल्ली के लिए रवाना होने से पहले पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा झूठ बोलकर देश कमजोर करने का कार्य किया है, जबकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत मजबूत हुआ है। कांग्रेस के हरियाणा मांगे हिसाब अभियान के बारे पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले अपने 10 साल के कार्यकाल का हिसाब दें। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों में गरीब व्यक्ति की थानों में एफआईआर तक नहीं दर्ज होती थी। गरीबों को नौकरी नहीं मिलती थी, किसानों को फसल खराबे का उचित मुआवजा नहीं मिलता था और फसलों की एमएसपी भी नहीं मिलती थी। आज 14 फसलों की हरियाणा में एमएसपी पर खरीद होती है। गरीब से गरीब व्यक्ति को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने पवित्र संविधान पर बड़ा झूठ बोलकर अपमान किया। रेलवे स्टेशन पहुंचने पर स्टेशन सुपरिंटेंडेंट डीके सिंह तथा संजीव कुमार चौधरी ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और प्लेटफार्म तक उनकी अगुवाई की। बार-बार दिल्ली में बैठकों के बारे में पूछे जाने वाले प्रश्न के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय मंत्रियों से कई योजनाओं पर चर्चाओं के लिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्री दिल्ली आते रहते हैं। हरियाणा में शीघ्र ही विधानसभा चुनाव होने हैं और भाजपा तीसरी बार प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी।

नोएडा में सीईओ ने औद्योगिक सेक्टर का किया दौरा

नोएडा, (पंजाब केसरी) : नोएडा प्राधिकरण सीईओ डॉ. लोकेश एम ने सोमवार को औद्योगिक सेक्टर-164 का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सेक्टर में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया और प्रगति का जायजा लिया। सीईओ के साथ सिविल विभाग के उप महाप्रबंधक विजय रावल और वरिष्ठ प्रबंधक सतेंद्र गिरि और प्रबंधक वैभव नगर भी मौजूद रहे। नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि सेक्टर-164 नोएडा का एक महत्वपूर्ण विकासशील औद्योगिक क्षेत्र है, जिसमें कुल 67 औद्योगिक भूखंड नियोजित हैं। इनमें से 58 भूखंडों का कब्जा देने की सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं, जिनमें से 14 भूखंडों का भौतिक कब्जा उद्यमियों को दिया जा चुका है।

कोरोनिल को लेकर किए गए दावे वापस ले पतंजलि : हाईकोर्ट

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को कोरोना महामारी के दौरान लाखों लोगों की मौत के लिए एलोपैथी डॉक्टर्स को दोषी ठहराने और पतंजलि की कोरोनिल दवा को इलाज के रूप में बढ़ावा देने वाले सभी दावों को वापस लेने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर तीन दिन के अंदर बाबा रामदेव अपने बयान को वापस नहीं लेते हैं तो सोशल मीडिया प्लेटफार्म इसे तुरंत हटा दें। दरअसल, रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी और बाबा रामदेव की पंतजलि आयुर्वेद कंपनी की दवा कोरोनिल को कोविड का शर्तिया इलाज होने का दावा करने पर आपत्ति जताई थी। उस समय बाबा रामदेव ने कहा था कि कोरोनिल सिर्फ इम्युनिटी बूस्टर नहीं, बल्कि कोविड-19 ठीक करने की दवा है।

दिल्ली आर.एन.आई. नं. 40474/83
पंजाब केसरी
दिल्ली कार्यालय :
फोन आफिस: 011-30712200, 45212200,
प्रसार विभाग: 011-30712224
विज्ञापन विभाग: 011-30712229
सम्पादकीय विभाग: 011-30712292-93
मैगजीन विभाग: 011-30712330
फैक्स : 91-11-30712290, 30712384, 011-45212383, 84
Email: Editorial@punjabkesari.com

स्वत्वाधिकारी दैनिक समाचार लिमिटेड, 2-प्रिंटिंग प्रेस कॉम्पलैक्स, नजदीक वजीरपुर डीटीसी डिपो, दिल्ली-110035 के लिए मुद्रक, प्रकाशक तथा सम्पादक अनिल शारदा द्वारा पंजाब केसरी प्रिंटिंग प्रेस, 2-प्रिंटिंग प्रेस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से मुद्रित तथा 2, प्रिंटिंग प्रेस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से प्रकाशित।

नये औद्योगिक शहर

देश में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को गति देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने 12 नये औद्योगिक शहरों की स्थापना का निर्णय लिया है. इन शहरों के लिए जगहों की पहचान की जा चुकी है. ये शहर ढुलाई और राजमार्ग गलियारों के किनारे बसाये जायेंगे. नये औद्योगिक शहर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना और महाराष्ट्र में स्थापित किये जायेंगे. इस वर्ष के पूर्ण बजट में रोजगार और विकास पर अधिक ध्यान दिया गया है. अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाये रखने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सरकार ने अपनी प्रमुख प्राथमिकताओं में रखा है. इससे निर्यात में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है. आर्थिक सुधारों के साथ-साथ निवेश संबंधी नियमों को सरल बनाने से कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां और बड़े निवेशक भारत की ओर आकर्षित हो रहे हैं. इस पृष्ठभूमि में नये शहरों की जरूरत बढ़ती जा रही है. इन शहरों के लिए जल्दी ही कैबिनेट की मंजूरी मिलने की उम्मीद है. सरकार 10-12 हजार करोड़ की लागत से बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर बनायेगी, जिसके बाद इन शहरों में कंपनियों के लिए जगहें आवंटित की जायेंगी. उल्लेखनीय है कि जब डेढ़ दशक पहले दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारे के पहले चरण की परिकल्पना की गयी थी, तब गुजरात में धोलेरा, मध्य प्रदेश में विक्रम उद्योगपुरी, महाराष्ट्र में शेंद्रा बिडकीन और दिल्ली के निकट उत्तर प्रदेश में दादरी को विकसित करने की योजना बनी थी. उसके बाद आंध्र प्रदेश में कृष्णापट्टनम, कर्नाटक में तुमाकुरु, हरियाणा में नांगल चौधरी तथा उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा का विकास हुआ. नये 12 शहर बनाने में भी उसी मॉडल का अनुपालन किया जायेगा, जिसके आधार पर पूर्ववर्ती औद्योगिक शहरों को स्थापित किया गया है. ऐसी परियोजनाओं को पूरा करने में 10-15 साल लग जाते हैं, पर केंद्रीय सचिव राजेश कुमार सिंह ने आशा जतायी है कि नयी परियोजनाओं में कम समय लगेगा क्योंकि प्रस्तावित शहर बड़े शहरों के नजदीक हैं. इन शहरों की स्थापना में इसलिए भी कम समय लग सकता है कि इनका आकार कम है. उल्लेखनीय है कि अपने बजट संबोधन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह घोषणा भी की है कि देश के 100 शहरों में या उनके निकट ऐसे औद्योगिक पार्कों को स्थापित करने की योजना है, जिनमें सभी इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध होंगे. औद्योगिक गलियारों के विकास से देशभर में सड़कों, भंडारण केंद्रों, रिहायशी इलाकों, रेल स्टेशनों, हवाई अड्डों आदि का एक विशाल नेटवर्क बनता जा रहा है. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के विकास में एक बड़ी चुनौती कौशलयुक्त श्रम बल का अभाव है. औद्योगिक पार्कों एवं शहरों के बनते जाने के साथ कौशल विकास भी होता रहा है, तो भारत निश्चित ही एक औद्योगिक शक्ति बनकर उभरेगा.

नये औद्योगिक शहर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना और महाराष्ट्र में स्थापित किये जायेंगे.

नये तेवर एवं कलेवर में अखिलेश यादव

प्रभु चावला
एडिटोरियल डायरेक्टर
द न्यू इंडियन एक्सप्रेस
prabhuchawla@newindianexpress.com

उन्होंने पिता के राजनीतिक गठबंधन- मुस्लिम एवं यादव- में बदलाव कर पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक (पीडीए) का नया नारा दिया. इसका बड़ा असर हुआ और सपा की सीटें पांच से बढ़कर 37 हो गयीं. अधिकतर उम्मीदवार गैर-यादव थे. अखिलेश ने एक आधुनिकतावादी- उदारवादी एवं पूंजीवादी मूल्यों के साथ मानवता-भाषा सीख ली है, जो उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल से इंगित होता है.

कभी भारत में एक बड़े पहलवान हुआ करते थे, जिनका नाम था मुलायम सिंह यादव. वे चक्र दांव में माहिर थे. समाजवादी पार्टी बनाकर उन्होंने उत्तर प्रदेश के राजनीतिक अखाड़े में भी बड़ी जीतें दर्ज कीं और बाद में राष्ट्रीय राजनीति की कई प्रतिस्पर्धाओं में रेफरी भी रहे. उनके पुत्र अखिलेश यादव ने स्टारडम का रहस्य समझा है- 141 करोड़ भारतीयों और 543 सांसदों द्वारा देखा और सुना जाना. कई युवा सांसद अपनी राजनीतिक हैसियत बेहतर करने के लिए नये-नये मित्र बना रहे हैं. अखिलेश सांसद से कहीं अधिक हैं- वे मुख्यमंत्री रह चुके हैं. क्षेत्रीय दलों के एक धरने में अखिलेश ने यह रेखांकित किया कि क्षेत्रीय ही राष्ट्रीय है. धरने पर उन्हें आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने आमंत्रित किया था. दोनों नेता सामाजिक या राजनीतिक रूप से शायद ही मिलते हैं. फिर भी अखिलेश ने आमंत्रण स्वीकार किया. यह समझदारी भरा कदम है क्योंकि वे अपना प्रभाव उत्तर भारत से आगे बढ़ाना चाहते हैं तथा 2029 तक समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाना चाहते हैं. बिना जाति का कार्ड खेले और मुलायम सिंह के लोहियावादी भार से मुक्त होकर वे स्वयं को आधुनिक मानस के साथ राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित करना चाहते हैं. सपा यादववाद को पीछे छोड़ चुकी है. लोकसभा चुनाव में 37 सीटों पर जीत के साथ तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद से अखिलेश बहुत सक्रिय हैं.

उनके शोध-आधारित भाषणों में कटाक्ष, कविता और विचारधारा का पुट रहता है. वे विभिन्न दलों के नेताओं से मिल रहे हैं और मीडिया से लगातार बातचीत कर रहे हैं. उन्होंने भविष्य की रणनीति बनाने के लिए अपने संसदीय दल की बैठकें की हैं. पार्टी सूत्रों के अनुसार, उन्होंने विपक्ष के बड़े नेताओं के साथ व्यक्तिगत और सामूहिक बैठकें भी की हैं. वे अपनी पत्नी डिंपल यादव के साथ लोकसभा अवश्य आते हैं तथा कैनेडी दंपत्ति के अंदाज में यह संकेत देते प्रतीत होते हैं कि ये आकर्षक राजनीतिक दंपत्ति अपने देश के लिए अच्छे इरादे रखते हैं. उन्होंने संसदीय एजेंडे को प्रभावित करने में सक्रिय भूमिका निभायी है. इस वर्ष उन्होंने कोलकाता, पटना, चेन्नई और मुंबई की यात्रा की है. यह उनके राजनीतिक स्टाइल में बड़ा बदलाव है. बीते एक दशक वे लखनऊ में रहे तथा विश्वस्त सहयोगियों से मिलते रहे. पार्टी की बैठकों के लिए ही वे घर से निकलते थे. शेष समय वे परिवार के साथ बिताते थे. अब कई साल बाद देश एक युवा क्षेत्रीय नेता को राष्ट्रीय भूमिका के लिए प्रयासरत देख रहा है. ममता बनर्जी, एमके स्टालिन और तेजस्वी यादव आम तौर पर अपने राज्यों में ही टिके हैं, जबकि अखिलेश दिल्ली में अपने सांसदों से जुड़े हुए हैं. उन्होंने गठबंधन बनाने-तोड़ने के भी प्रयोग किये हैं. असफलताओं के बावजूद वे डटे हुए हैं क्योंकि उम्र उनके पक्ष में है.

अखिलेश का मुख्य उद्देश्य सपा को एक समावेशी मंच बनाना तथा शीर्ष पर पहुंचना है. उन्होंने अपने पिता के स्टाइल से अलग रवैया अपनाया है तथा वे पुराने दागी नेताओं को हटा रहे हैं. मुलायम सिंह कांग्रेस-विरोध के एजेंडे पर जीतते थे. साल 2014 में उन्होंने चुनाव से ठीक पहले अपने वोट ट्रांसफर कराकर राहुल गांधी को जिताया था. साल 1998 में उन्होंने सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया था, पर कुछ साल बाद वे राष्ट्रपति पद के दावेदार प्रणव मुखर्जी के लिए समर्थन मांगने दस जनपथ गये. अखिलेश अपने पिता के पद-चिह्नों पर चल रहे हैं, पर इस मामले में बहुत अंतर भी है. पहले उन्हें अपने परिजनों से लड़ना पड़ा. मुलायम सिंह ने 2012 में विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश सपा का अध्यक्ष बनाया था. उनके दौरों ने अखिलेश को राज्य का पहला यूथ आइकन बना दिया और सपा को दो-तिहाई सीटें मिलीं. मुख्यमंत्री के रूप में जब अखिलेश अपना प्रभाव दिखाने लगे, तो परिवार के भीतर से ही उनका विरोध शुरू हो गया. उन्होंने मुलायम के बताये नामों को पद से हटा दिया. इससे नाराज होकर मुलायम सिंह ने अखिलेश को पार्टी से निकाल दिया. बेटे ने जवाब में पिता को ही अध्यक्ष पद से हटा दिया और पार्टी की कमान अपने हाथ में ले ली. अखिलेश शायद अकेले ऐसे भारतीय राजनेता हैं, जिनके पास ऐसा सलाहकार नहीं है, जिसके पास अपार शक्तियां हों. देशी-विदेशी संस्थानों से पर्यावरण इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके अखिलेश ने पर्यावरण प्रबंधन की कला में भी महारत पा ली है.

यादवों ने उन्हें पांच चुनाव में जीत दिलायी है, पर उनके इर्द-गिर्द कोई यादव नहीं है. उन्हें यादव के नेतृत्व वाली पार्टी को यादवों से मुक्त कर दिया है. अखिलेश ने अपने परिवार को राजी किया कि अगर उन्हें देश पर कभी शासन करना है, तो दूसरे समुदायों के साथ सत्ता में साझेदारी करनी होगी. उन्होंने पिता के राजनीतिक गठबंधन- मुस्लिम एवं यादव- में बदलाव कर पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक (पीडीए) का नया नारा दिया. इसका बड़ा असर हुआ और सपा की सीटें पांच से बढ़कर 37 हो गयीं. अधिकतर उम्मीदवार गैर-यादव थे. अखिलेश ने एक आधुनिकतावादी- उदारवादी एवं पूंजीवादी मूल्यों के साथ मानवता- भाषा सीख ली है, जो उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल से इंगित होता है. पर वे हड़बड़ी में नहीं हैं. वे पांच बार सांसद रहे हैं, 38 साल की आयु में मुख्यमंत्री और 45 साल में पार्टी अध्यक्ष बन चुके हैं. वे बहुत सोच-समझ कर अपनी राजनीतिक यात्रा पर बढ़ रहे हैं. वे अपनी राजनीतिक पहचान से टिके हुए हैं. भले ही कांग्रेसियों ने गांधी टोपी को त्याग दिया है, अखिलेश हर आयोजन में लाल टोपी के साथ अलग नजर आते हैं. वे दिल से समाजवादी हैं और मन से खुले विचार के. वे विनम्र हैं तथा उन्होंने कभी भी किसी भाजपा नेता के लिए कटु शब्दों का प्रयोग नहीं किया है. उत्तर प्रदेश की राजनीति में ध्रुवीकरण है, पर मुख्यमंत्री के रूप में योगी तथा विपक्ष के नेता के तौर पर अखिलेश के बीच व्यवहार हमेशा सभ्य रहा क्योंकि दोनों के लिए राज्य सबसे पहले आता है. दोनों की आयु लगभग समान है और भविष्य में दोनों ही प्रधानमंत्री पद के संभावित उम्मीदवार हैं. सवाल है कि 'यूपी के लड़के' (राहुल और अखिलेश) में विजेता कौन होगा. इसका कुछ जवाब 2027 के विधानसभा चुनाव से मिलेगा. इस संबंध में मुलायम की सीख है- मैच हारना ठीक है, अगर आप टूर्नामेंट जीतते हैं, तो मैच हारना ठीक है. राजनीति में कुछ स्थायी दोस्त और दुश्मन होते हैं, पर स्थायी हितों से समझौता नहीं होता.

(ये लेखक के निजी विचार हैं.)

पटरियों के किनारे जमा कचरे का निपटान करे रेलवे

पंकज चतुर्वेदी
वरिष्ठ पत्रकार
pc7001010@gmail.com

रेल पटरियों के किनारे की कई-कई हजार एकड़ भूमि अवैध अतिक्रमणों की चपेट में हैं. इन पर राजनीतिक संरक्षण प्राप्त भू-माफिया का कब्जा है, जो वहां रहने वाले गरीब मेहनतकश लोगों से वसूली करते हैं. इनमें से बड़ी संख्या में लोगों के जीविकोपार्जन का जरिया कूड़ा बीनना या कबाड़ी का काम करना ही है.

बीते छह जुलाई को केरल हाईकोर्ट ने एक स्वतः संज्ञान मामले में कहा कि रेलवे थोक में कचरा उपजा रहा है क्योंकि पटरियों पर पाया जाने वाला अधिकांश कचरा ट्रेनों से आता है. न्यायालय ने कहा कि रेलवे का कर्तव्य है कि वह ऐसे कचरा फेंकना बंद करे. अदालत ने यह भी कहा कि पटरियों पर फेंका गया कचरा जल निकायों में बह जाता है, जिससे पर्यावरण को नुकसान होता है. हालांकि स्टेशनों के पास कचरे का उचित प्रबंधन किया जाता है, पर पटरियों के किनारे से कचरा हटाने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाये जाते हैं. कहते हैं कि भारतीय रेल हमारे समाज का असली आईना है. इसमें इंसान नहीं, बल्कि देश के सुख-दुख, समृद्धि-गरीबी, मानसिकता-व्यवहार जैसी कई मनोवृत्तियां सफर करती हैं. भारतीय रेल 66 हजार किलोमीटर से अधिक के रास्तों के साथ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है, जिसमें हर रोज बारह हजार से अधिक यात्री रेल और कोई सात हजार मालगाड़ियां 24 घंटे दौड़ती हैं. इस नेटवर्क में हर रोज लगभग 2.30 करोड़ यात्री सफर करते हैं तथा एक अरब मीट्रिक टन सामान की ढुलाई होती है. दुखद है कि पटरियों के किनारे कूड़ा-कचरा सिस्टम की उपेक्षा की तस्वीर प्रस्तुत करते हैं. कई जगह तो प्लेटफार्म भी अतिक्रमण, अवांछित गतिविधियों और गंदगी का ढेर बने हुए हैं.

दिल्ली से आने-जाने वाले सभी रास्ते विदेशी पर्यटकों के लोकप्रिय रूट हैं और जब दिल्ली आने से 50 किलोमीटर पहले से ही पटरियों के दोनों तरफ कूड़े, गंदे पानी, बदबू का अंबार दिखता है, तो उनकी निगाह में देश की कैसी छवि बनती होगी! यह सब उन विज्ञापनों को मुंह चिढ़ाते दिखते हैं, जिनमें स्वच्छता अभियान की उपलब्धियों के आंकड़े दिखाये जाते हैं. असल में रेल पटरियों के किनारे की कई-कई हजार एकड़ भूमि अवैध अतिक्रमणों की चपेट में हैं. इन पर राजनीतिक संरक्षण प्राप्त भू-माफिया का कब्जा है, जो वहां रहने वाले गरीब मेहनतकश लोगों से वसूली करते हैं. इनमें से बड़ी संख्या में लोगों के जीविकोपार्जन का जरिया कूड़ा बीनना या कबाड़ी का काम करना ही है. ये लोग पूरे शहर का कूड़ा जमा करते हैं, अपने काम का सामान निकाल कर बेच देते हैं और बाकी को पटरियों के किनारे ही फेंक देते हैं, जहां धीरे-धीरे गंदगी के पहाड़ बन जाते हैं. यह भी आगे चल कर नयी झुग्गी का मैदान होता है. दिल्ली से फरीदाबाद रास्ते को ही लें, जो औद्योगिक क्षेत्र है. हर कारखाने वाले के लिए रेल की पटरी की तरफ का इलाका अपना कूड़ा, गंदा पानी आदि फेंकने का निशुल्क स्थान होता है. यहां काम करने वालों के आवास, नित्यकर्म का भी बेरोकटोक गलियारा रेल पटरियों की ओर ही खुलता है.

कचरे का निपटारा पूरे देश के लिए समस्या बनता जा रहा है. सरकार भी मानती है कि देश के कुल कूड़े का महज पांच प्रतिशत का ही ईमानदारी से निपटान हो पाता है. दिल्ली का तो 57 फीसदी कूड़ा परोक्ष या अपरोक्ष रूप से यमुना में बहा दिया जाता है या फिर पटरियों के किनारे फेंक दिया जाता है. कूड़ा-कचरे की गंभीर होती समस्या पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है. पटरियों के किनारे जमा कचरे में खुद रेलवे का भी बड़ा योगदान है. शताब्दी, वंदे भारत, राजधानी एक्सप्रेस जैसी प्रीमियम गाड़ियों में यात्रियों को अनिवार्य रूप से तीन से आठ बार तक भोजन परोसा जाता है. इन दिनों पूरा भोजन पैक्ड और एक बार इस्तेमाल होने वाले बर्तनों में ही दिया जाता है. यह हर रोज होता है कि अपना मुकाम आने से पहले खानपान की व्यवस्था करने वाले कर्मचारी बचा भोजन, बोतल, पैकिंग सामग्री के बड़े-बड़े थैले चलती ट्रेन से पटरियों के किनारे ही फेंक देते हैं. यदि हर दिन एक रास्ते पर दस डिब्बों से ऐसा कचरा फेंका जाए, तो जाहिर है कि एक साल में उस वीराने में प्लास्टिक जैसी नष्ट नहीं होने वाली चीजों का अंबार लग जायेगा. कागज, प्लास्टिक, धातु जैसा बहुत-सा कूड़ा तो कचरा बीनने वाले जमा कर रिसाइकलिंग करने वालों को बेच देते हैं. सब्जी के छिलके, खाने-पीने की चीजें, मरे हुए जानवर आदि कुछ समय में सड़-गल जाते हैं. इसके बावजूद ऐसा बहुत कुछ बच जाता है, जो हमारे लिए विकराल संकट का रूप लेता जा रहा है.

उल्लेखनीय है कि यही हाल इंदौर या पटना या बेंगलुरु या गुवाहाटी या इलाहाबाद के रेलवे ट्रैक के भी हैं. शहर आने से पहले गंदगी का अंबार पूरे देश में एक जैसा ही है. दिल्ली हो या फिर दूरस्थ कस्बे का रेलवे प्लेटफॉर्म, निहायत गंदे, भीड़ भरे, अव्यवस्थित और अवांछित लोगों से भरे होते हैं, जिनमें भिखारी से लेकर अवैध वेंडर और यात्री को छोड़ने आये परिजनों से लेकर भांति-भांति के लोग होते हैं. ऐसे लोग रेलवे की सफाई के सीमित संसाधनों को तहस-नहस कर देते हैं. कुछ साल पहले बजट में 'रेलवे स्टेशन विकास निगम' के गठन की घोषणा की गयी थी, जिसमें रेलवे स्टेशन को हवाई अड्डे की तरह चमकाने के सपने दिखाये थे. कुछ स्टेशनों पर काम भी हुआ, लेकिन जिन पटरियों पर रेल दौड़ती है और जिन रास्तों से यात्री रेलवे व देश की सुंदर छवि देखने की कल्पना करता है, उनके उद्धार के लिए रेलवे के पास न तो कोई रोड-मैप है और न ही परिकल्पना. **(ये लेखक के निजी विचार हैं.)**

https://t.me/AllNewsPaperPaid

देश दुनिया

नेपाल पर फिर से मंडरा रहा है पोलियो का खतरा

THE KATHMANDU POST
WITHOUT FEAR OR FAVOUR

नेपाल में लगातार तीन वर्षों तक पोलियो के एक भी मामले सामने न आने के बाद 2014 में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने देश को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया था. हालांकि कुछ दिनों पूर्व स्वास्थ्य और जनसंख्या मंत्रालय ने पोलियो वायरस के फिर से उभरने की घोषणा की, जिससे काठमांडू में पोलियो टीकाकरण अभियान की तैयारी तेज हो गयी. हालांकि यह वायरस क्लीनिकल नमूनों के बजाय नाला/ नदी के पानी के नमूनों में पाया गया था, पर यह नेपाल में स्वास्थ्य खतरों के बारे में गंभीर चिंता पैदा करता है. ये नमूने काठमांडू के नाले में मिले थे. वर्तमान में, नेपाल में पाये गये पोलियो वायरस का स्रोत अज्ञात बना हुआ है. पोलियो वायरस के लिए कोई विशिष्ट एंटी-वायरल दवा उपलब्ध नहीं है. ओरल पोलियो वैक्सीन (ओपीवी) का नेपाल सहित दुनियाभर में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है. इसमें जीवित, कमजोर पोलियो वायरस होता है, जो टीका लगाये गये बच्चे के शरीर में प्रतिकृति बनाता है और जब बच्चा मल त्याग करता है तो यह दूसरों में फैल जाता है. वर्तमान में काठमांडू में पाये गये वायरस से व्युतपन्न पोलियो वायरस को टाइप-3 कहा गया है. कई शोधकर्ताओं का मानना है कि कम टीकाकरण कवरेज और कम टीकाकरण वाली जनसंख्या के बीच ओपीवी से फैलने वाला कमजोर वायरस समुदाय में वैक्सीन व्युत्पन्न पोलियो वायरस के उद्भव के लिए अनुकूल स्थितियों को बढ़ावा देता है. फिलहाल, वैक्सीन व्युत्पन्न पोलियो वायरस का उद्भव कोई महत्वपूर्ण स्वास्थ्य जोखिम पैदा नहीं कर सकता है. इन उत्परिवर्तित वायरस का लगातार पता चलने से नेपाल और दुनियाभर में महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं. सो, नेपाल की पोलियो उन्मूलन स्थिति को बनाये रखने के लिए बच्चों में टीकाकरण की निगरानी और उसका अनुपालन महत्वपूर्ण हो गया है.

-डॉ शेर बहादुर पुन

बोधि वृक्ष

ध्यान का महत्व

आज हमारा जीवन दूसरों की एक मुस्कुराहट पर आश्रित है. कोई हमारी ओर देखे, मुस्कुराए तो हम प्रसन्न हो जाते हैं, अन्यथा निराश हो जाते हैं. इस प्रकार, हम कभी स्वयं के होकर नहीं रहते और अपने लक्ष्य से चूक जाते हैं. अतः, हमें चाहिए कि अपने कर्मों में सजग हों, जागृत हो कर रहें. इसका सरलतम उपाय है ध्यान. सदा याद रखो कि ध्यान स्वर्ण के समान अनमोल है. यह सांसारिक समृद्धि, मुक्ति तथा मन की शांति की प्राप्ति में सहायक होता है. कहते हैं कि ध्यान, जप से दस लाख गुणा बढ़ कर है. अर्थात, ध्यान में लगाया गया थोड़ा सा समय लाखों की संख्या में किये मंत्र जप के समान होता है. आंखें मूंद कर, फर्श पर आलती-पालथी लगाकर बैठ जाने का नाम ही ध्यान नहीं होता. अपने कर्मों, विचारों तथा वचनों में सजगता विकसित करना ही सच्चा ध्यान है. विचार पानी की छोटी-छोटी बूंदों के समान हैं, एकत्रित हो जाएं, तो वचनों तथा कर्मों की विशाल नदी बन जाएं. एक छोटा सा विचार हमारे भीतर पनप कर, एक विशाल नदी बनकर बाहर बह निकलता है और फिर हमारे वश से बाहर हो जाता है. प्रारंभ होती हुई एक नदी को रोक देना कठिन नहीं है, किंतु बड़ी होने पर यह हमारे वश की बात नहीं होती. अतः हमें अपने विचारों के प्रति सजग रहना चाहिए, क्योंकि विचार वचन का रूप लेते हैं और वचन कर्म का. फिर इसके प्रवाह की दिशा में परिवर्तन अत्यंत कठिन हो जाता है. इसलिए हमें अपने विचार, वचन तथा कर्म को लेकर अति सजग रहना चाहिए. यदि सांचा ही बिगड़ जाए, तो उसमें डाला गया कोई भी पदार्थ ठीक नहीं बनेगा. उसी प्रकार, यदि हम अपने मन का निर्देशन भलीभांति नहीं करते, तो उसमें से जो भी आयेगा- विचार अथवा वचन- अनुचित ही होगा. अतः, सर्वप्रथम अपने मन को संयमित करो. इसका एकमात्र उपाय ध्यान है. ध्यान के माध्यम से हमारा अपने भीतरी मौन से आमना-सामना होता है. ध्यान जीवन का आवश्यक अंग है. इससे हमारे मन-वचन-कर्म पवित्र होते हैं. प्रतिदिन थोड़ा समय ध्यान के लिए अवश्य रखना चाहिए.

-श्री माता अमृतानंदमयी देवी

अंतरराष्ट्रीय मैत्री दिवस

एकजुट दुनिया की राह बनाती है मैत्री

देवेंद्रराज सुथार
टिप्पणीकार
devendrakavi1@gmail.com

हमारा विश्व गरीबी, हिंसा, मानवाधिकार हनन जैसी अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा है, इससे शांति, सुरक्षा, विकास और सामाजिक सद्भाव कमजोर होते हैं. इन संकटों और चुनौतियों का सामना करने के लिए मानव एकजुटता की साझा भावना को बढ़ावा देने और उसका बचाव करके उनके मूल कारणों का समाधान किया जाना चाहिए. जिसका सबसे सरल तरीका है- मैत्री. मैत्री के माध्यम से सौहार्दपूर्ण संबंधों को सिंचित और विश्वास के मजबूत संबंध विकसित कर हम उन मूलभूत बदलावों में योगदान दे सकते हैं जो स्थायी स्थिरता प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं.

उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2011 में अंतरराष्ट्रीय मैत्री दिवस की घोषणा इस विचार के साथ की गयी थी कि देशों, संस्कृतियों और व्यक्तियों के बीच मैत्री शांति प्रयासों को प्रेरित और समुदायों के बीच सेतु का निर्माण कर सकती है. प्रस्ताव में युवाओं को भावी नेताओं के रूप में सामुदायिक गतिविधियों में शामिल करने पर जोर दिया गया है, जिससे अंतरराष्ट्रीय समझ और विविधता के प्रति सम्मान को बढ़ावा मिले. दरअसल मैत्री दिवस की यह पहल यूनेस्को द्वारा शांति की संस्कृति को मूल्यों, दृष्टिकोणों और व्यवहारों के एक समूह के रूप में परिभाषित करने के प्रस्ताव पर आधारित है, जो हिंसा को अस्वीकार करते हैं और समस्याओं को हल करने के उद्देश्य से उनके मूल कारणों को संबोधित करके संघर्षों को रोकने का प्रयास करते हैं. इसे 1997 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था.

मैत्री सीमाओं, संस्कृतियों और विचारधाराओं से परे होती है और यह ऐसे माहौल को बढ़ावा देती है, जहां विश्वास और आपसी सम्मान पनप सकता है. अतः वैश्विक शांति और सद्भाव प्राप्त करने में मैत्री के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता. राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक मतभेदों से अक्सर विभाजित दुनिया में मैत्री सुलह और सहयोग की राह प्रदान करती है. मैत्री के माध्यम से हम विविधता की समृद्धि की सराहना करना सीखते हैं. इस प्रयास में युवाओं की भागीदारी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है. यह दिवस सरकारों, संगठनों और व्यक्तियों के लिए सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा देने वाली पहलों में निवेश करने के लिए कार्रवाई का आह्वान भी करता है. अंतर-सांस्कृतिक संवाद और समझ को प्रोत्साहित करने वाले कार्यक्रमों को प्राथमिकता देकर समाज शांति और सहयोग की नींव को मजबूत कर सकता है. वैश्विक अनिश्चितता के समय मैत्री बनाने का कार्य एकजुट दुनिया का मार्ग प्रशस्त कर सकता है.

आपके पत्र

मॉनसून की बेरुखी से सूखे खेत

मॉनसून की बेरुखी से किसान परेशान हैं. सावन महीने में भी धूल उड़ रहे हैं और खेतों में दरारें पड़ गयी हैं. धान के बिचड़े सूख रहे हैं. किसान हलकान हैं और खेतिहर मजदूर हांफ रहे हैं. सावन महीना मनभावन व हरियाली का होता था, लेकिन समय के साथ सब बदल गया. संसद व बिहार विधानमंडल के सत्र चालू हैं, लेकिन वहां भी किसानों की कोई आवाज नहीं उठ रहा है. हाल ही में संसद में बजट पेश हुए. बड़े-बड़े अर्थशास्त्री बजट की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन किसानों की फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कोई कुछ नहीं कह रहा है.

प्रसिद्ध यादव, पटना

दूषित पानी पीने से पड़ रहे बीमार

पानी में हानिकारक पदार्थों जैसे सूक्ष्म जीव, रसायन, औद्योगिक, घरेलू या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से उत्पन्न दूषित जल आदि से शुद्ध पेयजल खराब हो गया है. देश के 639 में से 158 जिलों के कई हिस्सों में पानी खारा हो चुका है. भूजल के दूषित जल को शुद्ध करना बेहद कठिन कार्य है. नदी-तालाब आदि का 70 प्रतिशत पानी प्रदूषित हो चुका है. सरकारी आकड़ों के अनुसार 78 फीसदी ग्रामीण और 59 फीसदी शहरी घरों तक स्वच्छ पानी नहीं पहुंच रहा है. देश में 3.77 करोड़ लोग प्रति वर्ष दूषित पानी से बीमार हो रहे हैं.

सतीश कुमार, बेतिया

पोस्ट करें : प्रभात खबर, प्लॉट संख्या डी-9-10, पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल एरिया, पटना (बिहार) - 800013, ■ **मेल करें :** patna@prabhatkhabar.in पर ■ ई-मेल संक्षिप्त व हिंदी में हो. लिपि रोमन भी हो सकती है.

हिन्दुस्तान
1936
सत्य • सार्थक • सदैव

सियासत से आगे

राष्ट्रीय राजधानी के पुराने राजेंद्र नगर में एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में तीन छात्रों की त्रासद मौत के बाद नगर संस्थाओं और कानून व्यवस्था की एजेंसियों की सक्रियता संतोष की बात है। कोई आश्चर्य नहीं कि हर जिम्मेदार संस्था खुद को बचाने में लग गई है और आरोपियों के खिलाफ पूरी कड़ाई भी बरती जा रही है। दिल्ली नगर निगम ने रविवार को शहर के 13 अन्य सिविल सर्विस कोचिंग सेंटरों के बेसमेंट को सील कर दिया है। पीड़ित और आक्रोशित छात्र कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और सरकारी संस्थाओं को बेहिचक सुधार पर ध्यान देना चाहिए। जो भी सेंटर बेसमेंट या भूतल में चल रहे हैं, उनको बंद कराना जरूरी है। इसमें कोई शक नहीं कि कम किराये और अधिकतम फायदे के लिए ऐसे कोचिंग संचालक बेसमेंट को तरजीह देते हैं। मगर क्या बेसमेंट या खासकर प्रतिकूल मौसम में इनमें कक्षाओं का आयोजन बंद नहीं होना चाहिए? क्या जरा भी आशंका नहीं थी कि बेसमेंट में पानी जानलेवा भी हो सकता है? पुलिस ने छह से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया है, पर वास्तव में कार्रवाई उन लोगों पर होनी चाहिए, जो विद्यार्थियों की सुरक्षा के प्रति लापरवाह थे।

पहली नजर में कोचिंग सेंटर ने अक्षम्य लापरवाही का परिचय दिया। जब घटना शाम 6:35 बजे घटी, तब पुलिस और अग्निशमन विभाग के अधिकारियों को सूचना शाम 7:10 बजे क्यों दी गई? पानी इतना भर गया कि डूबे हुए छात्रों तक पहुंचने के लिए गोताखोरों को बुलाना पड़ा। अगर हम पीछे पलटकर देखेंगे, तो इंतजाम में अनगिनत कमियां नजर आएंगी, मगर अब जरूरत आगे की सुध लेने की है। आज हो क्या रहा है? दोषारोपण का दौर चल रहा है। दिल्ली की व्यवस्था के लिए जिम्मेदार संस्थाएं और नेता एक-दूसरे के सामने आ खड़े हुए हैं, तो इससे चिंता ही बढ़ती है। एक-दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे लोग अगर दिल्ली की सुरक्षा के लिए मिलकर काम करते, तो शायद यह हादसा ही नहीं होता।

देश भर से छात्र पढ़ने के लिए दिल्ली आते हैं, क्योंकि उनको यहां की व्यवस्था पर भरोसा है, पर अब दिल्ली को सोचना चाहिए कि वह उम्मीदों पर कितनी खरी उतर रही है?

दिल्ली में भवनों से जुड़े अनापत्ति-प्रमाणपत्र कैसे लिए-दिए जा रहे हैं? जहां पार्किंग और भंडारण की सुविधा होनी चाहिए थी, वहां पुस्तकालय और कक्षाएं कैसे चल रही हैं? इस हादसे के बाद दिल्ली में भवन व्यवस्था में सुधार आए, तो बात बने। आज छात्र सुधारों की मांग कर रहे हैं, पर उनके साथ कौन खड़ा है? देश भर से छात्र पढ़ने के लिए दिल्ली आते हैं, क्योंकि उनको यहां की व्यवस्थाओं पर भरोसा है। वे दिल्ली को अपने गांव-शहर से बेहतर जगह मानते हैं। मगर अब दिल्ली को सोचना चाहिए कि वह देश की उम्मीदों पर कितनी खरी उतर रही है?

बेशक, दिल्ली आज सुविधाओं का एक बड़ा केंद्र है, पर अपनी कमियों से हमने उस पर अक्सर दाग लगाया है। कमियों पर सियासत गलत नहीं, लेकिन जब हर तरफ सियासत ही होने लगे, तब जल्दी समाधान की उम्मीदें कमजोर पड़ने लगती हैं। सियासी दल एक-दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन पर उतर आए हैं। मामला सड़क से संसद तक पहुंच गया है, पर असली मुद्दा यह है कि आज छात्र अपनी सुरक्षा के प्रति कितने आश्वस्त हैं? उन्हें आगे आकर कौन आश्वस्त करेगा? अब समय आ गया है कि शहरों में हम सियासत की ओर बार-बार न देखें, हमारे लिए व्यवस्था का चाक-चौबंद होना सबसे जरूरी है। जो संस्थाएं हैं, उन्हें निर्धारित ढंग से काम करने देना चाहिए। अधिकारियों को सुधार की कमान थमानी चाहिए और युद्ध स्तर पर एक-एक नागरिक की सुरक्षा पुख्ता होनी चाहिए, छात्र और लोग यही चाहते हैं।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 29 जुलाई, 1949

शरणार्थियों की सम्पत्ति

विभाजन के फलस्वरूप लाखों हिन्दू-सिख शरणार्थी पाकिस्तान से भारत आये हैं और उतनी ही बड़ी संख्या में मुस्लिम शरणार्थी भारत से पाकिस्तान गये हैं। इन शरणार्थियों ने अपने पीछे बहुत सी चल-अचल सम्पत्ति छोड़ी है। इस सम्पत्ति के बारे में लाखों व्यक्ति की दिलचस्पी है। वे उसका सन्तोषजनक ढंग से निपटारा करने को उत्सुक हैं। इसीलिए भारत और पाकिस्तान की सरकारें भी इस बारे में दिलचस्पी रखती हैं। उनकी कोशिश यह है कि शरणार्थियों को उनकी सम्पति का उचित मुआवजा मिल जाये। इस सम्बन्ध में भारत और पाकिस्तान के बीच कराची में एक समझौता हुआ था। पाकिस्तान ने एक नया आर्डिनेन्स निकालकर इस समझौते की इतिश्री कर दी है। उसकी यह कार्रवाई इकतरफा है और उससे यह सवाल पैदा होता है कि पाकिस्तान के साथ किये गये समझौतों को आखिर कितना महत्व दिया जाये?

शरणार्थी सम्पत्ति की समस्या को निपटाने का एक तरीका यह हो सकता था कि भारत और पाकिस्तान की सरकारें शरणार्थी सम्पत्ति का संयुक्त रूप से मूल्यांकन करवातीं और स्वयं उस मूल्य को अदा करने की जिम्मेदारी ले लेतीं। यह सबसे सीधा तरीका होता और दोनों सरकारें अपने हिस्से के शरणार्थियों को दिक्कत और परेशानी से बचा लेतीं। किन्तु पाकिस्तान को यह रास्ता मान्य नहीं हुआ। हिन्दू-सिख शरणार्थियों की सम्पत्ति का मूल्य मुस्लिम शरणार्थियों की सम्पत्ति की तुलना में बहुत अधिक है और इसलिए पाकिस्तान यह समझता है कि यदि वह इस जिम्मेदारी को अपने सिर पर ले ले तो उसका दिवाला पिट जायेगा। कराची में शरणार्थी सम्पत्ति के सम्बन्ध में यह समझौता हुआ था कि शरणार्थियों को निजी तौर पर उसे बेचने या अदला-बदली करने की सुविधा दी जायेगी। इस सुविधा का लाभ हिन्दू-सिख शरणार्थियों ने उतना नहीं उठाया, जितना मुस्लिम शरणार्थियों ने। हिन्दू-सिख शरणार्थियों की शिकायत रही कि पाकिस्तान में उनके रास्ते में तरह-तरह के अड़ंगे लगाये जाते हैं, जिससे वे या तो अपनी सम्पत्ति बेच नहीं पाते और यदि बेचते हैं तो बहुत कम मूल्य प्राप्त होता है। इस बीच भारत में शरणार्थी सम्पत्ति सम्बन्धी कानून का क्षेत्र विस्तृत कर दिया गया। अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग कानून प्रचलित हैं, इसलिए समानता लाने की दृष्टि से ऐसा किया गया।

नगरों का प्रबंधन न हो जाए जानलेवा

यहां स्कैन करें
के के पाण्डेय | प्रोफेसर, शहरी प्रबंधन, आईआईपीए

कोई भी अव्यवस्था किसी की जान पर भारी न पड़े, इसलिए अब हमें 'अर्बन रिन्यूअल पॉलिसी', यानी शहरों का नवीनीकरण करने की नीति बनानी होगी।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक के बाद एक हो रहे हादसे शहरी नियोजन की गंभीर कमियों की ओर इशारा कर रहे हैं। राजेंद्र नगर की घटना में, जिस पुस्तकालय में अचानक पानी भर जाने से तीन छात्र-छात्राओं की डूबकर मौत हो गई, उसे बेसमेंट में चलाने की अनुमति ही नहीं थी। इसी तरह, बीती 22 जुलाई को मध्य दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर रहे एक नौजवान की इसलिए मौत हो गई, क्योंकि उसने जल भरे रास्ते से बचने के लिए एक लोहे के गेट को पकड़ लिया था, जिसमें खुले तारों की वजह से करंट दौड़ रहा था। पिछले साल मुखर्जी नगर में एक कोचिंग संस्थान में लगी आग में 60 से अधिक बच्चे घायल हो गए थे, जबकि जहां उनको पढ़ाया जा रहा था, वह स्थान छात्रों की संख्या के हिसाब से काफी छोटा था। साफ है, प्रशासनिक चूक बच्चों के जीवन पर भारी पड़ती दिखी है। इस चूक का खामियाजा महज पीड़ित परिवार नहीं भुगतते, बल्कि राष्ट्र को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ती है, क्योंकि किसी भी देश के लिए मानव संसाधन बेशकीमती होता है।

बहरहाल, ऐसे मसलों पर किसी सियासी आरोप-प्रत्यारोप में उलझे बिना हमें यही सुनिश्चित करना है कि इसका उचित समाधान हो। यह तय करना ही होगा कि कोई भी अव्यवस्था किसी की जान पर भारी न पड़े। इसके लिए हमें 'अर्बन रिन्यूअल पॉलिसी', यानी शहरों के नवीनीकरण की नीति बनानी होगी। वास्तव में, आज भीड़भाड़ वाले अनेक क्षेत्र शहरों के मध्य में आ गए हैं, जबकि वहां का बुनियादी ढांचा आज की जरूरत के हिसाब से नहीं है। वहां नियम-कायदों के पालन में भी काफी दिक्कतें पेश आती हैं। लिहाजा, वहां या तो पूरी तरह रद्दोबदल करते हुए नया ढांचा विकसित किया जाए, अन्यथा जरूरत के हिसाब से मौजूदा ढांचे में ही अपेक्षित सुधार किए जाने चाहिए।

ऐसे क्षेत्रों को तकनीकी शब्दावली में 'कोर सिटी एरिया' कहते हैं। इनकी आर्थिक क्षमता काफी अधिक होती है, लेकिन अनियोजित विकास और पुराने बुनियादी ढांचे की वजह से इनकी आबादी की सघनता, क्षमता और जरूरी बुनियादी सुविधाओं में कोई मेल नहीं बैठ पाता। दिल्ली सरकार ने ही पिछले दिनों एक अध्ययन के हवाले से बताया था कि राजधानी में ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए काफी निवेश की जरूरत है। देखा जाए, तो बारापुला, नजफगढ़ और यमुना पार के इलाके को तीन अलग-अलग भागों में बांटकर जल-निकासी की व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। अभी इन तीनों इलाकों की जल-निकासी व्यवस्थाओं में कोई सामंजस्य नहीं है। यहां प्राकृतिक जल-निकासी से आंखें मूंद ली गई हैं।

सवाल उठाए जाते हैं कि इस तरह के व्यवस्थागत बदलाव के लिए पैसे कहां से आएंगे? वास्तव में, हमारे पास पैसों की उस तरह कमी नहीं है, जितनी बताई जाती है। जिस तरह से सरकारें मुफ्त की रेवड़ियां बांटती हैं, उसका अगर एक हिस्सा ही ऐसे ढांचागत कार्यों में नियमित रूप से खर्च किया जाए, तो लोगों को काफी राहत मिल सकती है। मुफ्त की रेवड़ियों का ही असर है कि जनहित सेवाओं के संचालन अथवा प्रबंधन में जिस तरह पैसे खर्च करने की जरूरत होती है, उतना सरकारों के पास नहीं बच पाता और उनको केवल आपात स्थिति के लिए अपनी तैयारी रखनी पड़ती है। राजेंद्र नगर हादसे में ही घटना के बाद तमाम तरह की कमियों की बात सामने आई है। आलम यह है कि जल व्यवस्था को ही दुरुस्त करने के लिए आवश्यक पाइपों की मरम्मत और प्रतिस्थापना का काम नियमित तौर पर नहीं हो रहा, जबकि यह आवश्यक माना जाता है।

शहरी ढांचे की बेहतरी या नवीनीकरण का काम मूलतः नगर निकायों का है, लेकिन संबंधित विभागों में जरूरी समन्वय बन ही नहीं पाता। दिल्ली में ही जल-आपूर्ति का मामला दिल्ली जल बोर्ड के पास है, तो जल-निकासी की व्यवस्था नगर निकाय के हवाले। ऐसे में, जब तक स्थानीय निकायों पर पूरी तरह से समन्वय की जिम्मेदारी नहीं डाली जाएगी, तब तक इस तरह की समस्या बनी रहेगी।

इस मसले का समाधान इसलिए भी आवश्यक है, क्योंकि 2047 तक विकसित देश बनने का लक्ष्य हमने तय कर रखा है। चूंकि योजनागत काम नहीं हो रहा, इसलिए आर्थिक क्षमता से भरे इन क्षेत्रों से हमें उचित फायदा नहीं मिल रहा। हम चाहें, तो मुंबई के धारावी से सबक ले सकते हैं, जहां नवीनीकरण का प्रयास तेज किया गया है। इस तरह के काम हर शहर में क्षेत्रों को चिह्नित करके उचित संदर्भ में किए जा सकते हैं। ऐसा इसलिए भी करना चाहिए, क्योंकि भारत में मुंबई और दिल्ली महानगर ही आने वाले समय में ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए दिल्ली को लंदन, टोक्यो या न्यूयॉर्क से मुकाबला करना होगा और यह तभी संभव है, जब यहां बुनियादी ढांचे पर काम किया जाए। दिल्ली, मुंबई के अलावा बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई और कोलकाता भी आर्थिक विकास के दौर में ट्रिलियन डॉलर वाली अर्थव्यवस्था बनने के दावेदार हैं। ऐसे में, शहरों में नीतिगत और ढांचागत बदलाव अपरिहार्य है। मंझले और छोटे शहर राजकीय व अंतरराज्यीय प्रतिस्पर्द्धा से आर्थिक विकास को गति दे सकते हैं।

'अर्बन रिन्यूअल पॉलिसी' के फायदे यूरोपीय देशों में खूब देखे गए हैं। वास्तव में, दुनिया के तमाम देश ऐसी समस्याओं से जूझते रहे हैं, लेकिन वही इससे सफलतापूर्वक निकल पाते हैं, जो इसके लिए पर्याप्त दृढ़ता दिखाते हैं। यूरोपीय देशों ने समयानुकूल अपने यहां ढांचागत बदलाव किए। इसका नतीजा यह है कि आज वहां सघन आबादी वाले अनियोजित क्षेत्र नहीं दिखते। अच्छी बात है कि इस बार केंद्र सरकार ने आम बजट में बिहार, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों पर खास ध्यान दिया है। इससे वहां आधारभूत ढांचे पर निवेश हो सकेगा। अब इन राज्यों की आय बढ़ाने की व्यवस्था करनी होगी। इसके लिए सभी आकार के शहरों का विकास आवश्यक है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन में नवीनीकरण पर ज्यादा काम नहीं हो सका है।

कुल मिलाकर, हमें शहरों के आर्थिक विकास का काम नगर निकायों के हवाले करना होगा। उसे ही यह तय करना चाहिए कि कौन-सा क्षेत्र किस गतिविधि के अनुकूल है और इसके लिए कैसा ढांचागत सुधार किया जाए। इस काम में बड़े और छोटे शहरों की अलग-अलग भूमिका होगी। शीर्ष विभागों को इस प्रक्रिया पर निगरानी रखनी चाहिए और जरूरत के मुताबिक समन्वय करना चाहिए। वास्तव में, नगर निकायों की मजबूती ही नगरीय व्यवस्था को बेहतर बनाती है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

हिसाब लगा रहा आंध्र प्रदेश कि बजट से कितना मिलेगा

दक्षिण एक्सप्रेस
यहां स्कैन करें
एस. श्रीनिवासन | वरिष्ठ पत्रकार

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2024-25 में कई घोषणाएं की हैं, जिनका मकसद आंध्र प्रदेश को खुश करना है। एहसान चुकाने की भावना स्पष्ट है, क्योंकि आंध्र प्रदेश ने तीसरी मोदी सरकार को समर्थन जारी रखने का वादा किया है। इस दक्षिणी राज्य को अपने विकास के लिए संसाधन मिले हैं, विशेष रूप से राजधानी अमरावती के लिए, जो मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की पसंदीदा परियोजना है।

निर्मला सीतारमण को इस सूबे के लिए विशेष पैकेज की घोषणा करने में कठिनाई हो रही थी, क्योंकि 2026 तक लागू 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद ऐसा करना संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने सिफारिशों को जोड़ने का थोड़ा घुमावदार तरीका चुना। वित्त मंत्री ने यह वादा किया है कि चालू वित्त-वर्ष में 15,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था के अलावा आंध्र को भविष्य में भी अतिरिक्त राशि मिलेगी। बैंक, एशियाई विकास बैंक आदि से उसके लिए राशि की व्यवस्था की जाएगी। इसने आंध्र के नेताओं और उसके नौकरशाहों को उलझा दिया है। शुरुआती धन्यवाद के बाद अब नायडू शांत हैं। वे इस बात का अध्ययन कर रहे हैं कि उन्हें धनराशि कैसे व किस रूप में मिलेगी और इसका राज्य की वित्तीय स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? इसका तात्कालिक नतीजा यह हुआ है कि राज्य के पूर्ण बजट को दो महीने के लिए स्थगित कर दिया गया है।

केंद्र से मिलने वाले धन को लेकर संशय की स्थिति है और आंध्र प्रदेश सरकार ने अपने बजट को दो महीने के लिए टाल दिया है।

फिलहाल राज्यों को चार तरह से धन दिए जाते हैं। पहला, वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित विभाज्य पूल से। दूसरा, केंद्रीय अनुदान के रूप में, जिसे चुकाना नहीं होता। तीसरा, केंद्रीय मदद के रूप में ब्याज सहित और चौथा, केंद्र द्वारा व्यवस्थित बहुपक्षीय फंडिंग एजेंसियों से ऋण के रूप में। वित्त मंत्री ने आंध्र को चौथे विकल्प का प्रस्ताव दिया है। नायडू के शुभचिंतक उन्हें केंद्र से ऋण देनदारी का कुछ हिस्सा वहन कराने की सलाह दे रहे हैं। राज्य और केंद्र, दोनों गारंटी जारी करते हैं। राज्य के मामले में प्रदेश के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बैंकों से ऋण लेने के लिए गारंटी जारी की जाती है। बहुपक्षीय एजेंसियों द्वारा वित्त पोषण के मामले में संप्रभु गारंटी केंद्र द्वारा दी जाती है। मगर केंद्र की गारंटी के बावजूद चूक की स्थिति में योजना की देनदारी अंततः राज्य सरकार की होगी।

कुल मिलाकर, आंध्र प्रदेश को अंतिम तौर पर क्या मिलेगा, यह अभी बहुत साफ नहीं है। शायद इन्हीं संदेहों या मुद्दों का जायजा लेने के लिए नायडू ने अपने पूर्ण बजट को स्थगित कर दिया है। इस प्रांत की वित्तीय स्थिति खराब है, क्योंकि इसका करीब आधा राजस्व (48 प्रतिशत) ऋण चुकाने में चला जाता है। नायडू पर अपने चुनावी वादों को पूरा करने की अतिरिक्त जिम्मेदारी है। वह अब आगले दो महीनों का उपयोग अपने पूर्ववर्ती जगन मोहन रेड्डी द्वारा घोषित कई योजनाओं को त्यागने और कुछ शुरू करने के लिए करना चाहते हैं। इस बीच, नायडू अब तक कई कदम उठा चुके हैं। वह पहले ही भूमि स्वामित्व अधिनियम को रद्द कर चुके हैं। इस अधिनियम को लेकर विवाद था। इसके तहत कोई भी संपत्ति के किसी टुकड़े पर अपना दावा पेश कर सकता था और सुबूत पेश करने की जिम्मेदारी संपत्ति के मालिक पर होती। यह कानून काफी अलोकप्रिय हो गया था और अब लोगों में खुशी है।

आंध्र प्रदेश और बिहार पर अभूतपूर्व फोकस के बावजूद दक्षिणी राज्यों में लोग बिहार से नाराज नहीं हैं, क्योंकि यह पिछड़ा प्रदेश है और इसे केंद्र से अतिरिक्त मदद की जरूरत है, पर अन्य राज्यों के प्रति संवेदनशीलता की कमी ने उन्हें नाराज कर दिया है। बिहार जीएसडीपी, प्रति व्यक्ति आय व लगभग सभी सामाजिक संकेतकों के मामले में राष्ट्रीय औसत से नीचे है, इसलिए उसके लिए विशेष प्रयासों की जरूरत है। दूसरी ओर, आंध्र प्रदेश एक विश्व स्तरीय राजधानी के निर्माण के लिए धन की मांग कर रहा है। यह नायडू की पुरानी योजना है, पर पिछली जगन सरकार ने समीकरण बदल दिए थे, जिससे यह पंगु हो गई थी। अब सत्ता में लौटने के बाद नायडू फिर इस पर जोर दे रहे हैं। इस परियोजना पर उनका और उनकी सरकार का बहुत कुछ दांव पर लगा है। ऐसे में, यह जरूरी है कि देश के प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को खुश रखें।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

राष्ट्रवाद कैसे विदा होगा

सवाल आया है कि राष्ट्रवाद के विदा हो जाने पर क्या होता है? तब प्रज्ञा आती है। परंतु मुझे लगता है कि इस प्रश्न का निहितार्थ यह नहीं है। इसका तात्पर्य है, राष्ट्रवाद का विकल्प क्या हो सकता है? विकल्प खोजने की कोई भी प्रक्रिया प्रज्ञा नहीं ला सकती। यदि मैं एक धर्म छोड़कर दूसरा स्वीकार कर लूं, एक पार्टी का परित्याग कर दूसरे में शामिल हो जाऊं, तो इसमें प्रज्ञा नहीं है।

राष्ट्रवाद कैसे विदा होगा? केवल तभी, जब हम उसकी परीक्षा करके बाह्य और आंतरिक क्रियाओं में उसके महत्व के प्रति जागरूक होकर उसके तमाम निहितार्थों को समझ लेंगे। बाह्य रूप से राष्ट्रवाद लोगों को वर्गों, श्रेणियों में विभाजित करता है, युद्ध और विनाश लाता है और इस बात से हर जागरूक व्यक्ति परिचित है। भीतरी तौर पर, मानसिक रूप से किसी महान तत्व, किसी देश, किसी धारणा से अपना तादात्म्य कर लेना आत्म-विस्तार का ही एक तरीका है। किसी छोटे से गांव में या बड़े शहर में, जहां कहीं मैं रहता हूं, वहां मेरी कोई गिनती नहीं होती; परंतु यदि मैं किसी बड़ी वस्तु, देश के साथ जुड़ जाता हूं, खुद को हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई कहता हूं, तो मेरे अहंकार को गौरव मिलता है, इससे मुझे तुष्टि, प्रतिष्ठा और खुशदिली का एहसास होता है।

किसी बड़ी चीज के साथ तादात्म्य कर लेना उन लोगों की एक मनोवैज्ञानिक जरूरत है, जो यह महसूस करते हैं कि आत्म-विस्तार जरूरी है और इससे लोगों के बीच द्वंद्व व संघर्ष का जन्म होता है। अतः राष्ट्रवाद से न केवल बाहरी द्वंद्व उभरता है, बल्कि आंतरिक कुंठाएं भी पनपती हैं। जब कोई व्यक्ति राष्ट्रवाद की समस्त प्रक्रिया को समझ लेता है, तब इसका उन्मूलन हो जाता है। तब इसके स्थान पर किसी विकल्प को लाने की आवश्यकता नहीं रह जाती। क्योंकि जैसे ही आप विकल्प के रूप में किसी दूसरी बात को स्वीकार करते हैं, तो यह आत्म-विस्तार का एक और साधन बन जाता है, आप किसी विश्वास के जरिये अपने को पोषित करने लगते हैं। अतः किसी भी प्रकार का विकल्प, चाहे वह जितना आदर्शपूर्ण हो, अज्ञान का ही एक रूप है। यह तो वही बात हुई, जैसे कोई व्यक्ति धूम्रपान की जगह चूसने वाली गोली, सुपारी अथवा ऐसे ही किसी अन्य पदार्थ का उपयोग करने लगेः लेकिन यदि कोई व्यक्ति धूम्रपान की सारी समस्या को, इसकी आदत के स्वरूप को, ऐंद्रिक अनुभूतियों को और तमाम मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को वस्तुतः समझने लगे, तो धूम्रपान अपने आप छूट जाएगा।

अपने बाह्य रूप से राष्ट्रवाद लोगों को अलग-अलग वर्गों, श्रेणियों में विभाजित करता है, युद्ध एवं विनाश लाता है और इस बात से दुनिया का हरेक जागरूक व्यक्ति परिचित है।

राष्ट्रवाद अपने विषैलेपन व दुनिया में जारी झगड़ों समेत तभी समाप्त हो सकता है, जब प्रज्ञा विद्यमान हो और प्रज्ञा सिर्फ परीक्षाएं पास करने अथवा पुस्तकों के अध्ययन से नहीं आती। प्रज्ञा तब आती है, जब समस्याओं के उपजते ही उनको समझ लिया जाता है।

जे कृष्णमूर्ति

एंटोनियो गुटेरस | संयुक्त राष्ट्र महासचिव

इक्कीसवीं सदी में भूख के लिए कोई जगह नहीं है। भूख से मुक्त दुनिया न केवल अनिवार्यता है, बल्कि वित्तीय उपायों से इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। आइए, मिलकर हम भूख को इतिहास की किताबों में समेटें!

अनुलोम-विलोम
नीति आयोग की बैठक

बैठक से दूर रहकर अपना कर्तव्य न भूले विपक्ष

आखिर सरकार करे, तो क्या करे? उसने हर सत्र के शुरू होने से पहले सर्वदलीय बैठकें करके देख ली। दोनों सदनों के अध्यक्ष और उप-सभापति ने बारंबार समझा-समझाकर सहयोग की अपील कर ली। प्रधानमंत्री ने भी बार-बार सदस्यों से सदन को शांतिपूर्वक बहस के जरिये चलने/चलाने की विनम्र अपील कर डाली। बावजूद इसके एनडीए को सत्ता के आरंभ (2014) से अभी तक विपक्ष का सहयोग नहीं मिल पाया है। इसके उलट हर सत्र में विपक्षी सांसदों के 'वाक आउट', हंगामे, अनर्गल बहस के अलावा सरकार को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। नीति आयोग की बैठक का भी लगभग सभी विपक्षी दलों ने बहिष्कार कर दिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री आईं जरूर, लेकिन उन्होंने भी यह आरोप लगाकर बाहर का रास्ता नापा कि उनको बोलने नहीं दिया गया, माइक बंद कर दिया गया। हालांकि, सरकार ने इससे इनकार किया है। क्या देश के मतदाताओं ने भारी संख्या में विपक्ष को इसीलिए भेजा है कि वे उनके हितकारी कार्यों पर संसद में बहस करने के बजाय सब कुछ हंगामे या बहिष्कार की भेंट चढ़ा दें? विपक्ष मतदाताओं के बहुमूल्य मतों को समझे। इतनी नासमझी न करे कि मतदाता उनको अपरिपक्व या विघ्नसंतोषी ही समझने लगे। सड़क पर न सही, मगर संसद में तो मतदाताओं की भावनाओं के अनुरूप उनको सौंपी गई जिम्मेदारी के प्रति वे गंभीरता दिखाएं और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए मतदाताओं से किए वादों को सदन में बैठकर पूरा करें। तभी उनका निर्वाचन सार्थक माना जाएगा।

शकुंतला महेश नेनावा, टिप्पणीकार

यह राजनीति उचित नहीं

नीति आयोग ऐसा कोई मंच नहीं, जिसे दलगत राजनीति का अखाड़ा बनाया जाए। वैसे भी, इस बार तो नीति आयोग की बैठक का एजेंडा देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के उपाय और सुझावों पर केंद्रित था। आखिर इस एजेंडे पर विपक्षी दलों के मुख्यमंत्री को राजनीति करने की क्यों सूझी? वे यह ठान चुके हैं कि वे किसी भी, यहां तक के राष्ट्रीय हित के विषय पर भी सरकार के साथ मिलकर चलने को तैयार नहीं। इसकी झलक संसद में मिल ही चुकी है। विपक्षी दलों का तर्क है कि उन्होंने नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार इसलिए किया, क्योंकि बजट में विपक्ष-शासित राज्यों की कथित तौर पर अनदेखी की गई। एक तो यह जनता को गुमराह करने वाला तर्क है, और यदि ऐसा लगता है, तो उन्होंने अपनी बात आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री के समक्ष कहने का अवसर गंवना क्यों पसंद किया?

विनय सिंह, टिप्पणीकार

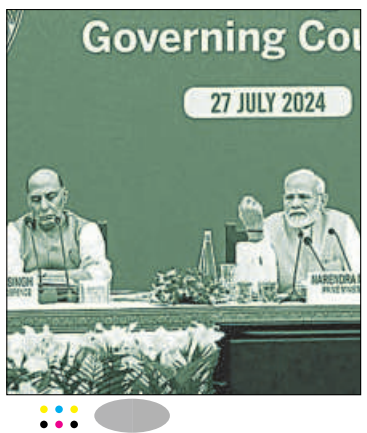

पूरा दोष विरोधी दलों पर नहीं दिया जा सकता

नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार सभी विपक्षी दलों के मुख्यमंत्री ने किया। ममता बनर्जी आईं और तुरंत निकल गईं, क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें बोलने नहीं दिया गया। यह बैठक राज्यों को अपनी वित्तीय स्थिति केंद्र के सामने रखने का मौका दे रही थी। लिहाजा, जो मुख्यमंत्री इसका बहिष्कार कर रहे थे, वे अपनी जनता के साथ ही धोखा कर रहे थे। कांग्रेस और दूसरी पार्टियां जिस तरह से सांविधानिक बैठकों का राजनीतिकरण कर रही हैं, वह वाकई चिंताजनक है। सत्तारूढ़ दल की नीतियों का विरोध करना विपक्ष का धर्म है, लेकिन विरोध में वाजिब मुद्दे भी उठाए जाने चाहिए। मगर, सच यह भी है कि पूरा दोष विपक्ष को नहीं दिया जा सकता। संविधान के मुताबिक, केंद्र सरकार राज्य सरकारों के जरिये ही देश को संभाल सकती है। राज्य सहयोग नहीं करेंगे, तो केंद्र का काम करना कठिन है। केंद्र को लचीला रुख अपनाना चाहिए। एक विपक्ष की मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठक में आती हैं, तो उनको आप निर्धारित चंद मिनटों से ज्यादा बोलने नहीं देते, जबकि दूसरे विपक्षी मुख्यमंत्री आए ही नहीं थे। ऐसे में, उनका समय तो ममता बनर्जी को दिया जा सकता था। मान लिया कि कांग्रेस और ममता की राजनीति सब जानते हैं, लेकिन सरकार को थोड़ा इनको साथ लेने की कोशिश करनी ही चाहिए, क्योंकि यह देश का मामला है। विपक्ष में कई ऐसे नेता हैं, जो भाजपा के रुख का सम्मान करते हैं। बीजेपी ऐसे विपक्ष के लोगों को अपना पक्ष समझा सकती है। अलबत्ता, जो बैठक में नहीं आने की घोषणा कर चुके थे, उन्हें मनाने के लिए कुछ नहीं किया गया। ये कोई नौकरशाहों की बैठक नहीं थी, देश के विकास के लिए बुलाई गई बैठक थी। भाजपा को प्यार से विरोधियों को मात देनी चाहिए थी। उम्मीद है, पार्टी आगे ऐसी बैठकों में इसका ख्याल रखेगी।

अतुल कुमार श्रीवास्तव, टिप्पणीकार

जरूरी है बहिष्कार

यह सही है कि नीति आयोग जैसी बैठकों से दूरी नुकसानदेह है, पर विरोधी दलों के पास अब कोई उपाय भी नहीं बचा था। यह अब साफ-साफ दिखने लगा है कि विपक्षी दलों की सूबाई सरकारों के साथ दोयम दरजे का व्यवहार किया जा रहा है। उनको पर्याप्त बजट तक आवंटित नहीं किए जा रहे। यहां तक कि विपक्षी नेताओं के माइक बंद कर दिए जाते हैं। ऐसे में, बैठकों का बहिष्कार उनका एक अहिंसक प्रतिरोध माना जाएगा, जिसका स्वागत किया जाना चाहिए। उम्मीद है, इससे सत्तारूढ़ दल पर कुछ असर पड़ेगा और वह विपक्षी दलों को साथ में लेकर आगे बढ़ने की सदिच्छा दिखाएगा। इससे देश को फायदा ही होगा।

रोहित, टिप्पणीकार

विभाजनकारी राजनीति

कसभा में आम बजट पर चर्चा करते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जिस तरह अपना यह पुराना आरोप नए सिरे से दोहराया कि बजट बनाने वालों में कोई एससी-एसटी और ओबीसी अधिकारी नहीं होता, उससे यदि कुछ स्पष्ट है तो यही कि वह समाज को बांटने वाली विभाजनकारी राजनीति पर अड़े हैं। वह यह बात पहले भी कई बार कह चुके हैं और सरकार की ओर से हर बार उन्हें विस्तार से यह बताया जा चुका है कि ऐसी स्थिति क्यों है और किस तरह इसके लिए कांग्रेस की तत्कालीन सरकारें ही जिम्मेदार हैं, लेकिन वह कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं। वह जानबूझकर इस तथ्य की भी अनदेखी कर रहे हैं कि संप्रग सरकार के समय भी यही स्थिति थी। वैसे तो उच्च स्तर की नौकरशाही में यथासंभव सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, लेकिन शासन के हर फैसले में शामिल अधिकारियों की जाति गिनना खतरनाक जातिवादी राजनीति है। राहुल गांधी एक तरह से यह कहना चाह रहे हैं कि अनारक्षित वर्गों के अधिकारी आरक्षित वर्गों के हितों की उपेक्षा करते हैं। एक बार वह यहां तक संकेत कर चुके हैं कि उच्च जाति के शिक्षक प्रश्नपत्र बनाते हैं, इसलिए आरक्षित वर्ग के छात्र फेल हो जाते हैं। आखिर यह भड़काऊ राजनीति नहीं तो और क्या है? राहुल गांधी के रुख-रवैये से यही लगता है कि वह अभी भी चुनावी मुद्रा में हैं। आखिर वह जो कुछ मोदी सरकार से चाह रहे हैं, उसे कांग्रेस संगठन और साथ ही अपने दल द्वारा शासित राज्य सरकारों में क्यों लागू नहीं कर रहे हैं? क्या मोदी सरकार ने उन्हें ऐसा करने से रोक रखा है? उन्हें बताना चाहिए कि कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश में बजट बनाने में आरक्षित वर्गों के कितने अधिकारियों की हिस्सेदारी होती है? वह मोदी शासन की तरह मीडिया में भी आरक्षित वर्गों के प्रतिनिधित्व का प्रश्न भी कई बार उठा चुके हैं, लेकिन यह देखने को तैयार नहीं कि आखिर उनके परिवार के प्रभुत्व वाले मीडिया संस्थान में इन वर्गों के कितने लोगों की हिस्सेदारी है? राहुल गांधी ने बजट पर सरकार को घेरने के लिए महाभारत का उल्लेख करते हुए यह भी कह डाला कि जैसे अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेर लिया गया था, उसी तरह देश को भी मोदी सरकार ने घेर रखा है। उन्होंने प्रधानमंत्री समेत जिन छह लोगों को इस घेराबंदी के लिए जिम्मेदार ठहराया, उसमें अंबानी-अदाणी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और आरएसएस प्रमुख को भी शामिल कर लिया। स्पष्ट है कि वह मनमाने और बेतुके तर्क देने में संकोच नहीं कर रहे हैं। वह अपनी ऐसी बातों से चर्चा में तो आ जाते हैं और उनके समर्थक उनकी वाह-वाही करने में भी जुट जाते हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष के तौर पर वह न तो समाज को कोई सही दिशा दे पा रहे हैं और न ही सरकार को कोई सार्थक सुझाव।

गौरव को धक्का

कभी देश के लिए सौर ऊर्जा का माडल बना जहानाबाद जिले का धनरई गांव आज इस मामले में अपना गौरव खो चुका है। वर्ष 2013 में यह देश का पहला ऐसा गांव बना था, जहां सौर ऊर्जा से उत्पादित बिजली की तीन हजार घरों में निशुल्क आपूर्ति की जा रही थी। अंतरराष्ट्रीय संगठन ग्रीन पीस के सौजन्य से स्थापित इस यूनिट की उस वक्त इतनी प्रशंसा हुई कि देशभर की कई पंचायतों को इसके माडल के अध्ययन के लिए प्रेरित किया गया। वर्तमान में इसके निष्क्रिय हो जाने से बिहार के इस गौरव को धक्का लगा है। वजह भी बड़ी नहीं। महज पांच लाख रुपये की व्यवस्था न हो पाने के कारण तीन करोड़ की यह सौर ऊर्जा यूनिट ठप पड़ी है। जिन घरों में इसकी निशुल्क बिजली की आपूर्ति की जा रही थी वे अब शुल्क चुकाकर बिजली का उपभोग कर रहे। राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत तब के तत्कालीन मुखिया अजय सिंह यादव को इस दशा के लिए अफसोस है। कहते हैं, रेवड़ी की तरह बिजली बांटने और समुचित प्रबंधन न होने की वजह से यूनिट ठप हो गई। वर्तमान डीडीसी कहते हैं स्थिति से वरीय अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा। इस अवस्था को प्राप्त होने के पूर्व ही इसपर काम होना चाहिए था। यह जानकारी थी कि इसमें लगी बैटरी की आयु पांच वर्ष है। यह बैटरी निष्क्रिय हो जाएगी तो आपूर्ति ठप हो जाएगी। नई बैटरी के लिए पांच लाख रुपये की आवश्यकता थी। इस राशि की व्यवस्था के लिए कोई उपाय नहीं किए गए। यदि तीन हजार घरों पर प्रतिमाह न्यूनतम राशि तय कर दी जाती तब भी इसका रख रखाव सहज हो जाता। स्थानीय उपभोक्ताओं को भी पहल करनी चाहिए थी।

स्थानीय प्रशासन और आमजन के प्रयास से देश के पहले सौर उर्जान्वित जहानाबाद जिले के धनरई गांव का गौरव पुनः प्राप्त हो सकता है।

कह के रहेंगे — माधव जोशी

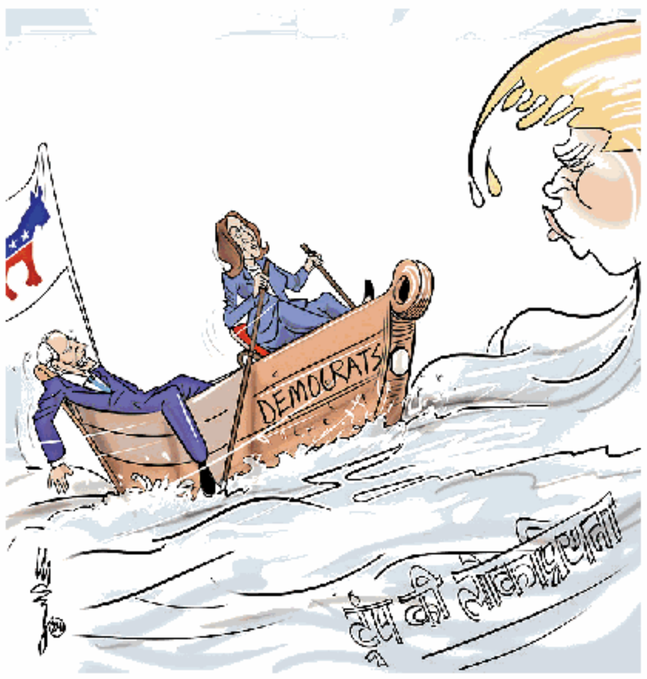

जागरण जनमत — कल का परिणाम

क्या दिल्ली के कोचिंग सेंटर में हुआ हादसा कोचिंग संचालकों के साथ ही शासन-प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है।

आज का सवाल
क्या प्रधानमंत्री मोदी को यूक्रेन की यात्रा करनी चाहिए?

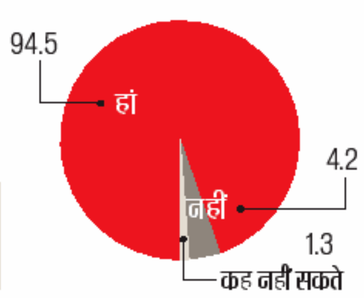

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आत्मघाती अंतर्कलह से बचे भाजपा

राज कुमार सिंह

चुनावी प्रदर्शन की समीक्षा से कई राज्यों में भाजपा में असंतोष के जो स्वर मुखर हो रहे हैं, उनसे लगता है कि कमजोरियों की जांच-पड़ताल गलत दिशा में जा रही है

भाजपा के स्वीकार न करने से यह सच नहीं बदल जाएगा कि 18वीं लोकसभा चुनाव में उसे बड़ा झटका लगा। पांच साल के शासन के बाद 2019 में पिछली बार से भी 21 सीटें ज्यादा जीतने वाली भाजपा इस बार 240 पर सिमट गई। 1984 में दो सीटों से 2019 में 303 सीटों तक का सफर तय करने वाली भाजपा इस झटके को नजरअंदाज नहीं कर सकती, लेकिन चुनावी प्रदर्शन की समीक्षा से कई राज्यों में असंतोष के जो स्वर मुखर हो रहे हैं, उनसे लगता है कि कमजोरियों की जांच-पड़ताल गलत दिशा में जा रही है। कमजोर प्रदर्शन के कारणों की पहचान अंतर्कलह को हवा दे रही है। निश्चय ही कमजोर प्रदर्शन के कुछ कारण रहे होंगे, पर उनकी पहचान नीति-रणनीति के बजाय सिर्फ व्यक्तियों के रूप में किए जाने का रास्ता अंततः आत्मघाती अंतर्कलह को जन्म देता है। 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 400 से भी ज्यादा सीटें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या से उपजी सहानुभूति से मिली थीं, लेकिन वही कांग्रेस 2014 में 44 और 2019 में 52 सीटों पर सिमट गई तो उसके लिए उसका अंतर्कलह भी जिम्मेदार रहा। 18वीं लोकसभा चुनाव में भाजपा ने अपने लिए 370 और राजग के लिए 400 सीटों का नारा दिया था, लेकिन परिणाम दावों से बहुत कम आए। चुनाव से पहले जुड़े तेदेपा और जदयू जैसे सहयोगियों की बदौलत राजग ने बहुमत से भी 19 ज्यादा यानी 293 सीटें हासिल कर लीं, पर उत्तर प्रदेश से लेकर कर्नाटक तक और बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक भाजपा का चुनावी प्रदर्शन निराशाजनक रहा।

हर राज्य के अपने राजनीतिक-सामाजिक समीकरण होते हैं। इसलिए हर राज्य में हार के कारणों की समीक्षा में एक फार्मूला नहीं चल सकता। हां, एक कारण ज्यादातर राज्यों में समान हो सकता है कि राष्ट्रीय नेतृत्व, खासकर प्रधानमंत्री मोदी के करिश्मे पर निर्भर संगठन ज्यादा सक्रिय नहीं हुआ। कार्यकर्ता कमर कसकर मैदान में नहीं उतरे। जब बड़े नेता दावा कर रहे थे कि देश ने इस बार 400 पार का मन बना लिया है तो शायद कार्यकर्ताओं को पिछले दो चुनावों की तरह 'मेरा बूथ सबसे मजबूत' जैसे जुनून के साथ काम करने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव वाले महाराष्ट्र में राजग की सीटें आधी से भी कम रह जाना, हरियाणा में आधी सीटें हार जाना और झारखंड में 12 से आठ पर आ जाना भाजपा के लिए कम झटका नहीं है। बंगाल में सीटें बढ़ने के दावों के बीच 18 से भी घटकर 12 रह जाना भी बड़ा झटका है। झटका कर्नाटक और राजस्थान में भी लगा। हाल में जिन सात राज्यों में 13 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हुए, उनमें भी मध्य प्रदेश के अलावा भाजपा का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। ऐसे में कमतर प्रदर्शन के कारणों की समीक्षा और भी जरूरी है, पर यह सुनिश्चित करना आलाकमान की जिम्मेदारी है कि इसकी आड़ में महत्वाकांक्षी नेता अंतर्कलह को हवा न दे पाएं। पार्टी में ही अपने विरोधियों पर निशाना साधने की कोशिश अन्य राज्यों में भी है, पर यूपी में तो यह कवायद पूरी तरह अंतर्कलह में तब्दील नजर आती है।

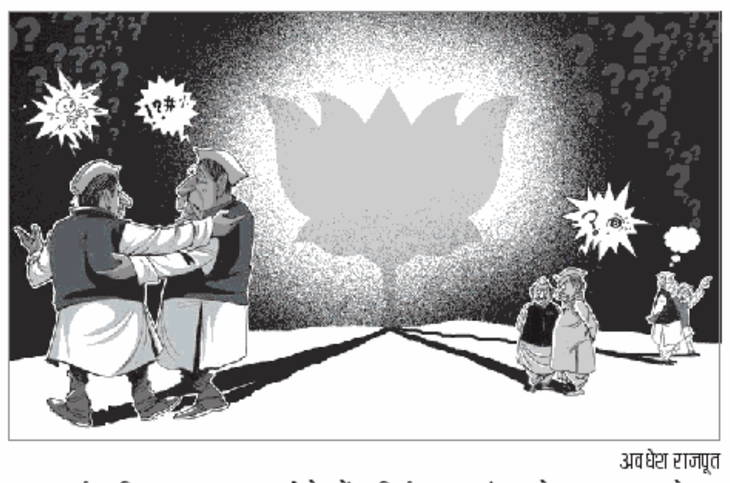

अवधेश राजपूत

जब भाजपा के अंदर से ही यूपी में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों को हवा दी जा रही हो तो फिर मुख्य विपक्षी दल सपा के मुखिया अखिलेश यादव 'सौ लाओ, सरकार बनाओ' का मानसूनी आफर देने से क्यों चूकेंगे? सच है कि भाजपा आलाकमान ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बदलने का संकेत नहीं दिया, लेकिन यह भी तो सच है कि लोकसभा चुनाव बाद और जोर पकड़ गईं ऐसी अटकलों का खंडन भी नहीं किया। 2014 के लोकसभा चुनाव में जब भाजपा ने उत्तर प्रदेश की 80 में 71 सीटें जीतने का करिश्माई प्रदर्शन किया था, तब योगी सिर्फ एक सांसद थे। उस समय केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश अध्यक्ष और अमित शाह मुख्य चुनावी रणनीतिकार थे, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत मिलने पर मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद योगी राष्ट्रीय स्तर पर भी पार्टी के स्टार प्रचारक के रूप में उभरे। आज प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री शाह के साथ वही भाजपा का तीसरा बड़ा चेहरा हैं। बुलडोजर न्याय की आलोचना के बावजूद राज्य की शासकीय व्यवस्था में सुधार से इन्कार नहीं किया जा सकता। निःसंदेह 2019 के लोकसभा चुनाव में भी उत्तर प्रदेश में भाजपा की सीटें घट कर 62 रह गई थीं और 2022 के विधानसभा चुनाव में भी सीटें घटीं, लेकिन क्या उसके लिए अकेले योगी को जिम्मेदार ठहराना तर्कसंगत है? केशव प्रसाद मौर्य तो अपनी विधानसभा सीट हारने के बाद भी उपमुख्यमंत्री बनाए गए। क्या 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा-बसपा गठबंधन बड़ा कारक नहीं रहा? क्या किसान आंदोलन 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रमुख कारक नहीं था? फिर भी भाजपा लोकसभा की 80 में से 62 सीटें जीत गई और बहुमत से दूसरी बार सरकार भी बना ली तो क्या उसका तनिक भी श्रेय मुख्यमंत्री को नहीं मिलना चाहिए?

योगी की अपनी कार्यशैली है। वह किसी दबाव के बिना जो सही लगता है, वही फैसला लेते हैं, पर क्या मुख्यमंत्री बनाते समय यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता नहीं थी? असल कारण तो आलाकमान ही बेहतर जानता होगा, लेकिन अगर दोनों उपमुख्यमंत्री ही कैबिनेट समेत जरूरी बैठकों में शामिल होना जरूरी न समझें तो सार्वजनिक रूप से मुख्यमंत्री की क्या छवि बनेगी? राज्य में समीक्षा बैठकों के बाद शायद पहली बार दिल्ली में दोनों उपमुख्यमंत्री मुख्यमंत्री के साथ नजर आए। किसी राज्य का मुख्यमंत्री बदलना कोई अनहोनी घटना नहीं। कांग्रेस में तो एयरपोर्ट पर ही मुख्यमंत्री बदलने का फरमान सुना दिया जाता था। भाजपा ने भी कभी दिल्ली तो कभी उत्तराखंड में बीच कार्यकाल मुख्यमंत्री बदले। गुजरात में तो पहली बार के विधायक भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाते हुए पूरा मंत्रिमंडल ही बदल दिया गया, पर क्या चेहरा बदल देना भर चुनाव जीतने की गारंटी है? जिन राज्यों में चुनावी प्रदर्शन निराशाजनक रहा, वहां बेहतरी के लिए भाजपा आलाकमान को कदम उठाने ही चाहिए, लेकिन इस तरह नहीं कि अनुशासित पार्टी की परंपरागत छवि को तार-तार होकर अंतर्कलह मीडिया की सुर्खियों से लेकर चौपालों तक पर चर्चा का विषय बन जाए।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं)

response@jagran.com

अपनी सीमा पार करतीं ममता बनर्जी

अवधेश कुमार

ममता सरकार सीएए के तहत तो लोगों को नागरिकता देने के विरोध में है, लेकिन बांग्लादेशियों को शरण देने को उतावली है

पिछले दिनों तृणमूल कांग्रेस की शहीद दिवस रैली में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा बांग्लादेश के लोगों को राज्य में शरण देने का बयान हतप्रभ करने वाला रहा। सामान्य तौर पर किसी राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा ऐसे बयान की कल्पना नहीं की जा सकती है। अंतरराष्ट्रीय नियम कहते हैं कि किसी दूसरे देश की आंतरिक समस्या में तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जाता, जब तक वहां मानवाधिकारों का लगातार सरेआम उल्लंघन नहीं हो रहा हो। संबंधित देश अगर अपने निर्दोष नागरिकों के विरुद्ध अत्याचार करने लगे तभी अंतरराष्ट्रीय समुदाय या कोई देश उसके खिलाफ सामने आ सकता है, लेकिन यह भी राष्ट्र की नीति होती है, किसी राज्य की नहीं। राज्य सरकार ज्यादा से ज्यादा केंद्र के समक्ष अपनी इच्छा प्रकट कर सकती है कि हमें इस संदर्भ में कैसी नीति अपनानी चाहिए। यह चिंताजनक है कि देश की एक मुख्यमंत्री, जो केंद्र में भी मंत्री रह चुकी हैं, सरेआम अपनी संवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन करें। इस तरह का बयान देने का हक प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री या फिर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता को ही हो सकता है। बांग्लादेश को लेकर ममता बनर्जी का यह वक्तव्य स्वाभाविक ही आपत्तिजनक लगा है, तभी सधे हुए शब्दों में वहां की सरकार ने इसका प्रतिवाद किया।

शहीद दिवस रैली को संबोधित करतीं ममता ● फाइल

ममता बनर्जी का बयान अनायास नहीं हो सकता। वास्तव में बंगाल में लगभग 30 प्रतिशत मुस्लिम वोट उनके सत्ता में बने रहने का एक बड़ा आधार बन चुका है। लगता है वह इसके लिए किसी सीमा तक जाने को तैयार हैं। मुस्लिम वोट की राजनीति भारत में ऐसे ही होती रही है। यही ममता बनर्जी बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में मजहबी रूप से पीड़ित गैर मुसलमानों को मानवता के आधार पर नागरिकता देने के लिए भारत सरकार द्वारा बनाए गए कानून सीएए का मुखर होकर विरोध कर रही हैं। भारत के ज्यादातर दलों ने सेक्युलरवाद की इसी तरह धज्जियां उड़ाई हैं। भारत ने दूसरे देशों के नागरिकों को शरण दी है। उदाहरण के लिए म्यांमार से आए 79 हजार शरणार्थी भारत में रह रहे हैं। तमिलनाडु के शरणार्थी शिविरों में श्रीलंका से आए 58 हजार 457 श्रीलंकाई तमिल रह रहे हैं। 1959 में तिब्बत में चीनी हस्तक्षेप के बाद बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा के साथ आए लगभग एक लाख शरणार्थी भी अलग-अलग जगहों पर शरण पाए हुए हैं। यह निर्णय किसी राज्य सरकार ने नहीं किया। ममता बनर्जी ने भारत के स्वयंभू शासन की तरह व्यवहार किया है। उन्हें पता होना चाहिए कि शरण देने का दायित्व भी केंद्र सरकार का ही है, कोई राज्य सरकार ऐसा नहीं कर सकती। यद्यपि हमारे देश में शरण देने को लेकर कोई उपयुक्त कानून नहीं है। भारत संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी संबंधी व्यवस्था का सदस्य नहीं है। इसी तरह 1990 में प्रवासी मजदूरों के लिए तैयार कन्वेंशन आफ माइग्रेंट वर्कर्स के 59 सदस्य देशों में भी भारत नहीं है। 1967 के प्रोटोकाल रिलेटेड टू द स्टेटस आफ रिफ्यूजीज पर भी भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया है। हालांकि भारत अपनी स्वाभाविक संवेदनशीलता के अनुरूप इनका पालन करता है।

एक तरफ विपक्षी सांसद संविधान लहराते हुए बता रहे हैं कि हम संविधान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं और दूसरी ओर ममता बनर्जी स्वयं इस तरह संविधान का उल्लंघन करती नजर आ रही हैं। क्या ममता का बयान संघीय ढांचे पर प्रहार नहीं है? अगर ममता बनर्जी के बयान का विरोध नहीं हुआ तो आगे कोई दूसरी राज्य सरकार पाकिस्तान, अफगानिस्तान या फिर चीन को लेकर भी दरवाजा खोलने की बात कर सकती है। जिन पश्चिमी देशों ने संयुक्त राष्ट्र के तहत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शरणार्थियों और आप्रवासियों के लिए लोकतंत्र और मानवाधिकार आदि राजनीतिक विचारधारा के नाम पर निहित स्वार्थों के कारण आश्रय देने की व्यवस्थाएं बनवाईं, अपने यहां मानवाधिकारों एवं मजहबी स्वतंत्रता की रक्षा के नाम पर कानून बनाए और फिर दुनिया को भी ऐसा ही करने की सीख दी, आज उन्हीं देशों में इसके विरुद्ध कदम उठाए जा रहे हैं। अमेरिका से लेकर पूरे यूरोप में बिना पासपोर्ट, वीजा के विकासशील और गरीब देश के लोगों के प्रवेश को रोका जा रहा है। उन देशों की राजनीति में यह बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इसके आधार पर आज वहां के नेताओं एवं पार्टियों को वोट मिल रहा है। वे देश इसके कारण आंतरिक अशांति के शिकार हो गए हैं और इससे मुक्ति चाहते हैं। उन्होंने मानवाधिकार, लोकतंत्र एवं मजहबी स्वतंत्रता आदि के नाम पर ऐसे स्टैंड लिए कि आज अपने ही देश की रक्षा की दृष्टि से उसके विरुद्ध खड़ा होना कठिन हो रहा है। हमारे देश के नेताओं ने इसका अनुमान आजादी के बाद ही लगा लिया था कि पड़ोसी देशों की हालत खराब होने का शिकार हम हो सकते हैं। इसीलिए उन्होंने विनम्रता के साथ संयुक्त राष्ट्र की ऐसी किसी व्यवस्था पर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया था और यह नीति आज तक जारी है। किंतु वर्तमान राजनीति में अनेक विपक्षी दल उसी तरह की भाषा बोल रहे हैं, जैसी एक समय पश्चिम में स्वयं को लेफ्ट-लिबरल मानने वाले बोलते थे तथा सरकारों ने उन नीतियों को लागू किया।

राजनीति में एक-दूसरे का प्रतिस्पर्धी या विरोधी होना स्वाभाविक है, किंतु इसके लिए देश की सुरक्षा और आंतरिक व्यवस्था को जोखिम में डालना किसी दृष्टि से स्वीकार नहीं किया जा सकता। ममता बनर्जी को कम से कम अपने बयान पर खेद प्रकट करना चाहिए। विपक्ष के नेताओं को भी आगे आकर बोलना चाहिए कि हमारी राजनीतिक लड़ाई आंतरिक है, किसी बाहरी देश के मामले में भारत सरकार का निर्णय ही मान्य होगा।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

चरैवेति चरैवेति

समय गतिवान है, जीवन गतिमान है। मन गतिवान है, बुद्धि गतिवान है। प्रतिभा गतिमान है, विकास गतिवान है। धर्म गतिमान है, नीति गतिवान है। समाज गतिमान है, देश गतिवान है। संसार गतिवान है, प्रकृति गतिमान है। इसलिए अणु के अंदर परमाणु गतिमय है। शरीर के भीतर आत्मा गतिमान है। गतिवान रहना ही कर्मयोग है। सांस चलती रहती है, तभी तक जीवन है। जीव चलता रहता है, तब तक जीवित है। अर्थात चलते जाना-चलते रहना-यही जीवन की गति है, दशा है, स्थिति है। रुकना मृत्यु की दशा है, दिशा है। अहर्निश चलने का नाम ही तो जिंदगी है। जन्म से लेकर मृत्यु तक चलते ही रहना है, रुकना नहीं है। आगे बढ़ना है, दौड़ना है, संघर्षरत रहना है।

चरैवेति चरैवेति। अर्थात चलते रहना, चलते रहना। रुकना नहीं, ठहरना नहीं, जड़ता नहीं। हर हाल में गतिमान रहना, यही जीवन का मंत्र है। सदा गतिशील रहना, यह लोक दर्शन है। पल-पल सक्रिय होना, यह जीव मात्र का नियम है। अनवरत संघर्षरत होना, यह मानव की नियति है। चलते रहो, पग-पग आगे बढ़ते रहो-यही मानव विकास का मार्ग है। कर्तव्य पथ पर कभी ठहरना नहीं है। जिस तरह धर्म का चक्र चलता रहता है, उसी प्रकार कर्म का रथ भी बराबर चलता रहता है। सूर्य, चंद्र और नक्षत्रमंडल अनवरत यात्रा करते हैं। कर्म करते रहना और गतिमय बने रहना जगत का आधार है, ईश्वरीय आदेश है। जो ठहर गया, गतिहीन हो गया-उसे निर्जीव मान कर समाज से बाहर फेंक दिया जाता है। जो स्थिर हो गया, संज्ञा शून्य हो गया-वह चुक गया।

गति की क्षमता प्रकृति ने सबको दी है, लेकिन मन जितनी उड़ान भर सकता है, शरीर कभी ऐसा नहीं कर सकता। जीव गति के ही आलंब हैं। यह परिवर्तन का भी सूचक है, जो प्राकृतिक प्रक्रिया है। विधि का विधान क्रमिक विकास को बाधित नहीं करता। चरैवेति चरैवेति का मंत्र मानव जीवन का रहस्य है।

डा. राघवेंद्र शुक्ल

पाठकनामा

pathaknama@pat.jagran.com

समृद्ध है भारत की संस्कृति

हृदयनारायण दीक्षित का 'धरोहरों के संरक्षण का कर्तव्य' शीर्षक से प्रकाशित आलेख पढ़ा। उन्होंने भारत में उपस्थित प्राचीन धरोहरों के संरक्षण और संवर्धन की आवश्यकता पर जोर दिया है। यह वर्तमान समय की मांग भी है, क्योंकि प्राचीन स्मारक सभ्यता और संस्कृति के संवाहक और राष्ट्र की धरोहर होते हैं। हाल में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति ने असम के अहोम राजवंश के 'मैदाम' को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। यह मैदाम असम के चराईदेव जिले में अहोम राजवंश की कब्रगाह है। अहोम असम में उपस्थित एक अति समृद्ध और शक्तिशाली राजवंश था जिसने असम पर 600 साल तक राज किया। इसकी अपनी विशिष्ट धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान थी। हालांकि भारत में अब तक केवल 43 स्थल ही विश्व धरोहर की सूची में शामिल हैं, जो एक चिंतनीय स्थिति है, क्योंकि दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जिसका गौरवशाली इतिहास रहा है। यहां सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक काल, मौर्य काल, गुप्त काल, विजयनगर साम्राज्य आदि रहे हैं। यहां पर कई प्रकार की विशिष्ट कलाएं हैं। जैसे गांधार, मथुरा और अमरावती मूर्ति कलाएं, नगर, द्रविड़ और वेसर मंदिर कलाएं और लेखन में रामायण एवं महाभारत जैसे महाकाव्य तथा वेद, पुराण, उपनिषद, अर्थशास्त्र आदि उपस्थित हैं। अतः हम अपने समृद्ध इतिहास को पहले तो स्वयं जानें एवं समझें और उसे दुनिया के सामने प्रस्तुत करें।

गुलशन कुमार, फरीदाबाद

मंदिरों में विशिष्ट सुविधा अनुचित

भारत में धार्मिकता और आस्था का प्राचीन इतिहास है, इसी कारण देश के विभिन्न मंदिरों में लाखों श्रद्धालु प्रतिवर्ष दर्शन के लिए आते हैं। हाल के वर्षों में कुछ मंदिरों में दर्शन के लिए शुल्क लिया जा रहा है, जबकि विशिष्टों को निशुल्क दर्शन की सुविधा दी जा रही है। देश के बड़े मंदिरों जैसे उज्जैन के महाकाल मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर, देवघर वैद्यनाथ मंदिर, तिरुपति बालाजी मंदिर, शिरडी साई मंदिर और वैष्णो देवी मंदिर आदि में विभिन्न प्रकार के दर्शन के लिए लंबी कतार के बावजूद अलग अलग शुल्क निर्धारित किए गए हैं। जबकि मंदिरों में विशिष्ट लोगों को बिना अपनी बारी की प्रतीक्षा किए निशुल्क दर्शन की अघोषित सुविधा दी जाती है। सवाल यह उठता है कि क्या धार्मिक स्थलों पर दर्शन के लिए इस तरह भेदभावपूर्ण शुल्क लेना और विशिष्ट लोगों को निशुल्क दर्शन करने देना क्या उचित है? आम या मध्यवर्गीय लोग ऐसे शुल्क को वहन करने में सक्षम नहीं भी हो सकते हैं, जबकि विशिष्ट लोगों शुल्क देने में कोई परेशानी नहीं है, फिर भी उन्हें निशुल्क दर्शन की सुविधा दी जाती है। धार्मिक दृष्टिकोण से सभी भक्तों को समान रूप से भगवान के दर्शन करने का अधिकार होना चाहिए। यह भेदभाव सामाजिक असमानता को न केवल बढ़ावा देता है, बल्कि धार्मिक स्थलों के प्रबंधन की निष्पक्षता पर भी प्रश्नचिह्न लगाता है। इससे समाज में नकारात्मक संदेश जाता है कि केवल संपन्न लोग ही भगवान के शीघ्र दर्शन के योग्य हैं। मंदिर प्रबंधन को चाहिए कि वे अपने निर्णयों में सामाजिक न्याय का उचित ख्याल रखें और धार्मिक समानता का पालन करें, ताकि बिना भेदभाव के दर्शन हो सके।

डा. संजीव कुमार, राजेन्द्र पथ, गया

कोचिंग हादसा भ्रष्टाचार का परिणाम

दिल्ली में कोचिंग संस्थान में हुई त्रासदी केवल एक दुर्घटना नहीं है, बल्कि एक संगठित लापरवाही और भ्रष्टाचार का परिणाम है। इस घटना ने प्रशासन और नगर निगम की व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है। यह घटना हमें याद दिलाती है कि हमारी नागरिक संरचनाओं में कितनी गहरी समस्याएं मौजूद हैं। मूल समस्या प्रशासनिक लापरवाही और भ्रष्टाचार की है। जब तक इन समस्याओं को जड़ से नहीं उखाड़ा जाएगा, इस प्रकार की घटनाएं होती रहेंगी। कोचिंग संस्थान के संचालकों और नगर निगम के अधिकारियों के बीच मिलीभगत साफ नजर आती है। इस प्रकार के संस्थान सुरक्षा मानकों की अनदेखी कर रहे हैं, जिससे मेधावी व निर्दोष विद्यार्थियों की जान खतरे में पड़ रही है। इस समस्या का समाधान कठोर नियमन और निगरानी से ही संभव है। सरकार को चाहिए कि वह सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करवाए और दोषी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करे। इसके अलावा, नगर निगम को अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेना चाहिए और हर निर्माण स्थल की नियमित जांच करनी चाहिए। हमारे देश में शहरी नियोजन और विकास की स्थिति दयनीय है। मुंबई और बेंगलुरु जैसे महानगरों में भी भवन निर्माण के नियमों की अनदेखी के चलते दुर्घटनाएं होती रहती हैं। सरकारी भवनों तक में सुरक्षा उपायों की अनदेखी होती है। समय रहते सख्ती नहीं की गई तो भविष्य में गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। आम जनता को भी जागरूक होना होगा।

अवनीश कुमार गुप्ता, पटना

पोस्ट

हमें सिखाया गया कि मुगल महान शासक थे, अहोम वंश के बारे में छात्रों को कभी नहीं पढ़ाया गया। ऐसे में इतिहास की किताबों को फिर से लिखे जाने की तत्काल आवश्यकता है। छात्रों को उनके पूर्वजों के बारे में बताना चाहिए।

प्रमोद कुमार सिंह@SinghPramod2784

अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी के बुलडोजर का विरोध करते रहे हैं, पर दिल्ली में ओल्ड राजेंद्र नगर हादसे में उनके बुलडोजर माडल की ही मांग कर बैठे।

दिव्य कुमार सोती@DivyaSoti

नई शिक्षा नीति लागू कर लीजिए, लेकिन कोटा, मुखर्जी नगर का कोचिंग का व्यापार हमारी ढहती शिक्षा व्यवस्था का चीखता स्मारक है। इन कोचिंगों में ऐसी कौन-सी घुट्टी पिलाई जाती है, जो सरकारी स्कूल, कालेज के अध्यापक और प्रोफेसर नहीं पढ़ा सकते हैं?

अतुल कुमार राय@AuthorAtul

जब तक भ्रष्ट और निकम्मा बाबू सिस्टम नहीं ठीक होगा, तब तक किसी को सत्ता में ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कभी करंट से मरो, कभी पानी भरने से।

सेलर@sailorsmoon

जनपथ

चर्चा है कुरुक्षेत्र की तो क्यों रखना मौन,
जनता ही अब तय करे अभिमन्यु है कौन?
अभिमन्यु है कौन किसे था सबने घेरा,
दुर्योधन है कौन कहां है उसका डेरा??
कुछ भी बोलो आप न लगता उसमें खर्चा,
पर निकले जब बात दूर तक जाए चर्चा!!

- ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व.पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान सम्पादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान सम्पादक -संजय गुप्त

जागरण प्रकाशन लिमिटेड के लिये आनन्द त्रिपाठी द्वारा दैनिक जागरण प्रेस C-5, C-6 & 15 इंडस्ट्रियल एरिया, पाटलिपुत्रा, पटना - 800013 से प्रकाशित एवं मुद्रित, सम्पादक (बिहार/प.बंगाल)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी, स्थानीय सम्पादक - आलोक मिश्रा * दूरभाष : 0612-2277071, 2277072, 2277073

E.mail : patna@pat.jagran.com, R.N.I. NO. BIHHIN/2000/03097* इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर.बी.एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी पटना जीपीओ रजि.नं. R-10/NP-18/14-16 समस्त विवाद पटना न्यायालय के अधीन ही होंगे। वर्ष 25 अंक 109

****

दैनिक जागरण

प्रसन्नता से स्वास्थ्य मिलेगा और चिंता से रोग

विभाजनकारी राजनीति

लोकसभा में आम बजट पर चर्चा करते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जिस तरह अपना यह पुराना आरोप नए सिरे से दोहराया कि बजट बनाने वालों में कोई एससी-एसटी और ओबीसी अधिकारी नहीं होता, उससे यदि कुछ स्पष्ट है तो यही कि वह समाज को बांटने वाली विभाजनकारी राजनीति पर अड़े हैं। वह यह बात पहले भी कई बार कह चुके हैं और सरकार की ओर से हर बार उन्हें विस्तार से यह बताया जा चुका है कि ऐसी स्थिति क्यों है और किस तरह इसके लिए कांग्रेस की तत्कालीन सरकारें ही जिम्मेदार हैं, लेकिन वह कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं। वह जानबूझकर इस तथ्य की भी अनदेखी कर रहे हैं कि संप्रग सरकार के समय भी यही स्थिति थी। वैसे तो उच्च स्तर की नौकरशाही में यथासंभव सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, लेकिन शासन के हर फैसले में शामिल अधिकारियों की जाति गिनना खतरनाक जातिवादी राजनीति है। राहुल गांधी एक तरह से यह कहना चाह रहे हैं कि अनारक्षित वर्गों के अधिकारी आरक्षित वर्गों के हितों की उपेक्षा करते हैं। एक बार वह यहां तक संकेत कर चुके हैं कि उच्च जाति के शिक्षक प्रश्नपत्र बनाते हैं, इसलिए आरक्षित वर्ग के छात्र फेल हो जाते हैं। आखिर यह भड़काऊ राजनीति नहीं तो और क्या है?

राहुल गांधी के रुख-रवैये से यही लगता है कि वह अभी भी चुनावी मुद्रा में हैं। आखिर वह जो कुछ मोदी सरकार से चाह रहे हैं, उसे कांग्रेस संगठन और साथ ही अपने दल द्वारा शासित राज्य सरकारों में क्यों लागू नहीं कर रहे हैं? क्या मोदी सरकार ने उन्हें ऐसा करने से रोक रखा है? उन्हें बताना चाहिए कि कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश में बजट बनाने में आरक्षित वर्गों के कितने अधिकारियों की हिस्सेदारी होती है? वह मोदी शासन की तरह मीडिया में भी आरक्षित वर्गों के प्रतिनिधित्व का प्रश्न भी कई बार उठा चुके हैं, लेकिन यह देखने को तैयार नहीं कि आखिर उनके परिवार के प्रभुत्व वाले मीडिया संस्थान में इन वर्गों के कितने लोगों की हिस्सेदारी है? राहुल गांधी ने बजट पर सरकार को घेरने के लिए महाभारत का उल्लेख करते हुए यह भी कह डाला कि जैसे अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेर लिया गया था, उसी तरह देश को भी मोदी सरकार ने घेर रखा है। उन्होंने प्रधानमंत्री समेत जिन छह लोगों को इस घेराबंदी के लिए जिम्मेदार ठहराया, उसमें अंबानी-अदाणी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और आरएसएस प्रमुख को भी शामिल कर लिया। स्पष्ट है कि वह मनमाने और बेतुके तर्क देने में संकोच नहीं कर रहे हैं। वह अपनी ऐसी बातों से चर्चा में तो आ जाते हैं और उनके समर्थक उनकी वाह-वाही करने में भी जुट जाते हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष के तौर पर वह न तो समाज को कोई सही दिशा दे पा रहे हैं और न ही सरकार को कोई सार्थक सुझाव।

आपदा प्रभावितों की पीड़ा

प्राकृतिक आपदाओं के लिहाज से अति संवेदनशील श्रेणी में शामिल उत्तराखंड में आपदा प्रभावितों की पीड़ा के निवारण में सिस्टम की सुस्ती परेशानी बढ़ा रही है। जो तस्वीर दिख रही है उससे यह भी कह सकते हैं कि सिस्टम ने आपदा प्रभावितों को एक प्रकार से उनके हाल पर छोड़ा हुआ है। प्रदेश के चार जिलों-उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में ग्यारह वर्ष पहले आपदा में नदी-नालों पर जो पुल बह गए थे, उनका पुनर्निर्माण अभी तक नहीं हो पाया है। इनमें ज्यादातर वह पुल हैं जो सुदूरवर्ती गांवों को जिला मुख्यालय से जोड़ते हैं। बावजूद इसके आपदा प्रभावितों का इंतजार बना हुआ है। वर्तमान में इन जनपदों में दो दर्जन स्थानों पर नदी-नालों को पार करने का एकमात्र साधन ट्रालियां हैं। कहीं पर लोक निर्माण विभाग ने तो कहीं पर स्थानीय लोगों ने इस तरह के प्रबंध किए हुए हैं। ट्राली के जरिये आवाजाही वाले स्थानों पर आए दिन जान का खतरा बना रहता है। उचित रखरखाव न होने के कारण ट्रालियों के नदी के ऊपर से गुजर रहे तारों पर अटकने की घटनाएं आम हैं। कुछ दिन पहले भी चमोली में इसी तरह लोग तीन घंटे तक उफनाती पिंडर नदी के ऊपर ट्राली पर फंसे रहे। मानसून काल में इस तरह के खतरे बढ़ जाते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न यह कि क्या इस तरह आपदा प्रभावितों के सब्र की परीक्षा ली जानी चाहिए? कब तक उनकी जिंदगी यूं ही तारों पर झूलती रहेगी? इस बारे में कौन सोचेगा और कब सोचेंगे? ट्राली वाले स्थानों पर पक्के पुलों के निर्माण की योजनाएं अफसरों की हीलाहवाली के चलते फाइलों से बाहर नहीं निकल पा रही हैं। कुछेक स्थानों पर जहां काम हो भी रहा है, उसकी गति बेहद धीमी है। इससे आपदा प्रभावितों की चिंता बढ़ रही है।

> आपदा प्रभावितों के धैर्य की परीक्षा नहीं ली जानी चाहिए। उनके कष्टों के निराकरण के लिए सिस्टम की सुस्ती तोड़ने की जरूरत है

आत्मघाती अंतर्कलह से बचे भाजपा

राज कुमार सिंह

चुनावी प्रदर्शन की समीक्षा से कई राज्यों में भाजपा में असंतोष के जो स्वर मुखर हो रहे हैं, उनसे लगता है कि कमजोरियों की जांच-पड़ताल गलत दिशा में जा रही है

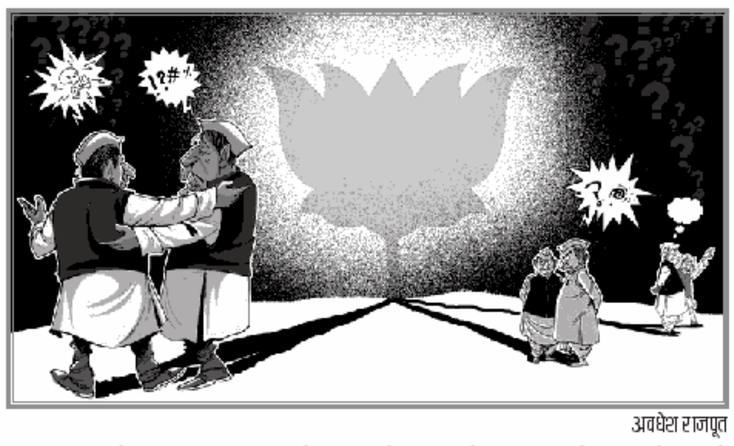

अवधेश राजपूत

भाजपा के स्वीकार न करने से यह सच नहीं बदल जाएगा कि 18वीं लोकसभा चुनाव में उसे बड़ा झटका लगा। पांच साल के शासन के बाद 2019 में पिछली बार से भी 21 सीटें ज्यादा जीतने वाली भाजपा इस बार 240 पर सिमट गई। 1984 में दो सीटों से 2019 में 303 सीटों तक का सफर तय करने वाली भाजपा इस झटके को नजरअंदाज नहीं कर सकती, लेकिन चुनावी प्रदर्शन की समीक्षा से कई राज्यों में असंतोष के जो स्वर मुखर हो रहे हैं, उनसे लगता है कि कमजोरियों की जांच-पड़ताल गलत दिशा में जा रही है। कमजोर प्रदर्शन के कारणों की पहचान अंतर्कलह को हवा दे रही है। निश्चय ही कमजोर प्रदर्शन के कुछ कारण रहे होंगे, पर उनकी पहचान नीति-रणनीति के बजाय सिर्फ व्यक्तियों के रूप में किए जाने का रास्ता अंततः आत्मघाती अंतर्कलह को जन्म देता है। 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 400 से भी ज्यादा सीटें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या से उपजी सहानुभूति से मिली थीं, लेकिन वही कांग्रेस 2014 में 44 और 2019 में 52 सीटों पर सिमट गई तो उसके लिए उसका अंतर्कलह भी जिम्मेदार रहा। 18वीं लोकसभा चुनाव में भाजपा ने अपने लिए 370 और राजग के लिए 400 सीटों का नारा दिया था, लेकिन परिणाम दावों से बहुत कम आए। चुनाव से पहले जुड़े तेदेपा और जदयू जैसे सहयोगियों की बदौलत राजग ने बहुमत से भी 19 ज्यादा यानी 293 सीटें हासिल कर लीं, पर उत्तर प्रदेश से लेकर कर्नाटक तक और बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक भाजपा का चुनावी प्रदर्शन निराशाजनक रहा।

हर राज्य के अपने राजनीतिक-सामाजिक समीकरण होते हैं। इसलिए हर राज्य में हार के कारणों की समीक्षा में एक फार्मूला नहीं चल सकता। हां, एक कारण ज्यादातर राज्यों में समान हो सकता है कि राष्ट्रीय नेतृत्व, खासकर प्रधानमंत्री मोदी के करिश्मे पर निर्भर संगठन ज्यादा सक्रिय नहीं हुआ। कार्यकर्ता कमर कसकर मैदान में नहीं उतरे। जब बड़े नेता दावा कर रहे थे कि देश ने इस बार 400 पार का मन बना लिया है तो शायद कार्यकर्ताओं को पिछले दो चुनावों की तरह 'मेरा बूथ सबसे मजबूत' जैसे जुनून के साथ काम करने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव वाले महाराष्ट्र में राजग की सीटें आधी से भी कम रह जाना, हरियाणा में आधी सीटें हार जाना और झारखंड में 12 से आठ पर आ जाना भाजपा के लिए कम झटका नहीं है। बंगाल में सीटें बढ़ने के दावों के बीच 18 से भी घटकर 12 रह जाना भी बड़ा झटका है। झटका कर्नाटक और राजस्थान में भी लगा। हाल में जिन सात राज्यों में 13 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हुए, उनमें भी मध्य प्रदेश के अलावा भाजपा का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। ऐसे में कमतर प्रदर्शन के कारणों की समीक्षा और भी जरूरी है, पर यह सुनिश्चित करना आलाकमान की जिम्मेदारी है कि इसकी आड़ में महत्वाकांक्षी नेता अंतर्कलह को हवा न दे पाएं। पार्टी में ही अपने विरोधियों पर निशाना साधने की कोशिश अन्य राज्यों में भी है, पर यूपी में तो यह कवायद पूरी तरह अंतर्कलह में तब्दील नजर आती है।

जब भाजपा के अंदर से ही यूपी में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों को हवा दी जा रही हो तो फिर मुख्य विपक्षी दल सपा के मुखिया अखिलेश यादव 'सौ लाओ, सरकार बनाओ' का मानसूनी आफर देने से क्यों चूकेंगे? सच है कि भाजपा आलाकमान ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बदलने का संकेत नहीं दिया, लेकिन यह भी तो सच है कि लोकसभा चुनाव बाद और जोर पकड़ गई ऐसी अटकलों का खंडन भी नहीं किया। 2014 के लोकसभा चुनाव में जब भाजपा ने उत्तर प्रदेश की 80 में 71 सीटें जीतने का करिश्माई प्रदर्शन किया था, तब योगी सिर्फ एक सांसद थे। उस समय केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश अध्यक्ष और अमित शाह मुख्य चुनावी रणनीतिकार थे, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत मिलने पर मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद योगी राष्ट्रीय स्तर पर भी पार्टी के स्टार प्रचारक के रूप में उभरे। आज प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री शाह के साथ वही भाजपा का तीसरा बड़ा चेहरा हैं। बुलडोजर न्याय की आलोचना के बावजूद राज्य की शासकीय व्यवस्था में सुधार से इन्कार नहीं किया जा सकता। निःसंदेह 2019 के लोकसभा चुनाव में भी उत्तर प्रदेश में भाजपा की सीटें घट कर 62 रह गई थीं और 2022 के विधानसभा चुनाव में भी सीटें घटीं, लेकिन क्या उसके लिए अकेले योगी को जिम्मेदार ठहराना तर्कसंगत है? केशव प्रसाद मौर्य तो अपनी विधानसभा सीट हारने के बाद भी उपमुख्यमंत्री बनाए गए। क्या 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा-बसपा गठबंधन बड़ा कारक नहीं रहा? क्या किसान आंदोलन 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रमुख कारक नहीं था? फिर भी भाजपा लोकसभा की 80 में से 62 सीटें जीत गई और बहुमत से दूसरी बार सरकार भी बना ली तो क्या उसका तनिक भी श्रेय मुख्यमंत्री को नहीं मिलना चाहिए?

योगी की अपनी कार्यशैली है। वह किसी दबाव के बिना जो सही लगता है, वही फैसला लेते हैं, पर क्या मुख्यमंत्री बनाते समय यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता नहीं थी? असल कारण तो आलाकमान ही बेहतर जानता होगा, लेकिन अगर दोनों उपमुख्यमंत्री ही कैबिनेट समेत जरूरी बैठकों में शामिल होना जरूरी न समझें तो सार्वजनिक रूप से मुख्यमंत्री की क्या छवि बनेगी? राज्य में समीक्षा बैठकों के बाद शायद पहली बार दिल्ली में दोनों उपमुख्यमंत्री मुख्यमंत्री के साथ नजर आए। किसी राज्य का मुख्यमंत्री बदलना कोई अनहोनी घटना नहीं। कांग्रेस में तो एयरपोर्ट पर ही मुख्यमंत्री बदलने का फरमान सुना दिया जाता था। भाजपा ने भी कभी दिल्ली तो कभी उत्तराखंड में बीच कार्यकाल मुख्यमंत्री बदले। गुजरात में तो पहली बार के विधायक भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाते हुए पूरा मंत्रिमंडल ही बदल दिया गया, पर क्या चेहरा बदल देना भर चुनाव जीतने की गारंटी है? जिन राज्यों में चुनावी प्रदर्शन निराशाजनक रहा, वहां बेहतरी के लिए भाजपा आलाकमान को कदम उठाने ही चाहिए, लेकिन इस तरह नहीं कि अनुशासित पार्टी की परंपरागत छवि को तार-तार होकर अंतर्कलह मीडिया की सुर्खियों से लेकर चौपालों तक पर चर्चा का विषय बन जाए।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं)

response@jagran.com

अपनी सीमा पार करतीं ममता बनर्जी

अवधेश कुमार

ममता सरकार सीएए के तहत तो लोगों को नागरिकता देने के विरोध में है, लेकिन बांग्लादेशियों को शरण देने को उतावली है

शहीद दिवस रैली को संबोधित करतीं ममता। फाइल

पिछले दिनों तृणमूल कांग्रेस की शहीद दिवस रैली में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा बांग्लादेश के लोगों को राज्य में शरण देने का बयान हतप्रभ करने वाला रहा। सामान्य तौर पर किसी राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा ऐसे बयान की कल्पना नहीं की जा सकती है। अंतरराष्ट्रीय नियम कहते हैं कि किसी दूसरे देश की आंतरिक समस्या में तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जाता, जब तक वहां मानवाधिकारों का लगातार सरेआम उल्लंघन नहीं हो रहा हो। संबंधित देश अगर अपने निर्दोष नागरिकों के विरुद्ध अत्याचार करने लगे तभी अंतरराष्ट्रीय समुदाय या कोई देश उसके खिलाफ सामने आ सकता है, लेकिन यह भी राष्ट्र की नीति होती है, किसी राज्य की नहीं। राज्य सरकार ज्यादा से ज्यादा केंद्र के समक्ष अपनी इच्छा प्रकट कर सकती है कि हमें इस संदर्भ में कैसी नीति अपनानी चाहिए। यह चिंताजनक है कि देश की एक मुख्यमंत्री, जो केंद्र में भी मंत्री रह चुकी हैं, सरेआम अपनी संवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन करें। इस तरह का बयान देने का हक प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री या फिर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता को ही हो सकता है। बांग्लादेश को ममता बनर्जी का यह वक्तव्य स्वाभाविक ही आपत्तिजनक लगा है, तभी सधे हुए शब्दों में वहां की सरकार ने इसका प्रतिवाद किया।

ममता बनर्जी का बयान अनायास नहीं हो सकता। वास्तव में बंगाल में लगभग 30 प्रतिशत मुस्लिम वोट उनके सत्ता में बने रहने का एक बड़ा आधार बन चुका है। लगता है वह इसके लिए किसी सीमा तक जाने को तैयार हैं। मुस्लिम वोट की राजनीति भारत में ऐसे ही होती रही है। यही ममता बनर्जी बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में मजहबी रूप से पीड़ित गैर मुसलमानों को मानवता के आधार पर नागरिकता देने के लिए भारत सरकार द्वारा बनाए गए कानून सीएए का मुखर होकर विरोध कर रही हैं। भारत के ज्यादातर दलों ने सेक्युलरवाद की इसी तरह धज्जियां उड़ाई हैं। भारत ने दूसरे देशों के नागरिकों को शरण दी है। उदाहरण के लिए म्यांमार से आए 79 हजार शरणार्थी भारत में रह रहे हैं। तमिलनाडु के शरणार्थी शिविरों में श्रीलंका से आए 58 हजार 457 श्रीलंकाई तमिल रह रहे हैं। 1959 में तिब्बत में चीनी हस्तक्षेप के बाद बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा के साथ आए लगभग एक लाख शरणार्थी भी अलग-अलग जगहों पर शरण पाए हुए हैं। यह निर्णय किसी राज्य सरकार ने नहीं किया। ममता बनर्जी ने भारत के स्वयंभू शासन की तरह व्यवहार किया है। उन्हें पता होना चाहिए कि शरण देने का दायित्व भी केंद्र सरकार का ही है, कोई राज्य सरकार ऐसा नहीं कर सकती। यद्यपि हमारे देश में शरण देने को लेकर कोई उपयुक्त कानून नहीं है। भारत संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी संबंधी व्यवस्था का सदस्य नहीं है। इसी तरह 1990 में प्रवासी मजदूरों के लिए तैयार कन्वेंशन आफ माइग्रेंट वर्कर्स के 59 सदस्य देशों में भी भारत नहीं है। 1967 के प्रोटोकाल रिलेटेड टू द स्टेटस आफ रिफ्यूजीज पर भी भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया है। हालांकि भारत अपनी स्वाभाविक संवेदनशीलता के अनुरूप इनका पालन करता है।

एक तरफ विपक्षी सांसद संविधान लहराते हुए बता रहे हैं कि हम संविधान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं और दूसरी ओर ममता बनर्जी स्वयं इस तरह संविधान का उल्लंघन करती नजर आ रही हैं। क्या ममता का बयान संघीय ढांचे पर प्रहार नहीं है? अगर ममता बनर्जी के बयान का विरोध नहीं हुआ तो आगे कोई दूसरी राज्य सरकार पाकिस्तान, अफगानिस्तान या फिर चीन को लेकर भी दरवाजा खोलने की बात कर सकती है। जिन पश्चिमी देशों ने संयुक्त राष्ट्र के तहत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शरणार्थियों और आप्रवासियों के लिए लोकतंत्र और मानवाधिकार आदि राजनीतिक विचारधारा के नाम पर निहित स्वार्थों के कारण आश्रय देने की व्यवस्थाएं बनवाईं, अपने यहां मानवाधिकारों एवं मजहबी स्वतंत्रता की रक्षा के नाम पर कानून बनाए और फिर दुनिया को भी ऐसा ही करने की सीख दी, आज उन्हीं देशों में इसके विरुद्ध कदम उठाए जा रहे हैं। अमेरिका से लेकर पूरे यूरोप में बिना पासपोर्ट, वीजा के विकासशील और गरीब देश के लोगों के प्रवेश को रोका जा रहा है। उन देशों की राजनीति में यह बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इसके आधार पर आज वहां के नेताओं एवं पार्टियों को वोट मिल रहा है। वे देश इसके कारण आंतरिक अशांति के शिकार हो गए हैं और इससे मुक्ति चाहते हैं। उन्होंने मानवाधिकार, लोकतंत्र एवं मजहबी स्वतंत्रता आदि के नाम पर ऐसे स्टैंड लिए कि आज अपने ही देश की रक्षा की दृष्टि से उसके विरुद्ध खड़ा होना कठिन हो रहा है। हमारे देश के नेताओं ने इसका अनुमान आजादी के बाद ही लगा लिया था कि पड़ोसी देशों की हालत खराब होने का शिकार हम हो सकते हैं। इसीलिए उन्होंने विनम्रता के साथ संयुक्त राष्ट्र की ऐसी किसी व्यवस्था पर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया था और यह नीति आज तक जारी है। किंतु वर्तमान राजनीति में अनेक विपक्षी दल उसी तरह की भाषा बोल रहे हैं, जैसी एक समय पश्चिम में स्वयं को लेफ्ट-लिबरल मानने वाले बोलते थे तथा सरकारों ने उन नीतियों को लागू किया।

राजनीति में एक-दूसरे का प्रतिस्पर्धी या विरोधी होना स्वाभाविक है, किंतु इसके लिए देश की सुरक्षा और आंतरिक व्यवस्था को जोखिम में डालना किसी दृष्टि से स्वीकार नहीं किया जा सकता। ममता बनर्जी को कम से कम अपने बयान पर खेद प्रकट करना चाहिए। विपक्ष के नेताओं को भी आगे आकर बोलना चाहिए कि हमारी राजनीतिक लड़ाई आंतरिक है, किसी बाहरी देश के मामले में भारत सरकार का निर्णय ही मान्य होगा।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

चरैवेति चरैवेति

समय गतिवान है, जीवन गतिमान है। मन गतिवान है, बुद्धि गतिवान है। प्रतिभा गतिमान है, विकास गतिवान है। धर्म गतिमान है, नीति गतिवान है। समाज गतिमान है, देश गतिवान है। संसार गतिवान है, प्रकृति गतिमान है। इसलिए अणु के अंदर परमाणु गतिमय है। शरीर के भीतर आत्मा गतिमान है। गतिवान रहना ही कर्मयोग है। सांस चलती रहती है, तभी तक जीवन है। जीव चलता रहता है, तब तक जीवित है। अर्थात चलते जाना-चलते रहना-यही जीवन की गति है, दशा है, स्थिति है। रुकना मृत्यु की दशा है, दिशा है। अहर्निश चलने का नाम ही तो जिंदगी है। जन्म से लेकर मृत्यु तक चलते ही रहना है, रुकना नहीं है। आगे बढ़ना है, दौड़ना है, संघर्षरत रहना है।

चरैवेति चरैवेति। अर्थात चलते रहना, चलते रहना। रुकना नहीं, ठहरना नहीं, जड़ता नहीं। हर हाल में गतिमान रहना, यही जीवन का मंत्र है। सदा गतिशील रहना, यह लोक दर्शन है। पल-पल सक्रिय होना, यह जीव मात्र का नियम है। अनवरत संघर्षरत होना, यह मानव की नियति है। चलते रहो, पग-पग आगे बढ़ते रहो-यही मानव विकास का मार्ग है। कर्तव्य पथ पर कभी ठहरना नहीं है। जिस तरह धर्म का चक्र चलता रहता है, उसी प्रकार कर्म का रथ भी बराबर चलता रहता है। सूर्य, चंद्र और नक्षत्रमंडल अनवरत यात्रा करते हैं। कर्म करते रहना और गतिमय बने रहना जगत का आधार है, ईश्वरीय आदेश है। जो ठहर गया, गतिहीन हो गया-उसे निर्जीव मान कर समाज से बाहर फेंक दिया जाता है।

गति की क्षमता प्रकृति ने सबको दी है, लेकिन मन जितनी उड़ान भर सकता है, शरीर कभी ऐसा नहीं कर सकता। जीव गति के ही आलंब हैं। यह परिवर्तन का भी सूचक है, जो प्राकृतिक प्रक्रिया है। विधि का विधान क्रमिक विकास को बाधित नहीं करता। चरैवेति चरैवेति का मंत्र मानव जीवन का रहस्य है।

डा. राघवेंद्र शुक्ल

नशे के विरुद्ध एकजुट हो समाज

आयुषी दवे

प्रधानमंत्री मोदी का भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य युवा पीढ़ी को ड्रग्स के अभिशाप से दूर रखकर ही संभव है

पिछले दिनों 'मन की बात' में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों से ड्रग्स की चुनौती की चर्चा की, जो एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। सचमुच आज के बदलते परिवेश में हर परिवार चिंतित रहता है कि कहीं उनका बच्चा इसकी चपेट में न आ जाए? समूचे विश्व में नशे का कारोबार 30 लाख करोड़ रुपये से भी अधिक का है। भारत में लगभग 10 लाख करोड़ रुपयों के ड्रग्स का अवैध कारोबार है। अलग-अलग राज्यों के लोग विभिन्न नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे हैं। बीते कुछ वर्षों की बात करें तो पंजाब, केरल, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में नशा करने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है।

भारत में नशीले पदार्थों के सेवन करने वालों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट, 1985 की अलग-अलग धाराओं में कार्रवाई की जाती है। इसमें नशे का सेवन करना, बेचना, घर में रखना और ड्रग्स कारोबारियों की मदद पर सजा का प्रविधान है, लेकिन फिर भी नशे की प्रवृत्ति बढ़ना चिंताजनक है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का एक डाटा बताता है कि अकेले वर्ष 2022-23 में सरकार ने लगभग 100 करोड़ रुपये विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नशा उन्मूलन और पीड़ितों की मदद के लिए दिए। यकीनन नशा नहीं करने से बचा पैसा दूसरे विकास कार्यों में लग सकता है, लेकिन वर्षों से सरकारों को मजबूरन अपना खजाना इन कामों में खर्च करना पड़ रहा है। नशे की गिरफ्त में फंसे लोगों की मदद के लिए एक नया विशेष केंद्र 'मानस' भी अब कार्यरत है। इसे ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई में बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। इसके लिए हेल्पलाइन, पोर्टल के साथ एक टाल फ्री नंबर 1933 है। इस पर कोई भी न केवल जरूरी परामर्श ले सकता है, बल्कि ड्रग्स से जुड़ी कोई जानकारी गोपनीय तौर पर भी दे सकता है। कुछ दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने भी नशा रोकने में जुड़ी सभी एजेंसियों को चेताया था कि ड्रग्स के कारोबार से जुड़े पूरे अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का भांडाफोड़ करना होगा, महज नशा करने वालों को पकड़ने से काम नहीं चलेगा। इससे कमाया पैसा देश की सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरा भी है। कोशिश हो कि एक ग्राम ड्रग्स भी भारत में नहीं आने पाए।

निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी का 2047 तक भारत को हर क्षेत्र में सर्वप्रथम बनाने का लक्ष्य है। यह युवा पीढ़ी को ड्रग्स के अभिशाप से दूर रखकर ही संभव है। इसके लिए समन्वित प्रयासों की जरूरत है। इसमें केंद्र एवं राज्य सरकारें, संबंधित एजेंसियां और आमजन भी जुड़ें। सख्ती से ज्यादा ड्रग्स के खिलाफ जागरूकता की जरूरत है, ताकि सब समझें कि यह कैसे न केवल हमारे शरीर, बल्कि देश-दुनिया के लिए भी घातक है।

(लेखिका इंजीनियर हैं)

समृद्ध है भारत की संस्कृति

हृदयनारायण दीक्षित का 'धरोहरों के संरक्षण का कर्तव्य' शीर्षक से प्रकाशित आलेख पढ़ा। उन्होंने भारत में उपस्थित प्राचीन धरोहरों के संरक्षण और संवर्धन की आवश्यकता पर जोर दिया है। यह वर्तमान समय की मांग भी है, क्योंकि प्राचीन स्मारक सभ्यता और संस्कृति के संवाहक और राष्ट्र की धरोहर होते हैं। हाल में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति ने असम के अहोम राजवंश के 'मैदाम' को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। यह मैदाम असम के चराइदेव जिले में अहोम राजवंश की कब्रगाह है। अहोम असम में उपस्थित एक अति समृद्ध और शक्तिशाली राजवंश था जिसने असम पर 600 साल तक राज किया। इसकी अपनी विशिष्ट धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान थी। हालांकि भारत में अब तक केवल 43 स्थल ही विश्व धरोहर की सूची में शामिल हैं, जो एक चिंतनीय स्थिति है, क्योंकि दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जिसका गौरवशाली इतिहास रहा है। यहां सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक काल, मौर्य काल, गुप्त काल, विजयनगर साम्राज्य आदि रहे हैं। यहां पर कई प्रकार की विशिष्ट कलाएं हैं। जैसे गांधार, मथुरा और अमरावती मूर्ति कलाएं, नगर, द्रविड़ और वेसर मंदिर कलाएं और लेखन में रामायण एवं महाभारत जैसे महाकाव्य तथा वेद, पुराण, उपनिषद, अर्थशास्त्र आदि उपस्थित हैं। अतः हम अपने समृद्ध इतिहास को पहले तो स्वयं जानें एवं समझें और उसे दुनिया के सामने प्रस्तुत करें।

गुलशन कुमार, फरीदाबाद

मेलबाक्स

बेबसी के बीच बहे सपने

दिल्ली में कोचिंग संस्थान में हुई त्रासदी केवल एक दुर्घटना नहीं है, बल्कि एक संगठित लापरवाही और भ्रष्टाचार का परिणाम है। इस घटना ने प्रशासन और नगर निगम की व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है। यह घटना हमें याद दिलाती है कि हमारी नागरिक संरचनाओं में कितनी गहरी समस्याएं मौजूद हैं। मूल समस्या प्रशासनिक लापरवाही और भ्रष्टाचार की है। जब तक इन समस्याओं को जड़ से नहीं उखाड़ा जाएगा, इस प्रकार की घटनाएं होती रहेंगी। कोचिंग संस्थान के संचालकों और नगर निगम के अधिकारियों के बीच मिलीभगत साफ नजर आती है। इस प्रकार के संस्थान सुरक्षा मानकों की अनदेखी कर रहे हैं, जिससे मासूम छात्रों की जान खतरे में पड़ रही है। इस समस्या का समाधान कठोर नियमन और निगरानी से ही संभव है। सरकार को चाहिए कि वह सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करवाए और दोषी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करे। इसके अलावा नगर निगम को अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेना चाहिए और हर निर्माण स्थल की नियमित जांच करनी चाहिए। हमारे देश में शहरी नियोजन और विकास की स्थिति दयनीय है। यह स्थिति तब है, जब यह अनुमान है कि 2030 तक देश की 40 प्रतिशत आबादी शहरों में होगी। ऐसे में यह कहना उचित है कि जब हम मौजूदा आबादी का बोझ ढोने में नाकाम है तो आगे क्या होगा? मुंबई और बेंगलुरु जैसे महानगरों में भी भवन निर्माण के नियमों की अनदेखी के चलते दुर्घटनाएं होती रहती हैं। सरकारी भवनों तक में सुरक्षा उपायों की अनदेखी होती है। यहां की नगर निगम और प्रशासनिक अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। इससे साफ जाहिर होता है कि हमारे देश में नियम-कानून केवल कागजों पर ही सीमित हैं। नगर नियोजन विभाग और नगर निगम के अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कराना होगा और उन्हें जवाबदेह बनाना होगा। आखिरकार, इस घटना ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। यदि हम समय रहते इन समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे, तो भविष्य में और भी गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। जनता को भी जागरूक होना होगा और अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा। केवल तभी हम एक सुरक्षित और स्वस्थ समाज की कल्पना कर सकते हैं।

awanishg30@gmail.com

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए; नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,एफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

****

प्रवाह

महोत्सव विश्वास का 75

निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक
स्थापना वर्ष : 1948

खून-पसीने की कमाई पर कम और पूंजीगत लाभ पर उच्च दर से कर लगाया जाना चाहिए। -जॉन सी बोगल

यूनेस्को की रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया के सिर्फ सात फीसदी स्कूलों ने लड़कों व लड़कियों की शारीरिक शिक्षा के लिए एक समान समय रखा है। इसके बावजूद हरियाणा की मनु भाकर का पेरिस ओलंपिक में इतिहास रचना दर्शाता है कि अगर महिलाओं को पर्याप्त अवसर मिले, तो वे असाधारण ऊंचाइयां छू सकती हैं।

ताकि हर लड़की हो 'मनु'

देश के न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य हरियाणा के झज्जर की रहने वाली 22 वर्षीय मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में दस मीटर एयर पिस्टल के फाइनल में कांस्य पदक पर निशाना लगाकर इतिहास तो रचा ही है, अपनी इस उपलब्धि से उन्होंने यह भी साबित किया है कि अगर महिलाओं को पर्याप्त अवसर व प्रोत्साहन मिले, तो वे असाधारण ऊंचाइयों को छू सकती हैं। 2020 के टोक्यो ओलंपिक में भी पदक की दावेदार मानी जा रही मनु पिस्टल में खराबी की वजह से बेशक उस वक्त चूक गई थीं, लेकिन पेरिस में जिस तरह की उन्होंने वापसी की है, उससे अन्य स्पर्धाओं में भी उनके पदक जीतने की उम्मीदें तो बढ़ी ही हैं, उनकी उपलब्धि पेरिस में भारतीय दल का उत्साह बढ़ाने वाली भी है। मनु का यह पदक इसलिए भी खास है कि वह निशानेबाजी में ओलंपिक पदक जीतने वाली देश की पहली महिला खिलाड़ी तो बनी ही हैं, साथ ही, उन्होंने इस खेल में पदकों का बारह साल का सूखा भी खत्म किया है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले 2012 ओलंपिक में विजय कुमार ने रजत और गगन नारंग ने कांस्य पदक, तो 2008 ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने स्वर्ण और 2004 ओलंपिक में राज्यवर्धन राठौर, जो फिलहाल राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं, ने रजत पदक जीता था। मनु भाकर की इस ऐतिहासिक उपलब्धि का महत्व तब ज्यादा समझ में आता है, जब इसे हाल ही में यूनेस्को द्वारा प्रकाशित 'ग्लोबल स्टेट ऑफ प्ले' रिपोर्ट के संदर्भ में देखा जाए। रिपोर्ट खुलासा करती है कि दुनिया के महज 58 फीसदी देशों ने बालिकाओं के लिए शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य बनाया है। रिपोर्ट का यह कहना भी बेहद गंभीर है कि दुनिया के सिर्फ सात फीसदी स्कूलों ने लड़कों व लड़कियों के लिए शारीरिक शिक्षा का एक समान वक्त रखा है। एक ओर मनु भाकर की प्रेरणादायक सफलता है, तो दूसरी ओर यूनेस्को की रिपोर्ट की हकीकत है, जो दर्शाती है कि ज्यादातर देशों में बालिकाओं को अब भी वह मंच नहीं मिल सका है, जिसकी उन्हें जरूरत है। दुखद है कि खेलों के लिए खुद को तैयार कर रहे युवाओं को लैंगिक आधार पर कई तरह की असमानताओं का सामना करना पड़ता है। लिहाजा, हमें अपने समाज और स्कूलों में बालिकाओं के लिए खेलों में समान अवसर प्रदान करने के लिए और अधिक प्रयास करने की जरूरत है। ऐसी नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने की भी जरूरत है, जो बालिकाओं को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें और आवश्यक संसाधन और समर्थन भी प्रदान करें।

क्या पाया, क्या खोया

बजट के बाद बहस के केंद्र में आए कैपिटल गेन टैक्स बदलावों का असर अगले साल राजस्व संग्रह के आंकड़े आने के बाद ही स्पष्ट होगा। तब तक इस पर ही संतोष करना होगा कि ये बदलाव कर ढांचे के सरलीकरण की दिशा में हैं।

आम बजट के जिस प्रस्ताव से सबसे ज्यादा बहस उपजी, वह है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की दर में बदलाव और उससे जुड़े महंगाई सूचकांक समायोजन की विदाई। आम चर्चा में इसे इंडेक्सेशन बेनिफिट की समाप्ति बताया जा रहा है। बजट प्रस्तुति के हफ्ते भर बाद, अब जब यह तय है कि इस प्रस्ताव की वापसी की कोई संभावना नहीं, तो बेहतर होगा कि हम इसे स्वीकारें और समझने की कोशिश करें कि आम आदमी के लिए इसके क्या मायने हैं।

सबसे पहले आसान शब्दों में समझिए कि हुआ क्या है। मुख्यतः चार बदलाव हुए हैं। एक तो वित्त मंत्री ने पूंजीगत लाभ गणना की अवधि की परिभाषा बदल दी। शेयर बाजार में सूचीबद्ध प्रतिभूतियों के लिए एक साल से अधिक की होल्डिंग अवधि के लाभ को दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कहा जाएगा, तो दूसरी ओर, रियल एस्टेट, सोना, गैर-सूचीबद्ध प्रतिभूतियों, बॉन्ड, डिबेंचर जैसे अन्य सभी वर्गों में लगी पूंजी के लिए यह कट ऑफ अवधि दो साल हो गई। पहले इन वर्गों में अलग-अलग अवधियों से लॉन्ग टर्म लाभ तय होता था। दूसरा बदलाव यह कि टैक्स दरों में एकरूपता लाई गई। अब सभी निवेश वर्गों में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की एक ही दर (12.5 प्रतिशत) तय हो गई है। पहले यह प्रतिभूति बाजार के लिए 10 प्रतिशत और अन्य वर्गों के लिए 20 प्रतिशत होती थी। इक्विटी निवेश और इक्विटी म्यूचुअल फंडों के 12 माह से कम अवधि वाले अर्थात शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स की दर 15 से बढ़कर 20 फीसदी हुई है, जबकि गैर-इक्विटी निवेश वाले अन्य सभी वर्गों पर यह दर इनकम टैक्स के स्लैब ढांचे के तहत सामान्य आय मानकर तय होगी।

संजय अभिज्ञान
वरिष्ठ पत्रकार

तीसरा परिवर्तन यह कि टैक्स गणना में महंगाई के असर को शून्य करने के लिए जिन लागत सूचकांकों के आधार पर वास्तविक कीमत का हिसाब लगाया जाता था, वे विदा हुए। लंबी निवेश होल्डिंग अवधि वाले रियल एस्टेट जैसे सेक्टर के लिए तय किया गया है कि 2001 से पहले खरीदी गई सभी संपत्तियों के लिए ही इंडेक्सेशन बेनिफिट कायम रहेगा।

मतलब स्वर्ण या अचल संपत्तियों के लिए सरकारी मान्यता प्राप्त वेल्यूअर के उचित मूल्य प्रमाणपत्रों की आवश्यकता पड़ेगी, जो वे पुराने दौर से जुड़े सूचकांकों के आधार पर तैयार करेंगे। चौथा अहम बदलाव यह हुआ है कि म्यूचुअल फंडों में भी उनके निवेश पोर्टफोलियो की प्रकृति के हिसाब से दीर्घकालिक लाभ कर गणना होगी।

ये चारों बदलाव अच्छे हैं या बुरे? आर्थिक विवेक के तराजू पर तौलें, तो तीन बदलाव ऐसे हैं, जिनकी अच्छाई पर कोई विवाद ही नहीं। चूंकि अल्पकालिक लाभ पर टैक्स की दरें ज्यादा होती हैं, तो अच्छा ही है कि एक आम विक्रेता को अब रियायती दर के लिए तीन के बजाय केवल दो साल प्रतीक्षा करनी होगी। लिहाजा लॉन्ग टर्म की पात्रता का केवल 24 माह रह जाना स्वागतयोग्य है। इसी तरह सभी वर्गों में लॉन्ग टर्म टैक्स की एक ही (12.5 प्रतिशत) दर तय होना टैक्स ढांचा सरलीकरण का बड़ा कदम है। दस फीसदी से 20 फीसदी या दरम्यानी दरों का मकड़जाल विदा होने से सबको फायदा होगा-टैक्स अफसरों को, चार्टर्ड अकाउंटेंटों को और उन सभी करदाताओं को भी, जो अपनी टैक्स रिटर्न खुद भरना चाहते हैं। इसी तरह सोने या बॉन्ड में निवेश करने वाले अधिक सुरक्षित फंडों के ट्रीटमेंट को, शेयर बाजार में निवेश करने वाले-अधिक जोखिम, अधिक रिटर्न मार्का-फंडों से अलग करने की पहल भी उचित ही है, क्योंकि सबको एक ही लाठी से हांकने की जिद क्यों कायम रहे?

केवल एक बदलाव पर विवाद है। मकान-दुकान की खरीद कीमत और बिक्री कीमत के अंतर में से महंगाई के असर को निकाल बाहर करने की प्रैक्टिस समाप्त हो गई। दस साल पहले 40 लाख में खरीदा मकान आज अगर 90 लाख का बिका है, तो क्या समूचे 50 लाख के अंतर पर टैक्स की गणना हो? नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इन वर्षों में रुपये की कीमत भी तो गिरी। इसीलिए लागत सूचकांक के आधार पर खरीद और बिक्री के अंतर को कम करके वास्तविक मुनाफे का हिसाब लगाया जाता रहा है। यही इंडेक्सेशन या महंगाई सूचकांक समायोजन विदा हुआ है। आलोचक कह रहे हैं कि यह देखो, इंडेक्सेशन विदा हो गया। प्रशंसक कहते हैं कि यह देखो, टैक्स 20 से घटाकर साढ़े 12 प्रतिशत कर दिया। विरोधियों को अंदेशा है कि मकान-दुकान बेचने वाले ज्यादातर लोगों की टैक्स अदायगी बढ़ेगी। समर्थक कहते हैं कि ज्यादातर की टैक्स देनदारी कम होगी। वस्तुस्थिति यह है कि दोनों के दावे फिलहाल भरोसेमंद नहीं। वित्त वर्ष के अंत में टैक्स कलेक्शन आंकड़े आने तक कुछ नहीं कहा जा सकता। आमतौर पर टैक्स की दर कम होने से कुल कर राजस्व संग्रह बढ़ता है। लेकिन वित्त मंत्री ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की मद में अनुमानित राजस्व वृद्धि या कमी का आंकड़ा ही नहीं दिया है। मतलब स्वयं मंत्रालय को भरोसा नहीं कि खजाने को फायदा होगा या नहीं। चूंकि इक्विटी निवेशकों के आंसू पोंछने के लिए लॉन्ग टर्म टैक्स की छूट सीमा एक लाख से बढ़ाकर सवा लाख कर दी गई है, अंततः कुल राजस्व में नुकसान भी संभव है।

दूसरी आपत्तियां ज्यादा काबिलेगौर हैं। आरोप है कि 2001 के बाद खरीदी गई संपत्ति के लिए इंडेक्सेशन बेनिफिट खत्म करके, सरकार पिछले दरवाजे से वेल्थ टैक्स या विरासत कर थोपना चाहती है, हालांकि इस बात में ज्यादा दम नहीं, क्योंकि लाभ को नई प्रॉपर्टी या विशेष बॉन्ड में पुनर्निवेश करके अपने लाभ को यथावत रखने के पुराने प्रावधान यथावत हैं। दूसरा तर्क है कि वर्ष 2001 को कट आफ ईयर मानने के बजाय 2007 को कट ऑफ ईयर मानना चाहिए था, क्योंकि उससे पहले दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में सर्कल रेट ही लागू नहीं हुआ था। तीसरी शंका है कि प्रस्तावित कैपिटल गेन टैक्स ढांचा प्रॉपर्टी बाजार को काले धन का पार्किंग अड्डा बनाने की बड़ी बीमारी का सीधा इलाज नहीं करता। प्रॉपर्टी सौदों में टैक्स या स्टांप शुल्क बचाने के लिए वास्तविक भुगतान से कम कीमत की रजिस्ट्री कराने के राष्ट्रव्यापी विचलन पर कैसे नियंत्रण होगा-यह स्पष्ट नहीं। कीमतें फुलाकर रिहायशी प्रॉपर्टी को आम नागरिक से लगातार दूर ले जाने के गुनहगार फाइनेंसरों-सट्टेबाजों पर लगाम कसने की कोई उम्मीद भी इन प्रावधानों से नहीं बंधी। भविष्य में शायद दशा सुधरे, फिलहाल इसी पर संतोष कीजिए कि दिशा सही है।

edit@amarujala.com

https://t.me/AllNewsPaperPaid

जीवन धारा

जे. कृष्णमूर्ति

सम्मान के बिना प्रेम नहीं हो सकता। सम्मान व्यक्ति के अस्तित्व की स्वीकृति है। उसके 'होने' से आपका सहमत होना ही 'सम्मान' है। सम्मान के लिए दिमाग में छोटे-बड़े का भाव नहीं होना चाहिए।

सम्मान देना किसी के अस्तित्व की स्वीकृति है

प्रेम क्या है, *इस प्रश्न का कभी कोई सीधा उत्तर नहीं मिल पाया। प्रेम को समझने के लिए प्रेम का दर्शन समझना होगा। जहां प्रेम होता है वहां 'सत्ता' नहीं होती, 'अधिकार' नहीं होता, ईर्ष्या नहीं होती। परिवार के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, सेवक के लिए, सहकर्मी और पड़ोसी के लिए, राह चलते मनुष्य के लिए, समाज और पूरी दुनिया के लिए बस करुणा और सह-अस्तित्व होता है। केवल प्रेम में ही करुणा और सौंदर्य, सुव्यवस्था और शांति लाने का सामर्थ्य है। सिर्फ प्रेम ही है, जिसमें आपका संकुचित 'मैं' खो जाता है। प्रेम जाना नहीं जा सकता। इसे आप केवल तब महसूस कर सकते हैं, जब दिमाग पहले से जानी हुई चीजों से मुक्त हो जाए। तभी हम प्रेम की अवस्था में होते हैं। बाकी तो सब स्मृतियों के दुहराव हैं। जब हम कहते हैं कि मुझे फलां से प्यार है, तो जरा गहराई से सोचिए कि क्या हमारे इस कहने के पीछे उस व्यक्ति पर हमारे अधिकार होने का भाव नहीं होता? तब क्या हम यह नहीं कह रहे होते हैं कि उस आदमी या उस स्त्री पर हमारा अधिकार बनता है। 'तुम मेरी हो' या 'तुम मेरे हो'- ऐसा कहने का क्या अर्थ है? बस यही कि उस पर आपका अधिकार है और आप उसे अपने से बांधना चाहते हैं। जब हम प्रेम का दावा करते हैं, तो उसमें अधिकार और आधिपत्य का भाव होता है। इस अधिकार-भाव से ही जन्म लेती है ईर्ष्या, इसी से पैदा होता है खोने का डर और पैदा होती हैं तमाम किस्म की वे मानसिक उलझनें, जिनसे हम सब परिचित हैं। इसलिए, अधिकार-भाव होना प्रेम नहीं है। विज्ञान कहता है कि पानी में उठने वाली तरंगें केवल जल के अणुओं का अपनी ही जगह पर दोलन हैं। जल में उठने वाली तरंगें जल की सतह पर पड़ी वस्तुओं को कहीं किसी दिशा में नहीं ले जातीं। तरंगों से गति का एहसास होता है, लेकिन वास्तव में यह अपनी ही जगह पर हिलने-डुलने की एक उत्तेजना भर है। हलचलों से भरे तालाब में वह नहीं दिखता, जो नीचे तल में व्याप्त है। इसी तरह भावनाओं के हलचल से भरे मन में प्रेम नहीं दिखता। प्रेम तब दिखता है, जब मन ध्यान में होता है। सम्मान के बिना प्रेम नहीं हो सकता। सम्मान व्यक्ति के अस्तित्व की स्वीकृति है। किसी को सम्मान देना उसके 'होने' का मान करना है। उसके 'होने' से आपका सहमत होना ही 'सम्मान' है। दिमाग के हाथों विकृत मन 'बड़े' और 'छोटे' के भ्रम में पड़ा रहता है। आमतौर पर ऐसा क्यों होता है कि आप सम्मान केवल 'बड़े' का ही करते हैं। आपका सेवक, आपका साथी या आपका बच्चा आपके सम्मान का पात्र क्यों नहीं होता? आप उनका सम्मान करते हैं, जो आपको आपसे ऊपर और बड़े लगते हैं। आप अपने बॉस का सम्मान करते हैं। आपका व्यवहार और संबोधन तक 'बड़े' और 'छोटे' में विभाजित है। तो ऐसी विभाजित मानसिकता के साथ प्रेम की आपकी कोई घोषणा निरर्थक है। प्रेम तब होता है, जब आप 'अस्तित्व' मात्र का सम्मान करते हैं।*

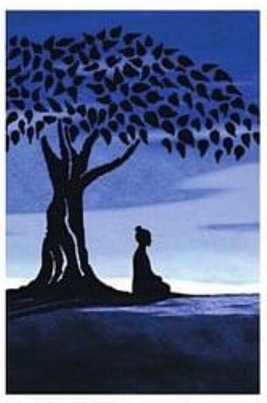

सम्मान में शर्त न हो

सूत्र

जब आप दूसरे के प्रति शर्त रहित सम्मान के भाव से भर जाते हैं। प्रेम तब होता है, जब आपका सीमित 'मैं' खत्म होकर उस व्यापक 'मैं' में विलीन होता जाता है, जहां 'मैं' के बोध का अस्तित्व ही नहीं रहता। जब आप प्रेम में होते हैं, तो ओस की हर बूंद, पेड़ का हर पत्ता और धरती का हर कण जान लेता है कि आप प्रेम में हैं।

दूसरा पहलू

तैराकी में सेकंड के एक अंश का अंतर स्वर्ण पदक को रजत में बदल सकता है। कई शीर्ष तैराक छोटी बढ़त के लिए भी डाटा खंगालते हैं।

ओलंपिक में तैराकों के दिमाग में चलता है गणित

दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे तेज तैराक केट डगलस सांख्यिकी में स्नातक की छात्रा हैं। वह पेरिस ओलंपिक की दो स्पर्धाओं में हिस्सा ले रही हैं। वह गणित के मामले में हमेशा अच्छी रही हैं। लेकिन वर्जीनिया विश्वविद्यालय में दाखिला लेने से पहले उसने कभी नहीं सोचा था कि तैराकी अपने आप में गणित की संख्या है, जिसे वह हल करने का प्रयास कर सकती है। उसे इस बात का एहसास तब हुआ, जब पता चला कि वह क्लासरूम में जिन अवधारणाओं को पढ़ती थी, उनका इस्तेमाल खेल में भी किया जा सकता है।

इन दिनों डगलस अक्सर एक्सेलेरोमीटर बेल्ट पहनकर पूल में उतरती हैं। यह वही उपकरण है, जो स्मार्टफोन और फिटनेस घड़ियों में पाया जाता है। वह जैसे ही तैरना शुरू करती है, वैसे ही सेंसर प्रति सेकंड 512 बार तीन स्थानिक दिशाओं में उसकी गति को मापता है। पेरिस में 4x100 मीटर फ्री-स्टाइल रिले का रजत पदक जीत चुकी 22 वर्षीय डगलस कहती हैं, 'इससे मुझे यह पता लगाने में सहूलियत होती है कि मैं कहां और अच्छा कर सकती हूं।' पेरिस में सभी तैराकों की चुनौतियां एक समान हैं-कौन तेजी से पानी में तैरकर सबसे पहले फिनिश लाइन छूता है। शीर्ष तैराक ड्रैग नामक बाधा को दूर करने के लिए कई तरीके अपनाते हैं, जिनमें बड़ी स्पर्धा से पहले शेविंग करना और फॉर्मूला-1 रेसिंग कार वाली सामग्री से बने स्विमसूट पहनना आदि शामिल हैं।

जेनी व्रेंटास
दुनिया की दूसरे नंबर की तैराक केट डगलस सांख्यिकी में स्नातक की छात्रा हैं। वह गणित की मदद से अपने प्रदर्शन को निखारने में लगी हैं।

शीर्ष तैराक ड्रैग नामक बाधा को दूर करने के लिए कई तरीके अपनाते हैं, जिनमें बड़ी स्पर्धा से पहले शेविंग करना और फॉर्मूला-1 रेसिंग कार वाली सामग्री से बने स्विमसूट पहनना आदि शामिल हैं।

तैराकी में अनुभव और कोच की नजर पर भी काफी कुछ निर्भर करता है, लेकिन डगलस और उनके अमेरिकी साथी नए प्रतिस्पर्धी तरीके खोज रहे हैं। वर्जीनिया के गणित के प्रोफेसर डॉ. केन ओनो के मार्गदर्शन में वे पानी में आगे बढ़ने के अनुकूल तरीकों पता करने के साथ ही उनका विश्लेषण कर रहे हैं। छोटे-छोटे बिंदुओं पर ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि सेकंड का सौवां हिस्सा भी पदक के बीच अंतर पैदा कर देता है। डगलस पेरिस में एकमात्र ऐसी तैराक हैं, जिन्होंने तैराकी में गणित के महत्व को लेकर शोधपत्र का सह-लेखन किया है। डॉ. ओनो का कहना है, 'तैराकी में गणित और भौतिकी का उत्तम प्रयोग होता है।' डगलस कहती हैं कि तैयारी के लिए पूल और शुष्क भूमि प्रशिक्षण, नींद, पोषण, दौड़ रणनीति और अन्य कई चीजों पर विस्तार से ध्यान देने की जरूरत है। किंतु गणित का उपयोग कुशल तैराक बनने में मदद करता है।

©The New York Times 2024

आंकड़े

चॉकलेट से कमाई

भारत में पिछले कुछ वर्षों से चॉकलेट की खपत बढ़ गई है। पांच वर्षों में सबसे ज्यादा 2024 में चॉकलेट से कर राजस्व प्राप्त हुआ है

2020	1.12
2021	1.25
2022	1.28
2023	1.44
2024	1.54

आंकड़े अरब डॉलर में हैं। | स्रोत : Stastista

कुंतलपुर के मंत्री ने भक्त चंद्रहास की हत्या करने के लिए उसे वन में भेजा, लेकिन संतरी चंद्रहास की भक्ति से इतने मोहित हुए कि अंगुली काटकर ही लौट आए।

चंद्रहास की भक्ति

केरल में मेधावी नामक धर्मात्मा राजा थे। उनके एकमात्र पुत्र का नाम चंद्रहास था। शत्रुओं ने मेधावी राजा की हत्या कर राज्य पर अधिकार कर लिया। रानी सती हो गईं। एक धाय चुपके से चंद्रहास को लेकर कुंतलपुर राज्य में चली गई। उसने चंद्रहास का पालन-पोषण किया। चंद्रहास तीन वर्ष के थे, तो धाय का भी निधन हो गया। फिर वहां की महिलाओं ने ही चंद्रहास का पालन-पोषण किया। एक दिन देवर्षि नारद उस जगह पहुंच गए, जहां चंद्रहास था। उन्होंने चंद्रहास को योग्य बालक जानकर 'राम' नाम का मंत्र दिया और शालग्राम की मूर्ति दी।

चंद्रहास की भक्ति इतनी बढ़ी कि वह जब भक्ति गीत गाते, तो लोग मोहित हो जाते थे। कुंतलपुर के राजा को पुत्र नहीं था। एक बार चंद्रहास ने ऋषियों के बीच मधुर धुन में भगवान के सुरीले गीत गाए। इस दौरान कुंतलपुर के राजा भी मौजूद थे। ऋषियों ने राजा से कहा कि आप इस बच्चे को अपना राजपाट सौंप दें। यह सुनकर राज्य के मंत्री ने चंद्रहास की हत्या करने की साजिश रची। उसने संतरी से कहा, वन में ले जाकर चंद्रहास की हत्या कर दो और निशान लेकर आना। संतरी जब चंद्रहास को वन में ले गए, तो बालक का तेज देखकर वे मोहित हो गए। उसने भगवान की पूजा की, इससे हत्या करने के लिए आए लोगों के दिल पिघल गए। उन्होंने चंद्रहास से कहा कि हम तुम्हें मार नहीं सकते। इसलिए निशान के लिए तुम्हारी एक अंगुली ले जा रहे हैं।

अंतर्यात्रा
संकलित

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 05 नवंबर, 1956

लड़ाई तुरंत बंद करने का भारत का प्रस्ताव पारित

लड़ाई तुरन्त बन्द की जाय
संयुक्त राष्ट्र सेना बनाने का निश्चय
महासभा द्वारा दो प्रस्ताव स्वीकृत

युद्ध की खबरें
बम वर्षा जारी

संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकटकालीन अधिवेशन ने भारत के प्रतिनिधि आर्थरलाल द्वारा पेश किया गया प्रस्ताव भारी बहुमत से पारित किया, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस व इस्राइल से मिस्र में तुरंत युद्ध रोकने की मांग की गई थी।

भारतीय भाषाओं में हो कानून की पढ़ाई

यदि लोगों को न्याय देने के साथ उन्हें न्याय मिलने का एहसास भी कराना है, तो देसी भाषाओं में कानून की पढ़ाई होनी चाहिए।

उमेश चतुर्वेदी | शिक्षा

वर्ष 1967 में वाराणसी से शुरू हुआ हिंदी आंदोलन भले ही राजनीति की भेंट चढ़ गया हो, लेकिन उस आंदोलन के साथ हिंदी केंद्रीय विमर्श का हिस्सा जरूर बन गई। इस आंदोलन को हिंदी विरोधियों ने जितना नुकसान नहीं पहुंचाया, उससे कहीं ज्यादा अंग्रेजी समर्थकों ने पहुंचाया। इस आंदोलन को देसी सीमाओं में भाषायी उपनिवेशवाद को बढ़ावा देने के रूप में इस तरह स्थापित कर दिया गया कि हिंदीभाषी भी मानने लगे कि हिंदी की बात करना एक तरह से वर्चस्ववाद को बढ़ावा देना है। लेकिन अब स्थितियां बदलने लगी हैं। अब भारत के प्रधान न्यायाधीश भी मानने लगे हैं कि कानून की पढ़ाई हिंदी माध्यम से भी होनी चाहिए।

बीती 14 जुलाई को लखनऊ के राम मनोहर लोहिया लॉ कॉलेज के दीक्षांत समारोह में प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ का यह कहना मामूली घटना नहीं है कि कानून की पढ़ाई हिंदी में भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सबसे ज्यादा हिंदीभाषी जनसंख्या वाले राज्य की राजधानी में होने के कारण ही उन्होंने हिंदी के समर्थन की बात की।

लंबे समय से न्यायपालिका में हिंदी समेत भारतीय भाषाओं में कामकाज किए जाने की मांग उठ रही है। अक्सर ऐसी मांगों पर न्यायपालिका ही ध्यान नहीं देती है। बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट में हिंदी में अपील करने की छूट के बावजूद वहां नियुक्त होने वाले जज अक्सर हिंदी याचिकाओं की अंग्रेजी प्रति मांगते रहे हैं। या फिर कुछ हाईकोर्ट में ऐसी व्यवस्था है कि अंग्रेजी प्रति देनी ही होगी। इस वजह से हिंदी ही क्यों, अन्य भारतीय भाषाओं में भी न्याय मिलने का लक्ष्य लगातार पीछे छूटता रहा है। लेकिन अब लगता है कि न्यायपालिका भी इस दिशा में सचेत हो रही है। उसे इसका भान हो रहा है कि देसी भाषाओं में न्याय देने का वक्त आ गया है।

न्यायपालिका की सोच में ऐसा बदलाव पहली बार नहीं दिख रहा है। न्यायमूर्ति नजीर ने 27 दिसंबर, 2021 को हैदराबाद के एक कार्यक्रम में कहा था कि भारतीय न्यायिक प्रक्रिया का अब भारतीयकरण होना चाहिए। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ इसी बात को अब ठोस ढंग से आगे बढ़ा रहे हैं। हिंदी या भारतीय भाषाओं के जरिये न्याय हासिल करने की राह में सबसे बड़ी बाधा संविधान के अनुच्छेद 348 की व्यवस्था है, जिसके अनुसार, अगर संसद कानून नहीं बनाती, तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अंग्रेजी में ही सुनवाई करेंगे। ऊपरी तौर पर देखें, तो लगता है कि अगर संसद चाहे, तो वह आसानी से ऐसे प्रावधान कर सकती है। वैधानिक नजरिये से यह राह आसान लगती है, लेकिन भारतीय, खासकर हिंदी के नजरिये से मौजूदा राजनीतिक हालात को देखें, तो यह बात इतनी आसान भी नहीं है।

अगर संसद में बिना राजनीतिक सहमति के इस प्रावधान के संशोधन का प्रस्ताव आता है, तो राजनीतिक वितंडा खड़ा होने से कोई नहीं रोक सकता। जिस देश में अब भी कई राज्य हिंदी में स्टेशन और बस स्टैंड तक के नाम रखे जाने को क्षेत्रीय अस्मिता से जोड़कर देखते हों, जहां नई शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं की वकालत के पीछे कुछ राजनीतिक दलों को हिंदी के वर्चस्ववाद की गंध लगती हो, वहां उच्च न्यायपालिका में भारतीय भाषाएं आसानी से लागू हो जाएं, संभव नहीं है।

कुछ महीने पहले गुजरात हाईकोर्ट में गुजराती में याचिका की वकालत वहां की बार एसोसिएशन ने की, तो वहीं के कुछ वकील उसके खिलाफ हो गए। इसकी वजह यह है कि ज्यादातर वकीलों की पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम से हुई है। गुजराती में लिखना-पढ़ना उनके लिए आसान नहीं है। इसलिए वे इसके विरोध में उतर आए। उत्तर प्रदेश में जमीन से जुड़े दस्तावेजों में खसरा और खतौनी जैसी शब्दावली आज भी प्रचलन में है। लेकिन अंग्रेजी माध्यम से पढ़े वकीलों को इस शब्दावली की जानकारी नहीं है। इसलिए वे इन्हें समझ भी नहीं पाते। जब वे समझ नहीं पाएंगे, तो न्याय क्या खाक दिलवाएंगे? इसलिए जरूरी है कि हिंदी ही नहीं, अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की कानूनी और दस्तावेजी शब्दावली की जानकारी कानून के छात्रों को दी जाए। स्थानीय भाषाओं में पढ़ाई इसका आसान विकल्प हो सकती है।

न्याय की भाषा में कहा जाता है कि न्याय होना ही नहीं, होते हुए दिखना भी चाहिए। आम भारतीयों को न्याय मिलता है, तो अंग्रेजी में होने की वजह से आम लोगों को पता भी नहीं चलता कि उसे न्याय मिला भी है या नहीं। खुशी की बात है कि अब न्यायपालिका खुद समझने लगी है कि भारतीयों को न्याय देना है और उन्हें न्याय मिलते हुए देखने का अनुभव भी मुहैया कराना है, तो भारतीय भाषाओं में कानून की पढ़ाई होनी चाहिए।

बर्फ और तूफान फूलों को तबाह कर सकते हैं,
लेकिन बीज नहीं मर सकते।

– खलील जिब्रान

धोखे का धंधा

रूस में एक और भारतीय युवक के युद्ध में मारे जाने को लेकर आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं। लोकसभा में विपक्ष के एक नेता के सवाल के जवाब में विदेश राज्यमंत्री ने कहा कि रूस ने अपनी सेना में भर्ती दस भारतीय युवकों को मुक्त कर दिया है और वे जल्दी ही वापस लौट आएंगे। इसी महीने प्रधानमंत्री ने रूस यात्रा के दौरान वहां के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात में यह मुद्दा उठाया था और कहा गया था कि रूस ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। बाकी युवाओं के भी जल्दी वापस लौटने की उम्मीद है। हालांकि अभी तक इस बात की ठीक-ठीक जानकारी नहीं है कि कितने भारतीय युवा रूसी सेना में शामिल किए गए हैं और उनमें से कितनों को युद्ध क्षेत्र में अगली कतार में तैनात किया गया है। पिछले दिनों जब दो भारतीय युवाओं के युद्ध में मारे जाने की खबर आई थी, और कुछ युवाओं ने अपनी तस्वीर डाल कर रिहाई की गुहार लगाई थी, तब इस बात का खुलाया हुआ था कि बड़ी संख्या में भारतीय युवाओं को रोजगार दिलाने के नाम पर धोखे से रूसी सेना में तैनात कर यूक्रेन के साथ युद्ध में तैनात किया गया है। तब भी सरकार ने आश्वस्त किया था कि ऐसे नौजवानों को वापस लाने की कोशिश की जा रही है।

दरअसल, नौकरी दिलाने के नाम पर कुछ एजंटों ने युवाओं से भारी रकम लेकर फर्जी कागजात के जरिए गुप्त रास्तों से उन्हें रूस भेज दिया। शुरू में इन नौजवानों को सुरक्षा सहायक के तौर पर भर्ती किया गया और फिर डरा-धमका कर युद्ध क्षेत्र में धकेल दिया गया। कुछ लोगों का अनुमान है कि सौ से ऊपर ऐसे युवा रूसी सेना में शामिल कर लिए गए हैं। अब सरकार ने उन एजंटों की पहचान शुरू कर दी है, जो धोखे से नौजवानों को विदेशों में नौकरी के लिए भेजती हैं। कुछ एजंट पकड़ भी लिए गए हैं। हालांकि इस तरह फर्जी कागजात बना कर युवाओं को नौकरी दिलाने के नाम पर विदेश भेजने का धंधा कोई नया नहीं है। ऐसे लोगों पर शिकंजा कसने के अनेक प्रयास हो चुके हैं, लोगों से अपील की जाती है कि विदेश मंत्रालय में पंजीकरण करा कर ही दूसरे देश में नौकरी आदि के लिए जाएं, मगर फिर भी गलत तरीके से विदेश जाने का सिलसिला रुक नहीं रहा। सरकार के सामने मुश्किल तब खड़ी हो जाती है, जब इस तरह दूसरे देशों में गए लोग किसी मुसीबत में फंस जाते हैं।

हमारे देश में बेरोजगारी का आलम यह है कि एक पद के लिए हजारों अभ्यर्थी कतार में लग जाते हैं। वे किसी भी तरह रोजगार पाना चाहते हैं। दूसरे देशों में चूंकि रोजगार के अवसर अधिक हैं और वहां वेतन आदि भी अच्छा मिल जाता है, इसलिए किसी भी दूसरे देश में जाने को तैयार रहते हैं। इसके लिए जमीन-जायदाद बेच कर एजंटों को पैसा देने को भी तैयार हो जाते हैं। इसी ललक का फायदा एजंट उठाते हैं। रूस भेजे गए नौजवानों को अगर वहां की सेना में भर्ती कर युद्ध क्षेत्र में तैनात न किया गया होता, तो यह मामला भी सामने न आता। ऐसे में फिर से सरकार के सामने यह प्रश्न रेखांकित हुआ है कि आखिर वह कबूतरबाजी करने वाले एजंटों पर नकेल कसने और गलत रास्ते से विदेश जाने वाले युवाओं को जागरूक कर पाने में सफल क्यों नहीं हो पा रही।

उपलब्धि और उम्मीद

पेरिस में चल रहे ओलंपिक खेलों का अभी शुरुआती दौर है और पदक तालिका में देशों और खिलाड़ियों के नाम दर्ज होने शुरू हुए हैं। भारत के नाम भी एक पदक दर्ज हुआ है। इससे आगे के सफर के लिए उम्मीद जगती है। रविवार को भारतीय निशानेबाज मनु भाकर ने दस मीटर एअर पिस्टल निशानेबाजी के महिला वर्ग में प्रतिभागी देशों के खिलाड़ियों को अच्छी चुनौती दी और उन्हें 221.7 अंक हासिल हुए। अंतिम दौर में वे तीसरे स्थान पर रहीं। उन्हें इस वर्ग की प्रतियोगिता में कांस्य पदक मिला और इसी के साथ पेरिस ओलंपिक में भारत के नाम पहला पदक दर्ज हुआ। अभी भारत को अन्य कई खेलों में हिस्सा लेना है और उसमें विश्व स्तर के खिलाड़ियों की क्षमताओं की चुनौतियों का सामना करना है। मगर पिछले कुछ वर्षों में हुई अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के दौरान कुछ खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन से जैसे उत्साहजनक संकेत मिले हैं, उससे पेरिस ओलंपिक में भी उनसे पदक लाने की उम्मीद है।

निशानेबाजी में मनु भाकर को मिले कांस्य पदक के साथ ही इस खेल में पदक मिलने का भारत का पिछले बारह वर्ष का इंतजार खत्म हुआ। दरअसल, इस उपलब्धि के साथ ही पहली निशानेबाज बन कर मनु भाकर ने एक इतिहास रच दिया है। हालांकि इससे पहले तोक्यो ओलंपिक में उनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा था और इसके लिए उन्हें कुछ आलोचनाएं भी झेलनी पड़ीं, लेकिन प्रसिद्ध कवयित्री और मानवाधिकार कार्यकर्ता माया एंजेलो की कविता 'स्टिल आइ राइज' यानी अभी मुझे आगे बढ़ना है से प्रेरणा लेने वाली मनु भाकर फिर से उठ खड़ी हुईं और अब वे ओलंपिक में पदक विजेता हैं। अब देखना है कि निशानेबाजी में भारत के अन्य खिलाड़ी और क्या हासिल कर पाते हैं। मनु भाकर को मिले कांस्य की अहमियत पदक तालिका में कुल नतीजों से अलग इस रूप में है कि किसी भी खेल प्रतियोगिता में शुरुआती जीत या हावी होने की स्थितियां बाकी खेलों के प्रदर्शन में भी दम भरती हैं। इस लिहाज से देखें तो पिछले ओलंपिक की पदक तालिका में संतोषजनक जगह बना सकने वाली भारतीय खिलाड़ियों की टीम के लिए मनु भाकर की उपलब्धि उत्साह बढ़ाने वाली साबित हो सकती है।

आर्थिक सुधारों के बरक्स बेरोजगारी

जमीनी स्तर पर बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। वास्तव में, शिक्षित युवाओं की स्थिति गंभीर है। इसमें सबसे खराब स्थिति देश के दलित, पिछड़े, अतिपिछड़े और आदिवासी समुदायों की है।

केसी त्यागी
पंकज चौरसिया

आजाद भारत में बेरोजगारी और अल्परोजगार हमेशा से महत्त्वपूर्ण मुद्दे रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने 7 जुलाई को 'डेटा मैन्युअल' नाम से एक रपट जारी की, जिसमें कहा गया है कि पिछले तीन-चार वर्षों में आठ करोड़ नौकरियां सृजित हुई हैं और जल्द ही अनेक बुनियादी ढांचा परियोजनाएं आ रही हैं, जो अधिक नौकरियां पैदा करेंगी। यह रपट मुख्य रूप से सकल मूल्यवर्धित, सकल मूल्य उत्पादन, श्रम रोजगार, श्रम गुणवत्ता, पूंजी स्टाक और पूंजी संरचना से संदर्भित होती है। इस रपट में कहा गया है कि विनिर्माण और सेवाओं में सृजित नौकरियों की कुल संख्या वित्तवर्ष 2014-23 के दौरान 8.9 करोड़ और वित्तवर्ष 2004-2014 के दौरान 6.6 करोड़ थी। इसमें यह भी कहा गया है कि भारत में कुल श्रमशक्ति 59.7 करोड़ है, जो हाल ही में जारी एएसयूएसई (केंद्रीय अनिगमित क्षेत्र उद्यमों के वार्षिक सर्वेक्षण) के अनुसार 56.8 करोड़ के बराबर है। श्रमशक्ति की यह कुल संख्या निजी रोजगार सर्वेक्षणों से काफी अलग दिखाई देती है।

कुछ समय पहले 'सेंटर फार मानिटरिंग इंडियन इकोनामी एजंसी' के रोजगार और बेरोजगारी संबंधी आंकड़े में बताया गया था कि जून 2004 में, बेरोजगारी दर पिछले महीने के सात फीसद से बढ़कर 9.2 फीसद पर पहुंच गई थी, जो आठ महीने का उच्चतम स्तर था। यह बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन के आधिकारिक आख्यान के विपरीत था। जमीनी स्तर पर बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। वास्तव में, शिक्षित युवाओं की स्थिति गंभीर है। इसमें सबसे खराब स्थिति देश के दलित, पिछड़े, अतिपिछड़े और आदिवासी समुदायों की है। श्रमबल भागीदारी दर से पता चलता है कि कितने भारतीय नौकरी की 'मांग' कर रहे हैं। इसमें वे लोग शामिल होते हैं, जिनकी उम्र पंद्रह वर्ष या उससे अधिक है। इसमें दो तरह के लोग शामिल होते हैं- वे जो रोजगार में कार्यरत हैं तथा दूसरे वे जो बेरोजगार और काम करने के इच्छुक हैं तथा सक्रिय रूप से नौकरी की तलाश कर रहे हैं।

देखा गया है कि अगर समय से नौकरी नहीं मिलती, तो बहुत से बेरोजगार हतोत्साहित होकर श्रमबल छोड़ देते, यानी सक्रिय रूप से नौकरी की तलाश करना बंद कर देते हैं। इस तरह कुल श्रमबल में बेरोजगारों का अनुपात गिर जाता है। भारत में आर्थिक सुधार के बावजूद, बेरोजगारी दर लगातार उच्च बनी हुई है, क्योंकि सामाजिक भेदभाव और सामाजिक-आर्थिक वास्तविकताएं श्रम बाजार में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अतिपिछड़ों के समक्ष आने वाली असुविधाओं को बढ़ाती हैं। वर्ष 2011-12 के एनएसएसओ के आंकड़ों के अनुसार, अनुसूचित जातियों में दिहाड़ी मजदूरों की हिस्सेदारी 63 फीसद थी। यह अन्य सामाजिक समूहों के मूल्यों से काफी अधिक है। ये आंकड़े ओबीसी के लिए 44 फीसद, उच्च जातियों के लिए 42 फीसद और बाकी के लिए 46 फीसद थे।

वास्तव में, देश के कुल आकस्मिक मजदूरों में से लगभग 32 फीसद अनुसूचित जाति के हैं, जो उनकी जनसंख्या हिस्सेदारी 16 फीसद से दोगुना है। अनुसूचित जातियों के सामने आने वाली असुविधाएं वेतनभोगी काम पर उनकी असंगत निर्भरता से कहीं अधिक हैं। चूंकि अनुसूचित जातियों को

काम पर रखने में जाति-आधारित भेदभाव का सामना करना पड़ता है, इसलिए उनकी बेरोजगारी दर भी बाकी आबादी से ज्यादा है।

उद्योग-स्तर की उत्पादकता और रोजगार को मापने वाले आरबीआइ की रपट के आंकड़े निजी संस्थानों द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के एकदम विपरीत हैं। मुंबई स्थित 'थिंक टैंक सेंटर फार मानिटरिंग इंडियन इकोनामी' के अनुसार, देश की बेरोजगारी दर पिछले वित्तवर्ष में बढ़कर आठ फीसद हो गई, जबकि पिछले दो वर्षों में यह 7.6 फीसद और 7.7 फीसद थी। 'थिंक टैंक' के मासिक आंकड़ों में अलग से कहा गया है कि जून में बेरोजगारी दर बढ़ कर 9.2 फीसद हो गई, जबकि मई में यह 7 फीसद और 12 महीने पहले 8.5 फीसद थी।

> सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि 15-29 आयु वर्ग के करीब 16 फीसद शहरी युवा 2022-23 में खराब कौशल और गुणवत्तापूर्ण नौकरियों की कमी के कारण बेरोजगार रह गए। निजी एजंसियों के अनुमान इससे कहीं ज्यादा हैं। सीएमआइई के अनुसार, युवा बेरोजगारी दर 45.4 फीसद तक पहुंच गई है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन और 'भारतीय थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फार ह्यूमन डेवलपमेंट' (आइएचडी) द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित ताजा रपट से पता चला है कि दक्षिण एशियाई राष्ट्र में तीन में से एक युवा न तो शिक्षा प्राप्त कर रहा है, न ही रोजगार या प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है।

कई विशेषज्ञ खासकर युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी दर को लेकर चिंतित हैं। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि 15-29 आयु वर्ग के करीब 16 फीसद शहरी युवा 2022-23 में खराब कौशल और गुणवत्तापूर्ण नौकरियों की कमी के कारण बेरोजगार रह गए। निजी एजंसियों के अनुमान इससे कहीं ज्यादा हैं। सीएमआइई के अनुसार, युवा बेरोजगारी दर 45.4 फीसद तक पहुंच गई है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन और 'भारतीय थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फार ह्यूमन डेवलपमेंट' (आइएचडी) द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित ताजा रपट से पता चला है कि दक्षिण एशियाई राष्ट्र में तीन में से एक युवा न तो शिक्षा प्राप्त कर रहा है, न ही रोजगार या प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है। इसमें यह भी बताया गया है कि उच्च शिक्षित युवाओं के बेरोजगार होने की संभावना उन लोगों की तुलना में अधिक है, जिन्होंने कोई स्कूली शिक्षा नहीं ली है।

आईएचडी रपट में कहा गया है कि स्नातकों के लिए बेरोजगारी दर 29.1 फीसद थी, जो उन लोगों के लिए 3.4 फीसद से लगभग नौ गुना अधिक है, जो पढ़ या लिख नहीं सकते। माध्यमिक या उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं में बेरोजगारी दर छह गुना अधिक 18.4 फीसद थी। इसका बाकी हिस्सा अल्परोजगार है या जिसे हम प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं, जहां लोग काम तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें बहुत कम वेतन मिल रहा है या वे बहुत कम दिनों के लिए काम कर रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन और मानव विकास संस्थान द्वारा 'भारत रोजगार रपट 2024: युवा रोजगार, शिक्षा और कौशल' में प्रस्तुत 'डेटा सेट' भारत में सामाजिक श्रेणियों में रोजगार में विविधता को उजागर करते हैं, यह देखते हुए कि दलित और आदिवासी व्यक्ति अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य श्रेणी के व्यक्तियों की तुलना में सामाजिक पदानुक्रम में निचले स्थान पर हैं। यहां तक कि हाशिए पर पड़े एससी या एसटी समूहों के उच्च शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी दर ओबीसी या सामान्य श्रेणी के उनके साथियों की तुलना में अधिक है।

अनुसूचित जनजाति के केवल 5.1 फीसद, अनुसूचित जाति के 7.3 फीसद और अन्य पिछड़ा वर्ग के 8.7 फीसद सदस्य औपचारिक रोजगार में हैं, जबकि सामान्य श्रेणी के 16 फीसद से अधिक सदस्य औपचारिक रोजगार में हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के 90 फीसद से अधिक सदस्य अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं, जबकि सामान्य श्रेणी सदस्यों में यह आंकड़ा 84 फीसद है। उच्च और मध्यम कौशल वाली नौकरियों के मामले में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी का प्रतिनिधित्व चार से दस फीसद के बीच है, जबकि सामान्य श्रेणी व्यक्तियों के लिए यह 20 फीसद है। 51 फीसद से अधिक सामान्य श्रेणी सदस्यों ने माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की है, जबकि इस मामले में 24 फीसद एसटी, 31 फीसद एससी और 40 फीसद ओबीसी सदस्य हैं। सामाजिक रूप से हाशिये पर पड़े युवाओं में ये उच्च बेरोजगारी दरें उपयुक्त रोजगार के अवसर हासिल करने में उनके सामने आने वाली चुनौतियों को उजागर करती हैं, सामाजिक असमानताओं को बढ़ाती और सामाजिक गतिशीलता में बाधा डालती हैं।

आभासी दुनिया का संजाल

गौरव बिस्सा

हाल ही में एक ऐतिहासिक तीर्थ स्थल और संग्रहालय पर पर्यटकों की संख्या नगण्य देखी गई, जबकि खानपान की दुकानों, नौका विहार, समुद्र तट आदि पर भारी भीड़ थी। भीड़ में प्रत्येक व्यक्ति वीडियो या रील बनाने, धीमी गति की फिल्म बनाने और फोटो खिंचवाने में व्यस्त था। ऐतिहासिक स्थलों के इतिहास और भूगोल के विषय में अभिभावक अपने बच्चों के प्रश्नों का जवाब नहीं दे पा रहे थे। वे बच्चों को फोटो खिंचवाने के लिए मुद्राएं बनाने के लिए प्रेरित कर रहे थे. बच्चों के प्रश्नों की बौछार से उनके अभिभावक बच्चों को झिड़क रहे थे, क्योंकि उन्हें खुद कुछ ज्ञान नहीं था। सवाल है कि क्या जीवन का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ भौतिक आनंद लेना भर रह गया है? क्या सिर्फ तस्वीरें खिंचवाना, सोशल मीडिया पर मशहूर होना, लोगों में यह दिखाना कि व्यक्ति बहुत आनंदित है आदि ही जीवन के लक्ष्य रह गए हैं?

यह स्थिति बहुत गंभीर है कि एक वयस्क नागरिक को इतिहास के बारे में सामान्य जानकारी भी नहीं है। व्यक्ति अपने राष्ट्र गौरव, अपनी थातियों, संस्कृति और अपने देश से इस स्तर तक कट चुका है कि वह बच्चों के मन में उठते प्रश्नों का उत्तर देने में असमर्थ है। जब एक माता-पिता को यह जानकारी नहीं कि उसके देश के महत्त्वपूर्ण गौरवशाली व्यक्तित्व कौन हैं, तो वे अपनी पीढ़ी में राष्ट्र गौरव के संस्कारों को कैसे बीजारोपित कर पाएंगे? अभिभावक सिर्फ भोजन, आनंद, मनोरंजन, तस्वीरों और सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरों या टिप्पणियों पर आने वाली पसंदगी और साझा किए जाने में ही अपनी जिंदगी की खुशी तलाशते प्रतीत हो रहे हैं। क्या वर्तमान अभिभावक अपने बारह से पंद्रह वर्षीय संतानों के साथ देश के ताजा घटनाक्रमों पर, वित्त और रक्षा नीति पर, सामान्य विज्ञान के सिद्धांतों, सांस्कृतिक गौरव आदि विषयों पर चर्चा करने में समर्थ हैं? शायद नहीं। यह अत्यंत कष्टदायक है।

हम घूमने क्यों जाते हैं? व्यंग्यात्मक भाषा में इसका उत्तर है- हम 'रील' बनाने, तस्वीरें खिंचवाकर सोशल मीडिया पर डालने के लिए घूमने जाते हैं! इसी को शायद जीवन की खुशी मान लिया गया है। खुशी को सिर्फ 'रील', सुंदर कपड़ों और भोजन करने से जोड़ दिया गया है। यह एक दुखद सत्य है। व्यक्ति अपने आनंद की जगह दूसरों को यह दिखाने में व्यस्त है कि वह बहुत सुखी है। आनंद की जगह दिखावे ने ले ली है। क्या 'रील' बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है, समाज को उसका क्या संदेश मिलेगा, इन सब पर समाज मौन है। यों किसी को अपनी सुविधा से खुद को अभिव्यक्त करने का अधिकार है, मगर यह भी सच है कि रील और तस्वीरों ने कई दंपतियों का जीवन खराब किया है। इन चित्रों और टिप्पणियों के कारण परस्पर समन्वय में कमी आ रही है, तुलना बढ़ रही है और दांपत्य जीवन कष्टप्रद हो रहा है। आनंद भीतर है। ऊपरी दिखावे, रील, फोटो, स्टेटस और कपड़ों से वास्तविक खुशी मिलनी असंभव है।

दरअसल, इस तरह के शौक के पीछे छिपी है लोगों द्वारा स्वीकार किए जाने की इच्छा। इस कार्य के पीछे दिखावा है, खुद को औरों से अधिक सुखी दिखाने का भाव है। दूसरे हमारी बात का समर्थन करें और हमें स्वीकार करें, क्या यह आवश्यक है? सोशल मीडिया पर फोटो डालकर या कुछ लिखकर व्यक्ति दूसरों से सराहना और स्वीकारोक्ति चाहता है। क्या मनुष्य खुद की नजर में इतना अशक्त और निर्बल है कि जब तक दूसरे लोग उसे खुश न मानें, तब तक वह खुश नहीं होगा? यह सोचने की जरूरत है कि हम पढ़ने के शौकीन हैं और हमने यह बात सोशल मीडिया पर लिखी। अब जो पढ़ने का शौकीन होगा, वह हमारे काम की तारीफ करेगा और जो शौक नहीं रखता होगा, वह आलोचना करेगा। इसमें मानसिक तनाव क्यों लेना? इंटरनेट एक खुला मंच है। कोई रोक-टोक नहीं हैं। जो जैसा चाहे, वैसा लिख सकता है। ऐसी अवस्था में दूसरों की टिप्पणियों को दिल से लगाया जाना अनुचित है।

सच यह है कि 'रील' और तस्वीरों के जरिए लोकप्रियता हासिल होने की प्यास जगाना बाजार का एक मायाजाल है, जिसे कंपनियों ने गढ़ा है। करीब बीस वर्ष पूर्व किराए पर परिधान लाकर दूल्हा-दुल्हन विवाह संपन्न कर लेते थे। वे समझते थे कि एक बार पहने जाने वाले महंगे परिधानों पर बेवजह खर्च करना ठीक नहीं है। अब ऐसे बचत प्रधान समाज में कंपनी अपना उत्पाद कैसे बेचे? इसलिए प्रत्येक समारोह और त्योहार का व्यवसायीकरण शुरू हो गया। समारोह में एक जैसे परिधान पहनना, फोटो खींचना आदि इसी रणनीति का हिस्सा हैं। भारत में विवाह के दौरान पहने जाने वाले महिलाओं के परिधानों का बाजार और 'रीलों' के निर्माण और तस्वीरें खिंचवाने की तथाकथित प्रतियोगिता के कारण मोबाइल का बाजार बेतहाशा वृद्धि कर रहा है।

कुछ दिनों पहले एक खबर आई कि मां ने किशोरी को मोबाइल छोड़कर पढ़ने को कहा और उसे मोबाइल के अत्यधिक इस्तेमाल करने पर टोका। इस बात से नाराज होकर किशोरी ने आमघाती कदम उठा लिया। ऐसे और भी समाचार आए दिन आते रहते हैं। आखिर क्यों व्यक्ति इतना अकेला, तन्हा और एकाकी हो गया है कि उसने मोबाइल के आभासी संसार को ही सच मान लिया है? यह समझना होगा कि आभासी इंटरनेट की दुनिया वास्तविक नहीं होती। इंटरनेट की दुनिया मायाजाल है और उसमें जो दिखता है, वो पूरी तरह सच नहीं है। न तो इसकी तारीफें सच्ची हैं और न ही आलोचना। इसलिए आभासी दुनिया को त्यागकर वास्तविक दुनिया में जीना ही जीवन है।

दुनिया मेरे आगे

> तस्वीरों और 'रील' के जरिए लोकप्रियता हासिल होने की प्यास जगाना बाजार का एक मायाजाल है। करीब बीस वर्ष पूर्व किराए पर परिधान लाकर दूल्हा-दुल्हन विवाह संपन्न कर लेते थे। वे समझते थे कि एक बार पहने जाने वाले महंगे परिधानों पर बेवजह खर्च करना ठीक नहीं है।

संपदा में हिस्सा

जबसे केंद्र सरकार ने राज्यों का मूल्य वर्धित कर यानी वैट को हटाकर 'एक देश एक कर' का नारा देकर माल एवं सेवा कर यानी की जीएसटी को लागू किया है, तबसे राज्यों की आर्थिक स्थिति खराब होती गई है। पहले जो कर राज्यों से बिकने वाली वस्तुओं पर लगा करता था, उस पर अधिकार राज्य का होता था। मगर जबसे जीएसटी आया, तबसे उसमें से आधा हिस्सा केंद्र के खाते में चला जाता है। इस घाटे के बदले केंद्र सरकार जो राज्यों को मुआवजा देती थी, उसकी भी मियाद पांच वर्षों के बाद खत्म हो चुकी है। ऐसे में राज्यों के ऊपर पूरी जिम्मेदारी आ गई है कि वे आमदनी बचाकर अपना खर्चा चला सकें। अब इस मसले पर सर्वोच्च अदालत ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले में खनिज संपदा वाले राज्यों के यह अधिकार दे दिया कि वे उस पर कर लगा सकते हैं। इस फैसले से झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओड़ीशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान जैसे खनिज संपदा से परिपूर्ण राज्यों को आर्थिक परेशानी में राहत मिलना तय है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने राज्यों को उनके यहां मौजूद संपदा पर हक देने का काम किया है।

– जंग बहादुर सिंह, गोलपहाड़ी, जमशेदपुर

एकांत बनाम एकाकीपन

'एकाकीपन का दंश' (संपादकीय, 24 जुलाई) में उल्लेख है कि बढ़ते एकाकीपन के लिए स्मार्टफोन भी जवाबदेह है, क्योंकि स्मार्टफोन के बढ़ते उपयोग के कारण व्यक्ति ने व्यक्ति से व्यक्तिशः मुलाकातें कम कर दी हैं। यानी व्यक्ति खुदगर्ज और आलसी हो रहा है। चर्चा और आवश्यक जानकारी फोन पर लेना एक सीमा तक ठीक है, लेकिन आदी होने पर तो व्यक्ति सामाजिक नहीं, बल्कि असामाजिक होकर अकेला पड़ जाता है। अकेलेपन में जीने वाला व्यक्ति एकांतवासी की अपेक्षा अधिक दुखी होता है, लेकिन एकांतप्रिय व्यक्ति क्रमशः अंतर्मुखी होने से रोगग्रस्त या अधिक संकट में नहीं रहता। सामान्यतः संकटकाल में व्यक्ति को परिजन, रिश्तेदार और दोस्तों की याद आती है और एकाकीपन में सामाजिकता और सामूहिकता की जरूरत का बोध होता है। व्यक्तियों के जुड़ाव में रहने पर ही सामाजिक सहयोग मिलता है।

– बीएल शर्मा 'अकिंचन', उज्जैन

सुविधा की नैतिकता

वर्तमान उपभोक्तावादी समाज हर विषय वस्तु को, चाहे वह मूर्त हो या अमूर्त, अपने स्वार्थ के अनुसार परिभाषित करने और उसे दूसरे लोगों द्वारा लागू करने की अपेक्षा में लगा रहता है और खुद इसका नकारात्मक रूप में लाभ प्राप्त करना चाहता है। इस अमूर्त शब्दावली में नैतिकता जैसे शब्द की बात करें तो पाएंगे कि हर व्यक्ति अपने पड़ोसी, मित्र, शत्रु, सगे संबंधी आदि लोगों से यह अपेक्षाएं रखता है कि वह हमारे प्रति नैतिक व्यवहार रखे, लेकिन खुद को सामने वाले प्रति नैतिक रूप से बदलने को तैयार नहीं है। इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझा जा सकता है। जैसा कि हर व्यक्ति अपनी बहू-बेटियों को सुरक्षित रखने की कवायद में रहता है, लेकिन दूसरे की बहू-बेटियों के प्रति कैसे-कैसे नकारात्मक विचार रखता है। इसलिए अगर समाज से नैतिकता के आयाम की अपेक्षा हम अपने प्रति रखते हैं तो पहले खुद को नैतिक बनाने की आवश्यकता है, तभी कोई सार्थक परिणाम सुनिश्चित हो सकता है।

– दिलीप चौरसिया, बहराइच, उप्र

सम्मान के संदर्भ

कारोबार को परे रखकर बात करें तो सड़कों पर इतने कम दामों में साहित्यिक पुस्तकों को बेचे जाने से बेहतर यह हो कि साहित्य को किसी वृद्धाश्रम, पुस्तकालयों या किसी को तोहफे में दे दिया जाए। इससे साहित्य का मान भी बना रहता। वर्तमान में ई-पत्रिकाओं का चलन ज्यादा होने से ये स्थितियां निर्मित हुई हैं। इस तरह बेचे जाने का चलन नया नहीं है। इसका दूसरा पक्ष यह भी है की शौकीन लोगों को किताबें कम दामों पर उपलब्ध हो रही हैं। साहित्य को संभालना और रखरखाव कठिन होता है। दीमक, नमी, आदि के कारण किताबें खराब हो जाती हैं। यहीं यह प्रश्न उठता है कि दीपावली पर साफ सफाई के दौरान क्या इन्हें भी रद्दी वालों के बेच दिया जाए या ऐसी जगह बांध के रख दिया जाए, जहां से दोबारा निकालना न पड़े। पढ़ने-लिखने से नए विचारों का उदय और ज्ञानार्जन में वृद्धि होती है।

– संजय वर्मा 'दृष्टि', धार, मप्र

www.readwhere.com

हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत न हो पाऊं फिर भी विचार प्रकट करने के आपके अधिकारों की रक्षा करूंगा। –वाल्तेयर

राजस्थान पत्रिका
संस्थापक
कर्पूर चन्द्र कुलिश

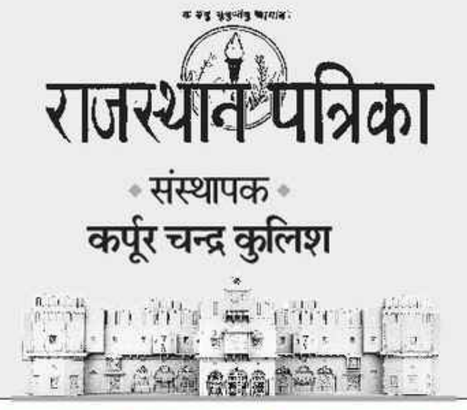

ड्रेनेज के रखरखाव में जानलेवा लापरवाही

आग लगने के बाद कुआं खोदना कोई अच्छी बात नहीं कही जाती। ऐसा करने से लाभ भी नहीं होता। लेकिन बात जब गैर जिम्मेदारी की होती है तो कुआं खोदने का काम आग लगने के बाद ही होता है। चाहे उत्तर प्रदेश के हाथरस में धार्मिक आयोजन में भगदड़ मचने के बाद मौतों का मामला हो या फिर दिल्ली के कोचिंग इंस्टीट्यूट में पानी भरने से तीन विद्यार्थियों की मौत की घटना, सवाल एक जैसे ही उठते हैं कि आखिर इन मौतों के लिए जिम्मेदार कौन है? कोचिंग इंस्टीट्यूट के संचालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस लापरवाही के लिए यह कार्रवाई होनी भी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि दिल्ली नगर निगम के आला अफसर आखिर घटना से पहले नींद में क्यों गाफिल थे?

हैरत इस बात की है कि बेसमेंट का इस्तेमाल सिर्फ स्टोरेज के रूप में करने की अनुमति थी लेकिन वहां लाइब्रेरी संचालित की जा रही थी। ऐसी जगह जहां पानी की निकासी तक की समुचित व्यवस्था नहीं हो, वहां आखिर लाइब्रेरी कैसे चल रही थी? क्या यह अंदाज नहीं लगाया जा सकता था कि यदि भारी बरसात के दौर में बेसमेंट में पानी भर गया तो क्या होगा? हादसे जब भी होते हैं लापरवाही से जुड़े कई सवाल हवा में तैरते रहते हैं लेकिन इनका जवाब कोई नहीं देता। हां, हादसे के बाद जांच, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई और मुआवजे की घोषणाएं जरूर तुरत-फुरत में हो जाती हैं। दिखावे के लिए आसपास के कुछ और कोचिंग संस्थानों के संचालकों को भी नोटिस थमाए गए हैं। क्या महज इस खानापूर्ति से ही प्रशासन अपनी जिम्मेदारी की इतिश्री समझ लेगा? बात अकेले दिल्ली की नहीं है। जयपुर से लेकर भोपाल और मुम्बई से लेकर बेंगलूरु तक एक जैसे हालात हैं। इमारतों के बेसमेंट में धड़ल्ले से लाइब्रेरी और कोचिंग संस्थान चल रहे हैं। सीवर लाइनों और ड्रेनेज के रखरखाव के मामले में दिल्ली जैसी लापरवाही भी हर जगह नजर आ रही है। सड़कों पर भी जलभराव की समस्या आम है। जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होगी तो दिल्ली जैसे हादसे कहीं भी हो सकते हैं। फिर दिल्ली में तो उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच टकराव भी समस्याओं के समाधान में बड़ी बाधा बना हुआ है।

दिल्ली की घटना की जांच का ऐलान कर दिया गया है। जांच कमेटी भी बना दी गई है। जाहिर है सिर्फ बेसमेंट में लाइब्रेरी चलना हादसे की वजह नहीं है। मुख्य वजह ड्रेनेज का फटना और बेसमेंट में अचानक पानी भरना है। इसलिए दिल्ली ही नहीं सभी शहरों में सीवर लाइनों और ड्रेनेज के रखरखाव पर ध्यान देने की जरूरत है, ताकि इस तरह के हादसे फिर न हों।

इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप पर विशेष | विश्वास के बल पर मजबूत संबंध बनेंगे तभी बेहतर दुनिया के लिए लोग एकजुट होंगे

दुनिया आज अनेक चुनौतियों, संकटों और विभाजनकारी ताकतों का सामना कर रही है। मानवीय एकजुटता की साझा भावना को बढ़ाया जाए तो इनसे निपटना संभव है। इसीलिए वर्ष 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस विचार के साथ 'इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप' (30 जुलाई) घोषित किया था कि लोगों, देशों, संस्कृतियों और व्यक्तियों के बीच मित्रता ही है जो समुदायों के बीच पुल का निर्माण करती है।

पीएम मोदी की रूस यात्रा से अधिक संतुलित अंतरराष्ट्रीय माहौल संभव

बोरिस वोलखोन्स्की
सह-प्राध्यापक, एशियाई एवं अफ्रीकी अध्ययन संस्थान, लोमोनोसोव मॉस्को राजकीय विवि

डॉ. इंदिरा गाजिएवा
हिंदी प्राध्यापिका, रूसी राजकीय मानविकी विवि, मॉस्को, रूस

लिलिया जारीपोवा
जूनियर रिसर्चर, अंतरराष्ट्रीय दक्षिण एशियाई अध्ययन केंद्र, रूसी राजकीय मानविकी विवि, मॉस्को, रूस

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की रूस यात्रा अनेक मायने में विशिष्ट थी। वैसे तो आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री अपना पद संभालने के बाद अपनी विदेश यात्राओं की शुरुआत किसी पड़ोसी देश की यात्रा से करते हैं पर यूक्रेन में चल रहे विशेष सैन्य अभियान और लगभग सभी देशों पर पश्चिम के राजनीतिक और राजनयिक दबाव (भारत को छोड़कर) के बावजूद इस बार पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने के लिए मॉस्को की यात्रा करना तय किया।

प्रधानमंत्री ने बाहरी दुनिया के समक्ष प्रदर्शित किया है कि भारत लगातार एक स्वतंत्र और संप्रभु विदेश नीति का पालन कर रहा है। उनकी यात्रा से वैश्विक स्तर पर पड़ने वाले इसके प्रभाव और द्विपक्षीय संबंधों को विभिन्न कोणों से देखा जा सकता है। भारत या अन्य कहीं भी, कोई भी समीक्षक यह उम्मीद नहीं करेगा कि रूस, चीन के साथ अपना सहयोग बंद कर देगा। रूस और चीन, 4 हजार किलोमीटर से ज्यादा लंबी सीमा साझा करते हैं। दूसरी ओर, द्विपक्षीय संबंधों में तमाम कठिनाइयों के बावजूद, चीन भारत का दूसरा व्यापारिक साझेदार (कभी-कभी नंबर एक) बना हुआ है। पश्चिम धीरे-धीरे वैश्विक मामलों में अपनी श्रेष्ठता खो रहा है और उसकी जगह एक नई दुनिया ले रही है। इस संदर्भ में, रूस-इंडिया-चीन यानी 'आरआइसी' का त्रिकोण, वैश्विक स्तर पर ब्रिक्स और क्षेत्रीय स्तर पर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन, दोनों समूह में नींव के रूप में काम करता है। यूक्रेन मामले में भारत का रुख हमेशा रूस के प्रति 'अनुकूल तटस्थता' का रहा है। इसका मतलब यह भी नहीं कि रूस के साथ सारी बाधाएं दूर हो गई हैं। दोनों देशों ने काफी हद तक व्यापार भुगतान में राष्ट्रीय मुद्राओं का सहारा लिया है जिससे असंतुलन उत्पन्न हुआ है। भारत को रूस में अपना निर्यात बढ़ाने की जरूरत है। हाल में, रूस और ईरान ने इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के शेष हिस्सों के निर्माण के लिए एक संगठन का गठन किया है जिससे व्यापार बढ़ेगा।

पश्चिम धीरे-धीरे वैश्विक मामलों में अपनी श्रेष्ठता खो रहा है और उसकी जगह एक नई दुनिया ले रही है। रूस-इंडिया-चीन यानी 'आरआइसी' का त्रिकोण, ब्रिक्स और एससीओ दोनों समूह में नींव के रूप में काम करता है।

इस यात्रा के दौरान मोदी ने रूसी भाषा में व्लादिमीर पुतिन को संबोधित किया और एक रूसी कहावत का हवाला देते हुए कहा-'एक पुराना दोस्त दो नए दोस्तों से बेहतर होता है।' दोनों नेताओं की बैठक नोवो-ओगारियोवो स्थित राजकीय आवास पर हुई, जहां पुतिन अपने सबसे नजदीकी व्यक्तियों को आमंत्रित करते हैं।

रूसी विश्वविद्यालयों में 26 हजार से अधिक भारतीय छात्र पढ़ते हैं। छात्रों के बीच अच्छा शैक्षिक आदान-प्रदान होना चाहिए। रूसी छात्रों की भारत के विश्वविद्यालयों में शैक्षिक इंटर्नशिप भी आवश्यक है। महामारी से पहले रूसी छात्र अपने खर्चे पर हिंदी सीखने भारतीय विश्वविद्यालयों में गए थे। पिछले वर्ष इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस ने तीन रूसी छात्रों के लिए भारत की 10 दिवसीय यात्रा की व्यवस्था भी की थी। छात्रों ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय और सेवाग्राम का दौरा किया। खुशी है कि मोदी इंटरेक्टिव इंस्टॉलेशन के उपयोग पर ध्यान दे रहे हैं। मोदी की मॉस्को यात्रा के दौरान 15 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। दोनों पक्षों ने चुनौतीपूर्ण भू-राजनीतिक माहौल में स्थायी और पारस्परिक रूप से लाभप्रद साझेदारी का निर्माण जारी रखने पर प्रतिबद्धता जताई और अंतरिक्ष में अन्वेषण, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग और ऊर्जा सहयोग पर जोर दिया गया। दोनों देशों ने 2030 तक व्यापार को 100 बिलियन डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। यह संकेत है कि इसका दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इस घनिष्ठता के चलते अधिक संतुलित अंतरराष्ट्रीय वातावरण तैयार हो सकता है।

क्रेमलिन के सेंट एंड्रयू हॉल में 9 जुलाई को राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया। पीएम मोदी ने यह भारत और रूस के बीच मित्रता के पारंपरिक संबंधों को समर्पित किया।

दोनों पक्षों के लिए चेन्नई-व्लादिवोस्तोक और पोलर मेरीटाइम रूट बेहद आशाजनक परियोजनाएं हैं। पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन ने दिखाया है कि विशेषाधिकार-प्राप्त रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों और पूरी दुनिया के लाभ के लिए जारी रहना निश्चित है।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

डेनमार्क से दोस्ती के 75 साल

हरित रणनीतिक साझेदारी के साथ आगे बढ़ रहे दोनों देश

फ्रेडी स्वेन
राजदूत, डेनमार्क दूतावास, नई दिल्ली
@patrika.com

डेनमार्क के साथ भारत की मित्रता के इस साल 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। दोनों देशों के बीच भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद ही 1949 में राजनयिक संबंध स्थापित हो गए थे और दशकों तक ये संबंध साझा लोकतांत्रिक परंपराओं व अंतरराष्ट्रीय शांति और स्थिरता की साझा इच्छा के साथ आगे बढ़ते रहे। पर इन संबंधों को असली जीवंतता तब मिली, जब सितंबर 2020 में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी व डेनमार्क की पीएम मेटे फ्रेडरिकसेन ने इन्हें हरित रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ा दिया।

हरित रणनीतिक साझेदारी जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए दोनों देशों की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। उस समय, इस नई साझेदारी की घोषणा करते हुए पीएम मोदी ने कहा था- 'डेनमार्क के पास कौशल है, भारत के पास उसे नापने का पैमाना है और दुनिया को नई तकनीकों की आवश्यकता है।' यह कथन दोनों देशों के बीच संयुक्त रोडमैप का प्रतिनिधित्व करता है।

पिछले चार सालों में हरित रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों को ऊर्जा, जल, सतत शहरी विकास, स्वास्थ्य, कृषि, समुद्री और बौद्धिक संपदा अधिकार (आइपीआर) जैसे विभिन्न क्षेत्रों में काफी करीब लाई है। पानी के क्षेत्र में, डेनमार्क और भारत के बीच पहला सहयोग राजस्थान राज्य में स्थापित किया गया था। दोनों देश सतत शहरी जल क्षेत्र विकसित करने पर सहयोग कर रहे हैं, जहां आरहूस शहर (डेनमार्क) और राजस्थान राज्य गैर-राजस्व जल को कम करने, सतत भूजल प्रबंधन, नदी के कायाकल्प और शहरी क्षेत्रों में एकीकृत जल प्रबंधन के माध्यम से रहने की क्षमता बढ़ाने पर सहयोग कर रहे हैं। जयपुर, उदयपुर और नवलगढ़ को आदर्श शहर के रूप में चुना गया है। डेनमार्क ही वह एकमात्र भागीदार देश है, जिसने राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर जल जीवन मिशन को रणनीतिक तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र परियोजना सेवा (यूएनओपी) को वित्त पोषित किया। इसके तहत पहले चरण (2021-2022) में उत्तर प्रदेश के 11 जिलों के 137 गांवों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। दूसरे चरण (2022-2024) में परियोजना को उत्तर प्रदेश, राजस्थान, असम और तमिलनाडु के 19 जिलों के 268 गांवों तक विस्तारित किया गया।

स्वच्छ नदी जल प्राप्त करना भारत-डेनमार्क सहयोग का एक और फोकस क्षेत्र है और दोनों देश वाराणसी में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला (एसएलसीआर) की स्थापना में लगे हुए हैं, जिस पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसेन के बीच 9 अक्टूबर 2021 को सुश्री मेटे की भारत यात्रा के दौरान सहमति बनी थी। ऊर्जा के क्षेत्र में भी अनेक डेनिश ऊर्जा विशेषज्ञ भारतीय संस्थानों में कार्यरत रहकर भारतीय सहयोगियों के साथ संयुक्त परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। इस साल की शुरुआत में, भारत और डेनमार्क ने ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया लॉन्च किया, जिसमें मुख्य रूप से शामिल डेनमार्क की कंपनियां भारत में हरित ईंधन के उत्पादन के लिए तकनीक लाने की क्षमता रखती हैं।

भारत-डेनमार्क राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने के अवसर पर डेनमार्क का मानता है कि हम भारत जैसे दोस्त के बिना पृथ्वी को नहीं बचा सकते। हरित रणनीतिक साझेदारी ने 2020 से हमारी दोस्ती का मार्गदर्शन किया है और हम न केवल अपने लिए, बल्कि दुनिया भर के अपने अन्य दोस्तों के लिए भी इसके लाभों को पहुंचाने की उम्मीद करते हैं। निस्संदेह अपने संसाधनों और विशेषज्ञता को साझा करके भारत और डेनमार्क एक उदाहरण स्थापित कर रहे हैं कि कैसे वैश्विक साझेदारी महत्त्वाकांक्षी राष्ट्रीय जलवायु लक्ष्यों व सतत विकास के लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने में सार्थक प्रगति कर सकती है। इसे हम अफ्रीकी देशों में सौर ऊर्जा लाने के लिए दोनों देशों द्वारा अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आइएसए) में मिलकर काम करने से भी समझ सकते हैं। दोनों देशों की हरित रणनीतिक साझेदारी का उद्देश्य यह भी है कि दोनों देशों के लोग इसके लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेने और धरती माता के साथ संतुलन में रहने के लिए प्रेरित होते रहें।

'शिक्षा के माध्यम से सार्क देशों के आपसी संबंध मजबूत करना लक्ष्य'

*साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, दक्षिण एशियाई देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए समर्पित संगठन के रूप में मित्रता का मूर्त रूप है। सार्क देशों के बीच आपसी तालमेल बढ़ाने, रिश्तों में बुनियादी मजबूती देने के लिए यह यूनिवर्सिटी एक सुदृढ़ सेतु का कार्य कर रही है। अन्य शिक्षा केंद्रों से अलग यह विश्वविद्यालय किन उद्देश्यों पर काम करता है, इस बारे में **यूनिवर्सिटी के चेयरमैन प्रो के.के. अग्रवाल** के साथ **पत्रिका संवाददाता डॉ. मीना कुमारी** की बातचीत के मुख्य अंश:*

Q साउथ एशियन यूनिवर्सिटी (एसएयू) के अध्यक्ष के रूप में आप अंतरराष्ट्रीय मित्रता को कैसे देखते हैं?
भारत देश वसुधैव कुटुंबकम् के सिद्धांत में विश्वास करता है। हमारे यहां बहुत से ऐसे विशेष दिन हैं जो भाई-बहन, भाई-भाई, मित्रों के रिश्ते को मजबूत करते हैं। वास्तविक उद्देश्य मेल-जोल बढ़ाना ही होता है। सार्क देशों के बीच सामाजिक-सांस्कृतिक-शैक्षणिक-भौगोलिक स्थिति सुदृढ़ हो, यही इस यूनिवर्सिटी का उद्देश्य है। दो राष्ट्रों की मित्रता से पहले व्यक्ति की व्यक्ति से मित्रता होना जरूरी है।

Q इस यूनिवर्सिटी की नींव किन उद्देश्यों के आधार पर, कब और कैसे रखी गई थी?
वर्ष 1985 में दक्षिण एशियाई देशों के बीच आपसी सहयोग व सौहार्दपूर्ण रिश्तों के लिए साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन (सार्क) का गठन हुआ जिसके सदस्य देश भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान और मालदीव हैं। जब 2010-11 में भारत इसका अध्यक्ष बना तो विश्वविद्यालय की स्थापना की योजना बनी, जहां सभी सार्क देशों के छात्र शोध एवं अनुसंधान कर सकें और क्षेत्रीय समस्याओं एवं चुनौतियों का मिलकर समाधान निकाल सकें। अग्रणी भूमिका निभाते हुए भारत ने इस विश्वविद्यालय परिसर के लिए दिल्ली में करीब 100 एकड़ जमीन मुहैया कराई। शेष अन्य देशों ने भी आर्थिक भागीदारी निभाई, जिससे करीब 1200 करोड़ रुपए की लागत से भव्य इमारत का निर्माण हो सका।

Q विश्वविद्यालय के माध्यम से सार्क देशों की आपस में मित्रता हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं?
गवर्निंग बॉडी में हर देश के दो-दो सदस्य हैं। यानी भारत सबसे ज्यादा व्यय करेगा परंतु इसके संचालन में सभी देश बराबर की भूमिका निभाएंगे। यह भारत की दोस्ती की मिसाल है।

Q दो देशों के बीच रिश्तों में उतार-चढ़ाव चलता रहता है, छात्रों पर इसके असर को कैसे अनुभव किया? भारत व पाकिस्तान के छात्रों में कभी कोई टकराव?
इस समय पाकिस्तान के छात्र नहीं हैं। जब थे, तब भी कभी कोई विवाद नहीं हुआ।

Q सार्क, जी 20 जैसे प्लेटफार्म दोस्ती बढ़ाने में कितने सहायक लगते हैं?
ये सभी प्लेटफॉर्म राष्ट्र स्तर के हैं और ये प्लेटफॉर्म देशों के बीच मित्रता बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुए हैं। व्यक्तिगत वेलफेयर पर फोकस से राष्ट्रों के बीच मित्रता हो तो और भी ज्यादा कारगर होगी।

Q एक दूसरे की कला-संस्कृति को जानने-समझने के लिए यहां कैसे प्रयास किए जाते हैं?
बिल्कुल। मेल-जोल बढ़ाने के लिए हर देश के खास त्योहार, सभी छात्र मिलकर मनाते हैं। आठों देशों के राष्ट्रीय उत्सव, मुख्य सांस्कृतिक कार्यक्रम, त्योहार भी मिलकर मनाते हैं। महीने में किसी एक दिन दूसरे देश का खाना बनता है। पहले सभी देशों का फूड फेस्टिवल भी होता था जो अब फिर से शुरू करने की योजना है। संग्रहालय बनाने की भी योजना है, जहां सभी देशों की कला-संस्कृति प्रतीकात्मक रूप से दर्शाई जा सके। जैसा कि एक्ट में शामिल है, यदि हम इस यूनिवर्सिटी के सेंटर अन्य देशों में भी खोलते हैं तो यह प्रयास आपसी मित्रता को सुदृढ़ करने में सहायक होगा। शैक्षिक नवाचार के लिए सार्क देशों के विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को एक सेमेस्टर के लिए आमंत्रित करने की भी योजना है।

Q यह यूनिवर्सिटी किस प्रकार से अलग है? यहां किन विषयों का अध्ययन व शोध होता है?
सार्क देशों के साझा और एक समान विषयों पर अध्ययन होता है। जैसे जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन, लैंड स्लाइड्स, सुनामी, साइक्लोन, समुद्र तटीय प्रबंधन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विषय। साझा समस्याओं पर गहन अध्ययन ही यूनिवर्सिटी का उद्देश्य है। जैसे उत्तराखण्ड, हिमाचल में लैंड स्लाइड्स पर हमारे वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं वैसे ही यदि साथ में नेपाल के कुछ क्षेत्रों पर भी अध्ययन कर लिया जाए तो शोध और उसकी उपयोगिता बढ़ जाएगी और आर्थिक दबाव भी कम होगा।

Q क्या यहां भी एनईपी को लागू किया गया है? अन्य देश के विद्यार्थियों पर इसका कैसा प्रभाव रहेगा?
नई शिक्षा नीति में स्थानीय भाषाओं को प्रमोट किया गया है। इसी तरह सार्क देशों की भाषाएं शामिल करने का प्रयास है।

Q आपके सामने प्रशासनिक दृष्टि से क्या-क्या चुनौतियां हैं?
आर्थिक असमानता देशों की दोस्ती के बीच आ रही है तो उसमें कुछ सुधार करना होगा। वहीं यह भी मानना चाहिए कि कभी भी यह असमानता पूर्ण रूप से खत्म नहीं हो सकती।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस: यह तकनीक बिजली और इंटरनेट जितनी ही महत्त्वपूर्ण है, यह नए औद्योगिक आधार की नींव हो सकती है

तानाशाहों की ताकत बनने से रोकना होगा एआइ को

सैम ऑल्टमैन
ओपनएआइ के सह-संस्थापक और सीईओ
द वाशिंगटन पोस्ट से विशेष अनुबंध के तहत

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता को जिस तेजी से हम पहचान रहे हैं, उसका मतलब है कि हमारे समक्ष सीमित विकल्प हैं। हम किस तरह की दुनिया में रहना चाहेंगे? क्या दुनिया का ऐसा नजारा होगा जिसमें अमरीका और सहयोगी देश दुनिया भर में एआइ प्रौद्योगिकी के लाभों को साझा करेंगे? अथवा अधिनायकवादी नेतृत्व वाले राष्ट्र अपनी ताकत को मजबूत करने के लिए एआइ का उपयोग करेंगे?

मौजूदा दौर में, अमरीका एआइ के विकास में सबसे आगे है। दुनिया की अधिनायकवादी सरकारें अमरीका के समान मानकों तक पहुंचने और आगे निकलने के लिए भारी मात्रा में धन खर्च करने को तैयार हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने धमकी भरे अंदाज में चेताया है कि जो देश एआइ की रेस में आगे निकल जाएगा, वही 'दुनिया पर राज करेगा' और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का भी कहना है कि उसका लक्ष्य 2030 तक एआइ में वैश्विक नेता बनने का है। अधिनायकवादी ताकतों का नजरिया प्रौद्योगिकी के लाभों पर कड़ी पकड़ बनाए रखने का रहेगा। और अगर वे एआइ प्रबंधन में नेतृत्वकारी स्थिति में हो जाती हैं तो वे फिर अमरीकी या अन्य देशों की कंपनियों को यूजर डेटा साझा करने के लिए मजबूर करेंगी। जासूसी के नए तरीके विकसित करने अथवा साइबर हथियार बनाने के वास्ते भी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करेंगी।

एआइ पर आधारित प्रणालियों का पहला अध्याय पहले ही प्रदर्शित किया जा चुका है। चैटजीपीटी, कोपायलट और अन्य सिस्टम्स जानकारी की दिशा में सीमित सहायक के रूप में कार्य कर रहे हैं। वह दिन अब ज्यादा दूर नहीं जब मानव समाज की कहानी में एक निर्णायक दौर की शुरुआत होगी। अगर हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि भविष्य में एआइ अधिकांशतः लोगों के लिए लाभकारी हो तो हमें अमरीका की अगुवाई वाले समान विचारधारा वाले देशों के साथ वैश्विक गठबंधन और नई रणनीति बनाने की जरूरत होगी। इसमें आगे बढ़ने के लिए अमरीका के सार्वजनिक और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों को कुछ बड़े मुद्दों पर ध्यान देना होगा। यूएस की एआइ फर्मों और उद्योगों को सावधानीपूर्वक कड़े सुरक्षा मानकों को तैयार करना होगा। एआइ का बुनियादी ढांचा महत्त्वपूर्ण है। यह तकनीक बिजली या इंटरनेट जितनी ही महत्त्वपूर्ण है। नए औद्योगिक आधार की नींव एआइ हो सकता है। हमें एआइ इनोवेटर्स, शोधकर्ताओं और इंजीनियरों की अगली पीढ़ी का पोषण और विकास करने की जरूरत है। ये सच्चे अर्थों में हमारे सुपरपावर हैं। एआइ के लिए सुसंगत कमर्शियल डिप्लोमेसी पॉलिसी विकसित करनी चाहिए। इसका मतलब यह कि चिप्स, एआइ ट्रेनिंग डेटा और अन्य कोड के लिए नियम तय करना। एआइ के विकास और नए मॉडलों के बारे में रचनात्मक रूप से सोचने की जरूरत है, विशेषकर सुरक्षा पर फोकस करना होगा। ग्लोबल साउथ एवं अवसरों से वंचित अन्य देशों की भूमिका सुनिश्चित करने के बारे में सोचना होगा। एआइ के लिए वैश्विक गठबंधन बनाने की दिशा में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जैसा कुछ बनाने पर चर्चा की गई है। एक अन्य विकल्प जापान और ब्रिटेन जैसे देशों में बनाए जा रहे एआइ सुरक्षा संस्थानों के नेटवर्क को एक साथ जोड़ना और एक निवेश कोष बनाना भी हो सकता है। एक अन्य सशक्त मॉडल इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन्ड नेम्स एंड नंबर्स (आइसीएएनएन) है। आइसीएएनएन में पूरी दुनिया के प्रतिनिधि लोकतांत्रिक वैश्विक समुदाय के समर्थन में इंटरनेट की अधिकतम लोगों तक पहुंच के अपने मुख्य मिशन के लिए समर्पित हैं। इसकी स्थापना 1998 में की गई थी ताकि इंटरनेट का सुरक्षित संचालन सुनिश्चित हो सके।

एआइ के लिए वैश्विक गठबंधन बनाने की दिशा में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जैसा कुछ बनाने पर चर्चा हुई है। एक सशक्त मॉडल इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन्ड नेम्स एंड नंबर्स (आइसीएएनएन) है। इसकी स्थापना 1998 में की गई थी ताकि इंटरनेट का सुरक्षित संचालन सुनिश्चित हो सके।

आपकी बात

ताकि न हो हादसा

नगर निकायों द्वारा नालों और ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करना चाहिए। बिजली विभाग को बिजली के तारों को व्यवस्थित रखना चाहिए, जिससे कोई हादसा न हो।
-तरुण रंगा, नोखा, बीकानेर

आज का सवाल

आर्थिक विषमता में कैसे कमी लाई जा सकती है?

ईमेल करें
edit@epatrika.com

patrika.com पर पढ़ें

पाठकों की प्रतिक्रियाएं

इसे स्कैन करें

पत्रिकायन का सवाल था, 'बारिश के मौसम में होने वाले हादसों को कैसे रोका जा सकता है?' प्रतिक्रियाएं ऑनलाइन भी देखें।
https://shorturl.at/N0G4J

चिंतन

'क्वाड' का चीन को स्वतंत्र हिंद-प्रशांत से कड़ा संदेश

चार देशों का ग्लोबल मंच क्वाड ने अपने संयुक्त बयान में चीन को दो टूक संदेश दिया है कि किसी भी देश को दूसरे देश पर हावी नहीं होना चाहिए। यह संदेश जरूरी है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान 'क्वाड' समूह का हिस्सा हैं। चारों देश अलग अलग समय ग्लोबल मंचों से चीन का चेताते रहे हैं और हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्वतंत्र आवाजाही की वकालत करते रहे हैं। इसके बावजूद दक्षिण चीन सागर में चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। चतुष्पक्षीय सुरक्षा संवाद (क्वाड) समूह के सदस्य देशों ने स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत को लेकर अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि की है। क्वाड ने सोमवार को एक ऐसा क्षेत्र बनाने की दिशा में काम करने का संकल्प लिया है, जहां कोई भी देश दूसरे देश को नहीं दबाए और प्रत्येक राष्ट्र हर प्रकार के दबाव से मुक्त हो। जापान की राजधानी टोक्यो में क्वाड की बैठक हुई, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शिरकत की है। 'क्वाड' देशों के विदेश मंत्रियों ने स्वतंत्र एवं नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखने और राष्ट्रों की स्वतंत्रता, मानवाधिकारों, लोकतांत्रिक मूल्यों, संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता के सिद्धांतों का सम्मान करने का आह्वान किया है। यह आह्वान चीन को सीधा संदेश है। चारों विदेश मंत्रियों ने चीन का सीधे तौर पर नाम लिए बिना पूर्वी और दक्षिण चीन सागर में स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की और किसी भी 'ऐसी एकतरफा कार्रवाई' के प्रति 'क्वाड' के कड़े विरोध को दोहराया जिसके जरिए बल या दबाव से यथास्थिति को बदलने की कोशिश की जाती है। दरअसल, क्षेत्रीय शांति, स्थिरता एवं समृद्धि में योगदान देने में सभी देशों की भूमिका है। भारत, जापान व ऑस्ट्रेलिया के साथ चीन का सीमा विवाद है तो अमेरिका के साथ ट्रेड वार है। दक्षिण चीन सागर में चीन की गतिविधियां बढ़ रही हैं, खासकर तट रक्षक और समुद्री मिलिशिया पोतों के खतरनाक इस्तेमाल हो रहे हैं। चीन द्वारा विवादित क्षेत्रों का सैन्यीकरण और दक्षिण चीन सागर में बलपूर्वक और डराने वाली गतिविधियां चिंतनीय है। चीन, दक्षिण चीन सागर के अधिकांश हिस्से पर दावा जताता है, जबकि फिलीपीन, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान भी इस समुद्री क्षेत्र को अपना हिस्सा बताते हैं। चीन ने अपनी प्रतिक्रिया में क्वाड समूह के देशों पर एशिया प्रशांत क्षेत्र में अन्य देशों के विकास को 'रोकने' के लिए 'कृत्रिम रूप से तनाव पैदा करने' और 'टकराव भड़काने' का आरोप लगाया है। समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीएलओएस) में प्रतिबिंबित कानून का पालन चीन समेत हर राष्ट्र को करना चाहिए। क्वाड ने सीमा पार से की जाने वाली आतंकवादी गतिविधियों समेत आतंकवाद और हिंसक चरमपंथ के सभी प्रारूपों की स्पष्ट निंदा की है। हाल में जम्मू-कश्मीर में सीमा पार से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी गतिविधियां बढ़ी हैं। क्वाड आतंकवाद पर भारत की नीतियों के साथ है। क्वाड ने अल-कायदा, आईएसआईएस/दाएश, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और उनके छद्म समूहों सहित सभी संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचीबद्ध आतंकवादी समूहों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने का पुनः आह्वान किया है। चीन को रोकना है तो, क्वाड को अपने संकल्पों के दिशा में आगे बढ़ने के लिए जमीनी स्तर पर रणनीति के साथ काम करना चाहिए। भारत व चीन सीमा विवाद पर जयशंकर ने सही रुख दिखाया है कि यह भारत व चीन का आपसी मामला है, इसमें किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।

मुद्दा
अवधेश कुमार

शिक्षा क्षेत्र की 'ट्रेजडी' कैसे दूर हो

दिल्ली के एक कोचिंग सेंटर में तीन छात्रों की अकल्पनीय दुखद मृत्यु हर चिंतनशील व्यक्ति को अंदर से हिला दी है। यह घटना अगर हम सबको अंदर से नहीं झकझोरता तो मान लीजिए कि हमने अपने अतीत में ठीक प्रकार से झांकने, वर्तमान को संभालने और भविष्य की वास्तविक चिंता करने से अपने को अलग कर लिया है। निश्चित रूप से कोचिंग करने आए उन तीन दुर्भाग्यशाली छात्रों का कोई दोष नहीं है। रौ आईएएस स्टडी सर्किल भारतीय सिविल सेवा के कोचिंग की दृष्टि से सबसे पुराना और सम्मानित नाम है। हालांकि पिछले ढाई दशकों में कई ऐसे कोचिंग संस्थान खड़े हो गए हैं, जिनका सम्मान और साख अभ्यर्थियों की दृष्टि में रौ के लगभग बराबर ही है। कल्पना करिए अगर इतनी पुरानी और सम्मानित संस्था की आधारभूत संरचना ऐसी है, जहां संकट में छात्रों के बचाव की आपात व्यवस्था नहीं तो अन्य संस्थाओं की कैसी स्थिति होगी? दुर्घटना के बाद दिल्ली पुलिस और प्रशासन जिस त्वरित गति से कार्रवाई कर रहा है अगर इन सबने अपनी निर्धारित भूमिका का निर्वहन पूर्व में किया होता तो शायद यह भयानक घटना नहीं घटती। शायद इसलिए क्योंकि इसके दूसरे पहलू भी हैं। व्यावसायिक क्षेत्र में भवनों का निर्माण, उसकी आंतरिक संरचना उसमें सुरक्षोपाय आदि के स्पष्ट मानक बने हुए हैं। बगैर उनके पूर्णता का प्रमाणपत्र नहीं दिया जा सकता। सुरक्षोपाय के पूरी जांच के बाद ही उनमें व्यावसायिक गतिविधियां चलाने के कानून और मानक निहित है। पहली दृष्टि में देखें तो सामान्य तौर पर हमारी आपकी सबकी दृष्टि में प्रतिदिन दिखने वाले प्रशासनिक सामाजिक भ्रष्टाचार का यह एक त्रासदीपूर्ण उदाहरण है।

घटना के बारे में जानकारी इतनी ही है कि ओल्ड राजेंद्र नगर में बारिश का पानी सड़कों पर भर गया जो दुकानों -मकान में घुसने लगा और बड़ी गाड़ियों के यू टर्न लेने से कुछ मिनट के लिए पानी इतनी तेजी से आया कि स्टडी सर्किल के बेसमेंट में लगे शीशे के दरवाजे टूट गए और मिनट में अंदर पानी भर गया। कुछ सौभाग्यशाली छात्र बच के निकल गए। ये तीन नहीं निकल सके। इसे अगर सामान्य दृष्टि से भी विश्लेषित करें तो नालियों, सड़कों पर जल जमाव के बीच यातायात की व्यवस्था, व्यावसायिक स्थलों के बचाव तथा भवन निर्माण में ऐसी सुरक्षित दरवाजे आदि के पहलू सामने आएंगे। इसके लिए कितने विभाग और लोग अपराधी दिखाई देते हैं यह बताने की आवश्यकता नहीं। कह सकते हैं कि जब बारिश काफी तेज हो तो एकाएक पानी का निकास संभव नहीं होता। बिल्कुल सही है। क्या इसके आधार पर ऐसी भयावह घटना को स्वाभाविक माना जा सकता है? बिल्कुल नहीं। दिल्ली के उपराज्यपाल का बयान है कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। यह एक सामान्य सा बयान है। कौन-कौन दोषी हैं, इनकी पहचान अपने आपमें सबसे बड़ा प्रश्न होता है। घटना बिल्कुल ताजा है, देशभर का ध्यान है , लोगों में आक्रोश है तो ऐसे समय कार्रवाई होती है। इसके बाद न्यायालय की लड़ाई, साथ ही साथ पूरी स्थिति की समीक्षा और फिर भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति

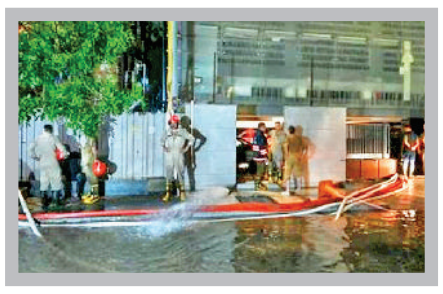

नहीं हो, इसके उपाय हमारे समाज और सत्ता प्रतिष्ठान के चरित्र में बहुत कम परिमाण में दिखता है। कोचिंग सेंटर को सील कर दिया गया। क्या सड़क के उस स्थान को सील किया जा सकता है जहां से पानी का तेज झोंका अंदर आया? क्या उन गाड़ियों की पहचान कर दंडित किया जाएगा, जिन्होंने ड्राइविंग मानकों का उल्लंघन कर गलत तरीके से यू-टर्न लिया और घटना घटा दी? क्या उस व्यावसायिक क्षेत्र के निर्माण की अनुमति और पूर्णता का सर्टिफिकेट देने वाले सारे लोगों की पहचान संभव है? इसी तरह युवाओं के करियर बनाने के नाम पर चारों तरफ दिख रहे कोचिंग सेंटरों में से कम से कम बड़े नामों की भी एक बार संपूर्ण जांच संभव है? इन प्रश्नों का उत्तर हम आप अच्छी तरह जानते हैं। किसी समस्या को संपूर्णता में देखने और दूरगामी सोच से स्थाई सामाधन की दिशा में बढ़ने की अवश्यकता होती है।

हमने अपनी पूरी शैक्षणिक- सामाजिक- आर्थिक व्यवस्था को इस स्थिति में पहुंचा दिया है जहां से लगता ही नहीं कि इसकी संभावना बची है। कोटा के कोचिंग सेंटरों की ट्रेजडी के का उदाहरण हमारे सामने हैं। नगरों में निर्माण और उसके संचालन का मुद्दा यहां शीर्ष पर दिखता है। इसके परे देखें तो क्या शिक्षा के लिए इस तरह के कोचिंग सेंटरों की वाकई आवश्यकता है? दिल्ली नहीं कोटा समेत समूचे देश में शायद ही कोई ऐसा शहर और कस्बा होगा, जहां छोटे-बड़े कोचिंग सेंटर नहीं होंगे। प्रतिक्रिया यही होती है कि विद्यालयों, महाविद्यालयों में अध्ययन-अध्यापन की स्थिति इतनी कमजोर है कि अगर छात्र अतिरिक्त कोचिंग में न जाएं तो उनके लिए वर्तमान प्रतिस्पर्धा के दौर में सफल होना मुश्किल है। प्रश्न उठता है कि आखिर हमारा शिक्षा ढांचा इतना लाचार क्यों हो गया? क्या लोगों ने इस बात पर गहराई से विचार किया कि भारत कभी अगर विश्व के लिए आकर्षण का केंद्र था तो उसकी शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, उन्हें इसका उत्तर मिला, हमारी शिक्षा छात्रों के लिए सच्चे ज्ञान की उच्चतम अवस्था को प्राप्त कर श्रेष्ठ मनुष्य बनने और समाज को दिशा देने जैसे कर्तव्य निर्वहन पर केंद्रित थी। ज्ञात इतिहास में ऐसे विश्वविद्यालय उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम पूरे देश में थे जहां विदेशों से भी छात्र आते थे। इसलिए भारत को वर्तमान शिक्षा प्रणाली जैसा ढांचा खड़ा करने की जरूरत नहीं थी। स्वतंत्रता के बाद शिक्षा सुधार के नाम पर परिवर्तनों की कोशिशें की गई किंतु मूल ढांचा वही रहा जो हमें अंग्रेजों ने दिया। इस व्यवस्था में लक्ष्य केवल करियर है। इसलिए गलाकाट प्रतियोगिता है और इसमें सफल करने के लिए लाखों की संख्या में ऐसे ही संस्थान खड़े हो गए हैं। कोचिंग तो छोड़िए, देश में प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक के कितने निजी संस्थान खड़े हो चुके हैं, इसकी गणना तक असंभव है। जो शिक्षा हमारे यहां स्वाभाविक रूप से समाज व्यवस्था में बिना अतिरिक्त व्यय के अपने आप मिलती थी वह इतना खर्चीला हो गया कि किसी सामान्य आदमी के लिए स्तरीय शिक्षा दिलाना असंभव है।

दुर्भाग्य से पूरी व्यवस्था इसी शिक्षा व्यवस्था से निकले लोगों के हाथों है। इससे संबंधित नैरेटिव और इकोसिस्टम इसी तरह का बना हुआ है। नई शिक्षा नीति में वर्तमान परिस्थितियों के अनुरुप ढांचे और व्यवहार में परिवर्तन की कोशिश है। किंतु इस पूरे इकोसिस्टम और नैरेटिव से खड़े लोग आसानी से इसको साकार नहीं होने देंगे। इसमें लगे लोगों का अनुभव यही आ रहा है कि पाठ्यक्रम में भी भारतीय दृष्टि से एक अध्याय जोड़ने के लिए समितियों में कितना संघर्ष करना पड़ता है। पूरा वातावरण पिछले करीब डेढ़ सौ वर्षों में ऐसा बना है जिसमें इससे बाहर निकाल कर नई शिक्षा व्यवस्था की ओर बढ़ने की कल्पना से लोग डरने लगते हैं। देश में अलग-अलग प्रकार की अनेक त्रासदियां इस शिक्षा व्यवस्था के कारण हो रही हैं। ऐसी घटनाओं से सबक लेकर हमें इस सड़े हुए शिक्षा तंत्र को बदलना चाहिए।

दिल्ली के एक कोचिंग सेंटर की त्रासद घटना अगर हम सबको अंदर से नहीं झकझोरता तो मान लीजिए कि हमने अपने अतीत में ठीक प्रकार से झांकने, वर्तमान को संभालने और भविष्य की वास्तविक चिंता करने से अपने को अलग कर लिया है। दुर्घटना के बाद दिल्ली पुलिस और प्रशासन जिस त्वरित गति से कार्रवाई कर रहें हैं, अगर इन सबने अपनी निर्धारित भूमिका का निर्वहन पूर्व में किया होता तो शायद यह भयानक घटना नहीं घटती। प्रश्न उठता है कि आखिर हमारा शिक्षा ढांचा इतना लाचार क्यों हो गया? देश में अलग-अलग प्रकार की अनेक त्रासदियां इस शिक्षा व्यवस्था के कारण हो रही हैं। ऐसी घटनाओं से सबक लेकर हमें इस सड़े हुए शिक्षा तंत्र को बदलना चाहिए।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया edit@haribhoomi.com पर दे सकते हैं।

बजट विश्लेषण
अखिलेश आर्येन्दु

प्राकृतिक खेती से बदलेगी भारतीय कृषि की तस्वीर

इस बार के आम बजट में केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खेती-किसानी को खास अहमियत दी है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की सभी पुरानी योजनाओं को बरकरार रखते हुए कृषि-क्षेत्र में तमाम तरह के बदलाव किए हैं। जिसमें खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ अगले 2 वर्षों में प्राकृतिक खेती के लिए 1 करोड़ किसानों को प्रोत्साहित करने की योजना है। जिसके तहत केन्द्र सरकार किसानों को धन मुहैया कराएगी। गौरतलब है कृषि एवं इससे संबद्ध क्षेत्र के लिए 1 लाख 52 हजार करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। खेती के वर्तमान तरीके से निकालकर प्राकृतिक खेती अपनाने पर किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए बजट में मुहैया कराई गई राशि, किसानों को घाटे की खेती से उबारने का क्रांतिकारी कदम कहा जाना चाहिए। यह पहली बार है जब केन्द्र सरकार ने किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की पहल की है, जिसमें किसानों को घाटे से उबारने के बाबत सरकार ने प्राकृतिक खेती के उत्पादों को बेहतर दाम दिलाने के बाबत बाजार या उपभोक्ता मुहैया कराने की बात की है। प्राकृतिक खेती में लागत प्रबंधन बेहतर है और उत्पाद महंगे बिकते हैं। कृषि में पैदा हुए उत्पाद महंगे बिकते हैं तो किसान की घाटे वाली खेती मुनाफे में आ जाएगी। बजट में किसानों की आय और फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के मद्देनजर बागवानी समेत 32 फसलों की 109 सर्वाधिक पैदावार वाली किस्में जारी करने का प्राविधान है, ये फसलें जलवायु अनुकूल होंगी। बजट में किसानों के लिए नये सिरे से जो कदम उठाने के प्राविधान किये जाने की बात की गई है उससे गांवों की तस्वीर बदल सकती है, यदि ईमानदार कोशिश शासन-प्रशासन के जरिए लगातार होती रहे।

बजट में कृषि क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र के साथ निजी क्षेत्र को आमंत्रित करने की बात की गई है। पर निजी क्षेत्र में निवेश किस जगह पर किया जाएगा? इसे साफ-साफ सरकार को बताना चाहिए। मोदी सरकार अपने तीसरे शासन काल में लगातार कृषि क्षेत्र के लिए बजट में वृद्धि करता आ रहा है। आंकड़े बताते हैं कि 2013-14 में कृषि का बजट जहां 21933.50 था, जो 2024-25 में बढ़कर 1.52 लाख करोड़ हो गया। आजादी के बाद खेती-किसानी के लिए इतना विशाल बजट पहली बार आवंटित किया गया है। पहली बार प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए धन मुहैया कराने के लिए बजट में विधिवत प्राविधान किया गया है।

प्राकृतिक खेती के प्रोत्साहन से जहां जल के दोहन में कमी आएगी वहीं पर खाद्यान्न की शुद्धता, जमीन की उर्वरता शक्ति का संरक्षण, जलवायु को अनुकूल रखने में मदद मिलने का साथ प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने से उर्वरकों, बीजों और छिड़काव करने वाले यंत्रों पर दी जाने वाली अरबों रुपये की सब्सिडी की बचत होगी और इससे देश की सेहत सुधारने में मदद मिलेगी। जाहिर तौर पर प्रदूषित अन्न, फल, सब्जियों और दूध के सेवन से मानसिक और शारीरिक बीमारियां लगातार बढ़ रही हैं। प्राकृतिक खेती से किसानों की आय ही नहीं बढ़ेगी, बल्कि जलवायु परिवर्तन से बढ़ती तमाम तरह की समस्याओं से निजात मिलने लगेगा।

आजादी के बाद वैज्ञानिक खेती के नाम पर रसायनिक जहरीली खेती की जाती रही है, जो हमेशा घाटे में ही रही। इसलिए बाजार को समझना और उसके अनुकूल फसल बोने को निश्चित करना ठीक है, लेकिन लागत में कमी करके किसानों का ज्यादा भला किया जा सकता है। गौरतलब है वित्त वर्ष 2022-23 में 1.23 ट्रिलियन भारतीय रुपये से अधिक मूल्य के उर्वरकों का आयात किया गया। इसलिए रसायनिक खेती की उपयोगिता और प्रासंगिकता पर भी गौर करने की जरूरत है। नाम मात्र की लागत में अधिक उत्पादन और जलवायु परिवर्तन के असर को कम करने में प्राकृतिक खेती ही सबसे ज्यादा फायदेमंद और उपयोगी है, इस हकीकत को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने से पर्यावरण, खाद्यान्न, भूमि, इंसान की सेहत, पानी की शुद्धता को और बेहतर बनाने में मदद मिलती है। आमतौर पर कृषि व बागवानी में बेहतर उपज लेने और बीमारियों के खात्मा के लिए फसलों में कीटनाशकों का इस्तेमाल जरूरी माना जाता है। लेकिन देशी तरीके से किए जाने वाली खेती और बागवानी ने इस धारणा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये कीटनाशक बेहतर उपज के लिए या बीमारियों को खत्म करने के लिए भले ही जरूरी माने जा रहे हों, लेकिन इससे कई तरह की जटिलताएं और बीमारियों की वजह बन गई हैं। बजट में प्राकृतिक खेती ओर कदम बढ़ाना कृषि में बदलाव की तरफ कदम है।

(लेखक पर्यावरण संरक्षण से जुड़े चिंतक व विश्लेषक हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

पसंद और नापसंद से मुक्त होना जरूरी

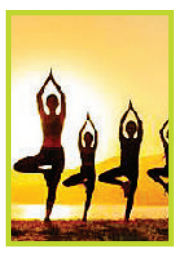

संकलित
दर्शन

आपने देखा होगा कि लोग बड़े गर्व से अक्सर कहते हैं, 'मुझे यह पसंद है, इसलिए मैं यह करके रहूंगा और वह मुझे पसंद नहीं है, इसलिए उसे मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि मैं स्वाधीन हूं।' क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि यह सोच सचमुच आपकी स्वाधीनता से जन्मा है? यह स्वाधीनता नहीं है, यह तो बेबसी है, लाचारी है। पसंद और नापसंद की बेड़ियों में आज लगभग पूरी मानवता जकड़ी हुई है। सभी पारिवारिक झगड़ों की जड़ में लोगों की व्यक्तिगत पसंद और नापसंद ही होती है। पसंद और नापसंद को लेकर समाज, राष्ट्र और धर्म तक बंटे हुए हैं। जब हमारे सोच का दायरा बहुत सीमित होता है, हम कई तरह के पूर्वाग्रहों से ग्रस्त हो जाते हैं, फिर हम पर पसंद और नापसंद की सनक सवार हो जाती है। तब हम उसे नहीं देख पाते, जिसकी जरूरत है। हम वही करते हैं, जिसे हम पसंद करते हैं। वह नहीं करते, जिसे किए जाने की आवश्यकता है। फिर शुरू होता है अविराम झंझटों व विवादों का सिलसिला और उसी में उलझकर रह जाता है हमारा लघु-जीवन। योग परंपरा में भीतरी आयाम को बहुत गहराई से देखा गया और भीतरी पराधीनता से मुक्त होने की कई तकनीकों का आविष्कार किया गया, क्योंकि जो भीतरी पराधीनता का शिकार नहीं है, उसे कोई बाहरी शक्ति उस पर नियंत्रण नहीं कर सकती। पसंद और नापसंद की सनक से मुक्त होने के लिए हमें अपनी चेतना पर काम करना होगा। एक जागरूक व्यक्ति ही यह देख पाने में सक्षम होता है कि किसी विशेष परिस्थिति में क्या आवश्यक है और क्या किया जाना चाहिए।

मुनि के शाप से देवराज इंद्र से छिन गया था स्वर्ग

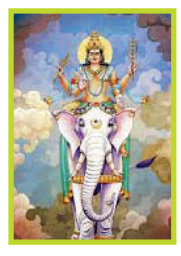

संकलित
प्रेरणा

एक दिन दुर्वासा मुनि विष्णु जी के पास पहुंचे। उस समय विष्णु जी ने दुर्वासा मुनि को अपनी दिव्य माला उपहार में दी। विष्णु जी से मिलकर दुर्वासा मुनि लौट रहे थे। तभी उन्हें रास्ते में देवराज इंद्र दिखाई दिए। इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर सवार थे और दुर्वासा मुनि पैदल थे। इन दोनों ने एक-दूसरे को देख लिया। उस समय दुर्वासा जी ने सोचा कि विष्णु जी ने जो माला दी है, वह मेरे किसी काम की नहीं है। ये माला इंद्र को दे देता हूं। इंद्र स्वर्ग के राजा हैं तो उनके गले में ये माला शोभा देगी। ऐसा सोचकर दुर्वासा मुनि ने विष्णु जी की माला इंद्र को उपहार में दे दी। देवराज इंद्र ने दुर्वासा जी से वह माला ले ली। उस समय देवराज इंद्र का अहंकार जाग गया। वह अपने ऐरावत हाथी पर बैठे हुए थे, स्वर्ग के राज-पाठ का घमंड था। इसी घमंड की वजह से इंद्र ने सोचा कि ये सामान्य सी माला मेरे काम नहीं आएगी। ये सोचकर इंद्र ने वह माला अपने ऐरावत हाथी के ऊपर डाल दी। ऐरावत ने अपनी सूंड से वह माला पकड़ी और पैरों से कुचल दी। ये सब दुर्वासा मुनि ने देख लिया, अपने उपहार का ऐसा अपमान देखकर वे क्रोधित हो गए। गुस्से में उन्होंने इंद्र से कहा कि आज तूने अपने राज-पाठ और पद के घमंड में मेरे उपहार का अनादर किया है, मैं तूझे शाप देता हूं, तेरा सारा वैभव चला जाएगा और तू स्वर्गहीन हो जाएगा। इसके बाद असुरों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया और देवता पराजित हो गए। इंद्र को स्वर्ग से जाना पड़ा था।

अंतर्मन

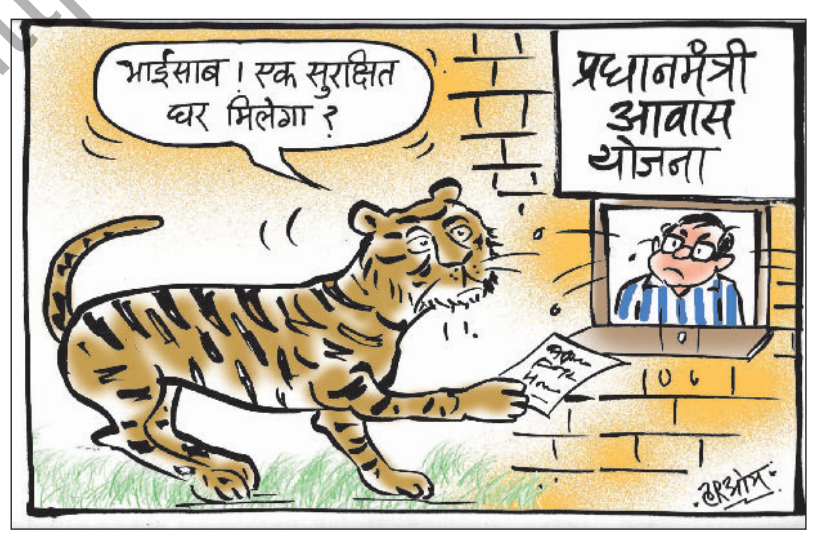

आज की पाती

देश का विकास उद्योग जगत पर निर्भर

देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने देश की आर्थिक व्यवस्था की मजबूती के लिए देश में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना जरूरी माना था। देश की आर्थिक व्यवस्था के लिए जब जवाहरलाल नेहरू के समक्ष तीन प्रस्ताव पेश किए गए, जिनमें मुख्यतः पहला गांधीवादी विचारधारा का, दूसरा एमएन राय का, और तीसरा देश के मुख्य पूंजीपतियों की विचारधारा का था, तो जवाहरलाल नेहरू ने देश के उस समय के सबसे बड़े उद्योगपतियों टाटा-बिड़ला के प्लान को ही स्वीकार किया था। देश के विकास में उद्योग जगत की भूमिका हमेशा रही है। नेहरू यह मानते थे कि उद्योगों को बढ़ावा देने से ही देश की आर्थिक व्यवस्था मजबूत हो सकती है। इसलिए आज भी जरूरत है कि उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए। *- कृष्ण कुमार शर्मा, बिलासपुर*

ट्रेंड

कोचिंग गैस चैंबर से कम नहीं

जब विज्ञापन की बात आती है, तो आप और हम रोज देखते हैं, अखबार का पहला पन्ना कोचिंग, दूसरा तीसरा कोचिंग इतना खर्चा कहां से आता है? कोचिंग एक ऐसा साइलो हो गया है, जो गैस चैंबर से कम नहीं है, यदि हम इसे डी-साइलो नहीं करेंगे तो समस्या होगी।

-जगदीप धनखड़, उपराष्ट्रपति

माफी मांगे कांग्रेस

मैं एक आदिवासी हूं और मुझे इस पर गर्व है। कांग्रेस पार्टी को पूरे आदिवासियों, दलितों और अन्य पिछड़े वर्गों से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस ने हमेशा आदिवासियों के अधिकारों का हनन किया है। कभी उन्हें न्याय नहीं दिया।

-किरण रिजिजू, केंद्रीय मंत्री

बहुत आभारी हूं

यह पदक जीतना एक सपना सच होने जैसा है, न केवल मेरे लिए बल्कि उन सभी के लिए जिन्होंने मेरा समर्थन किया है। मैं एनआरएआई, एसएआई, युवा मामले और खेल मंत्रालय, कोच जसपाल राणा सर, हरियाणा सरकार और खेल प्रेमियों की बहुत आभारी हूं।

-मनू भाकर, निशानेबाज

काम उबाऊ नहीं

एक वीडियो देखा जिसमें एक पुलिस कर्मी बेहद शानदार ढंग से यातायात को नियंत्रित कर रहा है। जो साबित करता है कि उबाऊ काम जैसी कोई चीज नहीं है। यह वही है जो आप इसे बनाना चुनते हैं।

-आनंद महेंद्रा, उद्योगपति

करंट अफेयर

हैरिस की आवाज की नकल का वीडियो किया साझा

अरबपति उद्योगपति एलन मस्क ने छेड़छाड़ किया हुआ एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया है जिसमें अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की संभावित उम्मीदवार कमला हैरिस की आवाज की नकल की गई है और वे बातें कही गई हैं जो उपराष्ट्रपति ने कभी नहीं कही हैं। इस वीडियो के कारण चुनाव में कृत्रिम मेधा (एआई) की गुमराह करने की ताकत को लेकर चिंताएं पैदा हो गई हैं। इस वीडियो ने तब लोगों का ध्यान आकर्षित किया जब मस्क ने इसे शुक्रवार शाम को अपने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर साझा किया, हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया कि इसे मूल रूप से पैरोडी (ऐसा वीडियो जिसमें किसी का उपहास उड़ाने के लिए उसकी आवाज और उसके अंदाज की नकल की जाती है) के रूप में जारी किया गया था। इस वीडियो में हैरिस के कुछ असल दृश्य जोड़े गए हैं लेकिन वीडियो में पीछे हैरिस की आवाज से मेल खाती जो आवाज सुनाई दे रही है वह वास्तव में उनकी नहीं है। वीडियो में हैरिस जैसी आवाज में कहा गया है, 'मैं, कमला हैरिस, राष्ट्रपति पद के लिए आपकी डेमोक्रेट उम्मीदवार हूं क्योंकि जो बाइडन ने बहस में आखिरकार उजागर कर दिया कि वह बूढ़े हो गए हैं।'

ऑफ बीट

दरियाई घोड़े उड़ते नहीं पर बड़े जानवर उड़ सकते हैं

1872 में कैलिफोर्निया के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के संस्थापक, लेलैंड स्टैनफोर्ड ने एक मान्यता की सच्चाई का पता लगाने के लिए एडवार्ड मुयब्रिज नामक एक विलक्षण आविष्कारक को काम पर रखा था। आविष्कारक को पता लगाना था कि क्या यह बात सच है कि घोड़ा जब दौड़ता है तो एक समय उसके चारों पैर जमीन छोड़ देते हैं। मुयब्रिज एक कुशल फ़ोटोग्राफ़र था और बीच-बीच में एक 'हवाई' घोड़े के धुंधले स्नैपशॉट लेने में कामयाब रहा - यह इस बात का उदाहरण है कि कैसे केवल नग्न आंखें तेज़, सूक्ष्म गति को नहीं पकड़ सकती हैं। वह अन्य लोगों के साथ इस बात को स्थापित करने में लगे रहे, जो बाद में सिनेमैटोग्राफी बना। उन्होंने हवा में उड़ते हुए कई जानवरों की तस्वीरें खींचना और उन्हें पकड़ने की कोशिश करना भी जारी रखा। एक अन्य बड़े जानवर, दरियाई घोड़े (जिसकी उन्होंने तस्वीर नहीं खींची) के बारे में मुयब्रिज ने लिखा: शुष्क भूमि पर यह शायद ही संभव है कि इसकी सबसे तेज़ चाल एंबल (मतलब तेज़ लेकिन फिर भी चार-चाप, पार्श्व अनुक्रम) ;के अलावा अन्य हो सकती है। एक वैज्ञानिक के रूप में जिसका शोध आंशिक रूप से इस बात पर केंद्रित है कि गैंडे, हाथी और जिराफ जैसे विशाल भूमि जानवर कैसे चलते हैं।

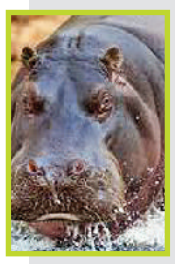

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से hbcgpati@gmail.com पर भेज सकते हैं।

https://www.epapr.in